

प्रकाशक,
मार्तण्ड उपाध्याय, मन्त्री,
सस्ता साहित्य मण्डल,
नई दिल्ली

मुद्रक
देवीप्रसाद शर्मा
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस
नई दिल्ली

लेखक की ओर से

“हमारी सारी शिक्षा व्यर्थ है, हमारी पाठशालाओ, विद्यालयों आदि पर जो कुछ व्यय किया जा रहा है; हम अक्षर-ज्ञान में जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह सब व्यर्थ है, जबतक कि हमें अपने साधारण नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों की शिक्षा नहीं दी जाती। शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने को अपने लिए, अपने कुटुम्ब के लिए, अपने समाज के लिए यथासंभव उपयोगी बना सके और समाज में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त कर सके। सच्चा नागरिक ही वास्तविक शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति है। मेरी तो यही आशा है, आकांक्षा है, यही अभिलाषा है। मैं तो उस दिन की उत्कण्ठा से प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब हमारे देश में सच्चे नागरिकों, वास्तव में कार्यकुशल नर-नारियों की हर प्रकार के कार्य में इतनी बहुतायत होगी कि हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर उसे निवाह सकेंगे, उसे स्थापित कर सकेंगे और अपने देश में उसी प्रकार से आत्मसम्मान-युक्त, स्वतंत्र-पुरुषोचित जीवन व्यतीत कर सकेंगे, जैसा अन्य देशों के स्त्री पुरुष कर रहे हैं।”

काशी के सुप्रसिद्ध कर्मशील विद्वान् श्री श्रीप्रकाश एम एल ए. ने अपने एक लेख के अन्त में उपर्युक्त विचार प्रकट किये हैं। वास्तव में शिक्षा उस समय तक व्यर्थ है जबतक कि वह व्यक्ति को एक उपयोगी श्रेष्ठ नागरिक नहीं बनाती।

आज हम बड़े गौरव के साथ यह कहते हैं कि आर्य-संस्कृति सर्वोत्कृष्ट है, आर्य-धर्म तथा आर्य-सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है। हम अपने ऐतिहासिक अतीत पर गर्व करते हैं। यह सब ठीक है और इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि गौरवमय अतीत उज्ज्वल भविष्य के लिए स्फूर्ति और बल प्रदान करता है। परन्तु जब हम अपने नागरिक जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो हमें घोर निराशा होती है यद्यपि जैसे-जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय नवचेतना बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हमारे नेताओं में

नागरिक-जीवन के सर्वतोमुख सुधार के लिए तीव्र अभिलाषा तथा चेष्टा भी स्पष्ट दीख पड़ती है ।

ससार का इतिहास यह बतलाता है कि किसी देश ने अपनी जो उन्नति की उसका श्रेय वहाँके नागरिकों के श्रेष्ठ और उच्चतम नागरिक-जीवन को ही रहा है । किसी देश में किसी महात्मा या महान् उन्नायक के जन्म लेने मात्र से ही राष्ट्र में जीवन का संचार नहीं होने लगता । इसके लिए तो समूचे राष्ट्र की आत्मा में चेतना की आवश्यकता होती है । प्रत्येक देश में महान् धार्मिक तथा राजनीतिक नेता तथा महापुरुष पैदा हुए हैं, परन्तु वास्तव में उन्नति उन देशों ने ही की है जिनकी जनता ने बहु-संख्यक श्रेष्ठ नागरिकों को जन्म दिया ।

नागरिक-जीवन को श्रेष्ठ बनाने की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या हमारे देश के सामने भी है । अभी तक हमारी शिक्षा-प्रणाली में इस महत्त्वपूर्ण अंग की उपेक्षा की गयी है । नागरिक-शास्त्र के ज्ञान के लिए कोई व्यावहारिक शिक्षा का प्रवर्धन हमारे विद्यालयों व विश्व-विद्यालयों में नहीं किया गया । हमारी शिक्षा-संस्थाओं में नागरिक शास्त्र (Civics) की सामान्य शिक्षा का प्रवर्धन तो है, पर वह पहले तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य विषय नहीं है और जो है उससे उसे कोई उपयोगी व्यावहारिक लाभ नहीं मिलता । विद्यार्थियों को नागरिक-शास्त्र की केवल सैद्धान्तिक शिक्षा दी जाती है जिसमें वे अपने जीवन में न कोई लाभ उठा सकते हैं और न वास्तविक भारतीय सांस्कृतिक एवं नागरिक जीवन से ही परिचय प्राप्त कर सकते हैं ।

मसारभर के शिक्षा-विशारद इससे सहमत हैं कि शिक्षा ही समाज के पुनर्निर्माण का आधार है । अतः हमें भारतीय शिक्षा-प्रणाली में ऐसे सुधार करने चाहिए जिसमें हमारे भावी नर-नारियों में अपनी मस्कृति, अपने आदर्शों, अपने विचारों एवं अपनी जीवन-प्रणाली के प्रति अनुराग एवं श्रद्धा का भाव उदय हो और वे वास्तविक अर्थ में सच्चे उपयोगी नागरिक बन सकें । सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के शब्दों में 'हमारा एक उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम भारत को संपृक्त, शान्त और

गौरवपूर्ण देखें जिसमें हमें जीवन का एक नवोन दृश्य देखने को मिले। हमें आर्थिक न्याय, सामाजिक समता तथा राजनीतिक स्वाधीनता के महान् आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

आज के युग में विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के चमत्कारों ने सारे ससार को एक परिवार बना दिया है। आज हमने इनके प्रताप से समय तथा दूरी पर आश्चर्यजनक विजय प्राप्त करली है। इसलिए इस युग में हमारी नागरिकता केवल नगर या राष्ट्र तक ही परिमित नहीं रह सकती। वास्तव में मानव-संस्कृति का लक्ष्य तो मानव-एकता है। इसलिए मैंने इस पुस्तक में नागरिकता पर व्यापक दृष्टि से विचार किया है और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीयता का नागरिक-जीवन से जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसकी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के साथ-साथ नागरिकता के सिद्धान्तों की मीमांसा करते हुए नागरिक-जीवन के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सभी पहलुओं पर सविस्तर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है।

आर्य संस्कृति ही ससार की सबसे प्राचीन तथा महान् संस्कृति है। अन्य संस्कृतियाँ इससे पैदा हुई हैं अथवा इसके विकृत रूप हैं। भारत में हिन्दू संस्कृति के रूप में यह संस्कृति आज भी विद्यमान है। परन्तु आज भारत में 'मुस्लिम संस्कृति' का भी अस्तित्व है। मैं इन दोनों संस्कृतियों को एक तो नहीं मानता क्योंकि दोनों में भारी मौलिक भेद है, तो भी मैं भारत में सांस्कृतिक एकता का समर्थक हूँ क्योंकि इस प्रकार के प्रयास से ही हमारे नागरिक-जीवन में समन्वय और सह-कारिता की भावना जाग उठेगी और उससे समूचे राष्ट्र का कल्याण होगा।

'सांस्कृतिक-जीवन अध्याय बड़ा होगा है। वह इस पुस्तक का मेरु-दण्ड है। इसके अन्तर्गत शिक्षा, भाषा, राष्ट्रभाषा, लिपि, साहित्य कला और संस्कृतियों पर विचार किया गया है। जहाँ भारतीय साहित्य एवं कला के विषय में विवेचन है, वहाँ मेरा अभिप्राय उनकी विशेषताओं तथा आदर्शों एवं विचारधाराओं पर ही प्रकाश डालना रहा है। मैंने भारतीय साहित्य तथा प्राचीन भाषाओं का जन-दृष्ट

७. राष्ट्रीयता

राष्ट्रीयता क्या है ?—राष्ट्रीयता के उदय के कारण—राष्ट्रीयता की भावनाएँ—भारतीय राष्ट्रीयता और ५० जवाहरलाल नेहरू ।

६८-८५

८. नागरिक-स्वाधीनता

अधिकार और कर्तव्य—नागरिक समानता—भारत का शासन-विधान और मौलिक अधिकार—आर्थिक समानता—वैयक्तिक स्वाधीनता—शरीर स्वाधीनता—विचार स्वाधीनता—गृह-विद्रोह या युद्ध-काल में नागरिक स्वाधीनता—समाचार पत्रों की स्वाधीनता—समा-मगठन की स्वाधीनता—धार्मिक स्वाधीनता—व्यावसायिक स्वाधीनता—अन्य नागरिक अधिकार—राजनीतिक अधिकार । ८६-११४

९. नागरिकों के कर्तव्य

अधिकार और कर्तव्य—कर्तव्य-परायणता की आवश्यकता—कर्तव्यों के प्रकार—शासन-प्रबन्ध में सहयोग—कानून-निर्माण में नागरिकों का योगदान—राज्यों के कानूनों का पालन—शान्ति-रक्षा में सहयोग—राज्य-कोष में कर तथा लगान आदि देना—स्वदेश-रक्षा—कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय ।

११५-१२६

१०. प्रजातन्त्र

प्रजातन्त्र क्या है ?—प्रजातन्त्र के प्रकार—प्रजातन्त्र का आधार—प्रजातन्त्र के तत्त्व—प्रजातन्त्र शासन के गुण—प्रजातन्त्र शासन के दोष—भारतवर्ष और प्रजातन्त्र—पाकिस्तान ।

१३०-१३६

११. धार्मिक जीवन

नागरिक जीवन और धर्म—वैदिक धर्म—जैन-मत—बौद्धमत—सिख-मत—हिन्दू-समाज के अन्य मत-मतान्तर—इस्लाम धर्म—ईसाई-धर्म—पारसी-धर्म ।

१४०-१५२

१२. सामाजिक जीवन

हिन्दू-जीवन—वैदिक वर्ण-व्यवस्था—वर्तमान-युग में वर्ण-

व्यवस्था—जाति-प्रथा—कुटुम्ब का प्रयोजन—संयुक्त-कुटुम्ब-प्रथा—
संयुक्त कुटुम्ब में स्त्री-पुरुष के अधिकार—संयुक्त-कुटुम्ब-प्रथा का
भविष्य—आश्रम - व्यवस्था—अस्पृश्यता—मुस्लिम-जीवन—उत्तरा-
धिकार—विवाह—तलाक । १५३-१७२

१३. नागरिकों का स्वास्थ्य

स्त्री-पुरुषों की मृत्यु-संख्या का अनुपात—भारत की मृत्यु संख्या—
भारत की जन-संख्या में वृद्धि—प्रसूति-काल में मृत्यु—जीवन-काल का
औसत—संक्रामक रोगों की वृद्धि और भीषणता—भारत के अपाहिज—
अस्वास्थ्य के कारण—स्वास्थ्य-सुधार के उपाय । १७३-१८७

१४. सांस्कृतिक जीवन

शिक्षा—प्राचीन काल में शिक्षा—स्त्रियों की शिक्षा—वर्तमान
शिक्षा-प्रणाली—अन्य शिक्षा संस्थाएँ—दलित जातियों में शिक्षा—
वर्णा-शिक्षा-पद्धति—भाषा और लिपि—हिन्दी-राष्ट्रभाषा—हिन्दी-भाषी
प्रान्त—अहिन्दी-भाषी प्रान्त—हिन्दुस्तानी—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन
और राष्ट्रभाषा—भारतीय साहित्य-परिषद और 'हिन्दी हिन्दुस्तानी'—
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और हिन्दुस्तानी—राष्ट्र-लिपि की समस्या—
साहित्य—हिन्दी-साहित्य—कला—भारतीय कला के आदर्श—संगीत-
कला—नृत्य कला—चित्र कला—वास्तु कला—मूर्ति-कला—नागरिक
जीवन और कला—संस्कृति—संस्कृति क्या है ?—आर्य-संस्कृति के
आदर्श—आर्य-संस्कृति की प्रवृत्तियाँ—अरबी और मुस्लिम संस्कृति—
मुस्लिम संस्कृति में परिवर्तन—आर्य-संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति का
प्रभाव—मुस्लिम संस्कृति पर आर्य-संस्कृति का प्रभाव—भारतीय-
संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव । १८८-२४५

१५. आर्थिक जीवन

आर्थिक स्थिति—औद्योगिक स्थिति—व्यापारिक स्थिति—भारत
के आर्थिक साधन—भारत का आर्थिक संगठन—भारत की गरीबी के
मूल कारण । २४६-२७६

कृषि—भूमि-प्रणालियाँ—बन्दावस्त—लगान की दर—जमींदारी प्रथा की उत्पत्ति और विकास—संयुक्तप्रान्त में जमींदार और उनके अधिकार—संयुक्तप्रान्त में किसान और उनके अधिकार—किमानों का कर्जा—उद्योग-व्यवसाय—कारखाने—पैदावार—ज्वायण्ट स्टॉक कम्पनियों की पूँजी—मजदूरों की दशा—मजदूरों के हित के लिए कानून ।

१६ राष्ट्रीय जीवन

शासन-पद्धति—भारतीय संघ-शासन—प्रान्तीय शासन-प्रणाली—गवर्नरों के अधिकार—प्रान्तीय व्यवस्थापक-मण्डल—स्थानिक स्वायत्त शासन—म्यूनिसिपल बोर्ड—ज़िला-बोर्ड—ग्राम-पंचायतें ।

राष्ट्रीय नवजागरण—राष्ट्रीयता का उदय—राजनीतिक मन्थाओं की स्थापना—राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) की स्थापना—वर्गभेद और स्वदेशी आन्दोलन—स्वराज की माँग ।

राष्ट्रीय आन्दोलन—गांधीयुग का आरम्भ—दमन तथा शासन-सुधार—असहयोग-आन्दोलन—स्वराज्य दल का जन्म—पूर्ण स्वराज की ओर—सत्याग्रह-आन्दोलन—गोलमेज-परिषद्—ऐतिहासिक उपवास—विधानवाद की ओर—नया शासन-विधान और कांग्रेस—कांग्रेस-मन्त्रि-मण्डल का पदत्याग—युद्धविरोधी सत्याग्रह—मुस्लिम लीग की राजनीति—नरमदल की राजनीति—हिन्दू-महासभा की राजनीति—भारतीय ईसाई और राष्ट्रीयता—दलितवर्ग और उसकी राजनीति ।

२७६-३१४

भा र ती य सं स् कृ ति

और

नागरिक जीवन

विषय-प्रवेश

समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जिन्होंने व्यक्तिगत हितों की सार्वजनिक रक्षा के लिए, सार्वजनिक व्यवहार में समता उत्पन्न करने-वाले कुछ सामान्य नियमों से शासित होने का समझौता कर लिया है। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विशेषताएँ होती हैं। इसी प्रकार समाज की भी विशेषताएँ होती हैं। समाज में व्यक्ति इन दोनों—व्यक्तिगत एवं समाजगत—विशेषताओं की रक्षा के लिए नियम बनाते हैं। समाज की प्रारम्भिक अवस्था में ये नियम अत्यन्त स्थूल और सामान्य होते हैं और जैसे-जैसे समाज विकसित और प्राविशील होता जाता है, वैसे-वैसे सामाजिक नियम अत्यन्त विस्तृत, विशद और जटिल होते जाते हैं। मानव-समाज का ऐतिहासिक दृष्टि में अवलोकन करने से यह कथन भली भाँति प्रमाणित होता है।

अनेक भारतीय और यूरोपीय राजनीति-विज्ञान-विशारदों का यह मत है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले समाज में अराजकता थी। समाज में न्याय और व्यवस्था के स्थान में शक्ति का शासन था। शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति दुर्बल व्यक्तियों का दमन करते थे। इसलिए इस दशा से तग आकर सबने इकट्ठे होकर समझौता किया और उसके फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। यह सामाजिक समझौता ही राज्य की उत्पत्ति का मूल है। मध्यकालीन यूरोपीय विचारक हॉब्स के अनुसार भी राज्य की उत्पत्ति से पूर्व अराजक दशा थी। हॉब्स के कथनानुसार इस अराजक दशा में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से निरन्तर लड़ा करता था। यह निगन्नर सघर्ष की दशा थी। सब एक-दूसरे पर सन्देह और अविश्वास करते थे। जिस तरह गुस्सेल भेड़िये एक-दूसरे को मार खाने के लिए एक-दूसरे पर झपटते रहते हैं उसी तरह मनुष्य भी आपस में एक-दूसरे का बिनाश करने के लिए सघर्ष करते रहते थे। उस समय न्याय-अन्याय और

उचित-अनुचित में कोई भेद नहीं था। उन समय गरीर-बल ही सब-कुछ था। महाभारत में अनेक स्थलों पर राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार के विचार मिलने हैं

“अराजक राष्ट्रो में धर्म स्थिर नहीं रह सकता। अराजक अवस्था में लोग एक-दूसरे को खा जाते हैं। अराजक दशा में पापी लोग दूसरों का धन छीनने ही में आनन्द अनुभव करते हैं। पर जब दूसरे लोग इन पापियों को लूटने लगते हैं, तब इन्हें राजा की आवश्यकता होती है। इस भयकर दशा में पापियों का भो तो भला नहीं होता, क्योंकि दो मिलकर एक को लूट खाते हैं और बहुत-से मिलकर दो को लूट लेते हैं। जो दास नहीं हैं, अराजक दशा में उन्हें दास बना लिया जाता है और स्त्रियों का बलपूर्वक अपहरण किया जाता है।

प्राचीन भारतीय विद्वान धर्म की स्थिति के लिए राजा को अनिवार्य समझते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि अराजक दशा में धर्म नहीं रह सकता। धर्म क्या सामान्य जीवन भी राजा के बिना नहीं रह सकता। पाणियों का उत्पत्ति-क्रम जारी रखने के लिए राजा चाहिए ही। धर्म, अर्थ, काम—इस त्रिवर्ग की प्राप्ति राज्य के बिना नहीं हो सकती।^१ मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह किसी नियामक के बिना नियन्त्रण में रह ही नहीं सकता। समाज में जहाँ कहीं भी सुव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण नियामक की सत्ता है। यदि मनुष्य सामाजिक मर्यादाओं एवं बन्धनों के अधीन न रहे, तो उसकी स्वच्छन्दता के फल-स्वरूप फिर अराजक दशा उत्पन्न हो जायगी। इस नियामक सत्ता के लिए महाभारत के शान्ति-पर्व तथा अन्य राज्य-विज्ञान के ग्रन्थों में ‘दण्ड’ शब्द का प्रयोग किया गया है

‘मनुष्य कहीं सम्मोह में पड़कर नष्ट न हो जाये, सम्पत्ति की रक्षा की जा सके, इसके लिए कोई मर्यादा चाहिए। इसी मर्यादा का नाम दण्ड है।’^२

१. महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय १५, श्लोक ३

२ “ “ “ “ १५, श्लोक १०

महाभारत में मानव-स्वभाव के सम्बन्ध में लिखा है—

“वह (मनुष्य) यदि यज्ञ करता है या दूसरे को भलाई करता है, तो केवल दण्ड के भय से। यदि वह दान करता है, तो केवल दण्ड के भय से। मनुष्य जो ठीक रास्ते पर चलता है, अपने व्यवहार को स्थिर रखता है उसका एक मात्र कारण दण्ड है।”^१

इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई। भारतीय विचारको के मतानुसार राजा ही धर्म, अर्थ, काम की उत्पत्ति का मूलधार है। प्राचीन काल में राजा की इस महत्ता के कारण ही कुछ विचारको ने राजा में दैवी शक्ति की कल्पना की। पद्म-पुराण में लिखा है—‘राजा नारायण या परमेश्वर के अंश से उत्पन्न हुआ है, वह किसी भी अवस्था में मनुष्य नहीं है।’^२

यूरोप में मध्यकाल में यूरोपीय विचारक तथा राजा राज्य की उत्पत्ति के ईश्वरीय या दैवी अधिकार में विश्वास करते थे। इस मत का पूर्ण विकास इंग्लैंड में स्टुअर्ट शासको और फ्रांस में चौदहवें लुई के समय में हुआ। चौदहवाँ लुई बड़े गर्व के साथ कहा करता था—‘मैं राजा हूँ। मेरी इच्छा राज्य की इच्छा है। मेरी आज्ञा राज्य का कानून है।’ इसी सिद्धान्त के आधार पर इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम और जेम्स अपने विरुद्ध आन्दोलन करनेवालों को ईश्वर की सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन करने का अराधी समझकर दण्ड दिया करते थे।

यद्यपि भारतवर्ष में राज्य का दैवी सिद्धान्त अत्यन्त प्राचीन काल में प्रचलित था, तथापि उसका इतना विकास नहीं हुआ था। वैदिक काल में राजा को ईश्वर या ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं समझा जाता था। भारत में कुछ मध्यकालीन विचारको ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धान्त का पतिपादन किया है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण यह था कि व्यक्ति पारस्परिक लूटमार,

१. महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय १५, श्लोक १२-१३

२. बालोऽपि नावमतव्यो मनुष्य इति भूमिष ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥

अन्याय और अव्यवस्था के परिणामस्वरूप दुःखी थे, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर यह निश्चय किया कि नमाज में नियम और मर्यादा द्वारा शांति और सुव्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए राज्य की स्थापना की जाये।

राज्य के आवश्यक अंग

‘राज्य’ शब्द एक निश्चित प्रदेश में वैध ढंग से ऐसी सुव्यवस्थित प्रजा का बोधक है जिसकी सख्या चाहे कम हो या अधिक, पर जो स्थायी रूप से उस प्रदेश में रहनेवाली हो और बाह्य नियन्त्रण से मुक्त हो। साथ ही जिसका अपना शासन हो और जो स्वभावतः उनकी आज्ञा-पालक भी हो। राज्य के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं—

१ प्रजा—यह राज्य का प्रमुख और अनिवार्य अंग है। प्रजा के अभाव में राज्य की कल्पना सम्भव नहीं, पर राज्य के लिए प्रजा की सख्या निर्धारित नहीं है। प्राचीन युग में रोम और यूनान में नगर-राज्य थे। परन्तु जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता गया, युद्धों का भय अधिकाधिक बढ़ता गया तथा नवीन-नूतन आविष्कारों की वृद्धि होती गयी, वैसे-वैसे राज्य बड़े-बड़े होने लगे और एक-एक राज्य में ३०-३० और ४०-४० करोड़ की प्रजा रहने लगी।

२ भू-खण्ड—प्रजा की तरह भू-खण्ड—निश्चित भू-खण्ड भी आवश्यक अंग है। भू-खण्ड के बिना भी राज्य की कल्पना सम्भव नहीं। यदि कोई जन-समुदाय समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करे भी और उसका एक प्रमुख भी हो, परन्तु यदि वह एक निश्चित भू-खण्ड में स्थायी रूप से निवास न करे तो वह राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। जन-समुदाय राज्य का निर्माण उत्ती दशा में कर सकता है, जब कि वह किसी प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करता हो। यह भू-खण्ड ऐसा होना चाहिए कि जिसपर किसी बाहरी सत्ता का अधिकार या नियन्त्रण न हो।

३. हित-एकता—राज्य के निर्माण के लिए एक निर्दिष्ट भूखण्ड पर रहनेवाली प्रजा में हितों की एकता का होना भी आवश्यक है। भाषा, संस्कृति, इतिहास और धर्म की दृष्टि से उनमें सामंजस्य होना जरूरी

। जिस राज्य की प्रजा में स्वाभाविक रूप में धार्मिक, साम्प्रदायिक, ऐति-
हासिक एवं भाषा-सम्बन्धी एकता एवं सामंजस्य नहीं होता, उस राज्य में
सामाजिक शान्ति स्थायी नहीं रहती। जातीय एकता भी अत्यन्त आवश्यक
है। राज्य की जनता में जाति, धर्म, सम्बन्धता, मन्त्रिणी और भाषा-सम्बन्धी
भेद-भाव ऐसे न हों जो राज्य-शासन और सामाजिक जीवन में अव्यवस्था
और अशान्ति पैदा कर दें।

४ शासन—शासन भी राज्य का प्रमुख अंग है। यदि किसी
निश्चित प्रदेश में जनता स्थायी रूप में रहती है और उसमें पारस्परिक
एकता भी है परन्तु यदि वह किसी शासन के अधीन नहीं है, तो वह
राज्य नहीं कहला सकती। शासन के अभाव में प्रजा के ऐसे नगठन
धार्मिक, आर्थिक या साम्प्रदायिक ही हो सकते हैं—राजनीतिक नहीं
हो सकते।

५ प्रभुता—प्रभुता भी राज्य का प्रमुख और आवश्यक अंग है।
प्रभुता का अर्थ यह है कि वह निर्दिष्ट प्रदेश जिनपर प्रजा स्थायी रूप
से रहती है, और जिसका अपना शासन है, वह किसी बाह्य शक्ति के
नियन्त्रण में न हो। स्वाधीनता के बिना कोई ऐसा प्रदेश राज्य नहीं
कहला सकता। उदाहरण के लिए, भारतवर्ष में मई १९३१ की जन-
गणना के अनुसार ३५ करोड़ जन हैं। परन्तु भारत का शासन और
प्रभुता भारतीय प्रजा के हाथ में नहीं है। इसीलिए राजनीतिक परिभाषा
में भारत राज्य नहीं है।

राज्य और शासन में अन्तर

उपर्युक्त विवेचन में राज्य और शासन का अंतर स्पष्ट है। सामान्यतया
राज्य और शासन को पर्याय या समानार्थक माना जाता है। परन्तु ऐसी
धारणा गलत है। राजनीतिक भाषा में राज्य और शासन में बड़ा भारी
अंतर है। राज्य एक राजनीतिक समुदाय है और शासन उसका एक अंग है।
देश के सभी निवासी सामान्यतया राज्य के सदस्य होते हैं, परन्तु शासन-
यंत्र का संचालन अल्प-संख्यक प्रजा के हाथ में होता है। यह तो नभ

है कि किसी राज्य की शासन-नीति में परिवर्तन करना समस्त जनता के हाथ में हो, परन्तु उस नीति के अनुसार शासन-प्रबन्ध का कार्य एक विशिष्ट वर्ग के हाथ में होता है। शासन में परिवर्तन होते रहते हैं, एक शासन का स्थान दूसरा शासन लेता है। परन्तु राज्य में परिवर्तन नहीं होता वह स्थायी रूप से वैसा ही रहता है। शासन राज्य का अंग है और राज्य की सुव्यवस्था के लिए शासन अनिवार्य है। यही कारण है कि शासन का महत्त्व राज्य से अधिक है।

राज्य और नागरिक

राज्य के मध्य को नागरिक कहा जाता है। इलाहाबाद विश्व-विद्यालय के राजनीति के प्रोफेसर डा० श्री वेणीप्रसाद के मतानुसार प्राचीनकाल में रोम-निवासी अधिकारों को ही नागरिकता समझते थे। जब रोम का साम्राज्य बढ़ा तब नागरिकता की नयी श्रेणियाँ हो गयीं। सबसे नीचे दर्जे की श्रेणी वह थी जिसमें लोगों को केवल दो-चार इने-गिने नागरिक-अधिकार ही प्राप्त थे और सबसे ऊँची श्रेणी वह थी जिसमें लोगों को सभी नागरिक और सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। वहाँ नागरिकता शब्द ही प्रचलित था, क्योंकि एथेन्स तथा अन्य यूनानी वस्तुओं की तरह रोम भी पहले-पहल वास्तव में एक नगर-राज्य ही था। अधिकारों का सबब, मिट्टान और व्यवहार दोनों में पहले केवल नागरिकों में था। बाद में एरान्तत्प से नागरिकों के साथ उनका मध्य केवल मिट्टान में ही रह गया। फिर नगर में निवास करना ही नागरिकता प्रामाण्य थी। जो नगर में रहता था वही नागरिक कहलाता था। बाद की उसका यह अर्थ नहीं रह गया। नागरिकता का सम्बन्ध मुख्यतः अधिकारों ही में रह गया। जो नगर में रहने लैस अधिकारों से वंचित होते थे, वे नागरिक नहीं कहलाते थे। उदाहरणस्वरूप ग्रीक नागरिक नहीं थे, क्योंकि उन्हें पीढ़ियाँ तो उन्होंने नगर में निवास किया था। उन्हें विदेशी के रूप में, जो श्रम में नगर के श्रमकों में निवास नहीं करते थे, लैस नगर के मध्य माने जाने और अधिकार-

त होते थे, नागरिक कहलाते थे ।^१

रोम और ग्रीस के नगर-राज्यों के निवासियों को 'नागरिक' कहा जाता था । उस समय नागरिकता से अभिप्राय नागरिक के अधिकारों से होता था और आधुनिक समय में भी नागरिकता से यही अभिप्राय है । परन्तु आधुनिक युग में नगर-राज्य नहीं हैं । उनके स्थान पर राष्ट्र-राज्य हैं । कालान्तर में नागरिकता की भावना में भी परिवर्तन हो गया है । नागरिकता का उद्भव रोम के छोटे-से नगर-राज्य में हुआ, परन्तु आधुनिक युग में वह समस्त देश-राज्य और राष्ट्र-राज्य में व्याप्त हो गयी है । अर्थात् नागरिक, चाहे वह नगर-निवासी हो चाहे ग्राम-निवासी, समानरूप से नागरिक अधिकारों का उपभोग कर सकता है ।

प्रोफेसर डा० बेनोप्रसाद का यह मत है कि

“अधिकारों के लिहाज से ग्रामवासी भी उसी प्रकार नागरिक हैं जिस प्रकार शहरवाले । यह बात जरूर है कि नगर राजनीतिक जीवन, धन, सभ्यता और संस्कृति के केन्द्र हैं, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि शहरवालों के हित के आगे हम गाँववालों के हित का विचार न करें । ग्रामवासियों के हित को नगर-वासियों के हित के अधीन करना उचित नहीं है । दोनों के हितों पर बराबर ध्यान रखना चाहिए । इसी प्रकार सबसे काम करने की आशा भी करनी चाहिए । व्यवसाय, सम्पत्ति-रक्षा, न्याय, कोटिभ्यक्त जीवन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक जीवन, तथा सघ-समिति के अधिकार और उनके साथ लगे हुए कर्तव्य गाँववालों से उतना ही सम्बन्ध रखते हैं जितना कि नगर-निवासियों से ।”^२

हिन्दी-साहित्य में 'नागरिक' शब्द का प्रयोग नगर-निवासी के अर्थ में प्राचीन समय से होता रहा है । हिन्दी में 'नागर' या 'नागरिक' शब्द का

१ डा० बेनोप्रसाद नागरिक शास्त्र • चौथा अध्याय, पृ० ७४-७५ (सन् १९३७)

२. उपर्युक्त ।

अर्थ है नगर में रहनेवाला । प्राचीन-काल में 'नागरिक' शब्द चतुर, शिष्ट तथा सम्पन्न के अर्थ में भी प्रयुक्त होता था । अंग्रेजी में 'मिटीजनशिप' का जो अर्थ है, वही अर्थ हिन्दी में 'नागरिकता' का भी है ।

इस सम्बन्ध में संक्षेप में यह जान लेना उचित होगा कि राजनीतिक भाषा में 'नागरिक' और 'प्रजा' इन दोनों में अन्तर है । स्वाधीन राज्य के निवासी नागरिक कहलाते हैं, और परन्तु, अर्द्धपरन्तु या एकतन्त्र राज्य के निवासी 'प्रजा' कहलाते हैं, यद्यपि वैदिक और भारतीय साहित्य में 'प्रजा' शब्द का प्रयोग नागरिक के अर्थ में ही किया गया है । वेदों के अनेक मंत्रों में राजा-प्रजा के कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख मिलता है । किन्तु आधुनिक समय में 'प्रजा' शब्द 'नागरिक' शब्द से हीन कोटि का है । 'प्रजा' से एक ऐसे जन-समुदाय का बोध होता है, जो ऐसे शासन के नियंत्रण में रहता है, जिसके नचालन में उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किमी भी रूप में हाथ नहीं ।

परन्तु इस सम्बन्ध में एक अपवाद है । इंग्लैण्ड के नागरिक 'प्रजा' कहलाते हैं, यद्यपि वे नागरिकता के अधिकारों से युक्त हैं । दूसरी ओर भारत के निवासी भी प्रजा कहलाते हैं, नागरिक नहीं, यद्यपि भारतीयों को नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हैं ।

नागरिक-शास्त्र क्या है ?

जिस समय यूनानियों ने अपने देश में नगर-राज्यों की स्थापना की उसी समय में रोमवासियों ने इटली में वैसे ही नगर-राज्य स्थापित किये । वे नगरों को 'सिडिटीस' कहते थे । अंग्रेजी में 'मिटी'—नगर—शब्द की उत्पत्ति इसी शब्द से हुई है । लैटिन भाषा के 'सिडिम' शब्द का अर्थ नागरिक है । प्राचीन समय में यूनान में 'पॉलिटिक्स' शब्द का प्रयोग नगर के मामलों के सम्बन्ध में किया जाता था । इसी प्रकार इटली में नगर के मामलों के सम्बन्ध में 'निक्किन' शब्द का प्रयोग किया जाता था । इस प्रकार भाषा-विज्ञान के अनुसार पॉलिटिक्स, राजनीति, 'निक्किन' और नागरिक-शास्त्र का एक-सा ही अर्थ है । रोम और यूनान की

सभ्यता का प्रभाव समस्त यूरोप के देशों पर पड़ा और नागरिकता, नागरिक सभ्यता आदि शब्दों का प्रयोग अन्य भाषाओं में भी होने लगा। यही कारण है कि राजनीति और नागरिकशास्त्र में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि उनके बीच विभाजक रेखा खींचना अनम्भव नहीं तो कठिन ज़रूर है।

राजनीति-विज्ञान और नागरिक-शास्त्र दोनों ही का राज्य के नागरिकों से सम्बन्ध है। वे मनुष्यों मानव-समाज तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन करते हैं। नागरिकों के अधिकारों और राज्य के प्रति उनके कर्तव्यों का प्रतिपादन नागरिक-विज्ञान का विषय है। नागरिक-शास्त्र ऐसी अवस्थाओं और परिस्थितियों का निर्देश करता है जो नागरिकों के अनुकूल होती हैं और जिनमें रहकर वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक उन्नति कर सकते हैं। नागरिक-शास्त्र इस बातका विवेचन करता है कि नागरिक-जीवन किस प्रकार उत्तम और सुखी बनाया जा सकता है। नागरिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए राज्य की ओर से क्या-क्या सुयोग, सुविधाएँ होनी आवश्यक हैं, किन-किन कार्यों में राज्य को व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे कौन-से उपाय हैं जिनके द्वारा प्रत्येक नागरिकको यह विश्वास हो जाये कि वह शान्ति-पूर्वक अपने धर्म के फल का उपभोग करना हुआ अपने राष्ट्र, नगर और विश्व में शान्ति-स्थापित करने में योग दे सकेगा।

राजनीति-विज्ञान और नागरिक-शास्त्र में अन्तर

विषय की दृष्टि से इन दोनों में तनिक भी अन्तर नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि एक जिस बात पर अधिक जोर देता है दूसरा उसपर उतना जोर नहीं देता। निम्नलिखित तुलनात्मक वर्णन में यह सहज में जाना जा सकता है—

राजनीति-विज्ञान

नागरिक-शास्त्र

१ राजनीति-विज्ञान विशेषतः १ नागरिक-शास्त्र विशेषतः
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विषयों स्थानीय विषयों से सम्बन्ध रखता

का विवेचन करना है ।

है ।

२ राजनीति-विज्ञान राजनीतिक मम्याओ और व्यवम्याओ के विकास का इतिहास बतलाता है ।

२ नागरिक-शास्त्र उमविकान को पहले से ही मान लेता है ।

३ राजनीति-विज्ञान मुख्यतः अधिकारों और उनकी प्राप्ति के उपायों पर जोर देता है ।

३ नागरिक-शास्त्र मुख्यतः कर्तव्यों और उनके सम्पादन के लिए आवश्यक शिक्षा और आचरण पर जोर देता है ।

अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि नागरिक-शास्त्र का विषय समूचे नागरिक-जीवन को श्रेष्ठ बनाना है—उसकी उन्नति करना है । वह सामाजिक अवम्याओं और परिस्थितियों की जाँच-पड़ताल करना है, इसलिए विज्ञान है और अनुसंधान के परिणामों का उपयोग नागरिक जीवन की उन्नति के लिए करना है, इसलिए वह कला भी है ।

नागरिक शिक्षा

नागरिक-शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता

नागरिक-शास्त्र का उद्देश्य नागरिक-जीवन को पूर्ण और ध्येष्ठ बनाना है । राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह नागरिक के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का यथावत् ज्ञान प्राप्त करके उनका पालन करे । यह ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब वह नागरिक-शास्त्र का भली भाँति अध्ययन करके उसके सिद्धान्तों, आदर्शों एवं नियमों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करे । भारत में स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों व छात्राओं को यह विषय पढ़ाया जाता है । परन्तु यह विषय वैज्ञानिक ही है । अभी तक नागरिक शास्त्र का अनिवार्य रूप से इन सस्याओं में अध्ययन नहीं किया जाता । इस कारण अधिकांश छात्र नागरिक-शास्त्र के सिद्धान्तों व नियमों में अनभिज्ञ ही रहते हैं । इसका परिणाम प्रत्यक्षत व्यावहारिक जीवन में देख पड़ता है । हममें नागरिक-भावना के अभाव का यह एक बड़ा कारण है ।

प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य के नागरिकों को शासन-कार्यों के प्रति दिलचस्पी हो । जिस राज्य के नागरिक स्वदेश की राजनीति में अधिक दिलचस्पी लेते हैं, उसमें प्रजातन्त्र की सफलता की अधिक संभावना होती है । जबसे भारत के ११ प्रान्तों में 'प्रान्तीय स्वशासन' की स्थापना हुई है, तबसे शासन-कार्य में जनता की दिलचस्पी पैदा होने लगी है । जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क होगयी है । यदि शासन नागरिकों के अधिकारों पर कुठाराघात करनेवाली किसी नीति या कार्य को करने का निश्चय करे, तो यदि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हैं, वे उसका विरोध करके सरकार को उसे बदल देने के लिए बाध्य कर सकते हैं ।

भारत में शिक्षा-शास्त्री और लोक-नेता यह अनुभव करने

लगे हैं कि भारत की शिक्षा-प्रणाली का पुनर्निर्माण इस ढंग से किया जाये कि उसमें भारतीय संस्कृति का पूरा विचार रखते हुए नागरिकता के श्रेष्ठ आदर्शों को स्थान मिले, जिसमें शिक्षा जीवनोपयोगी बनने के साथ साथ जीवन को ऊँचा उठानेवाली भी बन सके। वर्धा-शिक्षा-समिती की रिपोर्ट में इसी मन का प्रकाशन किया गया है। इस रिपोर्ट के योग्य लेखकों का यह मन विचारणीय है कि

“हमारी यह आकांक्षा है कि वे अध्यापक और शिक्षा-विशारद जो इस नवीन शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग को अपने हाथों में ले, इस योजना में निहित नागरिकता के आदर्शों को भलीभाँति समझ लें। आधुनिक भारत में नागरिकता देश के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और साम्प्रदायिक जीवन में अत्रिकायिक प्रज्ञानदाय हो जायगी। कम-से-कम नये युग की संस्कृति को अपनी समस्याओं अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानने-समझने के लिए सुयोग्य मिलना चाहिए। नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों के विवेकपूर्ण उपभोग के लिए कम-से-कम शिक्षा-प्राप्ति के निमित्त एक सर्वथा नयी प्रणाली की आवश्यकता है। दूसरे, आधुनिक समय में, विवेकशील नागरिक को समाज का सक्रिय सदस्य बनना चाहिए। उसमें अपनी क्षमता हो कि वह अपने समाज के सदस्य की हंमियन में किसी उपयोगी सेवा के रूप में समाज की प्रतिदान कर सके।”

द्विविधता का अध्ययन और नागरिकता

द्विविधता, नैतिक, समाज-विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनैतिक-शास्त्र, नागरिक-शास्त्र आदि सब विज्ञान सामाजिक विज्ञान हैं। इन विज्ञानों का मानव-समाज में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। उनका या करना अधिक उपयुक्त होगा कि मानव-समाज के अन्तर्गत यह ही एक विज्ञान या विज्ञान समूह है। इन विज्ञानों या परन्तु उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है कि हम उनके पर को दूसरे से अलग करते समय नहीं करते। मानव में वे मानव-समाज

पर विचार करने के विभिन्न दृष्टिकोण हैं ।

इतिहास मानव-समाज की अतीत काल की घटनाओं, कार्यों, ज्ञान और अनुभवों का वैज्ञानिक वर्णन है । प्राचीन युग के मानव-समाज के रीति-नियमादि के अध्ययन के आधार पर ही सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ है । नागरिक शास्त्र के उपादान तो स्पष्टतः इतिहास से प्राप्त किये गये हैं । समाज की अवस्था के विकास के साथ-साथ, उसके आदर्श, नियमों एवं अवस्थाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं । इन परिवर्तनों और अनुभवों के प्रकाश में सामाजिक विज्ञानों में भी परिवर्तन होते रहते हैं । अतः इतिहास के साथ साथ नागरिक-शास्त्र का भी अध्ययन जरूरी है ।

सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य

सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का उद्देश्य यह है कि मानव-जाति के उत्कर्ष और कल्याण के लिए नागरिकों में मानव-हित का सम्यक् विकास हो । समाज में जो अभाव और जो आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति के लिए नागरिकों को प्रेरणा व स्फूर्ति मिले । नागरिकों में मातृ-भूमि के लिए भक्ति-भावना तथा मानव के प्रति अनुराग पैदा हो और वे न्याय, न्याय प्रेम के आधार पर समाज-रचना कर सकें । नागरिकों को अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का ज्ञान पैदा हो और वे अपने अधिकारों की प्राप्ति, रक्षा एवं भोग कर सकें । सारांश यह है कि मानवता के चरम उत्कर्ष के लिए नागरिकों को सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करना अनिवार्य है । यदि मानव-हित की भावना से नया अध्ययन करके, उनके द्वारा प्रतिष्ठित मानवीय आदर्शों के अनुसार अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाया जाय तो विश्व में सहकारिता, न्याय, प्रेम और न्याय का राज्य स्थापित होना अनभव नहीं ।

नागरिक-शास्त्र के अध्ययन की पद्धति

नागरिक-शास्त्र का अध्ययन केवल ज्ञान-मार्ग ही नहीं होना चाहिए

बल्कि उसे शिक्षाप्रद और प्रयोगात्मक भी होना चाहिए। नागरिक शिक्षा ज्ञानवर्द्धक के साथ शिक्षाप्रद और प्रयोगात्मक होनी चाहिए। आजकल स्कूलों व कालेजों में इस विषय की जो शिक्षा दी जाती है, वह केवल ज्ञानवर्द्धक ही है। व्यावहारिक न होने से वह जीवनोपयोगी नहीं है।

नागरिक-शिक्षा ज्ञान-वर्द्धक हो—इसका अभिप्राय यह है कि पाठकों को नगर की, देश की और मसार की स्थिति और अवस्था का ज्ञान हो जाये। देश के राष्ट्रीय जीवन के विविध क्षेत्रों का ज्ञान जरूरी है। देश की नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अवस्था का ज्ञान प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। इन आवश्यक ज्ञान के अभाव में वह अपने कर्तव्य कार्यों का यथाविध पालन नहीं कर सकता।

नागरिक-शिक्षा शिक्षाप्रद भी हो—इसका मतलब यह है कि नागरिकों को शिक्षा ऐसे ढंग से दी जाये कि वे अपने परिवार, पाठशाला, कालेज, पड़ोस, वस्ती, ग्राम, नगर, समाज, राज्य और अन्त में विश्व के मानवों के प्रति सामाजिक व्यवहार के आधारभूत सिद्धान्तों को हृदयगम कर सकें। उन्हें अपना नागरिक जीवन सुखी और श्रेष्ठ बनाने के लिए पथ-प्रदर्शन मिले तथा उनमें सामाजिक समस्याओं के प्रति आदर और श्रद्धा पैदा हो तथा वे उनके संचालन एवं प्रवर्धन में सहयोगपूर्वक भाग ले सकें। नागरिकों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाये कि वे लोक-मग्रह, सामाजिक न्याय, सहकारिता, राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता के सिद्धान्तों को भली भाँति समझ लें।

नागरिक-शिक्षा सैद्धान्तिक होने के साथ-साथ प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक भी हो। नागरिक शिक्षा और नागरिक जीवन में स्पष्ट संबंध होना चाहिए। जिस प्रकार रसायन या भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी अपनी प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं, उसी प्रकार नागरिक-शास्त्र के विद्यार्थियों को मानव-समाज की प्रयोग-शाला में प्रयोग करने का अवसर मिलना चाहिए। स्वदेश और मसार के मानव समाज के संस्कारों, रीति-रिवाजों, सामाजिक दशाओं और नागरिक दशाओं का अध्ययन

और अन्वेषण करके नागरिक जीवन के अनेक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है यही नागरिक शिक्षा की व्यावहारिकता है। अपने नगर या ग्राम के जन-समाज की सामाजिक स्थिति, जीवनचर्या, आर्थिक जीवन आदि की जाँच-पड़ताल द्वारा प्रयोग शुरू किया जा सकता है और समय और सुविधा के अनुसार यह प्रयोग एक बड़े पैमाने पर भी किया जा सकता है।

नागरिक-शिक्षा के लिए तीक्ष्ण बुद्धि, कल्पना-शक्ति, सहानुभूति और सेवाभाव की बहुत जरूरत है। नागरिक-शास्त्र के विद्यार्थी को विचार-शक्ति से अधिक काम लेना चाहिए। अपने से अधिक श्रेष्ठ विद्वानों के विचारों, सिद्धान्तों और सम्मतियों से प्रभावित होकर, तर्कों की कसौटी पर उन्हें परखें बिना अपनाते से उसका प्रयोग निष्पक्षता से पूरा नहीं हो सकता। विद्यार्थी को चाहिए कि वह देश या ससार के मानव-समाज की स्थितियों और सामाजिक जीवन की जाँच-पड़ताल करते समय साम्प्रदायिक या सहीर्ण मनोवृत्ति से काम न ले। उसमें कल्पना-शक्ति की भी आवश्यकता है। कल्पना-शक्ति के अभाव में उसका प्रयोग सफल हो सकेगा, इसमें सन्देह है। जब हम समाज के विभिन्न व्यक्तियों, समुदायों और वर्गों की स्थितियों का निरीक्षण करते हैं, तो हम एक सीमा तक अपने को भी उन स्थितियों में अनुभव करके, उनकी दशा पर विचार करते हैं। उदाहरणार्थ, अगर प्रयाग-विश्वविद्यालय का राजनीति का एक छात्र सयुक्तप्रान्त के किसी पूर्वी जिले के ग्राम-जीवन का अध्ययन और निरीक्षण करना चाहे तो उसे अपने मानसिक दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस छात्र ने अपने जीवन का अधिक समय होस्टली में सुख और आनन्द के साथ बिताया है, जिसने नागरिक जीवन के लिए विज्ञान और आधुनिक अन्वेषणों ने जो सुविधाएँ और साधन प्रदान किये हैं, उनका उपभोग किया है, जिसने सिनेमा, नाटक, थियेटर, संगीत तथा नृत्य का आनन्द उठाया है और जो हर समय 'शिक्षित वातावरण' में साँस लेता रहा है, ऐसा विद्यार्थी यदि महसा ग्राम-जीवन के अध्ययन के लिए किसी गाँव को चले पड़े तो उसकी सारी दुनिया ही

बदल जायेगी। वह अपने को एक सर्वथा नये और अपरिचित वातावरण में पायेगा। इस ग्राम-जगत की आँकी के लिए उसे एक ग्रामीण होना होगा और ग्रामीण बनकर ही वह उनके मनोभावों, विचारों, आदर्शों और आवश्यकताओं को जान और समझ सकेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए उसे कल्पना-शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें सेवा-भाव का होना जरूरी है। इसके बिना वह जीवन का अध्ययन सफलतापूर्वक कर सकेगा। सेवा-भाव महानुभूति में उत्पन्न होता है। महानुभूति अर्थ है दूसरों के दुःख-सुख की अनुभूति। विद्यार्थियों में नागरिक भाव का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि उनमें लोक-मग्नता का भाव जगायी जाये। समाज-सेवा के लिए विमूक्त ध्येय है। केवल जरूरतों विद्यार्थी-वर्ग में समाज-सेवा के लिए सच्ची लगन की, प्रदर्शन की न

अपने गाँव के किसानों, अपने नगर के मजदूरों तथा दूसरे शोषित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जाँच-पड़ताल की जा सकती है। इस प्रकार वे उनके जीवन को सुधारने के लिए उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों में न केवल उनका ज्ञान ही बढ़ेगा बल्कि वे पीड़ित मानवता की सेवा भी कर सकेंगे।

विश्वविद्यालयों और कालेजों के छात्र एवं छात्राएँ 'सेवासथ' बनाकर निकटवर्ती गाँवों के निवासियों के सम्पर्क में आकर उनकी सामाजिक दशा का निरीक्षण कर सकते हैं। इन सेवा-मण्डलों द्वारा ग्रामवासियों का स्वास्थ्य, ज्ञान और शक्ति का सन्देश दिया जा सकता है। साक्षरता प्रसार के लिए प्रीड-पाठशालाओं का मंचालन, रोगियों की सेवा, जल में स्वास्थ्य के सिद्धान्तों व सफाई के नियमों का प्रचार, किसानों अपनी कृषि तथा धन्यों में सुधार करने के उपाय बतलाना, नगरों में मजदूरों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए प्रयत्न करना आदि आदि जन-सेवा के अनेक मार्ग हैं। इन साधनों द्वारा नागरिक शिक्षा का व्यावहारिक अध्ययन किया जा सकता है।

मैसूर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त-उत्सव में ६ अक्टूबर १९३८ ई. को स्वर्गीय दीनबन्धु श्री० एफ० एण्ड जे ने अपने दीक्षान्त भाषण में सभी प्र

के विचार व्यक्त किये थे

'मेरा ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस विश्व-विद्यालय के विद्यार्थी गांवों में जाते हैं, और अपनी कल्पना के अनुरूप कार्य का प्रतीक मैंने बगलौर में शुरू कर दिये गये काम में पा लिया है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि इस दिशा में इतने भी अधिक एकनिष्ठ प्रयत्न किया जाये। क्या कोई ऐसा आश्रम या बस्ती नहीं हो सकती, जिसका विश्वविद्यालय से सीधा सम्बन्ध हो, जिसकी अपनी इमारतें हो और जहाँ विश्वविद्यालय के वे स्नातक जा सकें जो दोन-दुखियों के दुःख में घुल-मिल जाने का सकल्प कर चुके हैं ?'

विद्यालय, विद्वन्मण्डल, संगीत-परिषद्, नाट्य-परिषद्, साहित्य-परिषद् आदि । कुछ मानव-समुदाय स्वतन्त्र हैं, दूसरे परतन्त्र हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो स्वतन्त्र देशों के प्रभाव में हैं अथवा अर्द्ध-स्वतन्त्र हैं ।

इन समस्त समुदायों में राज्य, धर्म और जाति-सम्बन्धी समुदाय ही प्रमुख हैं । आज के मानव-समाज में ये तीन तत्त्व मानव-एकता, मानव-संगठन और विश्व-शान्ति के लिए महान् सकट सिद्ध हो रहे हैं ।

सत्सार में प्रत्येक स्वतन्त्र राज्य उग्र राष्ट्रवादी है । वह सत्सार के दूसरे राष्ट्रों को अपने आधिपत्य, प्रभाव या अधिकार में लाना चाहता है । आज यूरोप, अमरीका, एशिया और अफ्रीका में इसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है । जर्मनी समस्त सत्सार में चक्रवर्ती राज्य की कामना करता है । इसी उद्देश्य से वह यूरोप में युद्ध में तल्लीन है । जापान एशिया का शिरोमणि होना चाहता है और इसलिए वह चीन और हिन्द-चीन को दमता हुआ ब्रह्मा की ओर पैर बढ़ा रहा है । इटली रोमराज्य का मधुर स्वप्न देख रहा है, इसलिए अफ्रीका में वह बमबर्षा कर रहा है । इस प्रकार ये स्वाधीन राष्ट्र-राज्य मत्सार की स्वाधीनता को कुचल रहे हैं ।

धर्म, जो वास्तव में मानव-समाज में एकता और आध्यात्मिक प्रेम तथा सहकारिता पैदा करने के लिए है, आज उग्र राष्ट्रवादी देशों की साम्राज्य-विस्तार की कामना की पूर्ति का साधन बन गया है । धर्म के नाम पर बड़े-से-बड़ा पाप किया जा रहा है और उन्ने पवित्र कृत्य सिद्ध कराने के लिए धर्माचार्यों तथा पोप-पादरियों को खरीदा जा रहा है ।

इसी प्रकार जाति (Race) की उग्र आत्म-चेतना आज सत्सार-सकट का कारण बन रही है । अबतक गोरी जातियाँ यह दावा करती रही कि हमें ईश्वर ने सत्सार की अन्य (काली, पीली, भूरी) जातियों को सभ्यता का सन्देश देने के लिए पैदा किया है, हमी मत्सार पर आधिपत्य करने के योग्य हैं, परन्तु अब इस युग में जर्मनी में हेर रिटलर या यह दावा हो रहा है कि केवल जर्मन ही पवित्र आर्य जाति के हैं, शेष यूरोप की जातियाँ वर्ण-सकर हैं । इसी कारण जर्मन रान की पवित्रता की रक्षा करने

के लिए हिटलर ने अपने राज्य से यहूदियों को देश-निकाला दे दिया ।

विश्व के महायुद्ध (१९१४-१८) के बाद यूरोप के राष्ट्रों ने धर्म राज्य तथा जाति के बन्धनों से ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के विकास के लिए राष्ट्रमण्डल की स्थापना करने का प्रयत्न किया । परन्तु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली ।

समर के महान् राज्य

आधुनिक काठ में ग्रेट-ब्रिटेन, संयुक्त-राज्य अमेरिका, सोवियट रूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, चीन विश्व के महान् राज्य हैं । पृथ्वी पर चार बड़े-बड़े महाद्वीप हैं—एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका (उत्तरी व दक्षिणी) । उनमें अमेरिका की राजनीति की कुलीन संयुक्त-राज्य अमेरिका के हाथ में है । दक्षिणी अमेरिका के राज्यों पर उसका प्रभाव और अधिकार है । प्रायः १०० वर्षों में संयुक्त-राज्य सारा-विश्व के अनुसार यूरोपीय राष्ट्रों के हस्तक्षेप में दक्षिणी अमेरिका को सक्त रखा हुआ है । उसके बाद ग्रेट-ब्रिटेन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह ब्रिटिश राष्ट्र-समूह की गुरी है और उसके चारों ओर उत्तरी अमेरिका तथा अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान और आयरलैंड में ब्रिटेन का साम्राज्य है । भारत में भी १५० वर्षों से ब्रिटेन के आधिपत्य में है । उस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य आज समस्त में सर्वोच्च शक्ति राज्य है ।

पाँच राज्य बड़े हैं और वे शेष २९ राज्यों पर अपना प्रभाव बनाये हुए हैं। जब उनको अपने किसी हित में बाधा जान पड़ती है तो वे दूसरे राष्ट्र में अपने अल्पमत की रक्षा के नाम पर युद्ध में प्रवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान् यूरोपीय युद्ध का आरम्भ भी इसी बहाने हुआ है। जर्मनी का यह अभियोग था कि पोलैण्ड में बसनेवाले जर्मनों के साथ पोल (पोलैण्डवासी) बड़े नृशंस और भीषण अत्याचार करते हैं। उनकी रक्षा के लिए ही जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण किया, ऐसा हेर हिटलर का दावा है। यूरोप के इन बड़े राष्ट्रों के अफ्रीका और एशिया में साम्राज्य है—उपनिवेश है, प्रभाव-क्षेत्र है। प्रत्येक महान् राष्ट्र का सदैव यही प्रयत्न रहा है कि वह अपने साम्राज्य, उपनिवेशों तथा प्रभाव-क्षेत्रों को सुरक्षित रखे तथा उनमें वृद्धि करे।

ससार की पराधीन जातियों

एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका में पराधीन और अर्द्ध-परतंत्र जातियों की प्रधानता है। सन् १९२९ की जन-संख्या के अनुसार ससार के समस्त देशों की कुल जन-संख्या १,९९,२५,२९,००० है।^१ एशिया, अफ्रीका और अमरीका में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, संयुक्त-राष्ट्र, नैदरलैण्ड, पुर्नगाल आदि देशों के साम्राज्य और उपनिवेश हैं। सन् १९१४-१८ के यूरोपीय महायुद्ध के पहले अफ्रीका में जर्मनी के भी उपनिवेश थे, परन्तु वार्साई की सन्धि के अनुसार उनका अधिकार जर्मनी से ले लिया गया और वे मित्र-राष्ट्रों के नियंत्रण में आ गये। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत पराधीन जातियों की जन-संख्या ४० करोड़ ५८ लाख २४ हजार है। यह नसार में सबसे बड़ा साम्राज्य है। इसके बाद नैदरलैण्ड का स्थान है। इस देश के साम्राज्य के अन्तर्गत पराधीन जातियों की जनसंख्या ६ करोड़ २ लाख १९ हजार है। फ्रांस तीसरा साम्राज्यवादी राष्ट्र है। उसके साम्राज्य के अन्तर्गत पराधीन जातियों की आबादी

१ लीग ऑफ नेशन्स की 'स्टैटिस्टिकल ईयरबुक' - १९३०-३१

एशिया के पराधीन राष्ट्र

एशिया में केवल दो राष्ट्र ऐसे हैं जो पाश्चात्य देशों के साथ प्रतियोगिता में ठहर सकते हैं। वे हैं जापान और तुर्किस्तान। इन दोनों राष्ट्रों ने आधी सदी में ही अपने देशों में कायापलट कर दी। एशिया में जापान, चीन, ब्रह्मा, तुर्किस्तान, तिब्बत, नेपाल, भारत, लका, हिन्दचीन, स्याम, इन्डोनेशिया, फारस, सीरिया, इराक, फिलस्तीन, कोरिया और फिलिपाइन द्वीप आदि राष्ट्र हैं। इनमें भारतवर्ष, ब्रह्मा, तथा लका ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हैं। फिलस्तीन राष्ट्रसंघ के शासनादेश के अनुसार ब्रिटेन के नियंत्रण में है। सीरिया पर फ्रांस का नियंत्रण है। नेपाल स्वतंत्र राज्य है, तो भी वह ब्रिटेन के प्रभाव में है। हिन्दचीन में फ्रांस का साम्राज्य है। इराक और सीरिया भी ब्रिटेन के कब्जे में हैं।

चीन यद्यपि स्वाधीन राष्ट्र है, तो भी उसकी दशा पराधीन राष्ट्र तक से गयी-बिती है। उसपर दस वर्षों से साम्राज्यवादी जापान की कोपदृष्टि है। उसने चीन के कई प्रान्तों का अपहरण कर लिया है और अब भी उसकी साम्राज्य-पिपासा शान्त नहीं हुई है। जापान का सिद्धान्त है कि एशिया एशियायी लोगों के लिए है। उसपर गैर-एशियायी राष्ट्रों की आधिपत्य जमाने का कोई अधिकार नहीं है। जापान जो आज से ५० वर्ष पहले औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा देश था, आज यूरोप से कला-कौशल सीखकर न केवल विज्ञान और कला की नकल अपने देश में कर रहा है बल्कि वह यूरोप की जैसी भयंकर स्थिति एशिया में भी पैदा कर रहा है। उसने यूरोप के नैतिकवाद और साम्राज्यवाद की नकल करने में सफलता प्राप्त की है और आज एशिया जापान के साम्राज्यवाद से सहम रहा है।

चीन में आन्तरिक कलह वर्षों से है। राष्ट्रीय एकता के अभाव में जापान ने सन् १९३१ में चीन पर आक्रमण कर दिया और उसके कई प्रदेशों को हड़प लिया। उस समय जापान राष्ट्रसंघ का सदस्य था। चीन भी राष्ट्रसंघ का सदस्य था। जब चीन पर जापान का आक्रमण

भारत में विदेशी राज्य ने भारत को राष्ट्रीयता की चेतना प्रदान की है। आज भारत में राष्ट्रीयता का अधिक प्रभाव है और इसने राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर अपनी गहरी छाप लगा दी है। भारत के प्रान्तों में ही नहीं बल्कि देशी राजाओं के राज्यों की जनता में भी स्वाधीनता पाने की आकांक्षा उत्पन्न होगयी है। राष्ट्रीय-महामा—कांग्रेस—का भारत के राष्ट्रीय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वह भारत की सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था ही नहीं है बल्कि एक अपूर्व राष्ट्रीय शक्ति है। उसका लक्ष्य है भारत की जनता के लिए स्वाधीनता प्राप्त करना। आज भारतीय जनता स्वाधीनता के पथ पर अग्रसर है। सन् १९३५ के भारतीय शासन-विधान के अनुसार भारत के ११ प्रान्तों में प्रान्तीय स्वशासन (उत्तरदायी शासन) की स्थापना १ अप्रैल सन् १९३७ से हो चुकी है। सात प्रान्तों में कांग्रेस-पार्टी के मणि-मण्डलो ने शासन चलाया है। कांग्रेस उपर्युक्त शासन-विधान को राष्ट्र के लिए अपर्याप्त और असन्तोषजनक मानती है और उसे अस्वीकार्य घोषित करती है। भारत के दूसरे राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक वर्गों ने भी इस विधान को असन्तोषप्रद घोषित किया और विशेष रूप से विधान की सघ-योजना का कांग्रेस और मुसलिम-लीग ने घोर विरोध किया यद्यपि विरोध करने में दोनों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न रहे हैं।

भारत की स्वाधीनता की समस्या आज बड़ी जटिल बन गयी है। भारत में साम्प्रदायिक कलह के कारण राष्ट्रीय एकाता का अभाव है। उसके अतिरिक्त देशी राज्यों के नरेश भी स्वाधीनता-प्राप्ति में रोजे अड़ाने हैं। १ सितम्बर १९३९ को यूरोप में महायुद्ध छिड़ जाने ने ब्रिटेन पोलैण्ड की रक्षा के लिए युद्ध में उतर पड़ा और भारत को भी युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। राष्ट्रीय महासभा ने ब्रिटिश सरकार की इस नीति पर असन्तोष प्रकट किया। उसका कहना है कि भारतीय जनता की सम्मति लिए बिना उसे युद्ध में शामिल करना उचित नहीं। इस प्रकार युद्ध ने भारत में एक बड़ा वैधानिक संकट पैदा कर दिया है।

इसके अलावा, फिलिस्तीन और सीरिया राष्ट्रमण्डल के शासनादेश के अनुसार

ब्रिटेन और फ्रांस के नियन्त्रण में हैं। सीरिया पर फ्रांस का नियन्त्रण है।

फिलस्तीन अंग्रेजों के संरक्षण में है। वास्तव में यह अरबों का देश है। एक अंग्रेज हाई कमिश्नर उसका शासन-प्रबन्ध एक कमिटी की सलाह से करता है। अरब इस प्रकार के संरक्षण के सदा से विरोधी रहे हैं। जबसे जर्मनी ने यहूदियों को निकाल दिया है तबसे उनके उपनिवेश के लिए तरह-तरह की योजनाएँ सोची जा रही हैं। यहूदी और अरब ये दो विभिन्न जातियाँ हैं। यहूदियों में बड़े-बड़े पूंजीपति हैं। उन्होंने फिलस्तीन में बसकर उसे चमन बना दिया है। उनकी आर्थिक दशा में बड़ा सुधार हो गया है। परन्तु इन दोनों में संघर्ष जारी है। अरब यह नहीं चाहते कि उनके देश का बँटवारा हो। दूसरी ओर यहूदियों की बढ़ती हुई संख्या के लिए प्रदेश की आवश्यकता है। यहूदी-अरब संघर्ष का अन्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक शाही कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि फिलस्तीन को अरब और यहूदियों में बाँट दिया जाय। इस प्रकार अरबों में और भी असन्तोष पैदा हो गया है।

सीरिया फ्रांस के आधिपत्य में है। परन्तु सन् १९२८ में वहाँ उत्तर-दायी शासन की स्थापना कर दी गयी।

भारत के उत्तर में स्थित तिब्बत देश पर भी ब्रिटेन का प्रभुत्व है। इन्डोनेशिया डच (हालैण्ड के) साम्राज्यवाद का शिकार है। इस देश में सन् १९२७ से स्वाधीनता-प्राप्ति का आन्दोलन हो रहा है। परन्तु अभी तक उसे स्वतन्त्रता नहीं मिल पायी है।

हिन्द-चीन फ्रांस का उपनिवेश है। उसकी प्रजा विदेशी शासन के विरुद्ध है। वह भी विदेशी बन्धन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है। इस समय जापान इस देश पर आक्रमण कर रहा है।

फिलिपाइन द्वीप पर संयुक्तराज्य अमेरिका का आधिपत्य है। इस देश के निवासी वर्गों से स्वाधीनता प्राप्ति के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। परन्तु उन्हें आज तक स्वतन्त्रता नहीं मिली है।

अफ्रीका के उपनिवेश

अफ्रीका सबसे पिछड़ा हुआ देश है। सोलहवीं सदी में जब दास-व्यापार बड़े वेग के साथ चल रहा था, तब यूरोप की जातियों ने इस स्वर्ण-भूमि पर पदार्पण किया था। कई शताब्दियों तक सभ्यता का पाठ सिखानेवाले गोरो के सम्पर्क में रहते हुए भी आज अफ्रीका के असली निवासी सभ्यता और संस्कृति में बहुत पिछड़े हैं। यूरोपीय जातियों को अफ्रीका में अपना आधिपत्य जमाने के लिए अधिक संघर्ष या युद्ध नहीं करना पड़ा, क्योंकि वहाँ की अधिकांश जातियाँ वन्य और असभ्य थीं। उन्होंने विदेशियों के चरणों में आत्म-समर्पण कर दिया। पिछले महायुद्ध (१९४१-१८) से पहले अफ्रीका में जर्मनी के कई उपनिवेश थे। परन्तु शान्ति-सन्धि के अनुसार ये उपनिवेश ब्रिटेन, फ्रांस और बेलजियम के अधिकार में आगये।

टोगानिका ब्रिटेन के आधिपत्य में चला गया। इसका कुछ उत्तरी-पश्चिमी भाग बेलजियम को मिला। जर्मन कैमरूस का अधिकांश भाग फ्रांस के हिस्से में आया। टोगालैण्ड फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बाँटा गया। 'दक्षिणी अफ्रीका यूनियन' ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश है। मिस्र पहले ब्रिटेन के अधीन था। परन्तु अब वह स्वतन्त्र राष्ट्र है। फिर भी ब्रिटेन का उसपर प्रभाव है। सन् १९३४ में इटली ने स्वतन्त्र राज्य अबीसीनिया को युद्ध में हराकर उसे अपने अधीन कर लिया। अब केवल लिबेरिया ही एकमात्र स्वतन्त्र राज्य है।

अमरीका में मुनरो-सिद्धान्त

नयुक्तराज्य अमरीका कई सदियों से यूरोप की राजनीति से अलग रहा है। वह यूरोप की सकटपूर्ण राजनीति की उत्पत्ति में अपने आपको सदैव बचाता रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति वॉशिंग्टन ने पहले-पहल १७ सितम्बर १७९६ को अपने भाषण में यह भावना व्यक्त की कि अमरीका को यूरोपीय जातों से अलग रहना चाहिए। इसके बाद सन् १८२३ में राष्ट्रपति मुनरो ने अपने नरेग में अमरीका की नीति का

स्पष्टीकरण किया। इस सन्देश में मुनरो ने यह घोषणा की कि यूरोप के राष्ट्रों को अब अमरीका (उत्तरी व दक्षिणी) में अपने उपनिवेश स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यूरोपीय देशों के ऐसे युद्धों में, जिनसे अमरीका का कोई मक्का नहीं, वह भाग नहीं लेगा और न ऐसा करना उसकी नीति के अनुकूल ही है। यूरोपीय देशों ने साम्राज्य-स्थापना की भावना से अमरीका महाद्वीप में प्रवेश किया तो उनका यह प्रयत्न अमरीका की शान्ति के लिए खतरा होगा। इस समय अमरीका में जो यूरोपीय उपनिवेश या पराधीन राज्य हैं, उनके साथ अमरीका का सबब वैसा ही बना रहेगा और मयुक्तराज्य अमरीका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सिद्धान्त 'मुनरो सिद्धान्त' के नाम से विख्यात है। इस सिद्धान्त का भविष्य में जो विकास हुआ उसके कारण मयुक्तराज्य समूचे अमरीका महाद्वीप का मरक्षक बन गया। इस समय समस्त अमरीका मयुक्तराज्य के आर्थिक साम्राज्यवाद का शिकार है। उसका अमरीका तट के निकटवर्ती द्वीपों पर अधिकार है। यही नहीं, मुद्र द्वीपों पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया है। हवाई और फिलिपाइन द्वीप मयुक्त-राज्य अमरीका के आधिपत्य में हैं। इसके अतिरिक्त उसने क्यूबा, हैटी, साण्टो डोमीनगो के साथ सन्धि करके उनकी भी स्वाधीनता पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। पनामा और निकारागुआ राज्यों के चुनावों के समय मयुक्तराज्य की मेनाओं का प्रबन्ध रहता है। इन सब राज्यों की वैदेशिक नीति पर भी उसका प्रभाव है।

साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ

साम्राज्यवाद क्या है—इसका मर्मस्पशी और वास्तविक विवरण एक भारतीय विद्वान के शब्दों में इस प्रकार है “स्वाधीनता और मानवता की राख से साम्राज्यवाद का जन्म हुआ है। बरसों नर-नारियों की आहों और अभिशापों से बना मुकुट साम्राज्य के सिर पर है। इसके कपड़े लाल रंग के हैं, इसके साथी अकाल, महामारी और भीषण रोग हैं। इसके आने के साथ भीषण आतंक छा जाता है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है। दूसरी भाषा, दूसरी सभ्यता और सत्कृति जबरदस्ती से लाद दी जाती है। अपनी इच्छा को दूसरे की इच्छा का अनुगामी बनना पड़ता है। क्या यह साम्राज्यवाद दुनिया के लिए मंगलमय, सुखप्रद, और जीवनदाता हो सकता है ?”

यह है साम्राज्यवाद का सजीव स्वरूप। इससे अच्छी उसकी व्याख्या और क्या हो सकती है। साम्राज्यवाद पूँजीवाद का अन्तिम और निखरा रूप है। पूँजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है। इसलिए साम्राज्यवाद भी आर्थिक है। आज का युग ही अर्थ-प्रधान है। राजनीति भी अर्थ-नीति की अनुचरी है। इसलिए आज के साम्राज्यवाद को आर्थिक साम्राज्यवाद कहा जाता है।

आर्थिक साम्राज्यवाद

आर्थिक साम्राज्यवाद का प्रादुर्भाव फ्रांस की राज्य-क्रान्ति और औद्योगिक क्रान्ति के बाद हुआ। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति का प्रभाव समस्त यूरोप पर पड़ा। फन्स्वरूप यूरोप के अधिकांश देशों में प्रजातन्त्र का बोलबाला रहा। जनता ने स्वेच्छाचारी एवतन्त्र शासन का अन्त कर के शासन की वागडोर अपने हाथ में ली। इसने सारे यूरोप में समता, स्वतन्त्रता और वन्धुत्व के आदर्शों की धूम मच गयी। प्रजातन्त्र के

प्रताप से राजसत्ता स्वेच्छाचारी राजाओं के हाथ से निकलकर उच्च मध्यमवर्ग के लोगों के हाथ में आ गयी। इससे मध्यमवर्ग ने लाभ उठाया। उद्योग-धंधों में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। अब पूँजीपति वर्ग के सामने अपना तैयार माल बाहर के देशों में भेजने की समस्या उपस्थित हुई।

अब ऐसे देशों की खोज होने लगी जिनमें तैयार माल बेचा और उनसे कच्चा माल सस्ते भाव में खरीदा जा सके। इसलिए उपनिवेशों की खोज के लिए साहसी नाविक निकल पड़े। रेल, तार, जहाज तथा मशीनों के आविष्कार ने उद्योग-धंधों में आश्चर्यजनक उन्नति कर दी। सबसे पहले एशिया, अफ्रीका आदि के देशों में यूरोपियन जातियों ने प्रवेश किया। इनमें उद्योग-धंधे बड़ी पिछड़ी दशा में थे। इसलिए उन्हें इन देशों में अपना माल खपाने और कच्चा माल खरीदने को एक बड़ा क्षेत्र और सुयोग हाथ लगा। इस उपनिवेश-विजय में प्रतियोगिता भी बीजरूप में विद्यमान थी। जब सबसे पहले यूरोप की विविध जातियाँ या देशवासी अफ्रीका और एशिया में आये तब उनका एकमात्र ध्येय व्यावसायिक ही था। वे इन महाद्वीपों के देशों में अपना व्यवसाय चाहते थे। परन्तु दूसरे देशवालों की प्रतिस्पर्धा से अपनी रक्षा करने के लिए हर एक की चेष्टा यह रही कि मेरा ही एकाधिकार कायम होजाये। इसके लिए प्रतियोगियों में संघर्ष चला। युद्ध लड़े गये। जब एक जाति का एकाधिकार इन महाद्वीपों में जम गया, तब इस बात की चेष्टा होने लगी कि इनके देशों पर राजनीतिक प्रभुत्व भी कायम किया जाये। विदेशियों की प्रतिस्पर्धा से अपने आपको सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक आविषत्य कायम किया गया। इस प्रकार यूरोप के साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने एशिया और अफ्रीका में उद्योग-धंधों में अपनी पूँजी लगाने के साथ-साथ उसकी रक्षा के लिए राज-सत्ता भी स्थापित की।

सुप्रसिद्ध लेखक श्री डाउल्ट ने यूरोप और अफ्रीका की औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के सम्बन्ध में लिखा है—

“यूरोप और अमरीका ने हाल ही के कुछ वर्षों में चीन के सिवा सत्तार के सभी स्वतन्त्र देशों पर आधिपत्य जमा लिया है। इस समय

में सब प्रकार के देशों पर आधिपत्य जमाने के लिए हुए। सभी देश जल्दी करना चाहते थे। जिन राष्ट्रों के पास उपनिवेश नहीं हैं उन्हें भविष्य में मिलने की आशा नहीं थी। यदि उन्हें उपनिवेश नहीं मिलेंगे, तो बीसवीं शताब्दी के होनेवाले आधिक शोषण में उनको सुयोग नहीं मिलेगा। यही कारण है जिससे यूरोपीय राष्ट्र साम्राज्यवादी नीति के कारण उन्मत्त हो गये हैं।''

राष्ट्रीय स्वाधीनता का शत्रु—साम्राज्यवाद

यद्यपि साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति मूलतः आर्थिक ही है, तो भी पूँजीयतियों का शासन पर प्रभुत्व होने के कारण साम्राज्यवाद अधिकृत देशों व उपनिवेशों में केवल जनता का आर्थिक शोषण ही नहीं करता बल्कि उनके शासन-यंत्र का भी संचालन करता है। इसलिए साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति राजनीतिक भी रही है। प्राचीन भारत और यूरोप में जो विशाल साम्राज्य स्थापित किये गये, उनका उद्देश्य राजनीतिक प्रभुता ही थी। आज भी इसी प्रभुता के लिए दूसरे देशों की स्वाधीनता का अपहरण किया जा रहा है।

यूरोपीय तथा अमरीकन राष्ट्र जहाँ-जहाँ अपने देशों की पताका लेकर गये वहाँ-वहाँ की राष्ट्रीय स्वाधीनता का दमन करके उनकी जनता को उन्होंने पराधीन बनाया। उन्होंने वर्षों तक युद्ध जारी रखे, लाखों सैनिकों ने अपने जीवन की आहुतियाँ दी और अपार धन-सम्पत्ति युद्ध-देवता के चरणों पर चढ़ायी। इस बलिदान के प्रसाद में उन्हें एशिया और अफ्रीका के देशों में 'राजनीतिक प्रभुता' प्राप्त हुई। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि यह 'राजनीतिक प्रभुता' विजित देशों की स्वाधीनता के लिए घातक सिद्ध हुई। इस तरह साम्राज्यवाद ने अधिकृत देशों की जनता का आर्थिक शोषण करके ही विश्राम नहीं लिया, बल्कि उनके आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक पतन के लिए भी अविश्राम प्रयत्न किया है।

१ एड ड्राउल्ट 'सोशल एण्ड पोलिटिकल प्रॉब्लेम्स एट द एण्ड ऑफ़ द नाइन्टीअथ सेञ्चुरी'।

जनता का आर्थिक शोषण

यह तो ऊपर रहा जा चुका है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अन्तिम मोर्चा है। पूंजीवाद जब उस स्थिति में पहुँच जाता है जबकि किसी देश के ग़ाम ज़ार जन-राशि और तैयार माल जमा हो जाता है, जो स्वदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भी बच रहता है, तब तैयार अधिक माल को बेचने के लिए दूसरे देशों की बाज़ की जाती है। उस वही साम्राज्यवाद के उदय का कारण है। एक पूंजीवादी देश दूसरे पूंजीवादी देश में अपना तैयार माल मुनाफ़े के साथ नहीं बेच सकता। इसीलिए वे ऐसे देशों की बाज़ करने हैं जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। ऐसे ही देशों में वे अपना तैयार माल अधिक मुनाफ़े के साथ बेच सकते हैं और कच्चा माल सस्ते दामों में खरीद सकते हैं।

साम्राज्यवादी राष्ट्र अतीतकाल के देशों का नाश करने जनता को स्वदेशी उत्पादन के मारना में उत्तम करता है तथा अपनी पूंजी में उस देश में उद्योग-धन्य गढ़े करता है। उस प्रकार पिछड़े हुए देशों में बड़े-बड़े कारखाने ग़ुल जाने हैं और साम्राज्यवादी राष्ट्र पूर्णतया उनके आर्थिक जीवन का नियन्त्रण करने लगते हैं। साम्राज्य में अधिकृत देशों में भी पूंजीवाद का शासन स्थापित हो जाता है।

राष्ट्रीय जागरण का दमन

साम्राज्यवादी राष्ट्र यह सोचते हैं कि वह अपने अस्तित्व देशों या उपनिवेशों की प्रजा का सर्वोत्तम प्रगति तथा प्रशासन में अग्रणी रहें। वह उनके नवदुर्ग की नवीन विचारधारा, समाज की सामाजिक अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत देशों के उत्थान-विधान में बाधा उत्पन्न करता है। अस्तित्व देशों में नवीन प्रगतिशील विचारधाराओं का प्रतिपादन करनेवाले व्यक्ति और राष्ट्रों पर जोर लगाया जाता है। समस्तवादीयों पर जोर नवीन नहीं जाती है और उस प्रकार में अस्तिता के अन्त में सन्धि करने के लिए नहीं। देशों का उत्थान होता है वह उस प्रकार है कि प्रगतिशील राष्ट्रों में, साम्राज्य

साम्राज्यवादी राष्ट्र यह भलीभाँति अनुभव करता है कि राष्ट्रीय जागरण उसके हित के लिए घातक सिद्ध होगा। परन्तु सच तो यह है कि साम्राज्यवादी राष्ट्र अपने सुव्यवस्थित कड़े शासन, दमन और शोषण से भी राष्ट्रीय जागरण को रोक नहीं सकता। ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध राजनीतिक लेखक प्रोफेसर श्री हैराल्ड लास्की का कथन है कि "साम्राज्यवाद पराधीन राष्ट्र की जनता में राष्ट्रीयता को जन्म देता है।" राष्ट्रीय जागरण तो साम्राज्यवाद की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जिसे रोकने की शक्ति स्वयं उसमें भी नहीं है।

भारत में राष्ट्रीयता का उदय वग-भग के साथ होता है। इसी समय स्वदेशी-आन्दोलन शुरू होजाता है। सन् १९१४ में जब यूरोपीय महायुद्ध शुरू हुआ, तब भारत में राष्ट्रीय असन्तोष अधिक बढ़ गया। इस असन्तोष को दबाने का ज्यो-ज्यो प्रयत्न किया गया, त्यो-त्यो वह उग्रतर होता गया। और जब युद्ध की समाप्ति पर भारत में रीलिट बिल पास किया गया, तब भारतीय असन्तोष ने उग्रतम रूप धारण कर लिया। इसी समय महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर उदय हुए। महात्मा गांधी ने दमन का विरोध करने के लिए जनता को अहिंसात्मक आन्दोलन का अस्त्र पदान किया। इससे जनता में निर्भयता, साहस और वृत्तिदान की भावना पैदा हुई।

सच तो यह है कि स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी भी राष्ट्र को किसी दूसरे राष्ट्र की जनता को इस मानवीय अधिकार से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। आज तक साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने इस सत्य को अनुभव नहीं किया। परन्तु इस बीसवीं सदी में यह प्रकाश के समान स्पष्ट है कि कोई भी राष्ट्र सदा के लिए गुलामी में नहीं रखा जा सकता। अधिकृत राष्ट्र में राष्ट्रीयता का विकास और उत्तरोत्तर वृद्धि साम्राज्यवाद के जीवन के लिए सकट है।

विश्व की अशान्ति का कारण

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि साम्राज्यवाद राष्ट्रीय स्वाधीनता

अन्तर्राष्ट्रीयता

आधुनिक काल में नागरिक-जीवन का सबब केवल अपने नगर, ग्राम या राज्य से ही नहीं, बल्कि समस्त ससार में है। मानवता परिवार, नगर और मातृभूमि से भी महान् है। परन्तु जाति धर्म, रंग एवं राष्ट्रीयता की उग्र भावना के कारण मानव-समाज कृत्रिम विभागों या समुदायों में विभाजित हो गया है। ससार में जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता जा रहा है, वैसे-वैसे मानव जाति यह अनुभव करती जा रही है कि धर्म, जाति और रंग के भेद कृत्रिम हैं और मानव-एकता में इन्हें बाधक नहीं होना चाहिए। अब ससार के मनुष्य यह अनुभव करने लगे हैं कि मानव-समाज का मगठन सत्य, न्याय और सहकारिता के आधार पर होना चाहिए। ससार के मानव हितैषी वैज्ञानिकों ने जो लोकोपयोगी आविष्कार किये हैं, उनके द्वारा मानव-एकता की भावना अधिक दृढ़ होती जा रही है। बिेत्तार के तार, रेडियो, दूर-दर्शन-यन्त्र आदि आविष्कारों ने मानव-एकता की स्थापना में बड़ा सहयोग दिया है। यही नहीं, प्रत्येक देश और प्रत्येक युग में ऐसे महापुरुष पैदा होते रहे हैं और आज भी ऐसे महापुरुष विद्यमान हैं जो सकीर्ण राष्ट्रीय बंधनों से मुक्त मानवता के पुजारी हैं। भारतवर्ष तो वैदिककाल से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आदर्श का समर्थक रहा है। अशोक और बौद्धधर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने विश्वबन्धुत्व के लिए त्रिशात्मक प्रयत्न किया। आधुनिक युग में भी महात्मा गांधी, विश्वकवि डॉ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर^१ और पं० जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीयता के पुजारी होने के साथ-साथ विश्व-नागरिक भी हैं। भारत की राष्ट्रीयता मानव-हित विरोधी नहीं है, इसलिए वह अन्तर्राष्ट्रीयता की पोषक है।

१ हाल ही में ७ अगस्त १९४१ को आपका देहावसान हो गया है।

प्रत्येक सभ्य राष्ट्र का शासन-प्रबन्ध जनता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा बनाये हुए कुछ मौलिक नियमों के द्वारा होता है, जिन्हें शासन-विधान का नाम दिया गया है। इन नियमों में स्पष्ट रूप से राज्य, शासन और नागरिकों के पारस्परिक कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख होता है। इन नियमों के अनुसार शासन-प्रबन्ध होने से नागरिकगण स्वाधीनता का उपभोग करते हैं। यदि कोई नागरिक किसी दूसरे के अधिकार पर आघात करता है अथवा आने कर्तव्य-पालन में त्रुटि करता है, तो समाज या राज्य उसे दण्ड देता है।

हम व्यक्तिगत जीवन में भी इसी नियम को देखते हैं। यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य को कोई हानि पहुँचाता है तो परिवार के सब सदस्य उसके ऐसे कार्य की निन्दा करते हैं, उसका विरोध करते हैं और उसे अपनी त्रुटि का अनुभव कराने के लिए उससे अमहयोग भी करते हैं।

जब एक परिवार, एक राज्य या एक राष्ट्र में हम यह व्यवस्था और नियम पाते हैं तब प्रत्येक राज्य के परस्परिक मन्वधों में इनका पालन क्यों नहीं होना चाहिए? जब किसी राज्य का कोई व्यक्ति कानून के विरुद्ध कोई काम करता है, तो समाज के हित के लिए राज्य उसे दण्ड देता है, क्योंकि यदि राज्य में सभी व्यक्ति उन्हीं प्रकार कानून के विरुद्ध काम करने लगेंगे, तो इससे समाज ने अपने कल्याण के लिए जो नियम बनाये हैं उनका उल्लंघन होगा और फलतः समाज का अनिष्ट होगा। परन्तु जब एक राज्य दूसरे राज्य पर अन्यायपूर्वक आक्रमण करे, तब क्या किया जाये? क्या राज्य को इस प्रकार स्वच्छद होकर निर्दोष राष्ट्र पर आक्रमण करने दिया जाये? जो राज्य को सर्वोपरि मानते हैं, वे यह कहेंगे कि राज्य पर किसीका नियन्त्रण नहीं है, वह व्यक्तियों की भाँति नैतिक नियमों में बँधा नहीं है, इसलिए उन्हीं कोन रोक सकता है? परन्तु हम यह साफ तौर से देखते हैं कि इन बीसवीं सदी में यह कथन कुछ अप्रासंगिक-सा है। आज हम यह अनुभव करते हैं कि मनुष्य का कोई देश अलग नहीं रह सकता। आज पृथ्वीका नभ्व ही

नहीं है। सब राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध उत्तरे घनिष्ठ होगये हैं कि एक देश की आन्तरिक राजनीति का दूसरे देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। तब यह कैसे संभव हो सकता है कि एक मजबूत राष्ट्र दूसरे पर अन्याय करता रहे और सब राज्य मिलकर उममा विरोध न करें ?

प्रोफेसर रामजे म्यूर ने अन्तर्राष्ट्रीयता के संबंध में लिखा है —

“अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर प्रगति का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों में कानून की सत्ता स्थापित करना है। किसी राज के पारस्परिक सम्बन्धों में कानून की सत्ता का स्पष्ट रूप उस प्रवर्तन में दिखलाई देता है जिसके द्वारा उनमें पारस्परिक मघपं का अवरोध होता है और शक्ति के निर्णय के स्थान में न्याय के निर्णय की स्थापना की जाती है। अतः अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर प्रगति का प्रयोजन अन्त में स्थायी शान्ति के लिए प्रगति ही है।”^१

राष्ट्रों की अन्योन्याश्रयता

इस युग में व्यवसाय और उद्योग ऊंची-से-ऊंची स्थिति को पहुँच चुके हैं। एक प्रकार से इस पाश्चात्य उद्योगवाद ने समस्त के राष्ट्रों को आत्म-निर्भरता में वचित कर दिया है। किसी देश में कोयले की अधिकता है, किसी देश में लोहा अधिक है, तो दूसरे देश में पेट्रोल और तेल अधिक है। इसी प्रकार किसी देश में उद्योग-धने अधिक है, तो कोई देश कृषि की पैदावार में अग्रगण्य है। कहीं रस्स और लाल ज्यादा पायी जाती है, किसी देश में रस्स पैदा होती है, तो किसी देश में मशीन जीया बनती है, रस्स पैदा नहीं होती। इस प्रकार प्रकृति ने इन प्राकृतिक सामानों का वितरण सारे समस्त में इस ढंग में किया है कि कोई भी एक देश दूसरे देश में मजबूत स्थापित नियो प्रिया उद्योग-व्यवसाय में उन्नति नहीं कर सकता। यही कारण है कि कोई राष्ट्र इस युग में आत्म-निर्भरता के मित्रान्त या प्रयोग नहीं कर सकता।

१. प्रोफे० रामजे म्यूर : 'नेशनलिज्म एण्ड इन्टरनेशनलिज्म' (१९१९) पृ० १३८

आधिक जीवन में इसी अन्योन्याश्रयता की भावना ने भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में अपने हितों की रक्षा के लिए दो भावनाओं को जन्म दिया—वे हैं सहकारिता और प्रतियोगिता। पहली भावना के विकास के परिणाम-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीयसंस्थाओं और सबंधों की स्थापना हुई तथा दूसरी भावना—प्रतियोगिता—ने आक्रमक आधिक राष्ट्रीयता को जन्म दिया। यह आक्रमक आधिक राष्ट्रीयता सहकारिता की विरोधिनी है और यही कारण है कि आज लाख चेष्टा करने पर भी आधिक राष्ट्रीयता के कारण कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय महयोग सफल नहीं हो रहा है।

प्रभुत्व का सिद्धान्त

वर्तमान काल में प्रभुत्व के सिद्धान्त का विकास अन्तर्राष्ट्रीयता का विरोधी सिद्ध हो रहा है। इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि सत्तार में राज्य ही सर्वोपरि सत्ता है—उसके ऊपर नियंत्रण करनेवाली कोई सत्ता नहीं है। अतः राज्य के नागरिकों का यह वर्तव्य है कि वे केवल राज्य के प्रति राजभक्त रहें, उसीकी पूजा करें उसीके आदेश का पालन करें और जब वह राज्य अपने विस्तार के लिए युद्ध करे तो नागरिकों को उसमें पूर्ण सहयोग देना चाहिए। यह प्रभुत्व का सिद्धान्त किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता में प्रियता नहीं पाता। ऐसी दशा में यह आशय करना कि राज्यों के नागरिक उस सत्ता के आदेश का पालन करेंगे, ग़र्र है। अब जब तक यह सिद्धान्त अपने इसी रूप में कायम रहेगा और इसमें आवश्यक परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संकल्पना संभव नहीं है।

पोकेसर ईसाई लग्गी का ज़यन है—

“प्रभुता-प्राप्त राज्यों (Sovereign States) में बँटा हुआ सत्तार उनके प्रभुत्व-सिद्धान्त के कारण उनके पारस्परिक संबंधों का स्वाधीनता के आधार पर सकलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी आदिपण्याली की प्रदूति प्रभुत्व (Sovereignty) को समाज में उन हितों का आशय देती है जिनके लिए शांति और युद्ध अपने विशेष उद्देश्यों

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अमरीका के राष्ट्रपति विलसन ने राष्ट्रसंघ की कल्पना की और अन्य राजनीतिज्ञों के सहयोग से उसे एक अन्तर्राष्ट्रीय जीवित सन्ध्या का रूप दिया गया। १० जनवरी १९२० को राष्ट्रसंघ की विधिवत् स्थापना हो गयी।

राष्ट्रसंघ के विधान में उसकी सबसे प्रथम धारा में उसका लक्ष्य इस प्रकार घोषित किया गया —

“प्रतिज्ञा करनेवाले राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए युद्ध न करने की मर्यादा को स्वीकार करके, राष्ट्रों में परस्पर प्रकटरूप से न्यायपूर्ण और सम्माननीय सम्बन्धों को कायम रखते हुए विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय विधान को क्रियात्मक रूप देंगे और यह बात विश्वासपूर्वक ध्यान में रखकर सुसंगठित राष्ट्रों की पारस्परिक सन्धियों की प्रतिज्ञाओं का पूरा आदर करते हुए न्याय की रक्षा के लिए राष्ट्रसंघ के इस विधान को स्वीकार करते हैं।”

विधान की इस प्रस्तावना में राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित सिद्धान्त स्पष्टतया निहित हैं—

१. अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता, शान्ति और सुरक्षा की स्थापना।

२. युद्ध की रोक।

३. राष्ट्रों में परस्पर समुचित, प्रकट और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना।

४. संसार की सरकारों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार आचरण।

५. अन्तर्राष्ट्रीय न्याय-व्यवस्था की स्थापना।

६. सन्धियों की समस्त शर्तों का पालन।

इस विम्लेषण से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रसंघ के दो मुख्य लक्ष्य हैं— एक तो संसार में शान्ति की स्थापना और दूसरा युद्धों को रोकना। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए राष्ट्रों में परस्पर सहायता और सुरक्षा आवश्यक है। राष्ट्रसंघ नान्तिक सुरक्षा में विश्वास करता है और कटनीति की शान्ति-स्थापना के लिए मानव शक्ति है।

विधान में यह स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि गणतन्त्र के मद्दम्य-राष्ट्रों में जो सन्धियाँ होंगी वे प्रकट रूप में की जाएंगी। गणतन्त्र में कोई सन्धि नहीं होगी और उन सन्धियों की मध्य के जास्मि में गजिस्ट्री भी होगी। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता की वृद्धि के लिए अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्थाएँ मनुष्यों के कल्याणार्थ स्थापित की गयी। युद्ध रोकने की सम्मथा बड़ी विकट है। राष्ट्रसंघ ने इसके लिए अन्तर्गोष्ठीय मुरम्भा पर जोर दिया तथा नि शस्त्रीकरण के लिए योजना बनाने का विचार किया।

राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत दो प्रमुख परिपदे हैं। पहली असेम्बली कहलाती है और दूसरी कौंसिल। असेम्बली में प्रत्येक स्वतन्त्र राज्य को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। कौंसिल राष्ट्रसंघ की कार्य-समिति है। सन् १९३२ में ममार के कुल ६६ राष्ट्रों में से ५५ राष्ट्र राष्ट्रसंघ के सदस्य थे।

सयुक्तराज्य अमरीका तो राष्ट्रसंघ के जन्म-काल में ही अलग रहा है। सन् १९३२ के बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति विगडनी गयी और पुन राजनीतिक क्षितिज पर युद्ध के बादल उमडने लगे। वस, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने एक-एक करके राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया। सबसे पहले जापान ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इटली और जर्मनी ने भी उसे त्याग दिया। इस प्रकार सन् १९३२ के बाद राष्ट्रसंघ का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता गया और अन्त में वह एक निर्जीव और शक्तिहीन सम्था रह गयी। राष्ट्रसंघ की उपर्युक्त दोनों परिपदों के निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए जेनेवा (स्वीजरलैंड) में उसका एक विगाल अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय है। इसके अन्तर्गत १३ विभाग हैं जो अपने-अपने कार्य को चलाते हैं।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ

शान्ति-सन्धि के १३वें भाग में अन्तर्गोष्ठीय मजदूर-संघ के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें लिखा है —

“राष्ट्रसंघ का उद्देश्य विश्व में शान्ति की स्थापना करना

है और शान्ति उसी समय स्थापित हो सकती है जबकि उसका आधार सामाजिक न्याय हो। आज मजदूरों की वर्तमान अवस्था इतनी अन्यायपूर्ण, कष्टमय और विकट है कि बहुतेरे मजदूरों के लिए मंहताजी होरही है। इसीलिए सत्सार में इतनी अशान्ति बट गयी है कि समूचे सत्सार की शान्ति और सामजस्य ही सकट में है। इस परिस्थिति में शीघ्र ही सुधार होना चाहिए—जैसे मजदूरों के दैनिक कार्य के घण्टे कितने हो कितने घण्टों का दिन माना जाये, कितने दिनों का एक सप्ताह माना जाये, मजदूरों की भरती का नियन्त्रण, बेकारी का निवारण, उचित वेतन निर्धारण करना, जब श्रमिक कार्य-काल में आहत होजायें या व्यथित हो तो उनकी रक्षा करना, बालकों, युवकों और स्त्रियों का संरक्षण, पृद्धावस्था तथा शरीर से शिथिल होनेपर जीविका की व्यवस्था, प्रवासी मजदूरों के हितों का संरक्षण, वास्परिक सहयोग से संगठित कार्य करने की सुविधा, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध तथा अन्य सुविधाएँ।”

उस भूमिका ने यह स्पष्ट है कि राजनीतिज्ञों को मजदूरों की अवस्था का अनुभव था और वे यह जानते थे कि यदि उनकी दशा में राज्यों ने सन्तोषप्रद सुधार नहीं किया तो उससे बड़ी अशान्ति होगी। अतः समस्त प्रमुख उद्योगवादी राष्ट्रों ने एक अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ की स्थापना की। इस संघ के निम्नान्त इस प्रकार है—

- (१) सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि श्रम को बाजार में बेचने-खरीदने की चीज न माना जाये।
- (२) मजदूरों व पूँजीपतियों को बंध उद्देश्यों के लिए मगठन करने का अधिकार है।
- (३) मजदूरों के पारिश्रमिक (मजदूरी) की दर उनकी पदवि निर्दिष्ट की जाये जो उनके देश, काम और स्थिति के अनुसार उचित हो।
- (४) जिन देशों में मजदूरों के लिए ८ घंटे का दिन तथा ४८ घंटे का सप्ताह नहीं माना जाता, उन देशों में भी निर्दिष्ट प्रतिदिन प्रत्येक कार्य प्रारम्भ किया जाये।

- (१) यदि मजदूर मजदूरी का एकही दर या उद्देश्य मिलाने चाहिए और, जहाँ तक संभव हो, मजदूरों के हितों का ध्यान रखा जाये।
- (२) सरकार या मजदूरों का जो भी अधिकार है उसे अधिकार प्राप्त कर सके और उनका नागरिक हितों का ध्यान हो सके।
- (३) पुष्पा और स्त्रियों का समान हितों का ध्यान मजदूरों दी जाये।
- (४) मजदूरों का हितों का जो नगरपालिका द्वारा नियंत्रित किया गया हो वह अधिकार दुष्टि में न्यायमग्न हो।
- (५) प्रत्येक राष्ट्र को अपने देश में ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि यह जाँच-पड़ताल हो जा सके कि उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन ठीक ढंग से होता है या नहीं। इस जान में स्त्रियाँ भी भाग ले।

मजदूर-संघ का संगठन भी राष्ट्र-संघ जैसा ही है। उनकी अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् में प्रत्येक राष्ट्र का प्रतिनिधि भेजन का अधिकार है। उसमें ५६ राज्यों के प्रतिनिधि हैं। अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् मजदूरों के कल्याण के लिए प्रस्ताव स्वीकार करती है और अपने सदस्य-राष्ट्रों को यह आदेश करती है कि वे उसके अनुसार अपने-अपने देश में कानून बनाकर उन्हें कार्यान्वित करें। परन्तु यदि कोई राष्ट्र इन प्रस्तावों के अनुसार कार्य न करे, तो संघ उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ की एक कार्यकारिणी समिति है और उसका 'सेक्रेट्रियट' भी जेनेवा में स्थित है। इस कार्यकारिणी में कुल ३२ सदस्य हैं। इनमें से ८ सदस्य स्थायी हैं। भारत भी एक स्थायी सदस्य है।

(३) स्थायी विश्व-न्यायालय

राष्ट्रसंघ ने हेग में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय की भी स्थापना की है, जो ३० जनवरी सन् १९२२ से अपना कार्य कर रहा है। इस न्यायालय को उन विग्रही राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों की जाँच करने व निर्णय देने का अधिकार है, जो राष्ट्रसंघ के सदस्य हैं तथा जिन्होंने न्यायालय के विधान^१ को स्वीकार कर लिया हो।

१. स्टैच्यूट ऑव कोर्ट (Statute of Court)

राष्ट्रसंघ की विफलता और उसके कारण

ऊपर कहा गया है कि राष्ट्रसंघ अब एक निर्जीव और शक्तिहीन संस्था बन चुकी है, अतः उसकी असफलता के कारणों पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। अबतक इस सम्बन्ध में जो विवेचन किया गया है, उससे यह भलीभाँति जाना जा सकता है कि राष्ट्रसंघ की विफलता के मूल कारण क्या हैं। फिर भी यहाँ सूक्ष्म रूप में उनका उल्लेख करना उचित है, जिससे पाठक आसानी से समझ सके और जब भविष्य में विश्व-शान्ति के लिए किसी विश्व-संस्था की स्थापना की जाये तो उन कारणों के निवारण के लिए प्रयत्न किया जाये

- (१) राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद ही यूरोपीय देशों में उसके प्रति विद्रोह उठ खड़ा हुआ। राज्य साम्राज्यवाद के नशे में पागल होकर मानवता के आदर्शों को भूल गये और मानव-एकता और विश्व-बन्धुत्व के प्रति उनकी भ्रष्टा कम होनी गयी। राष्ट्रसंघ प्रधान शक्तिसम्पन्न और साम्राज्यवादी राष्ट्रों के हाथ में स्वार्थ-साधन का अस्त्र बन गया। वह राज्यों के शासनों के प्रतिनिधियों का एक ऐसा गुट बन गया, जो वास्तव में मानव-समाज का माथन करने के अयोग्य थे। राष्ट्रसंघ का राज्यों के नागरिकों से कोई सम्बन्ध न रहा।
- (२) असफलता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है शक्तिसाली राष्ट्रों की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। राष्ट्रसंघ की स्थापना से इनमें तनिय भी सुधार नहीं हुआ। प्रभुता के सिद्धांत को, जो अन्तर्राष्ट्रीयता का विरोधी है, सभी राष्ट्र मानते रहे और इस प्रकार राष्ट्रसंघ के निश्चयों का राष्ट्रीय प्रभुत्व के सामने कोई भूत ही न रह गया।
- (३) विचारधारा-मध्यधीनत्व भी राष्ट्रसंघ की विफलता के लिए उत्तरदायी है। यूरोपीय महायुद्ध के बाद रूस में राज्य-शक्ति के फलस्वरूप समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। समस्त यूरोप में समाजवाद का प्रचार होने लगा। समाजवादी विचारधारा के पतिकूल इटली और जर्मनी में प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, और उसके फलस्वरूप फासिज्म और नाज़ीवाद इन दो नयी विचारधाराओं का

विकाम हुआ। इटली में मुनोलिनी ने कम्युनिस्टों का शांतिवाद के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इटली के विज्व-जान-कोय में मुनोलिनी ने लिखा है —

“फासिज्म का न तो शांति की आवश्यकता में विश्वास है और न उसकी उपयोगिता में। शांतिवाद में संघर्ष में बढ़ने की प्रवृत्ति छिपी हुई है। वह मूलन कायरता ही है। इसलिए ‘फासिज्म’ बलिदान के मुकाबिले में शांति को ठुकराता है। युद्ध और सिर्फ युद्ध में ही मनुष्य की शक्तियों की अधिक-से-अधिक परीक्षा होती है और उसे स्वीकार करने का साहम करनेवाली जातियों के मिर पर ही उच्चता का नेहरा बँधना है। और सब तरह की परीक्षाएँ नकली हैं। वे मनुष्य के सामने जीवन या मरण के चुनाव का मवाल पेश नहीं करती।”

इसी प्रकार जर्मनी में हेर हिटलर ने जर्मनों की मोरी हुई हिंसा-वृत्तियों को जगाने के लिए एक आत्मचरित्र लिखा और उसमें हिंसा, युद्ध और साम्राज्यवाद का यश गाया। उसमें लिखा —

“यदि कोई जीवन रहना चाहता है, तो उसे लड़ाई करनी चाहिए। और यदि कोई इस सतत संघर्षशील सत्ता में लड़ाई के प्रति उदासीन है, तो उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं।”

“ऐसा ममझोता—गुटबन्दी—जिसका उद्देश्य युद्ध में पड़ना नहीं है, बेकार और व्यर्थ है।”

स्पष्ट है कि ये विचारगाराएँ शांतिवाद और राष्ट्रमन के रक्ष्य के विरुद्ध हैं। जर्मनी और इटली आज १० वर्षों में भी अतिक्रमण ने नारे यूरोप में हिंसावाद, युद्ध और संघर्ष का प्रचार कर रहे हैं।

(५) राष्ट्रमन के आन्तरिक संगठन की श्रुतियाँ भी उसकी विकरता के लिए कम उत्तरदायी नहीं हैं। राष्ट्रमन स्वतन्त्र मध्य-राष्ट्रों की सरकारों के प्रतिनिधियों की संस्था है। राष्ट्रमन की मना

१-२ हेर हिटलर : ‘माइन कैंम्फ’ (मेरा संघर्ष) १८ वां जर्मन संस्करण, पृष्ठ ३१७ और ७४९।

वास्तव में प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र की सरकार में निहित है। स्वतंत्र राष्ट्रों के समझौते से संधि का विधान बना है। इसलिए अन्य मन्धियों की तरह राष्ट्र उसका भी उल्लंघन कर सकते हैं। और उसका जीवन उसके सदस्यों की श्रमकामना पर निर्भर है। राष्ट्रमंडल में प्रतिनिधित्व की प्रणाली बड़ी दोषपूर्ण है। वह राज्यों के नागरिकों की समस्या नहीं है, बल्कि सरकारों की गुटबन्दी है। हमारा बड़ा दोष यह है कि राष्ट्रमंडल वास्तविक अर्थ में पार्लमेन्ट नहीं है। वह राज्यों के नागरिकों के लिए विधान या कानून नहीं बना सकता। राष्ट्रमंडल की कार्य-पद्धति में भी दोष है। किन्नी निर्णय के लिए सर्वसम्मति होना आवश्यक है। सिर्फ ४० लाब स्विम प्रजा के प्रतिनिधि अपने एकमत ने किन्नी भी निर्णय को रद्द कर सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग का सर्वप्रथम और आधारभूत सिद्धान्त यह है कि सन्सार के सब राष्ट्रों के नागरिकों में मानवता के प्रति श्रद्धा हो। मानवता और मानव-आदर्शों के प्रति अनन्य श्रद्धा की भावना ही मानव-एकता को प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान कर सकती है। नागरिकों को यह अनुभव कराने की आवश्यकता है कि मानवता धर्म, जाति, सम्प्रदाय और वर्ग (रंग) के धर्मों से ऊपर है। जब तक राष्ट्रों में नागरिकों द्वारा मानवता के प्रति यह आदर-भाव पैदा न किया जायेगा जब तक सच्ची और स्थायी सहकारिता एवं शान्ति की स्थापना सम्भव नहीं है।

सन्सार में शान्ति की स्थापना करने में प्रत्येक राष्ट्र का सहयोग आवश्यक है। हर राष्ट्र को अपना यह धर्म मोक्षार्थ करना चाहिए कि वह सन्सार की शान्ति-रक्षा के लिए उत्तरदायी है। यदि यूरोप के किसी छोटे देश पर कोई अन्याय होता है, तो अनुरोध की यह नीति रखनी चाहिए कि उसने अनुरोध के हितों का कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसी प्रकार एशिया में किसी राज्य पर कोई अन्यायपूर्ण आक्रमण होता है, तो यूरोप के उसे राज्य का हक होगा कि इसमें यूरोप का कोई सम्मेलन भी है। समान ही किसी भी भाग में होनेवाला छोटे-से-छोटा उपद्रव जिसका शांति का पक्ष न हो, पर प्रत्येक राज्य को मनी-भानि समझना पड़ेगा।

समान रूप से उत्पन्न ऐसे भाग में ऐसा राज्य पत्र जानिया भी है जो राजनीतिक, आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टियों में पिछड़ी हुई है और जो इस समय साम्राज्यवादी राज्यों की साम्राज्य-निष्ठा की शिकार है। राष्ट्रमण्डल ने ऐसे राष्ट्रों को पिछड़ी हुई जानिया का सामन-प्रबन्ध सामना-देश-प्रणाली के अन्तर्गत विनियमित करने के विजेता राष्ट्रों के हाथ में देकर उन्हें उनका भाग्य-निर्णायक बना दिया। ऐसी पिछड़ी तथा पराधीन जातियाँ एशिया और अफ्रीका में अधिक हैं। अब समस्या यह है कि इनके मध्य में, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए क्या किया जाये इसके लिए सबसे पहले अन्तर्राष्ट्रीय समाज को यह सिद्धान्त बिना किसी अपवाद के स्वीकार करना चाहिए कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पराधीन राष्ट्र को स्वाधीनता दे दी जाये तथा उनकी रक्षा के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कमिशन नियुक्त किया जाये। इस कमिशन का कार्य इस प्रकार स्वतन्त्र किये गये राष्ट्रों को सबल राष्ट्रों की कोष-दृष्टि से बचाना हो।

इस प्रकार संसार के प्रत्येक राष्ट्र को, चाहे वह एशियायी राष्ट्र हो या अफ्रीकन, अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में समानता का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार जातीय प्रश्न का एकदम खतमा हो जाना ही श्रेयस्कर होगा।

राष्ट्रों के आपसी झगड़ों के फैसले के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय किया जाये। प्रत्येक राष्ट्र को इस न्यायालय में ही अपने ऐसे विवाद का निर्णय कराने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। इस न्यायालय में सभी राष्ट्रों का विश्वास होना जरूरी है। कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न इस न्यायालय

की अधिकार-सीमा के बाहर न होना चाहिए और न किसी राष्ट्र को इस सबध में कोई विशेष रियायते दी जानी चाहिए ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधान का निर्माण किया जाना और प्रत्येक राष्ट्र से उसका पालन कराने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

समस्त राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग तथा विश्व-शान्ति के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सगठन स्थापित होना चाहिए । यह सगठन सध के सिद्धान्त के आधार पर कायम हो । प्रत्येक राष्ट्र को अपने सामान्य मामलों का नियन्त्रण और प्रबध इस सगठन को सौंप देना चाहिए ।

यह अन्तर्राष्ट्रीय सगठन वैदेशिक नीति, अन्तर्राष्ट्रीय सेना, आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रीय राजस्व, उपनिवेशों की समस्या, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात, अन्तर्राष्ट्रीय भद्रा और प्रवास आदि मामलों का प्रबध कर सकता है ।

हमने सक्षेप में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धान्तों की रूपरेखा तथा मौलिक सिद्धान्तों का विवेचन किया है । इनपर विस्तृत रूप से विचार उसी समय किया जा सकता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की कोई व्यावहारिक और श्रेष्ठ योजना तैयार की जाये ।

ससार की एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय सस्था राष्ट्रसंघ के पतन के कारणों पर विचार करके उनके निवारण का प्रयत्न करना चाहिए । राष्ट्रसंघ के पतन से हमें यह न समझ लेना चाहिए कि ससार में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता संभव ही नहीं है बल्कि उसके लिए उचित तरीके से प्रयत्न करना चाहिए ।

भारतवर्ष और अन्तर्राष्ट्रीयता

अन्तर्राष्ट्रीय समाज में भारतवर्ष का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। यद्यपि भारतवर्ष इस समय अपनी राजनीतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए अग्रसर है, तो भी इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि भारत विद्वान्तान्ति के लिए आज भी सर्वश्रेष्ठ देन देने की क्षमता रखता है। चाहे जिस दृष्टि से देखा जाये, भारत विश्व-बन्धुत्व के आदर्श को कार्यरूप में परिणत करने में समर्थ है। भारत का प्राचीन इतिहास हमारे इस कथन की सच्चाई प्रकट करता है।

भारत का विश्व-प्रेम

ससार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान और पुगन्तन्ववेत्ता इस बात में एकमत हैं कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्थाएँ विश्व में प्राचीनतम हैं। जैसे-जैसे साहित्य, विज्ञान, राजनीति आदि के क्षेत्रों में अन्वेषण और अनुसंधान होने जा रहे हैं, वैसे-वैसे यह प्रकट होता जा रहा है कि भारतवर्ष न केवल आध्यात्मिक जगत् में ही शिरोमणि रहा है, प्रत्युत साहित्य, कला-कौशल, ज्ञान-विज्ञान, समाज-नीति और राजनीति में भी किसी सभ्य राष्ट्र में पीछे नहीं रहा। कुछ ही समय पहले पाश्चात्य यूरोपीय विद्वानों की दृष्टि में भारत एक ऐसा 'दार्शनिकों का देश' था, जहाँ केवल मानु-महान्मात्रों की ही पूजा होती हो। परन्तु राजनीति और इतिहास के सुविश्लेषण भागीय विद्वान प्रो० बेनीप्रसाद ने अपने 'राजपूर्ण गन्ध 'प्राचीन भारत में राज्य की स्थिति' और 'प्राचीन भारत में शासन का मित्रान्त' तथा भारत-विज्ञान इतिहासवेत्ता ग्वे

१ 'द स्टेट इन ऐशियन इण्डिया'।

२ 'थिअरी ऑफ गवर्नमेंट इन ऐशियन इण्डिया'।

डा० तानीपसाह जायसवाल ने आने सुविधायित गन्थ 'हिन्दू राजतन्त्र' द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि भारतवर्ष केवल आध्यात्मिक जगत् में ही शिरोमणि नहीं रहा है परन्तु राजनीति में भी अगण्य रहा है। कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' इस विषय का अनुपम ग्रन्थ है।

नमन्त भारतीय साहित्य विश्व-संस्कृति और विश्व-प्रेम की विचार-धारा में ओतप्रोत है। वैदिक संस्कृति की सगुने बड़ी विशेषता यही है कि वह लोकसंगठ अर्थात् मानव-समाज के कल्याण को प्रमत्त और ऊँचा स्थान देती है। वैदिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोकसंगठ का सिद्धान्त अन्तर्भूत है। इसी विशेषता का फल है कि भारत-भूमि में सदैव ते विश्व-भावना की पूजा होती रही है। आज भी भारत में जिस राष्ट्रीयता का यगोगान हो रहा है, उसका भी आधार विश्व-प्रेम और लोकसंगठ ही है।

'वैदिक संस्कृति के अनुसार विश्व-प्रेम और देश-प्रेम एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, प्रत्युत पूरक भाव हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य अपने कुटुम्ब से अनुराग रखता हुआ भी देशभक्ति से मूख नहीं मोड़ता, राष्ट्र-हित में अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान करने के लिए तत्पर रहता है, उसी प्रकार एक सच्चा देशभक्त भी विश्व-हित के लिए अपना सब-कुछ अर्पण कर सकता है। जिन विचारकों का यह कथन है कि राष्ट्रीयता (देशभक्ति) विश्व-प्रेम के लिए घातक है, उन्हें अपना यह कथन आधुनिक उग्र राष्ट्रीयता के लिए ही सीमित रखना चाहिए। जो राष्ट्रीयता हमें दूसरों से द्वेष करना नहीं सिखलाती, वह हमारे विश्व के लिए अवाञ्छनीय किस प्रकार हो सकती है ?'

आयुर्वेद के पृथिवी-सूक्त अ० १२-१ में ऐसे ही भाव मिलते हैं—

“हे पृथिवी ! मरणधर्मा पदार्थ अथवा मनुष्य तुझसे उत्पन्न होते हैं और तुझमें ही विचरण करते हैं—निवास करते हैं, तू द्विपद (मनुष्य)

१ 'हिन्दू पॉलिटी'।

२ रामनारायण यादवेन्दु 'राष्ट्रसंघ और विश्व-शान्ति', पृ० २३५

और चतुर्दश (चौपायो आदि) का पालन-पोषण करती हैं । जिन मनुष्यों के लिए उदय होता हुआ सूर्य किरणों के द्वारा अमृत, जीवन-प्रद प्रकाश भली प्रकार देना है, फँलाना है, वे पाँचों मानव जातिपाँ (गौर, लाल, धूमर, पीत और कृष्ण) तेरी ही हैं ।

[पृ० सू० अध्याय १०-१ १५ वां श्लोक]

“वे सब प्रजाएँ हमें मिलकर—इकट्ठी होकर—भरपूर करें और हे पृथ्वी ! तू वाणी की मधुरता मुझे दे ।

[पृ० सू० अ० १२-१ १६ वां श्लोक]

“हे मातृभूमि ! तू इकट्ठा रहने का महत् स्थल है अतएव तू महनी पूजनीया है । तेरा वेग, गति, एव रूपन महान् है और महिमा-सम्पन्न, महत्त्वशाली, सूर्य परमात्मा अथवा ऐश्वर्य सम्पन्न राजा प्रमादरहित होकर तेरी रक्षा करना है । ऐसी तू भूमि प्रकाश की चमक को भाँति हमें उत्तम रीति से चमका, प्रवृत्त कर जिसमें हममें कोई द्वेष-स्पृहा न करे ।”

[पृ० सू० अ० १०-१ १६ वां श्लोक]

अन्य दिवा है —

“यद्यप्यन्य अथवा एक गृह के सदृश नाना भाषण बोलनेवाले और अनेक व्यवसायवाले जनों को धारण करती हुई यह पृथिवी निश्चेष्ट नया निश्चल गो की भाँति मुझे घन की हज़ारा धाराएँ दुहाये ।

[पृ० सू० अ० १२-१ ४५ वां श्लोक]

वैदिक सभ्यता में समस्त मानव समाज एक परिवार है परन्तु विभिन्न भाषा, रंग-रूप व्यवसाय आदि के कारण वह अनेक भागा में बँट गया है । जिस प्रकार एक परिवार के सदस्य विभिन्न भाषा, मातृभूमि और व्यवसाय में अनुगत रहने हुए भी परिवार-बन्धन में प्रयत्न करने हैं उसी प्रकार समस्त मानव-समाज भी एकता के सूत्र में बंध रह सकता है ।

पृथिवी-पृष्ठ के उत्तम १० वं श्लोक में विश्व-प्रेम का आदर्श चित्रित करनेवाला है जो एक दुःख है । पृथ्वी पर निवास करनेवाली पाँचों मानव जातियों को सम्मिलित का आदिष्ट है । पदस्वच्छ आदिता ही वह आदर्श है । पृथ्वी के गौरव की शक्ति को ही समस्त म

शासन करने के लिए पैदा किया है और चीन तथा कृष्ण वर्ण की जातियाँ तो शासित होने के लिए ही पैदा हुई हैं । इसे यूरोपीय 'गौर जातियों का भार' (White man's Burden) कहते हैं । यूरोपीय जातियों में जातीयता की भावना इतनी उग्र है कि वे सारे नस्ल में गैरो का प्रभुत्व चाहती हैं । आज यूरोप रूसीके अभिशाप से पीड़ित है ।

विश्व-बधुत्व और सम्राट् अशोक

भारत में विश्व-प्रेम के सिद्धान्त केवल साहित्य और धर्म-ग्रन्थों तक ही सीमित नहीं रहे हैं, प्रत्युत् जीवन में—व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों में—उनको चरितार्थ किया गया है । व्यक्तिगत जीवन के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । किन्तु हम यहाँ अहिंसा, प्रेम और विश्व-बधुत्व का एक ऐसा उदाहरण देना चाहते हैं, जैसा नस्ल के इतिहास में दूसरा नहीं मिलेगा ।

मानवता को एक सूत्र में बांधने एवं नस्ल में प्रेम का साम्राज्य स्थापित करने में सम्राट् अशोक ने जो प्रयत्न किया वह वास्तव में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है । राष्ट्रपति विल्लम ग्रेडिड, अमरीका के शान्तिवादी निकोलस बटलर मरे (जिन्हें गत वर्ष शान्ति का नोबुल पुरस्कार मिला है), रोसि, रोम्यां रोलॉ और महात्मा गांधी आदि महापुरुषों के सामूहिक प्रयत्न असोस के कार्य की ही परम्परा हैं । प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास-लेखक श्री० एच० जी वॉलन ने अशोक के सन्वन्ध में लिखा है—

‘अशोक पहला सम्राट् है, जिसने मनुष्यों के सच्चे उद्देश्य और जीवन-पथ को लक्ष्य में रखकर मनुष्य जाति को शिक्षित किया । उसने विशाल सेना और बड़ी भारी शक्ति के होते हुए भी, सैनिक और राजनीतिक विजय नहीं की । उसने अपने शौर्य, पराक्रम और वीरता को दिखाने के लिए किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, किसी देश का सर्वनाश करने के लिए, किसी राष्ट्र को गुलाम बनाने के लिए, सुन्दर नगरों को धूल में मिलाने के लिए, बाह्यतो, पीड़ितों और दुःखितों के अभिशाप से, हाहा-

कार से और आँसुओं से भरी पृथ्वी को अधिक बोझिल तथा दुःखि-मानव-समाज को अधिक दुःखी नहीं किया। उसने धर्म-विजय की, धर्म-भिक्षुओं द्वारा अतृप्त और सतृप्त सत्तार को प्रेम और धर्म का अमृत-पाकराया।”

अपने चतुर्दश शिला-लेख में अशोक ने लिखवाया है —

“धर्म-विजय को ही ‘देवताओं के प्रिय’ प्रियदर्शी मृत्युत विजय मानते हैं। इस धर्म-विजय को ‘देवताओं के प्रिय’ ने यहाँ (अपने राज्य में) तथा छह सौ योजन दूर पड़ोसी राज्यों में प्राप्त किया है, जहाँ अन्तर्योग नामक यवन राजा राज्य करता है, और अन्तर्योग के बाद तुरमय अलिकिति, यक और अलिकसुन्दर नाम के चार राजा राज्य करते हैं और उन्होंने अपने राज्य के नीचे (दक्षिण में) चोल, पाण्ड्य तथा ताम्रपर्णी में भी धर्म-विजय प्राप्त की है। उसी प्रकार हिंदुराजा के राज्य में तथा विषवज्जियों में, यवनों में, कम्बोजों में, नाभक नाभ-पक्षियों में, भोजों में, पिति निकाय आद्यों में और पुलिन्दों में सब जगह लोग देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन अनुसरण करते हैं और अनुसरण करेंगे। जहाँ जहाँ ‘देवताओं के प्रिय’ के ‘दूत नहीं पहुँच सकते, यहाँ-वहाँ लोग ‘देवताओं के प्रिय’ का धर्माचरण, धर्म-विज्ञान और धर्मानुशासन सुनकर धर्म के अनुसार ध्याचरण करते हैं। इस प्रकार सर्वत्र जो विजय हुई है, वह विजय वान्तत्र में सर्वत्र आनन्द देनेवाली है। धर्म-विजय में जो आनन्द है, वह वट्टन प्रगाढ़ है, पर वह आनन्द क्षुद्र वस्तु है। ‘देवताओं के प्रिय’ पारलौकिक कल्याण को ही बड़ी भारी वस्तु समझते हैं। इसलिए यह धर्म-लेख लिखा गया है कि मेरे पुत्र और पोत्र जो हों, वे नया देश विजय करना अपना कर्तव्य न समझें। यदि कभी वे नया देश विजय करने में प्रवृत्त हों, तो उन्हें शान्ति और नम्रता में काम लेना चाहिए और धर्म-विजय को ही सर्वोच्च विजय मानना चाहिए। उसमें इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख-लान होता है। उद्योग ही उसके आनन्द का कारण हो, क्योंकि उसमें दृष्ट्योक और परलोक दोनों मिश्र होने हैं।”

अशोक के अशोक के शिला-लेख में लिखा है —

“सब मनुष्य मेरे पुत्र हैं, और जिस प्रकार मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्रगण सब तरह के हित और सुख को प्राप्त करें, उनी प्रकार मैं चाहता हूँ कि सब मनुष्य ऐहिक और पारलौकिक सब तरह के हित और सुख का लाभ उठावे। आप लोग इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि यह नीति श्रेष्ठ है।”

“अशोक ने २८ वर्षों तक मनुष्यों की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए कार्य किया। इतिहास के पृष्ठों में जिन हजारों सम्राटों, राजा-महाराजों आदि का उल्लेख है, उनमें केवल अशोक का नाम आवाश में तारे के समान जगमगाता है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर के साथ लिया जाता है। चीन, तिब्बत और भारत में भी (यद्यपि उन्होंने अशोक के सिद्धान्तों का परित्याग कर दिया है) उसकी महानता की परम्परा सुरक्षित है। आज भी जीवित मनुष्यों में अशोक की स्मृति फान्स्टेनटाइन या चार्लेमेगन की यादगार से कहीं अधिक जाग्रत है।” ये हैं अशोक के प्रति विश्व के एक महान् इतिहास-वेत्ता श्री एच० जी० वैंत्स के विचार। श्री वैंत्स के इस कथन की सचाई में सन्देह करना अज्ञता होगी, परन्तु भारत के सम्बन्ध में उन्होंने जो-जो कहा है उसके सम्बन्ध में इतना और कहना पर्याप्त होगा कि आधुनिक काल में भी भारत ने अशोक की परम्परा का त्याग नहीं किया है। आजके युग में महात्मा गांधी का अहिंसात्मक आन्दोलन अशोक के ही सिद्धान्तों का प्रतीक है।

हमारे कथन का सार यह है कि भारत प्राचीन समय से ही विश्व-प्रेम, विश्व-बन्धुत्व और अन्तर्राष्ट्रीयता का पुजारी रहा है। आज भारत अपनी स्वाधीनता की सिद्धि में लगा हुआ है और हमारा यह ध्रुव विचार है कि स्वाधीन भारत विश्व में सच्ची अन्तर्राष्ट्रीयता को जन्म देने में सफल होगा।

ससार की स्थिति और भारतवर्ष

आक्सफोर्ड-विश्वविद्यालय के राजनीति के प्रोफेसर श्री एल्मेड जिमन

ने भारत के सम्बन्ध में अपने एक विचार-पूर्ण निबन्ध में लिखा है —

“आनेवाले युग में भारत विश्व-राजनीति का प्रकाश-स्तम्भ बनेगा। अधिक स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ यह है कि यदि भारत ब्रिटिश कॉमनवैल्व से अपना सम्पर्क बनाये रखेगा और दूसरी ओर कॉमनवैल्व भी भारत को अपने सघटन में समुचित पद प्रदान करेगा तो विश्व-शान्ति और मानव-समाज के अभ्युदय का मार्ग अत्यधिक प्रशस्त हो जायेगा। यदि भारत और दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशों के बीच समानता के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न विफल रहा, तो उसका परिणाम न केवल कॉमनवैल्व पर प्रत्युत समग्र मानव-समाज पर पड़ेगा। अन्तर्जातीय गघर्ष के लिए एक विशाल रंगमंच तैयार होजायेगा।”

प्रोफेसर जिमर्न के कथन में यह स्पष्ट होजाता है कि अन्तर्गष्ट्रीय समाज में भारत का स्थान अद्वितीय है। परन्तु भारत के पराधीन देश होने में मानव-समाज की उन्नति में बड़ी अड़चन होरही है। राष्ट्रमन्त्र या विश्व की राजनीति में अधीनस्थ राज्यों का कोई स्थान नहीं है। वैसे भारतवर्ष राष्ट्रमन्त्र के जन्म-समय में ही उसका मौलिक मद्ध्यम रहा है, परन्तु उसकी मद्ध्यमता के कारण उसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और न विश्व-शान्ति की समस्या के समाधान में ही कोई योग मिला है। भारत का राष्ट्रीय शोकमन प्रारम्भ में ही राष्ट्रमन्त्र की मद्ध्यमता का प्रतीक रहा है। यह इसलिए नहीं कि भारत राष्ट्रमन्त्र के आदर्शों में विश्वास नहीं करता, बल्कि इसका कारण यह है कि वर्तमान परिस्थिति में, जहाँ राष्ट्रमन्त्र युग के मर्यादित राष्ट्रों के सूटनीतिज्ञों का एक गुप्त मण्डल बन गया है, भारत का राष्ट्रमन्त्र में सम्बद्ध रहना किसीके लिए निवारण नहीं होसकता।

यह प्रतिष्ठा सिन्धु-सागर में भारत की ओर से राष्ट्रमन्त्र की अस्मिता के प्रतिवेदन में सम्मिलित होने के लिए प्रतिनिधि-मण्डल जेनेवा की जाना है, परन्तु यह प्रतिनिधि-मण्डल मध्ये प्रथम में भारत

मित्रता का सम्बन्ध बनाने में प्रयत्नशील है वहाँ ब्रिटिश शासन की नीति उनके माँया विपरीत नहीं जागृही है और हमारे देशों में भारत का सम्बन्ध दृढ़ करना तो हर उमके अपने जगो—ब्रह्मा, लका आदि—को ही उममे विच्छिन्न किया जागृहा है ।

१ अप्रैल १९३७ तक ब्रह्मा भारत का ही एक प्रांत था । परन्तु इसके बाद से ब्रह्मा को भारत में पृथक् करके एक स्वतन्त्र किन्तु ब्रिटिश सरकार के अधीन देश बना दिया गया है । वही नहीं, ब्रह्मा के लिए अलग शासन-विधान भी बनाया गया है जिसके अनुसार उसका शासन होरहा है । ब्रह्मा में १० लाख भारतीय निवास करने हैं । वहाँके व्यवसाय और कृषि में १० करोड़ रुपये की भारतीय पूंजी लगी हुई है । वहाँ मद्रास के बहु-संख्यक महाजन, बिहार-बंगाल के मजदूर और भारतीय सरकारी नौकर तथा वकील आदि हैं । अब इनमें और ब्रह्मा के लोगों में प्रतिस्पर्धा बनी रहने लगी । इस प्रतिस्पर्धा और भारतीयों के प्रति ब्रह्मी लोगों की घृणा का दुष्परिणाम यह हुआ है कि भारतीय ब्रह्मा के चावल, लकड़ी और तेल का बहिष्कार कर रहे हैं ।

लका में भी भारतीय मजदूरों की संख्या ६ लाख है । वहाँ भारतीय पूंजी और भारतीय शिक्षितों का अभाव है । भारतीय मजदूरों के साथ भेदभाव किया जाता है । स्थानीय समस्याओं के चुनावों में ग्राम्य मत-धिकार के सम्बन्ध में भी भारतीयों के साथ भेदभाव से व्यवहार किया जाता है । इसका भी दुष्परिणाम यह हुआ कि भारतवासी लका के नारियल तथा दूसरी चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं ।

प्रवासी भारतीय

प्रवासी भारतीयों की समस्या के विशेषज्ञ स्वामी भवानीदयाल सन्यासी ने अपने एक लेख में प्रवासियों की स्थिति के सम्बन्ध में लिखा है —

“इस समय संसार में भिन्न-भिन्न देशों और उपनिवेशों में प्रवासी भारतीयों की जन-संख्या लगभग २५ लाख है । जहाँ-जहाँ वे बसे हुए

हैं, वहाँ-वहाँ उनको अपने देश की पराधीनता के कारण अपमान का कड़वा घूँट पीना पड़ता है। पौन सदी तक जारी रहनेवाली शतबदी-प्रथा का इतिहास वास्तव में भारतीयों की अपकीर्ति का ही इतिहास है और उसमें विशेषतः अन्यायो, अत्याचारों और अपमानों के ही अध्याय मिलेंगे। यद्यपि अनेक सहृदय महानुभावों के उद्योग से अब इस प्रथा का अन्त होगया है, तो भी इससे उत्पन्न स्थिति की सीमा अभी अगोचर है। इतने आन्दोलनों और बलिदानों के बाद भी न तो प्रवासियों के सकट का अन्त हुआ है और न उनकी अवस्था में आशा-जनक अन्तर ही पड़ा है। मजा तो यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत उपनिवेशों में उन्हें सबसे अधिक अपमान के धक्के सहने पड़ते हैं।^१

दक्षिण अफ्रीका में प्रवामी भारतीयों के कष्टों की कहानी बहुत लम्बी पुरानी और चिरपरिचित है। महात्मा गांधी ने यह सारी कथा 'दक्षिण अफ्रीका का नत्याग्रह' के रूप में लिखी है, विन्नार से जानने के लिए पाठकगण उसे पढ़ें।

अफ्रीका के उन प्रदेशों में जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य है प्रवामी भारतीयों की स्थिति स्मटन के शब्दों में इस प्रकार है —

“ दक्षिण अफ्रीका में हम रंगीन जातियों को गोरो के साथ समानता का पद नहीं दे सकते। हमारी समानता मौलिक रूप से इस सिद्धांत पर आश्रित है कि धर्म और राज्य में गोरो और रंगीन जातियों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। ”

ये शब्द दक्षिण अफ्रीका की यूनियन के प्रधान-मंत्री और राष्ट्रमण्डल के एक भाग्य-विधाता के हैं। जातीयता की यह भावना कितनी उग्र है।

दक्षिण-अफ्रीका में प्रवामी भारतीयों की परिस्थिति वस्तुतः अत्यन्त गौचनीय है। वहाँ जातीयता का सबने उग्र रूप देखने को मिलता है। वहाँ भारतीय कुली^२ समझे जाते हैं और उनके साथ बर्ना ही व्यवहार

१. स्वामी भवानीदयाल सन्यासी - प्रवासियों की परिस्थिति ('सरस्वती', जनवरी १९३७ ई०) ।

किया जाता है। वहाँ स्वामी भवानीदयाल सन्यासी के शब्दों में—

“आज भी भारतीयों के लिए ट्रामो और ट्रेनो में अलग डिब्बे हैं। डाकघरों, स्टेशनो और दफ्तरों में रंग-भेद का नग्न प्रदर्शन है। होटलों और थियेट्रो के द्वारों उनके लिए बंद हैं। न उन्हें पार्लमेण्टरी सभाधिकार हैं और न म्यूनिसिपल। कुलीगिरी के सिवा उन्हें और कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। जो भाई खेती और रोजगार करते हैं उनकी राह में इतने कांटे बिखेर दिये गये हैं कि वे पाग-पाग पर चुभते हैं। राम और कृष्ण के वंशज एव बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, शंकर और दयानन्द के अनुयायी यहाँ असंभव हविश्यों से भी निम्नतर समझे जाते हैं।”

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रवादी श्वेतांगों की परिपक्व ने हाल में जो प्रस्ताव पास किया है वह यह है —

“यूरोपीय ईसाई संस्कृति की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि यूरोपीयों और अयूरोपीयों में यथासम्भव अन्तर रखा जाये, उनका विवाह-संबंध कानून से जुर्म ठहराया जाये, अयूरोपीय स्कूलों में अन्य वर्णों के साथ गौराग अध्यापक की नियुक्ति रोकी जाये, कोई भी श्वेतांग किसी अश्वेतांग से नौकरी में नीचे के ओहदे पर न रखा जाये और गोरी स्त्रियाँ अयूरोपीयों के यहाँ नौकरी करने से रोकी जायें।”

नेटाल तथा ट्रांसवाल (दक्षिण अफ्रीका) में श्वेतांगों ने स्वतः भारतीयों को बसाया था, पर उनके साथ बीभत्स पाप और अत्याचार किये गये। उनपर व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाये गये और ऐसे कानून बनाये गये जिससे वे भूमि के स्वामी न बन सके। उनके लिए यूरोपियों से पृथक् मुहल्ले बनाये गये। सन् १९२४ में जनरल स्मट्स की सरकार के पतन के बाद नयी सरकार ने प्रवासी भारतीयों के साथ और भी सख्ती से व्यवहार किया। यह अत्याचार यही तक समाप्त नहीं हुआ। रंग-प्रतिषेध कानून (Colour Bar Bill) के जो वाद में कानून के रूप में बदल गया, अनुसार सरकार भारतीयों को दूसरे अयूरोपीयों की भाँति दक्षतापूर्वक किये जानेवाले काम-धन्धों (skilled occupations) से

वर्चित कर सकती है।

केनिया और युगाण्डा की अवस्था भी करणाजनक और सोचनीय है। यद्यपि केनिया की व्यवस्थापिका सभा में प्रवासी भारतीयों के पाँच प्रतिनिधि हैं, तो भी अल्पसंख्यक होने के कारण उनकी आवाज में कुछ बल नहीं है। केनिया के पठार (Highland areas) श्वेतान्गों के लिए सुरक्षित हैं। केनिया के निकट टेंगेनिका प्रदेश है। पहले यह जर्मनी का उपनिवेश था। परन्तु यूरोपीय महायुद्ध के बाद सन् १९२० से इसका शासन-प्रबन्ध राष्ट्रसंघ की शासनादेश-प्रणाली (Mandate System) के अन्तर्गत अंग्रेजों द्वारा किया जाता है। यहाँ भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है।

ऑस्ट्रेलिया में एक समय की कॉमनवेल्थ ने भारतीयों का प्रवास सर्वथा रोक दिया था। इस रोक के प्रमुख कारण जातीयता के उग्र भाव और अर्थ-शोषण ही थे। और तो और, उन भारतीयों का प्रवेश भी रोक दिया जो केवल भ्रमण के ही लिए—बसने के लिए नहीं—जाना चाहते थे। प्रवासियों की स्थिति में सुधार के लिए प्रायः ७५ वर्षों से लगातार आंदोलन हो रहा है। इसीके फलस्वरूप सन् १९०४ में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीयों के प्रवेश पर से यह रोक हटा ली और भारतीय भ्रमणकारियों के लिए वहाँ जाने का द्वार खुल गया।

न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ, भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी थी। सन् १९१९ में भारतीयों के लिए न्यूजीलैंड में प्रवास-सम्बन्धी कड़े-से-कड़े नियम बनाये गये। सन् १९२० में प्रवास-प्रतिबन्ध-कानून के द्वारा समस्त प्रवासियों पर कड़े नियम लगाये गये। जो न्यूजीलैंड जाना चाहता उसे पहले से आज्ञा प्राप्त करना जरूरी होता था।

कनाडा में भी प्रवासी भारतीयों को बड़े-बड़े अत्याचार और अपमान सहने पड़े हैं। भारतीयों के सिवा चीनी और जापानी लोगों पर भी प्रवास-सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये गये। सन् १९१० में कनाडा की सरकार ने प्रवास-सम्बन्धी जो नियम बनाये वे जापानियों की अपेक्षा भारतीयों के लिए

अधिक अपमानजनक और प्रतिबन्धकारी थे। सन् १९१४ में सरदार गुन्दनमिह के नेतृत्व में भारतीयों (विशेषतः मिक्को) का एक दल जापानी जहाज कोमागाता मार्ग में कनाडा के लिए गया। परन्तु वह जहाज बन्दर पर लगातार तीन मास तक लगा रहा। कनाडा की सरकार ने उसके यात्रियों को कनाडा में प्रवेश करने में रोक दिया। अन्त में उस जहाज को वापस लौटना पड़ा। कनाडा की फेडरल सरकार के आग्रह पर भी ब्रिटिश कोलम्बिया के प्रवासी भारतीयों को अब तक नागरिक अधिकार में वञ्चित रखा गया है।

दक्षिणी रोडेशिया में भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। परन्तु वहाँ प्रवासियों की संख्या बहुत कम है।

फिजी और मॉरिशस में सन् १९३० में भारतीय प्रवासियों की जन-संख्या क्रमशः ७६,७०० और २५,७९६ थी। ये अंग्रेजों की प्राउन कॉलोनी हैं। इनको आबाद करने में भारतीयों ने अपना बलिदान दिया और पुरस्कार में उन्हें अपमान और दमन मिला। फिजी की व्यवस्थापिका पण्डित में अब पाँच प्रतिनिधि लिये जाते हैं। तीन भारतीय प्रतिनिधि निर्वाचित और दो मनोनीत होते हैं। मॉरिशस की जनसंख्या में तीन हिस्से भारतीयों की आबादी है। परन्तु उसपर भी राजनीतिक दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है। मेडागास्कर फ्रान्स के अधीन है। वहाँ प्रवासी भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार तो नहीं होता, फिर भी उनकी वह स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए। जो उसनिवेश उन तथा पुर्तगाली लोगों के अधीन है, उनमें भी भारतीयों की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है। जर्जीवार नाममान के लिए मुद्रान के शायों में है, उसके शासन-प्रवर्ध में अंग्रेजों का प्रभाव है। हाउ में जर्जीवार में लॉग व्यापार के स्वयं में जो नया गानून बनाया, उसमें भारतीयों में बड़ा असन्तोष पैदा हो गया। भारतीय राष्ट्रीय समाज—राष्ट्रम—ने भारत में इसी गानू का प्रतिरोध किया था।

प्रवासी भारतीयों की सम्पत्ति सन्तुष्ट बड़ी दिखती है। प्रारम्भ में जिन भारतीयों ने अपनी पूँजी और धन में ब्रिटिश उपनिवेशों को उन

योग्य बनाया कि वे मनुष्यों के रहने योग्य बन सकें और उन्हें व्यापारिक दृष्टि से उन्नत बनाने में पूरा योग दिया, आज उन्हीं भारतीयों को श्वेतांग यह कहते हैं कि उन्हें उपनिवेशों में प्रवास का कोई अधिकार नहीं है। प्रवासियों की इस दयापूर्ण दशा का एक मात्र कारण है भारत की परतन्त्रता। परन्तु स्वाधीनता-प्राप्ति के साथ प्रवासियों के वे सकट दूर हो जायेंगे।

साम्राज्य-विरोधी सघ

ससार भर में साम्राज्यवाद का आतक इतना बढ़ गया है कि उसका विरोध करने के लिए सन् १९२७ ई० में ब्रिसेल्स में अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्य-विरोधी सघ (League Against Imperialism) की स्थापना की गयी। सस्था का मूल उद्देश्य साम्राज्यवाद की सभी विरोधी शक्तियों को एक म्यान में बाँधना है, क्योंकि साम्राज्यवादियों से मघर्ष के लिए यह आवश्यक है कि उसकी विरोधी शक्ति को संगठित किया जाये। इस सस्था का कार्य उपनिवेशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध हो रहे युद्ध को चलाये रखना है। भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) और भारतीय अधिवासी-सघ का इस सस्था से सम्बन्ध है।

ब्रिसेल्स (जर्मनी) में जो स्थायी सघ स्थापित किया गया उसका सभापतित्व इंग्लैंड के प्रसिद्ध मजदूर नेता जार्ज लेन्सबरी ने ग्रहण किया था। प० जवाहरलाल नेहरू ब्रिसेल्स की साम्राज्य-विरोधी परिषद् में सम्मिलित हुए थे। उसके सम्बन्ध में उन्होंने 'मेरी कहानी' में लिखा है —

“काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति साम्राज्य-विरोधी लीग के संरक्षक हैं। उनमें एक तो मि० आइन्स्टीन हैं और दूसरी थोमती सनयातसेन और मेरा लाला हैं रोम्यां रोलॉ भी। कई महीने बाद आइन्स्टीन ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों के जो झगड़े हो रहे थे उनमें लीग ने अरबों का पक्ष लिया था और यह बात उन्हें नापसन्द थी।”

१० जवाहरलाल नेहरू का डम मघ से पहले सम्पर्क था, परन्तु सन् १९३१ से कांग्रेस और सरकार के बीच दिल्ली में जो समझौता हुआ और उसमें नेहरूजी ने जो भाग लिया उसपर साम्राज्यवाद विरोधी सघ उनसे नाराज होगया और उमने उन्हें अपनी मद्रम्यता से अलग करने के लिए प्रस्ताव भी पास किया ।

पी० ई० एन० और भारत

पी० ई० एन०^१ क्लब कवियों, पत्रकारों, नाटककारों, मपादकों और उपन्यास-लेखकों की एक अन्तर्राष्ट्रीय-संस्था है । इंग्लैंड की प्रसिद्ध विदुषी लेखिका श्रीमती केथरिन ए० डामन स्कॉट ने लन्दन में अक्टूबर १९२१ में इसकी स्थापना की थी । पर इस समय इस संस्था की समस्त सससर में ४० देशों में शाखाएँ हैं । सुविख्यात अंग्रेजी उपन्यास-लेखक जॉन गैल्स-वर्दी प्रारम्भ से अग्नी मृत्यु तक इस संस्था के प्रधान रहे । उसके बाद यह सम्मान सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासवेत्ता श्री एच० जी० वैंत्स को दिया गया । इस समय वही इस संस्था के प्रधान हैं । पी० ई० एन० का उद्देश प्रत्येक स्थान के लेखकों में पारस्परिक सद्भावना और सहानुभूति पैदा करना है । पी० ई० एन० वास्तविक अर्थ में एक विश्व-संस्था है । यह उन लेखकों के विरुद्ध नहीं है जो उसके सदस्य नहीं हैं । उसमें जाति, रंग, राजनीति तथा राष्ट्रीयता के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं है । सससर के प्रमुख लेखक चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, श्वेतांग हों या पीतांग, जवान हों या वृद्ध गरीब हों या धनी, अथवा चाहे जिस धर्म, जाति या राष्ट्र के हों, इस संस्था के सदस्य हों सकते हैं—

भारत में भी पी० ई० एन० की शाखा सन् १९३३ ई० में दम्बई में स्थापित हो चुकी है । जब पी० ई० एन० की तेरहवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस मई १९३५ में बार्सिलोना नगर में हुई थी तो उसमें भारत की ओर से

P=Poets Playwrights (कवि, नाटककार), E=Editors - Essayist (सम्पादक निबन्धकार), N=Novelists (उपन्यासकार)

श्रीमती सोफिया वाडिया प्रतिनिधि की हैसियत से सम्मिलित हुई थी। इस सस्था के द्वारा समस्त प्रसिद्ध भारतीय लेखकों को परस्पर एक-दूसरे को जानने और समझने का ही सुयोग नहीं मिलता, प्रत्युत उनका अन्तर्प्रान्तीय साहित्यिक सम्पर्क भी होना है। यह सस्था दो दिशाओं में भारत में साहित्य की पगति के लिए कार्य करती है —

(१) अपने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मदस्य लेखकों की अंग्रेजी रचनाओं को ससार भर में प्रसिद्ध करना।

(२) अपने सदस्यों की भारतीय भाषाओं में लिखी गयी रचनाओं को समस्त भारत में प्रसिद्ध करना और भारत की विविध-भाषा-सम्बन्धी सस्कृतियों के सम्बन्ध में ज्ञान का प्रसार करना। इसी उद्देश्य के लिए एक अखिल भारतवर्षीय भाषा-समिति भी स्थापित की गयी है जिसमें अनेक भारतीय भाषाओं के प्रमुख प्रतिनिधि हैं।

इस शाखा की ओर से 'इण्डियन पी० ई० एन०' नामक एक मासिक पत्रिका भी निकल रही है, जिसमें सस्था की गतिविधि और लेख प्रकाशित होते रहते हैं।

भारतीय शाखा की प्रबन्ध-समिति इस प्रकार है —

(१) डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर	}	प्रधान
(२) श्री० रामानन्द चट्टोपाध्याय		उपप्रधान
(३) श्रीमती सरोजिनी नायडू		
(४) सर स० राधाकृष्णन्		
(५) श्रीमती सोफिया वाडिया		संगठनकर्त्री

उमके लिए बड़े-से-बड़ा बलिदान करने में तत्पर रहता है।

वे सम्बन्ध, जिनके कारण एक जन-समूह राष्ट्र कहलाता है, कई प्रकार के हैं—भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, धार्मिक और जातीय। इनमें सबसे प्रमुख भौगोलिक सम्बन्ध है। एक देश में रहने के कारण व्यक्तियों में देशभक्ति की भावना पैदा होजाती है और वे उसे अपनी मातृभूमि समझते हैं। एक ही संस्कृति एवं ऐतिहासिक परम्परा भी व्यक्ति-समूह के पारस्परिक बन्धनों को मजबूत बनाती है। एक धर्म के अनुयायियों में भी एक प्रकार का बन्धुत्व स्थापित होजाता है। आर्थिक हितों की समानता भी ऐसे सम्बन्धों को पैदा करने में सहायक है। अन्त में जातीय एकता—रक्त-सम्बन्ध—भी राष्ट्र का एक बन्धन है। परन्तु उसपर अधिक जोर देने आवश्यकता नहीं है। सच तो यह है कि आज ससार की कोई भी जाति अपने रक्त की पवित्रता का दावा नहीं कर सकती। परन्तु तो भी यूरोपियन जातियाँ अपनी जातीय भावना के कारण ससार में अन्याय और अनाचार कर रही हैं। अमरीका जैसे सभ्य और सुसंस्कृत देश में ह्विशियों पर भीषण अत्याचार किये जा रहे हैं। उनका 'लिंग' किया जाता है। अफ्रीका में भी काली जातियों के साथ गोरो के बर्बरतापूर्ण अत्याचार आज भी हो रहे हैं। जर्मनी में जातीय पवित्रता की भावना ने ऐसा उग्र और भयंकर रूप धारण किया कि हिटलर ने अपने देश से यहूदियों को निकाल दिया। हिटलर की यह धारणा है कि केवल जर्मन ही पवित्र आर्य हैं। यहूदियों के ससर्ग में रहने से जर्मनों का आर्यत्व नष्ट होजायेगा, इसलिए उन्हें जर्मनी में न रहने दिया जाये। विदेशों में गोरी जातियाँ प्रवासी भारतीयों को 'कुली' कहकर उनके साथ कैसा अन्याय करती हैं, यह तो सबको भलीभाँति विदित ही है।

प्रोफेसर रामजे म्यूर ने सिद्ध किया है कि जातीयता की भावना (अर्थात् यह विश्वास कि हमारी जाति ही नसार में सर्वश्रेष्ठ है और दूसरी जातियाँ अपवित्र या वर्ण-मकर हैं) ससार की जातियों में घृणा, रग-द्वेष, प्रतियोगिता और असान्ति पैदा करनेवाली है।

मसार में राष्ट्रीयता ने इतनी अशानि पैदा नहीं की जितनी कि जातीयता की भावना ने की है ।^१

राष्ट्र के लिए भाषा की एकता भी जरूरी है । जबतक जनसमूह में भाव-प्रकाशन सामान्य भाषा द्वारा न होगा, तबतक उसमें विचार की एकता भी पैदा नहीं हो सकती और जब विचार-एकता पैदा नहीं होगी, तो उसमें सांस्कृतिक एकता पैदा नहीं हो सकती । भारत में राष्ट्रीय नेताओं ने इस आवश्यकता का अनुभव किया है और इसी लिए सामान्य-भाषा—राष्ट्रभाषा—के निर्माण के लिए प्रयत्न हो रहा है ।

राष्ट्र की ऐतिहासिक परम्परा के मध्य में प्रोफेसर रामजे म्यू का मन है —

‘वीरों के महान् कृत्य और वीरता के साथ किया गया बलिदान ऐसा धोखे और पीछेछे भोजन है जिसमें राष्ट्र की आत्मा को शक्ति और स्फूर्ति मिलती है । इसीसे अमर और पाँचत्र परम्परा और इतिहास का निर्माण होता है, और फलतः राष्ट्र-निर्माण का मार्ग भी साफ होना है । इनके मुकाबिले धन-सम्पदा, जन और भूमि हेय प्रतीत होती हैं । जिस राष्ट्र के पास ऐसी स्मृतियों का अक्षय भण्डार है, उसके देश के आम-पाम रहनेवाले लोग, जिनका उससे न कोई जाति-मिश्र है और न धर्म नया भाव का संबंध उसमें मिल जाने में आत्मगौरव अनुभव करेंगे ।’

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता एक भावना है । जिस देश की जनता में सामान्य भावना है वही राष्ट्रीयता का मार्ग बनाने में सक्षम है ।

राष्ट्रीयता के उदय के कारण

आज हम राष्ट्रीयता का उदय उन सभी देशों में देख रहे हैं जो विदेशी-शासन के निरक्षण में हैं और जो देश स्वाधीन हैं उसमें तो राष्ट्रीयता का विकास ऐसी बखर दिना में हुआ है कि आज विद्वानों

१ रामजे म्यू ‘नेशनलिज्म एण्ड इण्टरनेशनलिज्म’ (१९१९)
पृ० ३८-३९

का यह मत है कि राष्ट्रीयता ही ससार में असान्ति का मूल है। स्वाधीन और पराधीन दोनों प्रकार के देशों में राष्ट्रीयता के विकास के भिन्न-भिन्न कारण हैं।

स्वाधीन देशों में विज्ञान, आविष्कार और औद्योगीकरण ने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। पाश्चात्य देशों में औद्योगिक क्रान्ति ने जनता के सामाजिक जीवन में आश्चर्यजनक क्रान्ति पैदा कर दी। पहले लोग छोटे-छोटे साधारण कम्बों और ग्रामों में रहते थे। अधिकांश लोग मेहनत-मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय था। यातायात तथा पत्र-व्यवहार के साधन वैज्ञानिक ढंग के न होने से परस्पर मेल-मिलाप भी कम होता था। साक्षरता एवं शिक्षा का बड़ा अभाव था। इन कारणों से उनमें राष्ट्र-भावना का विकास नहीं हो सका। यदि आप ३० वर्ष पूर्व की रूस, चीन, ब्रह्मा तथा भारत की स्थिति का अध्ययन करें तो आपको यह स्पष्ट होजायेगा कि भारत में भी पहले राष्ट्र-भावना नहीं थी। परन्तु जब उद्योग-धन्धों का विकास हुआ, नवीन आविष्कारों के कारण नयी-नयी मशीनें, यंत्र तथा औजार तैयार किये गये, तब उद्योगवाद का जन्म हुआ। उद्योगवाद ने पूँजीवाद को विकसित किया। पूँजीवाद ने अपनी रक्षा और वृद्धि के लिए देश में राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया और उसका मनमाना उपयोग किया।

आज सभ्य तथा स्वाधीन देशों में शिक्षा तथा समाचारपत्रों द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार किया जा रहा है। स्कूलों और कालेजों में प्रत्येक राष्ट्र ऐसी शिक्षा की योजना काम में ला रहा है जिससे अपने राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठता की छान छात्रों के हृदय पर पड़े। पूँजीपतियों द्वारा संचालित समाचारपत्र भी राष्ट्रीयता का प्रचार कर रहे हैं।^१

जो देश पराधीन हैं, उनमें राष्ट्रीयता के उदय के कारण इनसे भिन्न है। पराधीन राष्ट्रों में साम्राज्यवादी राष्ट्रों के द्वारा जो अधिक

१ डब्ल्यू बी करी - 'दि वेस फॉर फेडरल यूनियन' (१९४०)
पृष्ठ ५३।

शोषण किया जाता है तथा उनके आर्थिक जीवन को नष्ट कर दिया जाता है, उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अर्थात् अपने आर्थिक सर्वोत्थान से रक्षा पाने के लिए राष्ट्रीय भावना पैदा होती है। समस्त दास और पीड़ित जनता में वैदेशिक नियन्त्रण से मुक्ति पाने के लिए एकता का भाव पैदा होता है और वह इस आधार पर आन्दोलन उठाती है कि विदेशी बन्धन से मुक्त होजाने पर समस्त जनता का कल्याण होगा वरन् इस प्रकार राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होजाती है।

राष्ट्रीयता की भावनाएँ

आज के युग में हम राष्ट्रीयता की तीन भावनाएँ मुख्य रूप में पाते हैं। जनतन्त्रीय देशों में पूँजीवादी राष्ट्रीयता अपनी चरम-सीमा पर पहुँच चुकी है। अधिनायकतन्त्रवादी राज्यों में फैसिस्ट राष्ट्रीयता हिंस्र और युद्ध का प्रचार ही नहीं कर रही है बल्कि यूरोप की सभ्यता और स्वाधीनता के नाश के लिए युद्ध-क्षेत्र में सज्ज है। एक तीसरी राष्ट्रीयता की भावना का उदय स्वाधीनता के माधक भारत में हो रहा है जिसके प्रवर्तक मार्ग के अद्वितीय शान्तिवादी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसे हम मानववादी राष्ट्रीयता का नया नाम देगे।

(१) पूँजीवादी राष्ट्रीयता

फ्रांस की गणतन्त्रान्ति के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम तथा अन्य देशों में प्रजातन्त्र का उदय हुआ। स्वाधीनता, समता तथा बन्धुता के भावों का जनता में बड़ा प्रचार हुआ। सबसे पहली बार जनता ने एकात्मक शासन में मुक्ति पारी और प्रजा की स्वाधीनता की स्थापना की। इस तन्त्रान्ति के बाद प्रजातन्त्र के नाम पर व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का घोर प्रचार किया गया। इसका परिणाम यह निकला कि प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिज्ञ मिड, स्पेयर, मिन्टिक, ग्रीन और ब्रोन्सफ़ेल्ड ने सुन्दरमनुष्य व्यक्तिवाद का समर्थन किया।

अंग्रेजों का मत यह है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की

उन्नति उसकी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए भिन्न-भिन्न प्रकार के सब व्यक्तियों के लिए एक-सा कानून बनाना ठीक न होगा। सरकार को व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वतन्त्र रीति से अपनी उन्नति और विकास का अवसर देना चाहिए। इस प्रकार व्यक्तिवाद सरकार के कार्यों को बहुत ही मर्यादित मानता है। गीन ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि सरकार दमन या सुशासन के द्वारा समाज के आत्म-निर्णय के अधिकार में कोई बाधा न डाले। सब लोगों को अपने-अपने रास्ते से चलने देना उचित है।

व्यक्तिवाद का विकास उन्नीसवीं सदी में यहाँ तक हुआ कि व्यक्तियों को कानून की दृष्टि में समान समझा जाने लगा। प्रत्येक (वालिग) व्यक्ति को समान मताधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में समता का सिद्धान्त स्थिर किया गया।

राजनीतिक समता के कारण नागरिकों को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार मिला। प्रतिनिधि-संस्थाओं का विकास हुआ। प्रतिनिधि-संस्थाओं की यह विशेषता है कि राज्य का शासन जनता-द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। अतः इस प्रणाली के अन्तर्गत निर्वाचकों का अधिक महत्त्व है। जिस दल का पार्लमेण्ट में बहुमत होता है, उसी दल का नेता मन्त्रिमण्डल बनाता है और इस तरह वह सारे देश का शासन करता है। परन्तु पूँजीवाद के प्रभाव के कारण निर्वाचक स्वतन्त्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। चुनाव पूँजी-पतियों के हाथ में होता है। वे जिसे ठीक समझते हैं, उसीको चुनाव में खड़ा करते हैं और उसे कामयाब बनाने के लिए निर्वाचकों को तरह-तरह के प्रलोभन देते हैं। इस प्रकार निर्वाचकों और प्रतिनिधियों का पतन किया जाता है। देश के बड़े-बड़े प्रभावशाली पत्रों के स्वामी भी पूँजीपति ही होते हैं, जिससे समाचारपत्र भी ऐसे ही उग्मीदवारों का समर्थन करते हैं। अतः शोषित समाज के लिए राजनीतिक समता व्यर्थ सिद्ध होती है। वह स्वतन्त्रता से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता।

वेनितो मुसोलिनी ने उग राष्ट्रीयता का प्रचार आरम्भ से ही किया है। मुसोलिनी ने अपने एक लेख में लिखा है —

“... फासिज्म जितना अधिक सामयिक राजनीतिक दृष्टिकोण को अलग रखकर, मानवता के भविष्य और उसके विकास पर विचार एवं चिन्तन करता है, उतना अधिक न तो वह स्थायी शान्ति की उपयोगिता में विश्वास करता है और न ऐसा सम्भव ही है। इस प्रकार वह शान्तिवाद के उस सिद्धान्त को अस्वीकार करता है जिसकी उत्पत्ति सघर्ष के परित्याग और आत्मत्याग के सामने कायरता से हुई है।”

“सिर्फ युद्ध ही मानवीय शक्तियों को सबसे अधिक उत्तेजना प्रदान करता है और मानवों के हृदय पर श्रेष्ठता की छाप लगाता है।” अतः जो सिद्धान्त शान्ति को इस हानिप्रद कल्पना पर स्थिर है, वह फासिज्म का विरोधी है।

“वह (फासिज्म) मानव-समाज को आदिकाल के कबीले के जीवन से ऊँचा उठाकर मानव-शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है—जिसे साम्राज्य कहते हैं।

“फासिज्म के लिए साम्राज्य का विकास—अर्थात् राष्ट्र का विस्तार—शक्ति का आवश्यक प्रदर्शन है और इसका विपरीत अधःपतन का लक्षण है। जो जातियाँ उठ रही हैं, वे सदैव साम्राज्यवादी ही होती हैं। इसका परित्याग ही पतन और मृत्यु का लक्षण है।”

हिटलर की ओर से भी एक दगाव्दी से जर्मनी में हिंसा, युद्ध और दूसरे राष्ट्रों के प्रति घृणा तथा विद्रोह का प्रचार हो रहा है। उन्होंने भी अपने आत्मचरित्त ‘मेरा संघर्ष’ में लिखा है —

“यथार्थ में शान्तिवादी-मानववादी भावना पूर्णतः अच्छी है, परन्तु इस शर्त पर कि सबसे पहले सर्वोच्च मानव-वर्ग ने संसार को इस सीमा तक जीत लिया हो कि वह संसार का एकमात्र स्वामी बन जाये।”

१. सीन्योर मुसोलिनी ‘द पोलिटिकल एण्ड सोशल डॉक्ट्रीन ऑफ फासिज्म इन इन्साइबलोपोडिया इटैलियाना’ (१९३२)

इसलिए हमें पहले युद्ध करना चाहिए—शान्तिवाद शायद भविष्य में देखा जायगा।”

हिटलर ने जर्मन जनता में सामरिक भावना पैदा करने के लिए ही लिखा है —

“जर्मनी की सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए तुम्हें यह न पूछना चाहिए कि ‘हम किस तरह शस्त्रास्त्र बनायें?’ बल्कि यह भावना पैदा करनी चाहिए जिससे मनुष्यों में शस्त्र-धारण की क्षमता प्राप्त हो जाये। यदि ऐसी भावना लोगों में पैदा होजाये, तो उनकी इच्छा-शक्ति सहजो ढंग से प्रकट होसकेगी, जो उनमें से किसी को भी शस्त्रीकरण की ओर ले जायेगी। यो एक कायर व्यक्ति को १० पिस्तौल के बिये जाये, तो भी जब उसपर आक्रमण होगा तो वह एक गोली भी न छोड़ सकेगा।”

“ऐसे राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोलन को धिक्कार है, जो केवल विरोध पर निर्भर रहता है और युद्ध की तैयारी नहीं करता।”

उपर्युक्त अवतरणों में यह स्पष्ट है कि ‘राष्ट्रीय समाजवाद’ का आधार सैनिकवाद और हिंसा है। इस फासिस्ट राष्ट्रीयता का जर्मनी में समाचारपत्रों और स्कूलों द्वारा भी प्रचार किया जाता है। जर्मनी में डेर हिटलर ने उग्र राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए हर उपाय में काम किया है। ग्राफ़िक्स, चित्र, फिल्म, संगीत, मिनेमा, रेडियो आदि मर्याद उपयोग युद्ध और हिंसा के भाव को जगाने के लिए किया गया है।

जर्मनी में प्रचलित गीतों में भी काम, रक्त और यूर्हिशों के प्रति जर्मनी के हृदय में पान्थिस, युवापुर्ण और प्रतिहिंसा के भावों का कायम स्थायी रूप में जगाने की प्रयत्न देखा है।

उत्तरित पर जो नरक और अन्धकारकारी अस्तित्व जर्मनी द्वारा जिने गये हैं उनके अन्तिम उद्देश्य अहिंसा के पुनर्स्थापन के लिए है —

“जर्मनी ने यूरोपों पर जो अत्याचार किये हैं, उनकी कर्तव्य-प्रतिष्ठा में बेहोश है। प्रचलित काल के अत्याचारों के अन्तिम स्थायी हो

राष्ट्रीयता

गये थे जितने कि हिटलर पागल होगये प्रतीत होते हैं। धार्मिक जोश के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वह उग्र राष्ट्रीयता के धर्म का विकास कर रहे हैं जिसके नाम पर किया गया अमानवीय कार्य मानवीय बन सकता है। और जिसके लिए इहल परलोक में पुरस्कार मिलेगा।”

यह है इस उग्र राष्ट्रीयता का स्वरूप। इसका अधिक उल्लेख की आवश्यकता नहीं कि फासिज्म सत्सार में स्थायी शान्ति का है। वह अन्तर्राष्ट्रीयता में विद्वान् नहीं करता। उनका आराध्य राष्ट्रवाद, सैनिकवाद और साम्राज्यवाद है। फासिज्म स्वदेश के लिए अन्य देशों पर आधिपत्य को मानवता की शक्ति का प्रदर्शन मानता है। वह युद्ध को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि सन्देश विस्तार युद्ध के बिना सम्भव नहीं है। इसमें तनिक भी सन्देह वर्तमान युद्ध यूरोप में बढ़ती हुई पूँजीवादी और फासिस्ट राष्ट्रीय ही भयकर परिणाम है।

(३) मानववादी राष्ट्रीयता

महात्मा गांधी की राष्ट्रीयता अहिंसा और विद्व-प्रेम पर स्थित सबसे पहले मानव है और अन्त में भी मानव है। उनके हृदय में मान के लिए प्रेम है, आदर है और नकुचित जातीयता को वह दृष्टि से देखते हैं। अहिंसा के अनन्य पुजारी होने के कारण वह भी राष्ट्र की जनता को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने की भावना अपने सिद्धान्त के विरुद्ध मानते हैं। वह वास्तव में एक आदर्शवादी है।

गांधीजी स्वदेश के नागरिकों में एकता चाहते हैं—समन्वय हैं—सघर्ष नहीं। भारत में उनका लक्ष्य यह है कि उसके मतभेदों और विवादों को मिटाकर जनता को स्वराज्य के लिए किया जाये, स्त्रियों को उठाकर पुरुषों के समान राजनीतिक, सामाजिक धरानल पर बिठाया जाये, राष्ट्र को विभक्त करनेवाले

घृणा-द्रोहों का अन्त कर दिया जाये और हिन्दू-यम की अस्पृश्यता के सामाजिक कण्ठ में मुक्त कर दिया जाये ।' गांधीजी की यह प्रार्थना है कि 'यदि मेरा पुनर्जन्म हो, तो मैं अछूत होकर जन्मना चाहूँगा, ताकि मैं उनके दुःख-दर्व और अपमान में भाग ले सकूँ और अपने-आपको तथा उनको उस दयनीय दशा में हड़ाने का यत्न कर सकूँ ।'^१

उनकी दृष्टि में हिन्दू, मुसलमान, पाय्सी, ईसाई आदि में कोई भेद नहीं है। वह यद्यपि हिन्दू-यम का पालन करने हैं और हिन्दू होने का उन्हें गर्व है, तथापि समार के अन्य यमा के प्रति उनके हृदय में अगाध श्रद्धा है। इसका कारण यह है कि गांधीजी यमा की एकता में विश्वास करते हैं। उनका विचार है कि समार के सब यमों में तात्त्विक एकता है—उनके मूल सिद्धान्त एक-मे हैं। गांधीजी नागरिक समानता को भारत में स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है—

“जब युद्ध के बादल बिखर जायेंगे और भारत अपनी स्वाधीनता का अधिकार पा लेगा, तब मुझे शक नहीं कि कांग्रेसी लोग किसी मुसलमान, सिक्ख, ईसाई या पारसी को अपने प्रधान-मन्त्री के तौर पर वैसे ही सहर्ष स्वीकार करेंगे जैसे कि एक हिन्दू को। इतना ही नहीं, वह कांग्रेसी न भी हो, तो भी वैसे ही और किसी प्रकार के धर्म या वर्ण के भेद बिना उसे अधिकार देंगे ।”^२

महात्मा गांधी प्रजातन्त्र के प्रबल समर्थक हैं। वह राष्ट्र के विविध वर्गों, हितों और समुदायों में सहयोग और एकता चाहते हैं। वह किसी एक वर्ग का शासन नहीं चाहते। बहुमत के निर्णय में उनका विश्वास है। फासिज्म और नाजीवाद की उन्होंने सदैव निंदा की है और उन्हें सभ्यता एवं सस्कृति का शत्रु कहा है।

१ गांधी-अभिनन्दन-ग्रन्थ : सम्पादक—श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन (१९३९) पृ० १०

२-३ 'हरिजन-सेवक' (पूना) 'मेरा अन्याय' (गांधीजी) २८ सितम्बर १९४०

वह मानव-सेवा के सबसे महान् समर्थक हैं। सार्वजनिक जीवन में शुद्धि तथा सदाचार पर वह जोर देते हैं। उनमें मातृभूमि के लिए बड़े-मे-चड़ा त्याग और वलिदान करने की शक्ति है। परन्तु उनकी देशभक्ति उग्र एवं दूसरे राष्ट्र के लिए विघातिनी नहीं है। वह अपनी जन्म-भूमि के प्रति अनुराग रखते हुए भी मानवता-प्रेमी हैं, विश्व-शान्ति के समर्थक हैं।^१

गांधीजी का विश्वास है कि भारत की प्राचीन सभ्यता से ससार के विकास में सहायता मिल सकती है। नीचे गिरा हुआ भारत मानव-जाति को शाशा का सन्देश नहीं दे सकता। जाग्रत स्वनम्र भारत ही पीड़ित ससार की सहायता कर सकता है। गांधीजी कहते हैं कि यदि अंग्रेज लोग न्याय, शान्ति और व्यवस्था की अपनी भावना में सच्चे हों, तो आक्रान्ता शक्तियों को दबा देना और वर्तमान परिस्थिति को ही कायम रखना उचित नहीं है। हमारे माने हुए आदर्शों के विपरीत जो परिस्थिति हो उसे सुधारने से इन्कार करना भी हिंसा है। न्याय और स्वतन्त्रता के हमारे प्रेम में इस निष्क्रिय हिंसा से बचने का बल होना चाहिए। यदि साम्राज्यों का निर्माण मनुष्य की तृष्णा, क्रूरता और घृणा ने किया है, तो ससार को न्याय तथा स्वतन्त्रता की शक्तियों का साथ देने के लिए कहने से पहले हमें उनको बदलना होगा। हिंसा या तो सक्रिय होगी या निष्क्रिय। आक्रान्ता शक्तियाँ इस समय सक्रिय हिंसा कर रही हैं, वे साम्राज्यवादी शक्तियाँ भी हिंसा की उतनी ही अपराधिनी और स्वातन्त्र्य

१ My patriotism is both exclusive and inclusive. It is exclusive in the sense that in all humility I confine my attention to the land of my birth, but it is inclusive in the sense that my service is not of a competitive or antagonistic nature.

—‘महात्मा गांधीज स्पीचेज एण्ड राईटिंग्स’ (चतुर्थ संस्करण) .
जी० ए० नटेशन फं०, मद्रास

नया प्रजातंत्र की विरोधिनी हूँ, जो भूत-काल की हिंसा द्वारा प्राप्त अन्यायपूर्ण कामों का उपयोग करने में आज भी मग्न हूँ। जबतक इस मामले में ईमानदारी से काम न लेगे, तबतक हम मजबूरी में विश्व-व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकेंगे, और मसारा में युद्ध तथा युद्ध का भय जारी रहकर, अनिश्चय की व्यवस्था स्थायी होजायेगी। भाषा को स्वतंत्र कर देना ब्रिटिश ईमानदारी की अग्नि-परीक्षा है।^१

मार्च १९३९ के विश्व-संकटकाल में 'न्यूयार्क टाइम्स' के एक मवाददाता ने गांधीजी से ससारा के लिए मन्देश माँगा, तब उन्होंने कहा कि सब प्रजातंत्रों को एकदम निःशस्त्र होजाना चाहिए। उन्होंने बतलाया कि इसी एकमात्र हल से युद्धों का अन्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा—“मुझे यहाँ बैठे-बैठे ही निश्चय है कि इससे हिटलर की आँखें खुल जायेंगी और वह आप निःशस्त्र होजायेंगे।”

सवाददाता ने पूछा—क्या यह चमत्कार नहीं है ?

गांधीजी ने जवाब दिया—शायद। परन्तु इससे ससारा की उल्लेखनीय रक्तपात से रक्षा होजायेगी जो अब सामने दीख रहा है। कठोरतम धातु काफी आँच से नरम होजाती है, इसी प्रकार कठोरतम हृदय भी अहिंसा की पर्याप्त आँच लगने से पिघल जाना चाहिए और अहिंसा कितनी आँच पैदा कर सकती है उसकी कोई सीमा नहीं।^२ अर्थात् आधी शताब्दी के अनुभव में मेरे सामने एक भी ऐसी परिस्थिति नहीं आयी जब मुझे यह कहना पड़ा हो कि मैं असहाय हूँ और मेरी अहिंसा निरुपाय होगयी।^३

गांधीजी का अहिंसा की शक्ति में कितना गहरा विश्वास है, यह उनके उपर्युक्त कथन से साफ प्रकट होजाता है। यह मन्देश उन्होंने वर्तमान यूरोपीय युद्ध के प्रारम्भ होने से पहले दिया था जबकि ससारा

१ सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन . 'गांधी-अभिनन्दन ग्रन्थ' (१९४१)

पृष्ठ १५

२ वही पृ० २४

के राष्ट्रों का दसवीकरण बेहद बढ़ चुका था और युद्ध के बादल आकाश में मँडरा रहे थे ।

वर्तमान यूरोपीय युद्ध गुरु होने पर भारत में उसको स्वाधीन राष्ट्र घोषित करने की राष्ट्रीय माँग कांग्रेस की ओर से ब्रिटिश सरकार के नामने रखी गयी । आज दो वर्ष से अधिक समय बीत गया, परन्तु ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय माँग को स्वीकार नहीं किया । एक ओर तो ब्रिटिश सरकार की यह दृष्टि है, दूसरी ओर महात्मा गांधी भारत की स्वाधीनता के लिए युद्ध-काल में कोई ऐसा उग्र कार्य करना अहिंसा के सिद्धान्त के विरुद्ध समझते हैं जिससे अंग्रेज जाति सकट में पड़ जाये । गांधीजी बराबर सत्याग्रह के प्रश्न को इसी दृष्टि में टालते रहे थे । उनका कहना है कि अंग्रेजों की मकट-पूर्ण स्थिति ने लाभ उठाकर हमें स्वाधीनता प्राप्त करना शोभा नहीं देता । ऐसा करना भारतीय आर्य-मर्यादा के विरुद्ध है ।

गांधीजी को वर्तमान युद्ध ने इतनी दारुण व्यथा पहुँची कि उन्होंने घोर युद्ध-काल में, जबकि ब्रिटेन के लिए जीवन-मरण का मवाल था— अंग्रेजों से यह अपील की थी —

“राष्ट्रों के परस्पर के सबंध और दूसरे मामलों का निर्णय करने के लिए युद्ध का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग स्वीकार करें । मैं आपसे यह कहता हूँ कि इस युद्ध के समाप्त होने पर विजय चाहे जिस पक्ष की हो, प्रजातंत्र का कहीं नामोनिशान भी नहीं मिलेगा । यह युद्ध मनुष्य जाति पर एक अभिशाप और चेतावनी के रूप में उतरा है । यह युद्ध शाप रूप है, क्योंकि आज तक कभी मानव मानवता को इस कदर नहीं भूला था, जितना कि वह इस युद्ध के असर के नीचे भूल रहा है ।”

यद्यपि महात्मा गांधी भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलन के मंचालक और कांग्रेस के प्रधान नेता हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कट्टर

१ हरेक अंग्रेज के प्रति (महात्मा गांधी) ‘हरिजन-सेवक’ १३ जुलाई १९४०

विरोधी है, तो भी वह एक आदर्श मानववादी है। आज भी गांधीजी ब्रिटेन के प्रति मैत्री का निर्वाह कर रहे हैं—“मैं दावा करता हूँ कि मैं ब्रिटेन का आजीवन और निस्वार्थ मित्र रहा हूँ। एक वक्त ऐसा था कि मैं आपके साम्राज्य पर भी आशिक था। मैं समझता था कि आपका राज्य भारत को फायदा पहुँचा रहा है। मगर जब मैंने देखा कि वस्तु-स्थिति तो दूसरी ही है, इस रास्ते से भारत की भलाई नहीं हो सकती, तब मैंने अहिंसक तरीके से साम्राज्यवाद का सामना करना शुरु किया और आज भी कर रहा हूँ। मेरे देश के भाग्य में आखिर कुछ भी लिखा हो, आप लोगो के प्रति मेरा प्रेम वंसा ही कायम है और रहेगा। मेरी अहिंसा सारे जगत के प्रति प्रेम मांगती है और आप उस जगत के कोई छोटे हिस्से नहीं हैं। आप लोगो के प्रति मेरे उस प्रेम ने ही मुझसे यह निवेदन लिखवाया है।”

यह है गांधीजी की मानववादी राष्ट्रीयता। वह भारत के लिए स्वाधीनता चाहते हैं, परन्तु वह यह स्वाधीनता किसी दुर्बल राष्ट्र का शोषण करने या साम्राज्य की स्थापना करने के लिए नहीं चाहते।

यूरोप में युद्ध आरम्भ होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय महानभ (कांग्रेस) की कार्य-समिति ने १४ सितम्बर १९३९ को भारतीय माँग के सम्बन्ध में अपना जो ऐतिहासिक वक्तव्य प्रकाशित किया, उसमें यह स्वीकार किया गया है कि मसार में युद्ध का कारण फासिज्म और साम्राज्यवाद है। ऐलान किया गया था कि ब्रिटेन यूरोप में स्वाधीनता व प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है, परन्तु क्या ये स्वाधीनता व प्रजातन्त्र के सिद्धान्त यूरोप तक ही सीमित रहेंगे अथवा भारत में भी लागू किये जायेंगे? वस इसी प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए यह वक्तव्य प्रकाशित किया गया था। वक्तव्य में स्पष्ट शब्दों में कहा गया था—

“यदि इस युद्ध का उद्देश्य साम्राज्यवादी प्रदेशों, उपनिवेशों और

स्थापित स्वार्थों की वस्तुस्थिति को कायम रखना है, तो भारत को ऐसे युद्ध से कोई सरोकार नहीं है। अगर सवाल प्रजातन्त्र और प्रजातन्त्र के आधार पर स्थित समाज की व्यवस्था का है, तो भारत की उसमें बड़ी दिलचस्पी है। "यदि ब्रिटेन प्रजातन्त्र की रक्षा और विस्तार के लिए युद्ध में लड़ रहा है, तो उसे अपने अधिकृत देशों में से साम्राज्यवाद का अन्त कर देना चाहिए और भारत में पूर्ण प्रजातन्त्र की स्थापना करनी चाहिए। अतएव भारत की जनता को बिना बाहरी हस्तक्षेप के अपनी निर्वाचित विधान-निर्मात्री परिषद् से अपना शासन-विधान बनाने का अधिकार मिलना चाहिए और स्वयं ही अपनी नीति का संचालन करना चाहिए।

"स्वतन्त्र प्रजातन्त्रवादी भारत दूसरे स्वतन्त्र राष्ट्रों के साथ आक्रमण के विरुद्ध पारस्परिक रक्षा तथा आर्थिक सहकारिता के लिए खुशी से सहयोग करेगा। हम एक सच्ची विश्व-व्यवस्था की स्थापना के लिए काम करेंगे जिसका आधार स्वाधीनता और प्रजातन्त्र होगा और ससार के ज्ञान वित्तान और साधनों को मानवता के विकास और प्रगति में उपयोग किया जायेगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय सघटन के विरुद्ध नहीं है। वह उसमें पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रस्तुत है। परन्तु ऐसा करना उन्नी समय सफल हो सकता है जब पहले वह साम्राज्यवाद के बन्धन में मुक्ति पा ले।

भारतीय राष्ट्रीयता और पण्डित जवाहरलाल नेहरू

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीयता को अन्तर्राष्ट्रीय रंग में रंगकर वास्तव में राष्ट्र की एक महान् सेवा की है। आज भारत में नेहरूजी से बढ़कर कोई अन्तर्राष्ट्रीयता का समर्थक नहीं है। भारतीय राष्ट्रीयता को उग्र और सकुचित हो जाने से बचाने में नेहरूजी ने जो योग दिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पूर्णतः समाजवादी है परन्तु उनपर महात्मा गांधी के सिद्धान्तों और विशेषरूप से उनके

अहिंसा-मिशन का गहरा प्रभाव पड़ा है। महान्माजी की अहिंसा में उनका पूरा विश्वास है। वह साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी है और फासिज्म को साम्राज्यवाद का ही भयंकर रूप मानते हैं। उनकी यह धारणा है कि भारत का कल्याण समाजवादी व्यवस्था में होगा। वह शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीयता के मन्त्रों बड़े समयकों में हैं। उन्होंने स्वयम् अपने मन्त्र में लिखा है—

“फासिज्म और साम्यवाद इन दोनों में से मेरी सहानुभूति बिल्कुल साम्यवाद की ओर है। इस पुस्तक के इन्हीं पृष्ठों से यह मालूम हो जायेगा कि मैं साम्यवादी होने से बहुत दूर हूँ। मेरे स्तकार शायद एक हृदयक अब भी उन्नीसवीं सदी के हैं और मानववाद की उदार परंपरा का सुक्ष्मपर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि मैं उससे बिल्कुल बचकर निकल नहीं सकता।”

अन्तर्राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है—

“मैं नहीं जानता कि हिन्दुस्तान जब राजनीतिक दृष्टि से आजाद हो जायेगा, तो किस तरह का होगा और वह क्या करेगा? लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उसके लोग जो आज राष्ट्रीय स्वाधीनता के समर्थक हैं, व्यापक से व्यापक अन्तर्राष्ट्रीयता के भी समर्थक हैं। एक समाजवादी के लिए राष्ट्रीयता का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन बहुतेरे कांग्रेसी, जो समाजवादी नहीं हैं, लेकिन आगे बढ़े हुए हैं, वे सच्ची अन्तर्राष्ट्रीयता के पुजारी हैं। स्वाधीनता हम इसलिए नहीं चाहते कि हमें सबसे अलग होकर रहने की इच्छा है। इसके विपरीत हम तो इस बात के लिए बिल्कुल राजी हैं कि दूसरे देशों के साथ-साथ अपनी स्वाधीनता का भी कुछ भंश छोड़ दें कि जिससे सच्ची अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम हो सके। कोई भी साम्राज्य-प्रणाली, चाहे उसका नाम कितना ही बड़ा रख दिया जाये, ऐसी व्यवस्था की शत्रु है और ऐसी प्रणाली के द्वारा विश्वव्यापी सहयोग या शान्ति कभी स्थापित नहीं हो सकती।”

प० जवाहरलाल नेहरू ससार में सच्ची और स्थायी शान्ति चाहते हैं। उनकी यह ध्रुवधारणा है कि साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा शान्ति-व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। शान्ति-व्यवस्था के लिए सबसे पहले साम्राज्यवाद का अन्त कर देना जरूरी है। इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय सघटन के लिए प्रत्येक स्वाधीन राज्य को अपनी प्रभुता का कुछ अंश छोड़ना पड़ेगा। जबतक ससार में राष्ट्रीय राज्य कायम रहेंगे तबतक कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय सघटन सफल नहीं हो सकता। नेहरूजी इसे भली भाँति अनुभव करते हैं।

भावी समाज की रूपरेखा खींचते हुए नेहरूजी लिखते हैं—

“हमारा अन्तिम ध्येय तो यह हो सकता है कि समान न्याय और समान सुविधापूर्ण एक वर्ग-रहित समाज हो, ऐसा समाज जिसका निर्माण मानव-समाज को भौतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ऊँचा उठाने और उसमें सहयोग, निस्वार्थ सेवाभाव, सत्य-निष्ठा, सद्भाव और प्रेम के आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि करने के सुनिश्चित आधार पर हुआ हो, और अन्त में एक ऐसी संसार-व्यापी व्यवस्था हो जाये।”

यह है भारतीय राष्ट्रीयता का समुज्ज्वल स्वरूप और उसके उच्च मानवीय आदर्श जिनपर वास्तव में सच्ची अन्तर्राष्ट्रीयता की आधार-भित्ति रखी जा सकती है।

नागरिक-स्वाधीनता

ससार के सब विद्वानों का यह मत है कि नागरिक-जीवन का विकास और उत्कर्ष केवल स्वतन्त्र वातावरण में ही हो सकता है । नागरिक-स्वाधीनता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है । स्वाधीनता के बिना मानव न तो अपना आत्म-विकास कर सकता है, और न दूसरों की भलाई ही । राज्य सुसंगठित नागरिकों की एक संस्था ही है । उसका विकास नागरिकों के हित ही के लिए है । नागरिकों से रहित राज्य की कल्पना संभव नहीं । राज्य की उत्पत्ति इसी कारण हुई कि सब नागरिक निर्धारित रूप से स्वाधीनता का लाभ उठा सकें, क्योंकि अराजक दशा में मनुष्य न्याय का आश्रय न लेकर शक्ति के बल पर शासन करने लगते हैं ।

राज्य मानवों के हित के लिए है । अतः राज्य की ओर से प्रत्येक व्यक्ति अथवा नागरिक की सुख-सुविधा के लिए समान रूप से सम्यक् व्यवस्था होनी चाहिए । नागरिक-स्वाधीनता के उपभोग के लिए राज्य ने नागरिकों को विशिष्ट और निर्धारित अधिकारों की व्यवस्था की है । प्रोफेसर हैराट्ट लास्की के अनुसार 'नागरिक-स्वाधीनता ऐसे अधिकार हैं जो सामाजिक जीवन की उन अवस्थाओं की रक्षा के लिए जरूरी हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी मानव अपना आत्म-विकास नहीं कर सकता ।' सुप्रसिद्ध समाज-विज्ञानवेत्ता श्री हाबहाउम के मतानुसार 'सच्चा अधिकार उसके अधिकारी के वास्तविक मंगल का एक तत्त्व है, स्थिति है जो सामंजस्य के सिद्धान्त के आधार पर सार्वजनिक मंगल का ही एक प्रमुख अंश है ।'

इटली के महापुरुष और वीर देशभक्त मेत्रिनी नागरिक-स्वाधीनता को कर्तव्य-पाठन के लिए अनन्य आवश्यक मानते थे । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है—

“स्वाधीनता के बिना आप अपने किसी भी कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आपको स्वाधीनता का अधिकार है और आपका यह कर्तव्य है कि जो कोई सत्ता स्वाधीनता का निषेध करती हो, उसने उसे किसी भी उपाय से प्राप्त कर लो।”

राज्य और विशेषतः प्रजातन्त्र-राज्य का लक्ष्य है नागरिकों के जीवन-विकास तथा उत्कर्ष के लिए सामान्य सुयोग एवं सुविधाएँ प्रदान करना। राज्य नागरिकों के प्रति इस महान् कर्तव्य का पालन उसी दशा में कर सकता है जब कि उसे नागरिकों की स्थिति, अभाव एवं आवश्यकताओं का पूर्ण और सच्चा ज्ञान हो। राज्य को नागरिक-जीवन की अवस्थाओं का पूर्ण और सच्चा ज्ञान तभी हो सकता है जब कि नागरिकों को अपनी आकांक्षाओं के अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो। जब-जब सब नागरिकों को किसी प्रकार के भेद-भाव के बिना अपने मनोभाव एवं विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं होता, तबतक राज्य उनकी आकांक्षाओं का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार सामाजिक जीवन में स्वाधीनता का मूल्य सुस्पष्ट है। उदाहरणार्थ, किसी राज्य में किसानों को बड़ा कष्ट है, उनसे बेगार ली जाती है, जमींदार अधिक लगान वसूल करते हैं, चाहे जब मनमाने ढंग से उन्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है और उनकी मवेशी को चारा नहीं मिलता क्योंकि चरागाहों पर भी जमींदार खेती कराते हैं। अब यदि राज्य-शासन की ओर से कृषि-सुधार के लिए कोई योजना या कानून बनाया जाये और उनके सम्बन्ध में किसानों को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार न दिया जाये, सिर्फ जमींदारों की सम्मति से ही योजना या कानून बना दिया जाये, तो इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे निरदम या योजना से निस्तान-समाज का हित नहीं होगा। इसी प्रकार धारा-सभा में यदि कोई महिलोपयोगी कानून बनने जा रहा है, और उसपर पहले से राष्ट्र की महिलाओं के लोकमन को जानने का प्रयत्न नहीं किया जाता, तो ऐसे कानून के बन जाने से महिलाओं का क्या हित-साधन होगा? सब तो यह है कि जिन व्यक्ति को कोई अनाद या आदम्यता

है, वही भलोभांति अपनी आवश्यकता प्रकट कर मन्ता है।

अधिकार और कर्तव्य

नागरिकता एक महत्वपूर्ण सामाजिक अधिकार है। वह किसी व्यक्ति-विशेष या व्यक्ति-समूह की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं है। नागरिक समाज का एक अंग है और उसे जो नागरिक-अधिकार प्राप्त हैं, वे केवल इसलिए कि वह उनका प्रयोग उस ढंग से करे कि जिससे अपना हित-साधन करते हुए वह समाज के अन्य सदस्यों को हानि न पहुँचा सके। यदि किसी मनुष्य के नागरिक अधिकारों के प्रयोग में दूसरे को हानि पहुँची तो उसमें समाज का कल्याण नहीं हो सकता और जिस लोक-मग्नह की दृष्टि से राज्य ने नागरिक स्वाधीनता प्रदान की है, उसका अभिप्राय भी मिट्ट नहीं होता।

इससे यह सिद्ध होता है कि समाज में अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी उनका ही मूल्य है। यदि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार राज्य ने दिया है, तो दूसरे व्यक्तियों के लिए वही अधिकार कर्तव्य बन जाता है। उदाहरणार्थ, एक नागरिक अपने भाषण-स्वाधीनता के अधिकार का प्रयोग करता है, तो ऐसी दशा में दूसरे नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह उसकी इस स्वाधीनता में बाधा न डालें जबकि उसका भाषण कानून-विरुद्ध अथवा मानहानिकर न हो।

वास्तव में नागरिकों की पारस्परिक सहयोग की भावना और कर्तव्य-परायणता ने ही नागरिक-अधिकारों को जन्म दिया है। यदि नागरिक सहयोगपूर्वक नागरिक-स्वाधीनता की रक्षा व उसका उपयोग न करें और उन अधिकारों द्वारा जो कर्तव्य निर्धारित हुए हैं, उनका तत्परता से पालन न करें, तो हम समाज में अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते।

डा० बेनीप्रसाद का यह मत उचित है कि अगर उपयुक्त जीवन-निर्वाह की अवस्थाओं को सके शिवा मुश्किल रखना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को उनके उपयोग की आशा करनी चाहिए और साथ ही-साथ ही

आदमी को इस प्रकार काम करना उचित है कि दूसरे लोगों के उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। यही नहीं प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि ऐसी परिस्थितियों को सबके लिए सुलभ करने में निश्चित रूप से प्रोत्साहन दे। एक व्यक्ति के सम्बन्ध में जो अधिकार हैं, वह दूसरों के लिए कर्त्तव्य हैं। इस प्रकार अधिकार और कर्त्तव्य एक दूसरे के आश्रित हैं। वे एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। अगर कोई उनको अपने दृष्टिकोण से देखता है तो वे अधिकार हैं और अगर दूसरों के दृष्टिकोण से देखता है तो वे कर्त्तव्य हैं। दोनों सामाजिक हैं और दोनों असल में उपयुक्त प्रकार के जीवन की अवस्थाएँ हैं, जिन्हें समाज के सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना चाहिए।^१

नागरिक समानता

इंग्लैण्ड के सुविख्यात राजनीतिशास्त्री श्री हेरल्ड लास्की ने लिखा है —

“जिस राज्य में नागरिक स्वाधीनता को अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है वहाँ समानता होना भी जरूरी है। * राज्य में नागरिकों में जितनी अधिक समानता होगी सामान्यतया उतना ही अधिक वे अपनी स्वाधीनता का उपभोग कर सकेंगे।”^२

नागरिक-स्वाधीनता और समानता एक ही वस्तु नहीं हैं। दोनों में अन्तर है। यदि राज्य में कुछ निश्चित समानताएँ प्राप्त न हों तो यह मभव नहीं कि हम नागरिक-स्वाधीनता का उपभोग कर सकें।

समानता और असमानता के सबध में यह स्पष्ट रूप से जान लेना आवश्यक है कि विषय में प्राकृतिक समानता का वही भी अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक वस्तु में रचना, आकृति और रंग-रूप के कारण भिन्नता होना स्वाभाविक है। एक पिता की दो सन्तानों में भी आकृति, रूप-रंग,

१ डॉ० बेनीप्रसाद ‘नागरिक-शास्त्र’, पृ० ४१

२. लास्की ‘लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट’ (१९३०), पृ० १६-१७

आचार-विचार और स्वभाव की समानताएँ नहीं होती। अतः जब समाज या राज्य समानता की आवश्यकता पर जोर देता है तब उसका तात्पर्य उस प्राकृतिक समानता में नहीं होता।

ससार में दो प्रकार की असमानताएँ दिखायी देती हैं। एक प्रकार की असमानताएँ वे हैं जो प्राकृतिक योग्यता की विभिन्नताओं में उत्पन्न होती हैं और दूसरे प्रकार की वे हैं जो समाज या राज्य द्वारा उन्नत सुविधाओं की असमानताओं द्वारा पैदा हुई हैं।

अतः नागरिक-समानता का यह अभिप्राय नहीं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से समान बना दिया जाये या शिक्षा की दृष्टि में सब नागरिकों को समान बना दिया जाये। प्रत्युत नागरिक-समानता का अर्थ तो यह है कि आत्म-विकास के लिए समाज या राज्य द्वारा जो सुयोग्य एवं सुविधाएँ प्राप्त हैं, उनके उपभोग का प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार होना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में इसका मतलब यह है कि समाज या राज्य की ओर से ऐसी विभिन्नताओं एवं भेदभाव की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जिसके कारण व्यक्ति आत्म-शक्तियों का सम्यक् विकास न कर सके। इसका फलितार्थ यह है कि राज्य में किसी वर्ग-विशेष के लिए 'विशेषाधिकार' या 'विशेष रियायतें' नहीं होनी चाहिए। विशेषाधिकार तो समाज में विषमता को जन्म देते हैं।

यदि राज्य की ओर से ऐसा कानून हो कि उत्तरदायित्वपूर्ण उच्च सरकारी पदों पर केवल जमींदार या पूँजीपति वर्ग के उम्मीदवारों को ही नियुक्त किया जायेगा, वैश्यों, ब्राह्मणों अथवा दलित-वर्ग के व्यक्तियों को सेना में भरती नहीं किया जायेगा, या ब्राह्मणों तथा कायस्थ जातियों के व्यक्तियों को उच्च शिक्षा की अधिक सुविधाएँ दी जायेंगी तो, ऐसी व्यवस्था का दुष्परिणाम यह होगा कि शासन-संचालन के कार्य में जनता का एक बहुत बड़ा भाग वंचित रह जायेगा। ब्राह्मण, वैश्य तथा दलित-वर्ग के सेनाओं में भरती न होने में उनमें वे गुण पैदा न हो सकेंगे जो सैनिक-जाति में होते हैं। फलतः एक विशेष सैनिक जाति बन जायेगी और धीरे-धीरे देश की अन्य जातियाँ उसके अयोग्य हो जायेंगी। यदि केवल ब्राह्मणों या

नागरिकों के लिए ही शिक्षा की अधिक सुविधा रही, तो समाज के दूसरे वर्ग शिक्षा में पिछड़े रह जायेंगे। इसी प्रकार किसी वर्ग-विरोध को शासनाधिकार अथवा शिक्षा की सुविधाओं में जातपात, धर्म या रंग आदि के कारण वंचित रखना भी उसके साथ घोर सामाजिक अन्याय होगा।

अतः समाज में कुछ वर्गों के लिए 'विशेषाधिकार और कुछ वर्गों के लिए 'प्रतिबन्ध' दोनों ही विषमता को जन्म देनेवाले हैं। इनमें नागरिक जीवन में सामाजिक, सहयोग और शान्ति की जगह भय, स्पर्धा और अशान्ति के भाव पैदा होंगे। प्रोफेसर हैराल्ड लाम्बी का यह कथन सत्य ही है कि "प्रत्येक व्यक्ति को यथासम्भव समान सुयोग देना चाहिए जिससे वह उन शक्तियों का उपयोग कर सके जिन्हें उसने प्राप्त किया है।"

भारत का शासन-विधान और मौलिक अधिकार

भारत के शासन-विधान में नागरिकता के मौलिक अधिकारों का कहीं उल्लेख नहीं है। आज के युग में प्रत्येक प्रजातन्त्र-राज्य के विधान में नागरिकता के मौलिक अधिकारों की घोषणा को सबसे पहले महत्त्व का स्थान प्राप्त है। ऐसी दशा में भारत के शासन-विधान में यह अभाव, वास्तव में, नागरिक-स्वाधीनता के लिए एक खतरा है। यद्यपि नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रत्येक राज्य के स्वरूप पर निर्भर हैं, परन्तु यह तो स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य में नागरिकों को अधिकार होने चाहिएँ। जो राष्ट्र प्रजातन्त्रवादी है, उनमें उन राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक नागरिक अधिकार होते हैं जो फासिस्ट हैं। समाजवादी राज्यों में व्यक्तियों को और भी अधिक अधिकार होते हैं।

प० जवाहरलाल नेहरू का मत है कि

"अविष्य में भारत का सामाजिक संगठन चाहे जैसा हो, व्यक्ति की स्वाधीनता की रक्षा के लिए कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हम विधान में स्थान देना चाहते हैं। ये अधिकार इस प्रकार के हैं— धार्मिक स्वाधीनता, मत-प्रकाशन की स्वाधीनता, सभा-संगठन की

स्वाधीनता, संस्कृति और भाषा की रक्षा, कानून की दृष्टि में सभी नागरिकों की समानता और इसी प्रकार शान्तिाधिकार में, व्यवसाय-व्यापार में धर्म, जाति या 'सेक्स' के भेदभाव के बिना समानता और इसी प्रकार के अधिकार ।"

"हमारी यह धारणा है कि देश में समस्त अल्प-संख्यक जातियों के आश्वासन के लिए भारतीय शान्ति-विधान में इन मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में एक गारंटी होनी चाहिए ।

"इसके लिए कांग्रेस का कराची-प्रस्ताव और पाश्चात्य शासन-विधानों की नागरिक-स्वाधीनता-सम्बन्धी धाराएँ नमूने के तौर पर ली जा सकती हैं ।"

वर्तमान शासन-विधान की धारा २९८ में नागरिकों का यह अधिकार तो स्वीकार किया गया है कि सरकारी पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में या किसी सम्पत्ति के प्राप्त करने या बेचने अथवा व्यवसाय-व्यापार करने में केवल धर्म, जाति, जन्म-स्थान, रंग या इनमें से किसी के कारण कोई भी नागरिक अयोग्य न माना जायेगा ।

विधान की धारा २७५ में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति लिंग-भेद के कारण ब्रिटिश भारत में किसी 'सिविल सर्विस' या 'सिविल पोस्ट' पर नियुक्त होने के अधिकार से वंचित न किया जायेगा । परन्तु गवर्नर जनरल, गवर्नर और भारत-मन्त्री अपने विशेष आर्डर द्वारा स्त्रियों को सरकारी पदों पर नियुक्त होने के अधिकार से वंचित कर सकेंगे ।

शासन-विधान की २९८ वीं धारा के होते हुए भी भारत में ऐसे अनेक वर्ग हैं, जिन्हें जातिभेद के कारण, शान्तिाधिकार में व्यावहारिक समानता प्राप्त नहीं है । 'दलितवर्ग' जो हिन्दू-समाज का ही अंग है, आज भी उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता । यही नहीं इस वर्ग के सदस्यों को व्यापार-व्यवसाय में भी समानता प्राप्त नहीं

है। इस दंग के लोग बाजारों में कोई ऐसी दुकान नहीं खोल सकते जिसमें पाने-पीने की चीजें बिकती हों।

भारत में पदाधिकार के सम्बन्ध में रिंग-भेद की व्यवस्था शुरू से कायम है। आज भी विधान की २७५ वीं धारा के होते हुए महिलाओं को इंडियन मिजिल नॉर्विस, पान्तीय सिविल नॉर्विस आदि की प्रति-योगिताओं में बैठने की आज्ञा नहीं है। सेना में तो उनके लिए कानूनी प्रतिबन्ध है। यह चान्सल में विधान का एक बड़ा दोष है।

आर्थिक समानता

यदि राज्य में नागरिकों को आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त है और आर्थिक समानता नहीं है, तो इसका परिणाम यह होगा कि समाज में आर्थिक विषमता पैदा हो जायेगी और ऐसे वातावरण में सच्ची आर्थिक स्वाधीनता का उपभोग भी नहीं किया जा सकेगा।

जबतक आर्थिक समता की स्थापना नहीं हो जाती, तबतक राजनीतिक समता—नागरिकों का समान मताधिकार—व्यर्थ है। उसने वे आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकते। आधुनिक राज्य का केवल इतना यही कार्य नहीं है कि वह चोर और डाकुओं ने नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की ओर इस प्रकार नागरिक-स्वाधीनता की रक्षा करे, उनके लिए प्रजातन्त्र-शासन-पद्धति तथा अन्य नाना प्रकार के नागरिक सुखों के लिए सुविधाएँ प्रदान करे। आज के युग में इन सबसे नागरिक-जीवन का उत्कर्ष सम्भव नहीं। यह आर्थिक युग है। इसलिए राज्य को ऐसी आर्थिक व्यवस्था भी स्थापित करनी चाहिए जिसमें सभी नागरिक पूरी तरह सुखी रह सके और अपने जीवन को ऊँचा बना सकें। यदि राज्य में भयंकर बेकारी होगी, बेहद गरीबी होगी, कुछ मुट्ठी भर लोग लक्ष्मण और करोड़पति, मिलों और कम्पनियों के मालिक तथा भूमि के स्वामी होंगे और शेष विशाल जन-समुदाय को नागरिक जीवन की समान सुविधाएँ तो दूर भरपेट अब भी दोनों वक्ता न मिलेंगे, तो क्या यह आशा की जा सकती

है कि अधभूखे और अर्द्धनग्न जन आर्थिक स्वाधीनता भोग सकेंगे ?

आज संसार के सभी प्रजातन्त्रों में अधिकांश नागरिक आर्थिक दृष्टि से दुखी हैं। वहाँ भयंकर बेकारी गरीबी बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन पाश्चात्य प्रजातन्त्रों ने आज तक आर्थिक न्याय या आर्थिक समता की स्थापना के लिए ईमानदारी से कोई प्रयत्न नहीं किया। संसार में सोवियट रूस ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसने अपने शासन-विधान के मौलिक अधिकारों की घोषणा में यह स्वीकार किया है कि "सोवियट रूस के नागरिकों को परिश्रम करने का अधिकार है अर्थात् उनके काम के परिमाण तथा उसकी किस्म के अनुसार अपने परिश्रम के लिए नियत वेतन पर पारिश्रमिक का अधिकार है।"

सोवियट रूस में राज्य की ओर से प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यतानुसार काम माँगने का अधिकार है और उसके लिए नियत वेतन भी।

आर्थिक समता की स्थापना के लिए समाज को आर्थिक ढाँचा नये ढंग से खड़ा करना होगा। इसमें मौलिक परिवर्तन की जरूरत है। समस्त व्यवसायों, कम्पनियों, कारखानों, रेलों, बैंकों आदि पर राज्य का नियंत्रण या अधिकार होना चाहिए। श्री श्रीनिवास अयंगर ने लिखा है —

"संसार की आर्थिक व्यवस्था में सबसे अधिक सकट ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों ने पैदा किया है, इसलिए इनका पूर्णतः परित्याग किया जाये, साझेदारी भी मर्यादित कर दी जाये, उसके साझेदारों की संख्या कम कर दी जाये तथा उसका क्षेत्र भी सीमित कर दिया जाये। बैंक, बीमा, जहाज तथा यातायात आदि राज्य के अधिकार में हों। नहर आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर राज्य की ओर से किया जाये। शस्त्रादि बनानेवाली कम्पनियों का नियंत्रण भी राज्य के अधिकार में हो। इस प्रकार राज्य की ओर से राष्ट्रीय व्यवसाय-धन्यों को इतना प्रोत्साहन दिया जाये कि जिसमें बेकारी व गरीबी दूर हो जाये और वेतन तथा पारिश्रमिक का मान-दण्ड बढ़ जाये। संक्षेप में, एक नियोजित

आर्थिक योजना, जो जनता को समस्त श्रेणियों की मौलिक मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके, आज भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए सबसे पहली शर्त है; क्योंकि वह (प्रजातंत्र) उसी सीमा तक स्थायी होगा जिस सीमा तक वह जनता को यह गारण्टी दे सके कि जनता की आर्थिक उन्नति उसका प्रमुख लक्ष्य है । '१

वैयक्तिक स्वाधीनता

वैयक्तिक स्वाधीनता का अर्थ है व्यक्ति की स्वाधीनता । प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह दूसरे व्यक्ति की स्वतन्त्रता की भी रक्षा करे । आत्म-रक्षा का नियम भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता का ही एक फलितार्थ है । समाज या राज्य के निर्माण में नागरिकों का योगदान होना है, इसलिए नागरिकों की वैयक्तिक स्वाधीनता सामाजिक जीवन के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है । यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास न हो सके कि वह राज्य में वैयक्तिक स्वाधीनता का उपभोग कर सकता है, तो वास्तव में उसका जीवन दमर हो जायगा ।

मनुष्य का जीवन वैयक्तिक दृष्टि में ही मूल्यवान् नहीं है, बल्कि समाज और राज्य के दृष्टिकोण से भी वह बहुमूल्य है । यही कारण है कि राज्य मानव-जीवन की रक्षा को अपना पवित्र कर्तव्य समझता है । मानव-जीवन की रक्षा के लिए सेना और पुलिस का राज्य की ओर प्रबन्ध ज़रूर होता है । परन्तु पुलिस के लिए हर समय और हर स्थान में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना सम्भव नहीं है । इसलिए राज्य ने प्रत्येक व्यक्ति को आत्म-रक्षा का अधिकार दे रखा है । यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने के प्रयोजन से उसपर साक्षात्क आक्रमण करे, तो वह अपनी रक्षा के लिए प्रत्येक सम्भाव्य साधन को काम में ला सकता है । यहाँ तक कि यदि वह आक्रमणकारी

१ श्री श्रीनियास अयंगर • 'प्रॉब्लैम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इण्डिया' (१९३९), पृ० ६९

जीवन का अन्त भी कर दे तो राज्य उसे इसके लिए दण्ड नहीं दे। प्रत्येक देश में आत्म-रक्षा के लिए नागरिकों को अस्त्र-शस्त्र धारण का भी अधिकार है।

नाय ही चूंकि राज्य का यह परम कर्तव्य है कि वह नमन्त्र नागरिकों और व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करे, इसलिए यदि कोई व्यक्ति आत्मघात द्वारा अपने जीवन का अन्त करने का प्रयत्न करे, तो उसे इसके लिए दण्ड देना।

शरीर-स्वाधीनता

शरीर-स्वाधीनता का अभिप्राय यह है कि वह राज्य में अपने स्वतन्त्रता से रह सके। उनकी स्वीकृति, इच्छा या आगा के बिना कोई व्यक्ति उसके गृह में प्रवेश न कर सके और जबतक कि राज्य के कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट न जारी किया हो अथवा पुलिस को यह सन्देह न हो कि उसने राज्य के कानून के विरुद्ध ऐसा अपराध किया है जिससे वह बिना वारण्ट के भी गिरफ्तार किया जा सके तबतक राज्य भी उसे गिरफ्तार न कर सके। जब कोई भी नागरिक कानून के अनुसार न्यायालय में दोषी प्रमाणित न हो जाये और यह निस्सन्देह सिद्ध न हो जाये कि उसने वह अपराध उस समय किया था जबकि वह कानूनन अपराध था, तबतक केवल उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति अनिश्चित काल के लिए नजरबन्द किया जा सकता और न हवालान में २४ घंटे से ज्यादा रखा जा सकता है। जबतक वह दोषी प्रमाणित न हो जाये, तबतक उसे कोई शारीरिक दण्ड नहीं दिया जा सकता।

भारतवर्ष में नागरिकों को शरीर-स्वाधीनता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। यहाँ आज भी ऐसे दमनकारी कानून मौजूद हैं जिनके अस्तित्व में उन्हें शरीर-स्वाधीनता नहीं है। मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता आज से एक शताब्दी से भी अधिक पुराने 'रेग्यूलेशन' (१८१८) आज प्रचलित हैं, जिनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी न्याया

मे दोरी पमाणित किये वश तक राजबन्दी बनाकर रखा जा सकता है। सन् १९३१ के सत्याग्रह-आन्दोलन में महात्मा गांधी को दमन रेंगू-शाला (१८१८) के अनुसार राजबन्दी बनाकर पूना-जेल में रखा गया। जनवरी सन् १९३२ में श्री सुभाषचन्द्र बोस को इसी रेंगू-शाला के अनुसार राजबन्दी बनाकर रखा गया था।

भारत के हर एक पान्त में क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेंट एक्ट जारी है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को सदेह में गिरफ्तार करके राजबन्दी बनाया जा सकता है। पंजाब और बंगाल प्रान्त में राष्ट्रीय जागरण को दबाने के लिए घोर-से-घोर दमनकारी कानून आज भी प्रचलित हैं। वर्तमान युद्ध के कारण तो वह दमन अपनी चरम-सीमा को पार कर चुका है। सन् १९३७ में बंगाल के आनककारी-दमन-कानून के अनुसार वहाँ १६ हजार व्यक्ति नजरबन्द थे। बाद में महात्मा गांधी के प्रयत्न में कुछ नजरबन्द रिहा कर दिये गये।

नागरिकता का मौलिक सिद्धान्त यह है कि जबतक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध न हो जाये तबतक उसे दण्ड नहीं दिया जा सकता। केवल सन्देह में किसी को बन्दी बनाकर रखना तो कानून की दृष्टि में भी अन्याय है। ऐसा करने का अर्थ तो यह हुआ कि जिन लोगों के हाथ में कार्यकारिणी सत्ता है, वे ही न्यायाधीश बन गये।

विचार-स्वाधीनता

विचार-स्वाधीनता नागरिक-जीवन के विकास और उत्कर्ष के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण है। जिन राज्य के नागरिक विचार-स्वाधीनता (अर्थ मत-प्रकाशन की स्वाधीनता) का बेरोक-टोक उपभोग करते हैं, उन साहित्य, कला, ज्ञान-विज्ञान की आश्चर्यजनक प्रगति और प्रसार होता है। विचार किया जाये तो वास्तव में विचार ही मनोभाव प्रकट करने अमोघ साधन है। जिन देशों में विचार-स्वाधीनता नहीं उन देशों में विचार-मौलिकता को प्रोत्साहन मिलता है और न विचार-शक्ति के उपयोग के क्षेत्र ही मिलता है। जिस प्रकार तालाब का रखा हुआ जल

जाता है, उसमें रोग के जीवाणु पैदा हो जाते हैं और जल की स्वाम्यप्रद शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, उमी प्रकार जिस राज्य में विचार तथा उसके प्रकाशन की स्वाधीनता नहीं है, उसके नागरिकों का मानसिक विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। विचार-स्वाधीनता का उपभोग करनेवाले नागरिकों का विचार-प्रवाह उमी प्रकार विमल और पवित्र होता है जिम प्रकार नदी का जल।

कुछ लोगों का विचार यह है कि विचार स्वाधीनता पर इसलिए प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है कि गलत और भ्रान्तिपूर्ण विचार जनता में न फैलने पावे। परन्तु विचारों में तो भिन्नता उमी समय पैदा होती है जब किसी प्रश्न पर सन्देह हो। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि प्रश्न के दोनों पहलुओं पर विचार कर लिया जाये।

ब्रिटेन के प्रसिद्ध शिक्षा-विज्ञ श्री डबल्यू बी करी का मत है कि "मत-संघर्ष से ही ज्ञान और विद्वत्ता का जन्म होता है और मनुष्य अपने विचारों को भी उस समय तक भलीभाँति कभी नहीं समझ सकता जबतक कि उसने अपने विरोधी के विचारों को भली भाँति न समझ लिया हो। यह कहा जा सकता है कि विचार तो स्वतंत्र ही होता है, केवल भाषण पर ही प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। सैद्धान्तिक रूप से नज़रबन्दी की दशा में एक व्यक्ति चाहे जैसा विचार कर सकता है, परन्तु उसका विचार उसी समय फलप्रद हो सकता है, उसी समय वह अधिक विचार कर सकता है, जब उसे अपने विचारों पर बहस करने और उन्हें प्रकाशित करने का अधिकार हो और उसके विचारों में इतनी शक्ति हो कि वे कार्यप्रान्वित भी हो सके।"

विचारों की प्रगति और उसके साथ अन्य सभी प्रकार की उन्नति नये-नये विचारों के ही आधार पर निर्भर है। विचारों के विकास के लिए उनपर बहस और आलोचना के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

प्रोफेसर लास्की का यह कथन वास्तव में सच ही है कि—

'अधिकांश व्यक्ति जिन्हे निजी अनुभव के आधार पर विचार-मथन करने की सुविधा नहीं मिलती, विचार करना ही बंद कर देते हैं। जो व्यक्ति विचार करना बन्द कर देते हैं, वे सच्चे अर्थ में नागरिक नहीं रहते।'

अतः यह निर्विवाद है कि व्यक्तित्व के विकास, समाज के उत्कर्ष और राज्य की समृद्धि के लिए विचार और मत-प्रकाशन की स्वाधीनता अत्यन्त आवश्यक है।

मनुष्य अपने विचार मुख्यतः दो रूपों में प्रकट करता है—भाषण और लेखन। भाषण-स्वाधीनता का सभा-संगठन की स्वाधीनता से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनके अतिरिक्त मनुष्य अपने विचार समाचार-पत्र, पुस्तक, चित्र, संगीत, संकेत, कार्टून (व्यंग्यचित्र), रेडियो, चित्रपट आदि द्वारा व्यक्त करता है।

राज्य में प्रत्येक नागरिक को भाषण और लेखन की पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट करने एवं आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में भी उसे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। परन्तु इस सम्बन्ध में इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके सम्बन्ध में केवल ऐसे विचार ही व्यक्त किये जायें जो सार्वजनिक महत्त्व के हों। किसी नागरिक या व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन को सर्व-साधारण के सामने केवल सामाजिक हित की दृष्टि से ही प्रकट करना उचित है। यदि उससे समाज का हित नहीं होता तो ऐसा मत-प्रकाशन व्यर्थ है।

नागरिक के मत-प्रकाशन के अधिकार पर राज्य की ओर से कुछ प्रतिबन्ध भी लगाये जाते हैं। उन्हें ऐसे विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं है, जो ईश्वर या किसी धर्म के अनुयायियों की धर्म-भावना पर आघात करे, अश्लील हों, अपमान-जनक हों, राजद्रोहात्मक हों अथवा हिंसा, अशान्ति या उपद्रव को उत्तेजन दे।

नागरिकों को धर्म के सम्बन्ध में स्वाधीनता है। वे दूसरे धर्म के

२ हे जे लास्की : 'लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट' (१९३०); पृ. ९९

विचार-स्वाधीनता या मत-प्रकाशन की स्वाधीनता पर एक प्रति-
 और भी है—किन्नी व्यक्ति के लिए कोई अपमानजनक वचन न
 जाये और न लिखा जाये। जयन्तक अपमानजनक भाषण या लेख
 न हो और उसकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता न हो, तबतक
 प्रकाशन अनुचित है। यदि कोई व्यक्ति दुराचारी, भ्रष्टाचारी
 पतित है और उसका सार्वजनिक जीवन में प्रमुख स्थान है, तो
 उसे भ्रष्टाचार को, यदि वह सत्य है तो, जनता के सामने प्रकट करना
 सार्वजनिक हित में होगा। इसलिए ऐसा मत-प्रकाशन अपमानजनक
 ही कहा जा सकता।

विचार-स्वाधीनता और मत-प्रकाशन पर एक बड़ा प्रतिबन्ध यह है
 भाषण या लेख राजद्रोहात्मक न हो। सामाजिक नगठन अथवा
 निम्न-पद्धति के सम्बन्ध में प्रत्येक नागरिक को अपना मत प्रकट करने
 अधिकार है। भारत में सरकार के किसी कार्य की आलोचना तथा
 निंदा भी राजद्रोह माना जाता है। यहाँ राजद्रोह सबसे बड़ा
 जनीतिक अपराध है। भारतीय-दण्ड-विधान की धारा १२४ अ का
 प्रयोग सदैव भारतीय राष्ट्रीय जागरण का दमन करने के लिए किया
 जाता रहा है। जुलाई सन् १९३७ में जब भारत के नात प्रान्तों—मद्रास,
 बम्बई, संयुक्तप्रान्त विहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त, नीमा प्रान्त और आसाम
 कांग्रेस-दल के मन्त्रि-मण्डलों की स्थापना हुई, तो जनता ने सबसे
 पहले अंग्रेजी राज्य में नागरिक-स्वाधीनता का अनुभव किया। किन्नी भी
 व्यक्ति पर राजद्रोह का अपराध लगाना दण्ड कर दिया गया। बम्बई-
 सरकार के तत्कालीन गृह-मन्त्री श्री बम्बई-अमेम्बली ने
 अपने (१५ सितम्बर १९३७ के) एक भाषण में कहा था—

‘ कांग्रेस व्यक्ति की स्वाधीनता का समर्थन करती है, क्योंकि उसका
 सिद्धांत और प्रजातंत्र में अटल विश्वास है। हमारे लिए स्वाधीनता
 केवल भौतिक लाभ की चीज नहीं है। इसे हम इतिहास की भौतिकवादी
 व्याख्या की तुला में नहीं तोल सकते। स्वाधीनता हमारे लिए एक
 अमूर्त दण्ड का चमत्कार है। ईश्वर और कानून के राज्य में बोलना, काम

आतंकवाद घुट होजाने पर समूचे प्रान्त को नज़रबन्द-गिरिबंद बना दिया जाय या फौजी कानून (मासॉन ऑ) जारी कर दिया जाये । भारत में सन् १९१९ में अमृतसर, लाहौर, कसूर, गुजरावाला, और शेरपुरा में फौजी कानून जारी किया गया । इस प्रकार नागरिक-स्वाधीनता का बुरी तरह दमन किया गया । सन् १९३० में छोलापुर और पेशावर में फौजी कानून का शासन रहा ।

वर्तमान युद्ध के प्रारम्भ होने के बाद तुरन्त ही भारत के गवर्नर-जनरल ने भारत-रक्षा-कानून जारी कर दिया । इस कानून का ध्येय इतना व्यापक है कि आज सारे देश की स्वाधीनता का दमन इसीके द्वारा हो रहा है जबकि भारत-रक्षा-कानून का लक्ष्य है ब्रिटिश भारत की रक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा, कुशलतापूर्वक युद्ध-संचालन, अथवा समाज के जीवन के लिए आवश्यक चीजों और सेवाओं की व्यवस्था ।

सरकार ऐंसा क्यों किया करती है ? इसका उत्तर देते हुए प्रोफेसर लास्की ने लिखा है—

“... जब न्याय-व्यवस्था का कार्य सामान्य न्यायालयों से लेकर शासन के किसी दूसरे अंग को सौंप दिया जाता है, तो उसका सर्वत्र दुरुपयोग होता है । धर्मरक्षित की समुचित रक्षा के प्रश्न को इस विश्वास पर विस्मृत कर दिया जाता है कि आतंक के शासन से जनता की अभ्रष्टा (Disaffection) कम हो जायेगी । इसका कोई प्रमाण नहीं कि ऐसा हो जाता है । यदि ऐसा हो सकता, तो रूसी क्रान्ति ही न होती और आज भारतीय स्वायत्त-शासन के लिए कोई आन्दोलन न हुआ होता ।”

भारत में समाचार-पत्रों की स्वाधीनता पर भी कुठाराघात हो रहा है । नये-नये आर्डर जारी किये जा रहे हैं । इन सबके ऊपर सेंसर का एक-छत्र राज्य है । सभाओं और सम्मेलनों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं । पुलिस के अधिकारियों से पूर्व आज्ञा प्राप्त किये बिना कोई सभा नहीं की जा सकती, चाहे उस सभा का युद्ध से कोई सम्बन्ध ही न हो ।

प्रत्युत वह लोकमन बनाने का भी उतना ही शक्तिशाली साधन है। दाम्भ्यम प्रजातन्त्र की सफलता के लिए प्रगतिशील लोकमन की आवश्यकता है। उसके अभाव में उनका जीवन सफल नहीं हो सकता। गान्धि-मार्ग में समाचार-पत्र स्वराज की सरकारी नीति तथा कार्यों की आलोचना करने हैं जिससे जनता को सरकारी कार्यों का यथावत् ज्ञान हो सके। वे किसी भी सार्वजनिक प्रश्न को सरकार तक पहुँचाने के साधन हैं। परन्तु युद्ध-काल में तो समाचार-पत्रों का उत्तरदायित्व और भी महान् एवं गंभीर हो जाता है। युद्ध के कारण देश में जो भय और आतंक एवं गलतफहमियाँ तरह-तरह की अफवाहों के कारण पैदा हो जाती हैं, उनके दूर करने में समाचार-पत्र बड़ी सहायता करते हैं। युद्ध-मंचालन तथा देश-रक्षा के प्रयत्नों के सम्बन्ध में प्रचार के लिए समाचार-पत्र से बढ़ कर कोई साधन नहीं है।

भारतवर्ष में सरकार समाचार-पत्रों की स्वाधीनता का सदैव दमन करती रही है। इसका कारण यह है कि भारत के अधिकांश लोकप्रिय और प्रभावशाली अंग्रेजी तथा प्रान्तीय भाषाओं के पत्र राष्ट्रीय हैं अथवा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सहानुभूति रखते हैं। उन्हें भारत में अंग्रेजी सरकार की नीति की आलोचना करनी पड़ती है इसलिए उनके सिर पर भी हर समय 'प्रेस एक्ट' सवार रहता है।

सन् १९३१ में इंडियन प्रेस (इमजेंसी पाँवमें) एक्ट आतंकवाद का नाग करने के लिए बनाया गया। वह उसी समय की विशेष परिस्थिति के कारण बनाया गया था। परन्तु वह आज तक मौजूद है। अब समाचार-पत्रों को इसी कानून के अनुसार राजद्रोह, जातीय या वर्गीय द्रोह, फौजी-भर्ती-विरोध तथा सैनिकों को उत्तेजना देने आदि के लिए दण्ड दिया जाता है। इस कानून के अनुसार समाचार-पत्रों ने जमानते माँगी जाती है। जब कोई नया समाचार-पत्र शुरू किया जाता है तो उसके पकाशन से पहले ही जमानत माँग ली जाती है। ये जमानते नकद होती हैं और ५०० रुपये से लेकर १० या १५ हजार तक की होती हैं। जमानते देने के बाद यदि समाचार-पत्र सरकारी नीति के विरुद्ध

इसके साथ-ही-साथ राज का यह भी कर्तव्य है कि वह धर्म के नाम पर उसकी आँख में होनेवाले सामाजिक पापों के निवारण का प्रयत्न करे। हिन्दू-समाज में धर्म के नाम पर ऐसी अनेक कुप्रथाएँ प्रचलित हैं जो समाज के लिए हानिकारक हैं—जैसे, बाल-विवाह, बाल-हत्या, सती-प्रथा, नरमेध, धार्मिक अध-विश्वास, अस्पृश्यता, जानपान आदि। समाज-कल्याण के लिए इनके निवारण का भी राज्य की ओर से अवश्य प्रयत्न होना चाहिए। ऐसे प्रथाओं को धार्मिक हस्तक्षेप का नाम देना अविवेक है।

धर्म के सम्बन्ध में राज्य की निष्पक्षता का मतलब यह है कि राज्य को किसी एक धर्म के साथ अपनी विशेष सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए और न उसे राज्य-कोष से विशेष मदद ही देनी चाहिए। राज्य के द्वारा सब धर्मों और उनके अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। जब 'धर्म' नागरिक जीवन की शान्ति में बाधक हो अथवा किसी धर्म के अनुयायियों की ओर से सरकार के सामने ऐसी माँगें रखी जायें जिनका मौलिक नागरिक अधिकारों से संघर्ष हो, तो राज्य को सार्वजनिक हितों का पूरा ध्यान रखते हुए ऐसे मसलों का निवारण करना चाहिए।

भारत में गो-वध, मसजिद के सामने बाजा बजाने, ताजिया और आरती आदि प्रश्नों को लेकर हिन्दू-मुसलमानों में विरोध रूप से त्यौहारों के समय बड़े दंगे हो जाया करते हैं। प्रत्येक नागरिक को राज-पथ का प्रयोग करने का अधिकार है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी को अपने धर्म या समाज के जुत्स में भी शामिल होने का अधिकार है। हिन्दुओं को मन्दिरों में पूजा-पाठ और आरती करने का उतना ही अधिकार है जितना कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने का। अब यदि मुसलमानों का यह आक्षेप है कि नमाज के वक़्त सड़को पर बाजा न बजाया जाये या आरती न की जाये, तो क्या कभी मुसलमान भी यह सोचने का प्रयत्न करेंगे कि यदि इसी प्रकार हिन्दू भी यह आक्षेप करें कि आरती के समय कोई नमाज न पड़े या मुहर्रम के दिनों में ढोल न पीटे जाये क्योंकि इसने मन्दिरों के देवता अप्रसन्न होते हैं अथवा नागरिकों की नींद में खलल

पड़ता है, तो मुसलमान क्या करेंगे इस प्रकार के अविवेकपूर्ण औ-
धार्मिकता कट्टरताओं आयेगा का तो अन्त ही नहीं आयेगा। इसलिए
सामाजिक शांति के लिए सहनशीलता और वसुधाव की आवश्यकता है।

प्रत्येक धर्म के अनुयायी का यह भी अधिकार है कि वह अपने धर्म
का जनता में प्रचार करे अतः इस धर्मवाला का अपने धर्म में दीक्षित
करे। इस प्रकार यह धर्म-प्रचार अतः धर्म-परिवर्तन का कार्य शान्तिपूर्वक
होना चाहिए। वरप्रवक् किसी का धर्म में परिवर्तन उचित नहीं है।
अनाथा, नाबालिगों और विधवाओं का धर्म-परिवर्तन का अधिकार नहीं
होना चाहिए क्योंकि उन्हें प्रत्येक धर्मोन्मत्त उक्त विषयों बना लिया जाता है।

व्यवसायिक स्वाधीनता

व्यवसाय का वरचितन जीवन में है यह वाक्य सामाजिक
जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवसायिक स्वाधीनता का मतलब
है प्रत्येक व्यक्ति का अपनी रुचि या शक्ति अतः व्यक्ति के अनुसार
व्यवसाय स्वीकार करने का अधिकार। जिस मतलब का अपनी रुचि
के अनुसार काम मिल जाता है, वह उस वृत्ति में लग्न में करता है।
इसीलिए प्रत्येक को अपने मन का व्यवसाय समझ करन का अधिकार
होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी जानि धर्म या समुदाय के कारण
किसी भी व्यवसाय या मजदूरी पद में बचिन न दिया जाये। यदि वह
उसके योग्य न होगा तो स्वयं ही असह्य होगा। उसके अतिरिक्त
प्रत्येक व्यवसाय को अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन करने की पूरी
स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

अन्य नागरिक अधिकार

उपर्युक्त मीठिष्ठ अधिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकार भी
मानव-जीवन को सुखी बनाने के लिए जरूरी हैं—

प्राथमिक तथा उच्च-शिक्षा

राज्य की ओर से समस्त नागरिकों के वाङ्मय-वाङ्मयों की प्राथ-

मिक शिक्षा नि शुल्क हो, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए । उच्च शिक्षा-प्राप्ति के लिए भी राज्य को प्रोत्साहन देना चाहिए । जो जातियाँ शिक्षा में पिछड़ी हैं उनके लिए शिक्षा का विशेष प्रबन्ध होना चाहिए जिससे वे शीघ्र-से-शीघ्र दूसरी शिक्षित जातियों के समान बन सकें । छात्रवृत्तियों आदि द्वारा विश्वविद्यालयों में उनके लिए सब प्रकार की सुविधाएँ दी जानी चाहिए ।

आवागमन की स्वतंत्रता

प्रत्येक नागरिक को राज्य' की सीमा में भ्रमण तथा प्रवास का अधिकार होना चाहिए । यदि राज्य की सीमा से बाहर जाना हो तो पासपोर्ट की सुविधा प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए ।

सम्पत्ति का अधिकार

प्रत्येक नागरिक का अपनी अर्जित या प्राप्त सम्पत्ति और निजी आवश्यकता की चीजों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना उसका जीवन कठिन हो जायगा । परन्तु बड़े-बड़े व्यवसायों, कारखानों, कम्पनियों बैंकों, रेलों, खानों, भूमि आदि पर राज्य या समाज का अधिकार होना चाहिए जिससे उत्पत्ति तथा वितरण के साधनों से समस्त समाज लाभ उठा सके और वे किसी व्यक्ति-विशेष या समूह की ही वैयक्तिक सम्पत्ति न रहें ।

न्याय-प्राप्ति

प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि में समान है । इसका अर्थ यह है कानून धनी-निर्वन, मजदूर-भालिक, शिक्षित-अशिक्षित में भेद नहीं मानता । वह सबों के लिए एक-सा है । यदि कोई पूंजीपति भी हत्या का अपराधी है, तो कानून उसे प्राणदण्ड देगा और यदि कोई ब्रेज़्एट भी चोरी का अपराधी है तो कानून उसे कंठ की सजा देगा । किसी खास राज-

१ 'राज्य' की व्याख्या के लिए पहला अध्याय देखिए ।

राजनीतिक अधिकार

नागरिक-स्वाधीनता के अलावा नागरिकों के लिए राजनीतिक अधिकार भी आवश्यक हैं। राजनीतिक अधिकारों और नागरिक-अधिकारों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों की उत्पत्ति इसी सिद्धान्त के आधार पर हुई है कि राज्य नागरिकों को अपना जीवन सुखी बनाने के लिए समान सुविधाएँ प्रदान करे। राजनीतिक अधिकार मुख्यतः तीन प्रकार के हैं—

(१) मताधिकार (२) प्रतिनिधित्व का अधिकार (३) पदाधिकार

(१) मताधिकार

प्रजातन्त्र राज्य में प्रतिनिधि-संस्थाओं का सबसे अधिक महत्त्व है एक प्रकार से प्रतिनिधि-संस्थाएँ ही प्रजातन्त्र का आधार हैं। इन संस्थाओं का निर्वाचन होता है। इन निर्वाचनों के लिए जो निर्वाचक होते हैं, उनकी योग्यताएँ कानून द्वारा निर्धारित होती हैं। जो निर्वाचक की योग्यता रखते हैं, उन्हीं को मताधिकार प्राप्त होता है। जिन देशों में प्रजातन्त्र का अधिक विकास हो चुका है, उनमें प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। केवल नाबालिग और उन्मत्त व्यक्ति ही मताधिकार से वंचित रखे जाते हैं, क्योंकि वे अपने अधिकार का समुचित प्रयोग नहीं कर सकते।

भारतवर्ष में प्रान्तीय एवं केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाओं के लिए कुल ३३ करोड़ स्त्री-पुरुष मतदाता हैं। इस समय भारत की कुल जनसंख्या लगभग ४० करोड़ है। इन प्रकार ३३३ करोड़ जनता को यह महत्वपूर्ण और मूल्यवान् राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में मताधिकार सम्पत्ति और शिक्षा के आधार पर है। यही कारण है कि मतदाताओं की संख्या इतनी कम है।

(२) प्रतिनिधित्व का अधिकार

प्रत्येक निर्वाचक, जिसकी आयु २५ और ३० वर्षों में आधिकार हो

नागरिकों के कर्तव्य

अधिकार और कर्तव्य

पिछले अध्याय में नागरिकों के अधिकारों के सबध में हम विचार कर चुके हैं। परन्तु अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी घनिष्ठ सबध है, क्योंकि बिना कर्तव्य-पालन के अधिकारों का उपभोग संभव और समुचित नहीं है।

प्रत्येक राज या राष्ट्र में नागरिकों को भाषण-स्वाधीनता का अधिकार होता है। वह देश के कानून के अनुसार मर्यादा का पालन करते हुए अपनी इच्छानुसार विचार प्रकट करने में स्वतंत्र है। परन्तु उसके इस अधिकार के उपभोग के लिए यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि और दूसरे नागरिक उसकी विचार-स्वाधीनता में बाधा न डालें। उनपर किसी बाधा को उपस्थित न होने देने का उत्तरदायित्व ही उस नागरिक के लिए विचार-स्वाधीनता तथा भाषण-स्वाधीनता के अधिकार को जन्म देता है। यदि एक नागरिक एक सभा में या किसी जन-समुदाय में या अपने ग्राम की पंचायत के सदस्यों के बीच अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न करे और उसी समय दूसरे नागरिक उसके इस अधिकार के उपभोग में बाधा पहुँचाने के लिए किसी प्रकार से शान्तिभंग कर दें तो वह नागरिक अपने अधिकार का कभी उपभोग नहीं कर सकेगा।

इससे यह सिद्ध है कि जब किसी नागरिक को नागरिकता का कोई अधिकार प्राप्त होता है, तो यह अधिकार ही दूसरों के लिए कर्तव्य बन जाता है। दूसरों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे उसके प्रयोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करें।

इस प्रश्न पर एक दूसरे पहलू से भी विचार किया जा सकता है। यदि समाज के सभी सदस्य केवल अधिकारों पर तो जोर दे पर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करें, तो इसका परिणाम होगा उनके अधिकार-प्रयोग

(२) यज्ञ करना तथा कराना—अर्थात् समाज के कल्याण के लिए उत्तम और शुभ कर्म करना ।

(३) दान देना—अर्थात् ब्राह्मण ने अपनी साधना तथा तपस्या से जो ज्ञान सचय किया है, उसे जनता को देना । विद्या-दान सर्वोत्तम दान माना गया है ।

इन कर्तव्यों के साथ-साथ ब्राह्मण को यह अधिकार प्राप्त था कि वह दान स्वीकार करे । जनता उसकी सेवाओं के पुरस्कार में अपने धन के अनुसार ब्राह्मण को दान-दक्षिणा दे, उसकी भेट-पूजा करे, उसका आदर-आतिथ्य करे । ब्राह्मण अपने इन सर्वध्रेष्ठ और महत्त्वपूर्ण कर्तव्यों के पालन करने पर ही इनसे सम्बन्धित अधिकारों के भोग का अधिकारी बन सकता था । परन्तु जब ब्राह्मणों ने अपने इन कर्तव्यों की उपेक्षा करके सिर्फ दान-दक्षिणा ग्रहण करने पर ही जोर दिया, तब समाज का पतन हो गया । आज यह स्थिति है कि एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय या वैश्य अपने अधिकारों के निमित्त तो सदैव सघर्ष करने के लिए समर्थ है, परन्तु अपने कर्तव्यों के बारे में वह कुछ भी नहीं सोचता । इसीलिए तो आज समाज में न नागरिकों को अपने अधिकारों का उपभोग करने की स्वाधीनता है और न समाज में सगठन तथा सामंजस्य है ।

कर्तव्यों के प्रकार

कर्तव्य अनेक प्रकार के हैं । उनका वर्गीकरण भी कई प्रकार से किया जा सकता है । हम यहाँ कर्तव्यों को पाँच भागों में विभक्त करते हैं—

- (१) अपने प्रति कर्तव्य,
- (२) अपने परिवार के प्रति कर्तव्य,
- (३) नागरिकों के प्रति कर्तव्य,
- (४) समाज के प्रति कर्तव्य,
- (५) राज्य के प्रति कर्तव्य ।

(१) अपने प्रति कर्तव्य

प्रत्येक नागरिक का सबसे पहले अपने प्रति कर्तव्य है । यह वाक्य

का पालन करे। हिन्दू-शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेते ही जो तीन प्रकार के ऋणों—पितृ-ऋण, देव-ऋण और ऋषि-ऋण को अपने ऊपर ले लेता है उनमें इस प्रकार उसे पितृ-ऋण चुकाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है।

पति और पत्नी परिवार के प्रमुख सदस्य हैं। पति के पत्नी के प्रति कुछ विशेष कर्तव्य हैं और पत्नी के भी पति के प्रति विशेष कर्तव्य हैं। पति को पत्नी के भरण-पोषण का भार वहन करना पड़ता है। पत्नी के प्रति उसे वैवाहिक कर्तव्यों को भी पूरा करना पड़ता है। पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी के प्रति सच्चाई तथा प्रेम का व्यवहार करे और पत्नीव्रत का पालन करे। इसी प्रकार पत्नी को भी पति के प्रति भक्तिभाव रखकर पातिव्रत का पालन करना चाहिए। पत्नी गृह की स्वामिनी है और उसका कर्तव्य है कि वह घर की सब बातों की ठीक प्रकार व्यवस्था करे तथा सन्तान का यथोचित पोषण करे और उसे शिक्षा दे। पति-पत्नी का आपसी व्यवहार मैत्री के आधार पर होना चाहिए—अर्थात् पति पत्नी को दासी न समझे प्रत्युत उसे वास्तव में जीवन-सगिनी समझे।

माता-पिता के सन्तान के प्रति कुछ विशेष कर्तव्य हैं। उनका कर्तव्य है कि वे अपनी सन्तान का पालन-पोषण करे और उन्हें शिक्षित बनावे। इसी प्रकार भाइयों व बहनों तथा अन्य सम्बन्धियों के साथ भी प्रत्येक व्यक्ति को यथोचित प्रेम-पूर्वक सद् व्यवहार करना चाहिए।

हिन्दू-विधान में आचार्य की बड़ी पूजा की जाती है। आचार्य को एक प्रकार से बालक का आध्यात्मिक पिता ही कहा जाता है। आचार्य अर्थात् शिक्षकों व अध्यापकों के प्रति विद्यार्थियों को यथोचित व्यवहार करना चाहिए।

(३) नागरिकों के प्रति कर्तव्य

अपने या अपने परिवार के सदस्यों के प्रति नागरिक के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करने मात्र से ही नागरिक के कर्तव्यों की सम्पूर्ण

और उपद्रव बड़ी जामानी से पात रिये जा सक्त हैं। महनशीलता वास्तव मे मानवता का एक अमूल्य रत्न हैं। हमके अभाव मे मानवीय सद्गुणों का विकास होना सम्भव नहीं और न हमसे समाज का संगठन ही कायम रह सकता हैं। नागरिक का यह भी कर्तव्य हैं कि वह दूसरे नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति का भी वैसे ही आदर करे जैसा कि अपने जीवन व सम्पत्ति का करता हैं।

राज्य ने प्रत्येक नागरिक को आत्म-रक्षा (Self defence) का अधिकार दिया हैं। परन्तु उस अधिकार के साथ यह कर्तव्य लगा हुआ हैं कि वह दूसरे के जीवन व सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा भी करे। जनता की जो सार्वजनिक सम्पत्ति हो—जैसे बाग, पार्क, तालाब, कूप पाठशाला, धर्मशाला—उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हैं।

जीवन मे इस महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धान्त का सदा, सर्वथा, सर्वत्र पालन होना आवश्यक हैं कि प्रत्येक नागरिक को दूसरे नागरिकों के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे व्यवहार की वह अपने प्रति उनसे आशा रखता हैं। इस नियम पर चलने से समाज के व्यक्तियों मे कभी किसी विषय पर संघर्ष नहीं हो सकता और जीवन के सब काम बड़ी सफलता से चलते रह सकते हैं।

(४) समाज के प्रति कर्तव्य

हमने नागरिकों के कर्तव्यों के सबन्ध मे ऊपर जो निवेदन किया हैं, वह केवल व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक नागरिक के ही लिए हैं। नागरिक के कुछ कर्तव्य ऐसे भी हैं जिन्हें वह दूसरों के सहयोग से पूरा कर सकता हैं। ऐसे कर्तव्य समाजगत होते हैं। इनके पालन से समूचे समाज का कल्याण होता हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हैं कि वह दूसरे नागरिकों के साथ सहयोग-पूर्वक समाज के संगठन मे भाग ले। समाज के उत्कर्ष के लिए उसे राज्य की ओर से कई प्रकार के संगठन निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हैं। इस अधिकार का प्रयोग वह समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, व्यापारिक,

मासना-नागरिकों का भी मानना होता है। अमेरिका में अंग्रेजी में *Inhabitant* शब्दों की धारणा को प्राप्त करने पर भी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका में नागरिकों को ये दोनो अधिकार प्राप्त हैं।

राज्य के कानूनों का पालन

नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे राज्य के शासन विधान के तहत दूसरे कानूनों का पालन करें। प्रजातन्त्र-राज्य में शासन द्वारा शास्य होता है और धारासभाओं में भी प्रत्येक कानून धारण की शक्ति प्राप्त जाता है। इसलिए समस्त देश उस कानून में शास्य हो जाता है। जब कानून बन चुकता है तब समस्त जनता को यह पालना हो जाता है कि वह उसका सद्भावना के साथ पालन करें।

अब प्रश्न यह है कि यदि धारासभाओं और सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो समाज के लिए या उसके किसी वर्ग के लिए घातक है, तो क्या उस कानून के विरोधियों का यह कर्तव्य है कि वे पालन की अवज्ञा करें? इसमें कोई शन्देह नहीं कि प्रत्येक प्रजातन्त्र राज्य में नागरिकों को यह अधिकार है कि वे किसी भी कानून तथा सरकार के कार्य की आलोचना कर सकते हैं और उसके प्रति विरोध-प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इस प्रकार के विरोध-प्रदर्शन वैध (न्यायोचित) माने जाते हैं। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य है लोकमत द्वारा सरकार को यह बताना कि उसने जो कानून बनाया है वह समाज या किसी विशेष वर्ग के लिए घातक है जिससे सरकार उसमें सशोधन का प्रयत्न कर सके।

परन्तु कानून की अवज्ञा करना तो देश के विधान के अनुसार अपराध है। ससार के किसी भी सभ्य राज्य के विधान ने नागरिकों को यह अधिकार नहीं दिया है। संविधान प्रजातन्त्र-संघ के शासन-विधान में भी संघ नागरिक-संघ के विधान और उसके कानूनों को मानने, धर्म के अनुशासन को कायम रखने, सार्वजनिक कर्तव्य का आदर करने और समाजवादी सभा (सोसाइटी) के नियमों का पालन

[illegible]

राज्य-कोष में कर तथा लगान प्राप्ति देना

राज्य के पामन का सन्तान प्रजा प्राप्ति दिये गये १२ भाग दा. के रूप में आये हुए धन ने ही होता है। यदि राज्य में पामन दा. को के द्वारा पर्याप्त कोष प्राप्त नहीं होता तो यह जोतायोगी कार्या को ठीक प्रकार से करने में असमर्थ रहता है। इसलिए नागरिकों का कर्तव्य है कि वे ठीक समय पर निर्धारित टैक्स, मालगुजारी आदि सरकार को देते रहें। यदि सरकार कोई ऐसा कर लगाती है जो प्रजा पर भार है अथवा जो उचित नहीं है तो प्रजा का यह कर्तव्य है कि वह उसका विरोध करे।

स्वदेश-रक्षा

प्रत्येक देश के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्र आत्मरक्षण से स्वदेश की रक्षा के कार्य में अपने देश की सरकार की धन, जग आदि से पूरी सहायता करें। इसीलिए बहुत-से देशों में नागरिक सेनाएँ होती हैं। सोवियट राज्य में अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम है। इसी प्रकार युद्ध-काल में प्रत्येक विग्रही राष्ट्र में अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम प्रचलित हो जाता है। इस सम्बन्ध में मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि अनिवार्य सैनिक-सेवा का नियम नैतिकता और नागरिक स्वाधीनता की भावना के विरुद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है और

उमम जब्बदम्नी फोज म मैनिर का काम करेगा उचित नहीं।

इसका मत यह है कि देश की सभ्यता की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक का नैतिक सेवा करनी चाहिए। उसका काम उसका कर्तव्य ही नहीं धर्म भी है। यदि अनिवार्य सेवा का नियम न बना जाये तो नागरिक रक्षा के कार्य में सक्रिय भाग न लेना चाहता।

इस सम्बन्ध में हमारा मत यह है कि नागरिक में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वे स्वदेश के लिए सर्व प्राणोत्सर्ग करने का तत्पर रहें। ऐसी दशा में वे स्वयं-सेवा सेना न बनाने का प्रयत्न स्वयं ही करेंगे।

कर्त्तव्याकर्त्तव्य का निर्णय

व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब नागरिकों को यह निर्णय करना पड़ता है कि क्या कर्त्तव्य है और क्या अकर्त्तव्य है? ऐसे अवसरों पर उन्हें क्या करना चाहिए—यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है।

जब कभी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाये तब उन्हें यह विचार करना चाहिए कि जिस कार्य के करने से अधिक हित-साधन हो, समाज का लाभ हो, वही करना उचित है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इस प्रकार के निर्णय में त्याग तथा बलिदान की भावना का प्राधान्य होगा।

श्री भगवानदास केला ने इस सम्बन्ध में लिखा है—

“जिन कार्यों में भेदभाव न रखकर, समता का आदर्श रखा जाता है, जिनमें हम अपनी आत्मा की विशालता का अनुभव करते हैं, जिनमें स्वार्थ-परार्थ का प्रश्न नहीं उठता वे ही कर्त्तव्य हैं। इसके विपरीत जिन कार्यों से भेदभाव की उत्पत्ति होती है, अपने परार्थ का विचार होता है, अपना सुख-दुःख मुख्य समझा जाता है, जिनमें आत्मा के विस्तार की भावना न रख कर, उसे परिवार या नगर आदि के सीमित क्षेत्र में परिमित रखा जाता है, वे अकर्त्तव्य हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं कि

हमारा अपने परिवार या नगर आदि के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। नहीं नहीं जैसा कि अन्यत्र बताया गया है, हमारा कर्तव्य तो स्वयं अपने प्रति भी है। हाँ हमें दूसरों के हित को न भूलना चाहिए।”^१

श्री केलाजी ने जो सिद्धान्त उपर्युक्त अवतरण में स्थिर किया है, वह वास्तव में नागरिक जीवन के लिए एक उच्च मानवीय आदर्श है। इस सिद्धान्त के समुच्चय प्रकाश में नागरिकगण कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय बड़ी आसानी के साथ कर सकेंगे।

१ श्री भगवानदास केला 'नागरिक-शास्त्र (१९३२) पृ० ३१४

प्रजातन्त्र भारत के लिए नयी वस्तु नहीं है। यद्यपि प्राचीन भारत में आधुनिक ढंग की प्रजातन्त्र-प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, तो भी यह प्रमाणित हो चुका है कि वैदिक राजा या हिन्दू नरेश स्वेच्छा-चारी शासक नहीं होता था। प्राचीन काल में राजा का प्रजा की राज्य-समिति द्वारा चुनाव होता था।^१ राजा को मन्त्रि-परिषद् की सम्मति से शासन संचालन करना पड़ता था। मन्त्रि-परिषद् के बहुमत का राजा आदर करता था।^२ राजा के कर्तव्यों का विधान धर्म-शास्त्रों में प्रति-पादित होता था और उसके अनुसार ही उसे कार्य करना पड़ता था। प्रजा राजा की केवल धर्मयुक्त आज्ञाओं को ही मानने के लिए बाध्य थी।^३ प्रजा को राजा के चुनने का अधिकार था परन्तु वह उसे अधि-कार-च्युत भी कर सकती थी। राजा को प्रजा की सम्मति से कर वसूल करने का अधिकार था और वह पुलिस, सेना, सिविल सर्विस तथा राज्य के अन्य कार्यों का संचालन जाति-सघ, परिषदों या पंचायतों द्वारा करता था। उस समय आज जैसी वैधानिक परम्परा, पार्लियामेन्टरी प्रणाली और उत्तरदायी शासन नहीं था। परन्तु ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिनसे यह सिद्ध है कि प्राचीन काल में भारत में प्रजातन्त्र संस्थाएँ मौजूद थीं और सघ-शासन-प्रणाली का भी विकास हो चुका था।^४

प्रजातन्त्र के प्रकार

आधुनिक काल में प्रजातन्त्र के दो प्रकार हैं। एक प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र और दूसरा परोक्ष प्रजातन्त्र। प्राचीन यूनान और रोम में राज्य छोटे

१ 'अथर्व वेद' हवंडे ओरियण्टल सोरीज।

२. आत्ययिके कार्ये मन्त्रिणो मन्त्रिपरिषद् चाहूय यूयात् । ६३
तत्र यद्भूयिष्ठाः कार्यसिद्धिकरं वा यूयस्तत्कुर्यात् । ६४

—कौटिल्य अर्थशास्त्र - अधिकरण १; अ०

३. 'हिन्दू राजनीति' स्व० काशीप्रसाद जायसवाल।

४ उपर्युक्त

दी हैं। उन्हें मस्तिष्क और हृदय भी दिया है। वे अपनी मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के विकास से अपने जीवन को सुगी बना सकते हैं। यह तो स्वयंसिद्ध है कि मनुष्य अपनी समस्त शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास केवल स्वाधीन दशा में ही कर सकता है। यदि वे बंधन में रहे, तो उनका विकास स्वाभाविक ढंग से न हो सकेगा। यह भी स्वयंसिद्ध है कि मानव-जीवन का लक्ष्य शांति और आनन्द की प्राप्ति है। अतः राज्य और समाज को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें रहकर समस्त मानव अपने इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर सके। जिस समाज में कानून की व्यवस्था एवं नियमन की सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होगी, उसमें शेष जनता आनन्द-प्राप्ति के प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। अतः इसका निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने समाज, राष्ट्र या राज्य की नीतियों के निर्माण में योग देना आवश्यक है, क्योंकि ज़रतक सभी मनुष्यों को अपनी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सुयोग नहीं मिलेगा, तबतक समाज या राज्य यह निर्णय नहीं कर सकेगा कि समाज या राज्य के लिए कौनसे नियम हितकारी हैं अथवा किन नियमों के पालन न करने से समाज की हानि है? वस, प्रजातन्त्र का यही आधार है।^१

अमरीका की स्वाधीनता की घोषणा में जो सन् १७७६ ई० में की गयी थी यह घोषित किया गया था—

“हम इन सत्यो को स्वयं-सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा किये गये हैं। सृष्टिकर्ता ने उन्हें कुछ जन्म-सिद्ध अधिकार प्रदान किये हैं। इन अधिकारों में जीवन-स्वाधीनता और आनन्द-प्राप्ति के अधिकार शामिल हैं। इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकारों की स्थापना की गयी है। इन सरकारों को जो सत्ता प्राप्त है उसका आदि-स्रोत जनता ही है।”

१ ‘प्रजातन्त्र के मौलिक तत्त्व’: रामनारायण ‘यादवेन्दु’ ‘विश्वमित्र’ मासिक, अगस्त १९४०

राज्य को अपने समस्त नागरिकों की सुख-सुविधा के लिए समान अवसर व सुयोग देने चाहिए। समानता, के कई प्रकार हैं—राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता आदि। राजनीतिक समानता से प्रयोजन यह है कि राज्य के समस्त नागरिकों को, जो योग्य हों, देश के शासन-संचालन में भाग लेने का समान अधिकार हो। शासन-संचालन किसी वंश-विशेष का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए मताधिकार नागरिकों को प्राप्त है। वह इसी के द्वारा शासन में भाग लेने के अधिकारी है। परन्तु राजनीतिक समानता की सफलता के लिए सामाजिक समानता भी जरूरी है। जबतक समाज में प्रत्येक नागरिक को समान न माना जायेगा, तबतक उसका कोई राजनीतिक महत्त्व नहीं। इसी का एक फलितार्थ है—आर्थिक समता या आर्थिक न्याय। समाज में सब वर्गों के सुख के लिए आर्थिक समता जरूरी है। यदि पाश्चात्य देशों में प्रजातन्त्र-प्रणाली विफल सिद्ध हुई है तो उसका एक मात्र कारण यही है कि प्रजातन्त्र-प्रणाली ने पूँजीवाद के साथ गठ-बन्धन करके समाज में विषमता को जन्म दिया।

समाज में सच्ची बन्धुत्व की भावना उभी समय उत्पन्न हो सकती है जबकि उसमें नागरिक-स्वाधीनता और समानता का मिद्धान्त पूर्णतया प्रतिष्ठित हो गया हो और नागरिकों ने अपने दैनिक जीवन में उनके अनुसार आचरण करने का प्रयत्न किया हो।

प्रजातन्त्र के उपर्युक्त तीन तत्त्वों के अतिरिक्त राज्य के नागरिकों में सार्वजनिक शिक्षा की भी व्यवस्था हो। जबतक नागरिक सार्वजनिक प्रश्नों में दिलचस्पी न लेंगे तबतक प्रजातन्त्र का सफल होना संभव नहीं। इसके लिए नागरिक-शिक्षा के प्रचार की जरूरत है। जनता में उच्च सार्वजनिक जीवन के प्रति आकर्षण पैदा किया जाये। चरित्रवान् लोग सार्वजनिक कार्यों का संपादन करें। प्रत्येक नागरिक को स्वतन्त्र रूप से सोचने का अभ्यास डाला जाये तथा उसका दृष्टिकोण गतिशील बनाया जाये। लोकमत भी प्रगतिशील एवं शिक्षित होना चाहिए। मतलब यह है कि समस्त सामाजिक जीवन का पुनर्संगठन प्रजातन्त्र के आधार पर

(८) प्रजातन्त्र में जनता को नागरिक-शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग मिलता है। यह सार्वजनिक प्रश्नों के मध्य में दिलचस्पी लेती है। उसमें सार्वजनिक हित के प्रश्न पर अपना स्वतन्त्र मत प्रकट करने की क्षमता होती है।

प्रजातन्त्र-शासन के दोष

प्रजातन्त्र-शासन में जहाँ इतने गुण हैं वहाँ उसमें—उसकी प्रणाली में कुछ दोष भी हैं जिनमें से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं—

- (१) प्रजातन्त्र की शासन-संस्थाएँ मन्द गति से ही अपना कार्य-संचालन कर सकती हैं। किसी प्रश्न पर, आवश्यकता के समय, शीघ्रता से निर्णय करने की सुविधा कम होती है।
- (२) लोकमत की प्रगतिशीलता के कारण जनता के विचारों में परिवर्तन होता रहता है। किसी भी सार्वजनिक प्रश्न पर मन्त्रि-मण्डल में अथवा पार्लिमेंट में मतभेद होजाने में सरकारें त्यागपत्र दे देती हैं। फिर नये चुनाव होते हैं। इस प्रकार शासन-कार्य में अव्यवस्था बहुत होती रहती है।
- (३) प्रजातन्त्र-प्रणाली में बहुमत जब अल्पमत के विचारों का आदर नहीं करता तब अल्पमत अनेक प्रकार के विवाद तथा उपद्रव पैदा करता है। यह विवाद और संघर्ष पार्लिमेंट या धारासभा के सदस्यों तक ही समिति नहीं रहता प्रत्युत अल्पमत जनता पर भी अपना प्रभाव डालता है और जनता में उपद्रव और विद्रोह खड़े हो जाते हैं।
- (४) प्रजातन्त्र में जनता में नवीन आदर्शों, नवीन भावनाओं तथा नयी विचारधाराओं के कारण नवीनता के प्रति विशेष आकर्षण हो जाता है। इस प्रकार जनता में प्राचीन संस्थाओं को नष्ट करने और उनकी जगह नयी संस्थाएँ खड़ी करने का एक रिवाज-सा चल पड़ता है।
- (५) प्रजातन्त्र में प्रचार या प्रोपेगेंडा एक महान् शक्ति है। प्रत्येक

(जानुअर, १९३७) में अपना नया 'पूर्ण स्वाधीनता' को पाना मजूर किया तब उनके अध्यक्ष श्री मुहम्मदअली जिन्ना ने बड़े ओजस्वी शब्दों में लीग के 'योग की घोषणा' करते हुए कहा—'मुस्लिम लीग भारत के लिए पूर्ण राष्ट्रीय प्रजातन्त्रात्मक स्वराज्य चाहती है।' सिख, भारतीय ईसाई, दलितवर्ग, लिवरलदल, हिन्दू महासभा आदि सभी दल प्रजातन्त्र के आदर्श में विश्वास करते हैं।

पाकिस्तान

विगत लाहौर अधिवेशन (मार्च, १९४०) से मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके यह कुप्रचार करना शुरू कर दिया है कि भारत में दो राष्ट्र हैं—हिन्दू और मुसलमान। इसलिए भारत में प्रजातन्त्र-प्रणाली उपयुक्त नहीं है। हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए अलग-अलग राज्य होने चाहिए। मुसलमानों का राज्य—पाकिस्तान—उत्तर-भारत में रहे जिसमें सीमा-प्रान्त, विलोचिस्तान, पंजाब, सिन्ध, बंगाल आदि शामिल हो। शेष भारत में हिन्दू-राज्य कायम किया जाये। मुस्लिम लीग के नेता श्री जिन्ना ने यह पाकिस्तान की नयी योजना तैयार की है। परन्तु इस योजना को भारत के समस्त मुसलमानों ने तो क्या उनके बहुमत ने भी स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस, हिन्दू महासभा, सिख, ईसाई तथा लिबरल सभी इस योजना का घोर विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार भारत में पाकिस्तान की स्थापना राष्ट्र के लिए खतरनाक है। और इसकी स्थापना का स्वप्न भी पूरा नहीं हो सकता।

नहीं मिलता। धार्मिक ग्रन्थों में इस धर्म का नाम 'आर्यं धर्मं' लिखा है।

उत्तर भारत प्राचीन समय में 'आर्यवर्त' के नाम से प्रसिद्ध था और उसके निवासियों को 'आर्य' कहा जाता था। 'आर्य' का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, मान्य पुरुष।

चारों वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद) सत्तार के सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं और वैदिक धर्म सत्तार का आदि-धर्म है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की तो सबसे पहले उन्होंने चार ऋषियों को ज्ञान दिया। यही ईश्वरीय ज्ञान 'वेद' है जो उन ऋषियों के द्वारा मानव-समाज के लिए सुलभ हो सका।

उपनिषद् वेदों की व्याख्याएँ हैं जो बाद में ऋषियों ने की। इसी प्रकार दर्शनशास्त्र भी मुनियों द्वारा प्रणीत है। स्मृतियों में धर्म के नियम हैं। वे एक प्रकार से कानून-संग्रह हैं। सबने प्राचीन स्मृति मानवधर्म-संग्रह हैं। यह 'मनुस्मृति' के नाम से भी प्रसिद्ध है।

वेद, उपनिषद्, ब्राह्मण, शास्त्र, और मनुस्मृति सब मस्तुत भाषा में हैं। योगदर्शन के अनुसार वैदिक धर्मानुयायी को निम्न लिखित दस नियमों का पालन करना चाहिए। ये दस नियम इस प्रकार हैं —

- (१) अहिंसा—मन, वचन और कर्म से प्राणी-मात्र से प्रेम करना तथा किसी भी प्राणी को हानि न पहुँचाना।
- (२) सत्य—मन, वचन कर्म से सत्य का पालन करना।
- (३) अस्तेय—मन, वचन, कर्म से चोरी का त्याग।
- (४) ब्रह्मचर्य—वीर्य-रक्षा करते और समयपूर्ण जीवन बिताते हुए, ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म-प्राप्ति की साधना करना।
- (५) अपरिग्रह—जावश्यकता से अधिक का भण्डार न करना तथा स्वाभिमान-रहित रहना।
- (६) शौच—जलादि से शरीर तथा वस्त्रों की शुद्धि, पवित्र विचारों से मन की शुद्धि तथा ब्रह्म-ज्ञान से आत्मा की शुद्धि करना।
- (७) सन्तोष—पुरुषार्थ करना तथा हानि-लाभ में शोक न करना।

(८) तप—कष्ट सहन करते हुए भी धर्मसम्मत कार्यों का अनुष्ठान करना।

(९) स्वाध्याय—स्वयं पढ़ना तथा दूसरों को पढ़ाना।

(१०) ईश्वर-प्रणिधान—ईश्वर की भक्ति में आत्म-समर्पण।

इस प्रकार मक्षेप में, मूर्तरूप में योगदर्शन-कार ने धर्म के दस नियम बतलाये हैं। इनके अनुसार आचरण करके मनुष्य न केवल लौकिक सुख ही प्राप्त कर सकता है, प्रत्युत मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है।

वैदिक धर्म के मोक्षिक सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

(१) एकेश्वरवाद—इस विष्णु और ब्रह्माण्ड का कर्त्ता केवल एक ईश्वर है। वह सर्वशक्तिमान्, निर्विकार, अजन्म, अनादि, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ आदि है।

(२) जीव चेतन है और अनन्त है। वह अमर है, अजन्म है और अनादि है। जीव में इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न होता है। जीव जैसे तम करना है, वैसा ही उसे फल मिलता है। जब जीव थोड़ा कर्म करता है और उसे मोक्ष मिल जाता है तब वह १५ तरफ, ५९ अरब, २० करोड़ वर्ष बाद पुनः शरीर प्राप्ति करता है।

(३) जीव एक शरीर या त्याग करके दूसरी योनि में जाता है। इस प्रकार पुनर्जन्म में विद्यमान वैदिक सिद्धान्त है।

(४) वह सृष्टि-रचना प्रकृति और जीव में हुई है। प्रकृति जड़ है। उसमें चेतनता का अभाव है। प्रकृति का अभी नाश नहीं होता। सृष्टि में वह अनादि है, अमर है।

(५) वैदिक धर्म के अनुसार मानव-जीवन चार आश्रमा में विभाजित है—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, व्रतप्रस्थ और संन्यास।

(६) इसी प्रकार मानव समाज गुण, धर्म और स्वभाव के आधार पर चार वर्ग में विभक्त है—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

(७) वैदिक धर्म मुख्यतः और अग्रगण्य में सिद्ध है।

(८) वैदिक धर्म उत्तम और अग्रगण्य की भी प्रशंसा नहीं करता।

अतः मानवधर्म में वैदिक धर्म के द्वारा स्वभाव की प्रशंसा आदि-मानव में ही विद्यमान है, मानव को ही पुनर्जन्म प्राप्त करने का मार्ग है।

बुद्ध को भगवान् मानते हैं और उन्हें सर्वज्ञ एव अमर मानकर उनकी पूजा करते हैं ।

बुद्ध हिन्दुत्व के पुजारी थे । वह वास्तव में हिन्दु-समाज के एक महान् क्रान्तिकारी सुधारक थे । उनके महान् कार्य की विशेषता यह है कि उन्होंने उपनिषदों के सिद्धान्तों और वेद के उपदेशों को व्यावहारिक जीवन में ओतप्रोत कर उनकी सत्यता सिद्ध की । बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा के सन्ध पर भी उतना अधिक जोर नहीं दिया जितना लोक-कल्याण और सेवा-धर्म पर । उन्होंने भारत में प्रचलित जाति-प्रथा की निस्सारता को सिद्ध करके मानव-बन्धत्व की स्थापना की । उन्होंने स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार किया । वास्तव में बुद्ध विश्व-प्रेम के मानवीय उच्चादर्शों को जीवन में चरितार्थ करनेवाले मानवता के महान् पुजारी थे । परन्तु आज बौद्धमतानुयायी बुद्ध के आदर्शों व सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत आचरण कर रहे हैं ।

सिक्ख मत

सिक्ख मत नवीन मत है । यह हिन्दु-समाज में सुधार करने के लिए एक ऐसे युग में प्रचलित हुआ था जबकि हिन्दुत्व पतन की चरम सीमा को पहुँच चुका था । जब हिन्दुत्व पर विजातीय शासकों द्वारा आक्रमण हो रहा था, तब गुरु नानक (सं १४६९-१५३८) ने सिक्ख मत की स्थापना की थी । गुरु नानक ने देश में भ्रमण कर लोगों को यह सन्देश दिया कि सबको ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना चाहिए । कहा जाता है कि हिन्दुओं के अतिरिक्त मुसलमान भी नानक के भक्त बन गये । गुरु नानक का जातपान और अस्पृश्यता में विश्वास नहीं था । सब मनुष्य समान हैं—यही उनका मूल सिद्धान्त था । सिक्खों का धर्म-ग्रन्थ 'जादि-ग्रन्थ' है । सिक्खमतानुसार ईश्वर एक और सर्वव्यापक है, वह अभय, अमर, अजन्म, स्वाम्भू, महान् और स्वच्छ है । यह सत्य था सत्य है और सदैव सत्य रहेगा । उसके सिया दूसरा कोई नहीं । अनेक गुणों के कारण ईश्वर के अनेक नाम हैं, पर उसका मुख्य नाम

की जनगणना के अनुसार भारत में १२ लाख ५१ हजार १०५ जैन हैं।

यद्यपि हिन्दू धर्म जैन धर्म से भिन्न है परन्तु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जैन अपने को हिन्दू ही मानते हैं और हिन्दू भी जैन धर्मावलम्बियों को हिन्दू मानते हैं। वे गौ-पूजा करते हैं, हिन्दू देव-मन्दिरों में जाते हैं, हिन्दू उत्तराधिकार कानून को मानते हैं, हिन्दू पर्वों और उत्सवों को मानते हैं और भाषा और संस्कृति की दृष्टि से भी वे हिन्दू ही हैं।

(३) बौद्ध मत

बौद्ध मत की प्रतिष्ठा ईसा से पूर्व पाँचवीं शताब्दी में गौतम बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध के मतानुसार जीवन दुःखमय है, ममत्त्व दुःखों का कारण मोह और तृष्णा है। अतः इच्छाओं के दमन द्वारा ही दुःखों का परिहार हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बुद्ध ने निम्नलिखित नियमों के पाठन पर जोर दिया है—(१) अहिंसा (२) अस्तेय, (३) ब्रह्मचर्य (४) सत्य (५) दीर्घा-त्याग (६) शिष्ट भाषण (७) प्रलोभन-त्याग (८) घृणा-परित्याग (९) अज्ञान-निवारण

बौद्ध मत में मुक्ति के लिए ईश्वर-शक्ति और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसमें नीति-मार्ग पर अधिक जोर दिया गया है। उनकी दृष्टि में आत्म-सत्य ही मोक्ष का साधन है। बौद्ध मत में मोक्ष का परम उच्च स्थान प्राप्त है। इस धर्म का प्रसार एशिया में हुआ। यद्यपि भारत में तो बौद्ध-मतानुयायियों की संख्या बहुत ही कम है, परन्तु ब्रह्मा, बौद्ध, तिब्बत, मंगोलिया, चीन और जापान में बौद्ध मत का ही प्रचार अधिक है। इसी संस्था ने बौद्ध मत का अनुयायी बनकर उनके विचारों के लिए इन देशों में महान् उद्योग किया था।

बौद्ध मत के अनुयायी दो बड़े सम्प्रदाय हैं—हीनयान और महायान। हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी बुद्ध के शिष्यों के अन्तर्गत हैं, वे बुद्ध का पुरुष विचार के अन्तर्गत मानते हैं। विपरीत रूप से मुक्ति के लिए हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी

बुद्ध को भगवान् मानते हैं और उन्हें सर्वज्ञ एवं अमर मानकर उनकी पूजा करते हैं ।

बुद्ध हिन्दुत्व के पुजारी थे । वह वास्तव में हिन्दु-समाज के एक महान् क्रान्तिकारी सुधारक थे । उनके महान् कार्य की विशेषता यह है कि उन्होंने उपनिषदों के सिद्धान्तों और वेद के उपदेशों को व्यावहारिक जीवन में ओनप्रोत कर उनकी सत्यता सिद्ध की । बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा के सन्ध पर भी उतना अधिक जोर नहीं दिया जितना लोक-कल्याण और सेवा-धर्म पर । उन्होंने भारत में प्रचलित जाति-प्रथा की निस्सारता को सिद्ध करके मानव-बन्धत्व की स्थापना की । उन्होंने स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार किया । वास्तव में बुद्ध विश्व-प्रेम के मानवीय उच्चादर्श को जीवन में चरितार्थ करनेवाले मानवता के महान् पुजारी थे । परन्तु आज बौद्धमतानुयायी बुद्ध के आदर्शों व सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत आचरण कर रहे हैं ।

सिक्ख मत

सिक्ख मत नवीन मत है । यह हिन्दु-समाज में सुधार करने के लिए एक ऐसे युग में प्रचलित हुआ था जबकि हिन्दुत्व पतन की चरम सीमा को पहुँच चुका था । जब हिन्दुत्व पर विजातीय शासकों द्वारा आक्रमण हो रहा था, तब गुरु नानक (सं १४६९-१५३८) ने सिक्ख मत की स्थापना की थी । गुरु नानक ने देश में भ्रमण कर लोगों को यह सन्देश दिया कि सबको ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना चाहिए । कहा जाता है कि हिन्दुओं के अतिरिक्त मुसलमान भी नानक के भक्त बन गये । गुरु नानक का जातपान और अस्पृश्यता में विश्वास नहीं था । सब मनुष्य समान हैं—यही उनका मूल सिद्धान्त था । सिक्खों का धर्म-ग्रन्थ 'आदि-ग्रन्थ' है । सिक्खमतानुसार ईश्वर एक और सर्वव्यापक है, वह अभय, अमर, अजन्म, स्वयम्भू, महान् और दयालु है । वह सत्य था सत्य है और सदैव सत्य रहेगा । उसके सिवा दूसरा कोई नहीं । अनेक गुणों के कारण ईश्वर के अनेक नाम हैं, पर उसका मुख्य नाम

हो, लोगों ने देवियों की भी कल्पना की—जैसे सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती आदि। ब्रह्मा की देवी सरस्वती, विष्णु की देवी लक्ष्मी और शिव की देवी पार्वती या दुर्गा मानी गयी। इन तीनों देवियों को आदिशक्ति माना गया है और इनके उपासक शाक्त कहलाते हैं। इनके अलावा हिन्दू-समाज में कबीर-मठ, गुरु-मठ, गोसाईं सम्प्रदाय, माधव और नारायण सम्प्रदाय और चानमार्ग आदि अनेक पथ और सम्प्रदाय प्रचलित हैं जो किसी सत अवस्था या चार्य के नाम पर कायम हुए हैं।

आर्यसमाज

उन्नीसवीं सदी में जब भारत में वैदिक धर्म के प्रति हिन्दुओं की प्रतीति नष्ट हो रही थी, धार्मिक क्षेत्र में पाखण्ड और दम्भ का जोर बढ़ रहा था और समाज नैतिक पतन की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा था, तब धार्मिक हिन्दू जाति के अन्धविश्वास और अज्ञान को दूर करने के लिए स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना की। उन्होंने समस्त भारत में भ्रमण करके वैदिक-धर्म-विरोधी मत-मतान्तरों का खण्डन किया और वैदिक धर्म के सच्चे स्वरूप को जनता के सामने प्रस्तुत किया। स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज के १ नियम निर्धारित किये जो इस प्रकार हैं—

- (१) सत्र सत्य विद्या का और उससे समझे जानेवाले सब पदार्थों का आदिमूल परमात्मा है।
- (२) ईश्वर सच्चिदानन्द ब्रह्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान्, व्यापकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और मृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करना उचित है।
- (३) वेद सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना आर्यों का परम धर्म है।
- (४) सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने को सदा उद्यत रहना चाहिए।
- (५) सब काम धर्मानुसार सत्य और असत्य का विचार करके करना चाहिए।

- (६) ससार का उपकार अर्थात् आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य है ।
- (७) सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य आचरण करना चाहिए ।
- (८) अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए ।
- (९) प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अनो उन्नति समझनी चाहिए ।
- (१०) सब मनष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतप और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतन्त्र रहना चाहिए ।

आर्यसमाज के द्वारा हिन्दू-समाज में अनेक क्षेत्रों में सुधार हुए । उसने वेद-कालीन गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की स्थापना की तथा कन्याओं की शिक्षा के लिए अलग कन्या-गुरुकुल खोले । त्रियों में शिक्षा-प्रचार और परदा-प्रथा-निवारण के लिए खास तौर से काम किया । बाल-विवाह तथा वैवाहिक कुरीतियों के निवारण के लिए भी महान् प्रयत्न किया गया । मादक-द्रव्य-निषेध, हिन्दी-भाषा प्रचार विधवा-विवाह, अनाथों की रक्षा तथा शुद्धि-संगठन - ये आर्य-समाज के मुख्य अन्दोलन हैं । आर्यसमाज ने ऐसी सर्वतोमुखी क्रान्ति का प्रादुर्भाव किया कि जिससे मृतगम्य हिन्दू-जीवन में जागरण, शक्ति और स्फूर्ति का संचार होगया । भारतवर्ष में आज भी प्रत्येक नगर और जिले में आर्य समाज कार्य कर रहा है । भारत के बाहर भी यूरोप, अमरीका और अफ्रीका में जहाँ भारतीय प्रवासी रहते हैं, आर्यसमाज की संस्थाएँ हैं ।

ब्राह्म-समाज

सन् १८२८ में बंगाल में राजा राममोहन राय ने उपनिषदों के ग्रन्थ की उपामना के लिए 'ब्राह्मसमाज' की स्थापना की । सन् १९३० में सबसे पहले उनका मन्दिर स्थापित किया गया जिसमें सबको प्रवेश की आज्ञा दी गयी । ब्राह्मसमाजी मूर्तिपूजा, जानपात, अस्पृश्यता आदि कुप्रथाओं को नहीं मानते । इस प्रकार 'ब्राह्म-समाज' ने हिन्दुओं को विधर्मी होने से बचाया ।

रामकृष्ण-मिशन

सन् १८३३ में बंगाल में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। वे ईश्वर के अनन्य भक्त थे। सांसारिक सुखों को त्याग कर उन्होंने पयास-प्रत किया और योग-समाधि द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना की। उन्होंने यह अनुभव किया कि सब धर्मों में एकता है। इसलिए उन्होंने किसी धर्म का राखण नहीं किया। स्वामी विवेकानन्द, जो रामकृष्ण के महान् शिष्यों में से थे, वेदान्त के प्रचारण पण्डित थे। उन्होंने वेदान्त का प्रचार विदेशों में भी किया। स्वामी रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करनेवाली संस्था 'रामकृष्ण मिशन' नाम से प्रसिद्ध है।

इस्लाम धर्म

इस्लाम या मुसलमान धर्म सत्तार के प्रमुख धर्मों में से है। इसके संस्थापक हजरत मुहम्मद की जन्म-भूमि एशिया महाद्वीप के अरब देश में है। अरबवासियों के द्वारा ही यह धर्म भारत, अफगानिस्तान, मिश्र, तुर्की आदि देशों में फैलाया गया। मुहम्मद साहब के उपदेशों का संग्रह 'कुरान' में है। जब मुसलमानों का राज्य हिन्दुस्तान में हुआ तो उन्होंने भी अपना धर्म यहाँ प्रचलित किया। कई मुसलमान बादशाहों ने धर्मप्रचार के लिए हिन्दू जनता पर बड़े अत्याचार किये, किन्तु अकबर आदि ने जनता को पूर्ण स्वतन्त्रता दी। मुहम्मद साहब के उपदेशों का सार यह है —

- (१) एक ईश्वर में विश्वास करो।
- (२) कुरान में विश्वास करो।
- (३) खुदाई निर्णय, स्वर्ग और नर्क में विश्वास करो।
- (४) पैगम्बरों में भक्तिभाव रखो।
- (५) प्रतिदिन यह पाठ करना चाहिए कि "अल्लाह के सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मुहम्मद अल्लाह का पैगम्बर है।"
- (६) मक्का की ओर मुहूर्त करके दिन में ३ से ५ बार तक नमाज पढ़नी चाहिए।

(७) दान-शिक्षणा देनी चाहिए ।

(८) रमजान के दिनों में व्रत रखा जाए ।

(९) मरणा की तीर्थ-यात्रा करनी चाहिए ।

इस्लाम का मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं है । उमरा भ्रातृभाव और समानता का सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और उसका द्वार सब मनुष्यों के लिए खुला हुआ है । मुहम्मद साहब ने कर्म पर अधिक जोर दिया है । उन्होंने लिखा है—

“जो सब्चाई के साथ अपनी जीविका कमाते हैं, उन्हें ईश्वर प्रेम करता है ।”

“ईश्वर उन लोगों पर कृपा करता है जो अपनी मेहनत से कमाते हैं और भिक्षावृत्ति पर निर्भर नहीं रहते ।”

दान-शिक्षणा के सम्बन्ध में मुहम्मद साहब ने लिखा है—

“दान देना प्रत्येक मुसलमान का धर्म है । जिसके पास दान देने के लिए कुछ नहीं, उसे चाहिए कि वह दूसरों के साथ भलाई करे और दुराई से अलग रहे । यही दान है ।

“भूखों को भोजन दो, रोगियों की सेवा करो । आपत्ति-ग्रस्त व्यक्ति की (चाहे वह मुसलमान हो या शैर-मुसलमान) मदद करो ।”

सहनशीलता की भावना के सवध में मुहम्मद साहब का आदेश है—

“पूरा मुसलमान वही है जिसके वचन और कर्म से मानव-जाति सुरक्षित रहे । सावधान रहो ! वह मुसलमान नहीं जो व्यवहार करता है, चारों करता है, मदिरा-पान करता है या जो किसी के धन का अपहरण करता है ।”

“जो एहंस्वरवादी है और जो परलोक में विश्वास करता है, उसे अपने पड़ोसियों को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए ।”

“यदि तुम सृष्टि-रक्षयिता को प्रेम करते हो, तो पहले अपने सहयोगियों को प्रेम करो ।”

“ईश्वर उसके लिए दयालु नहीं जो मानव-जाति के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करता ।”

भारत में पुर्तगाल देशवासी व्यापार के लिए आये, तब उन्होंने यह ईसाई-धर्म का सूत्रपात किया। बाद में यहाँ ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राज्य उसके शासको द्वारा फैलाया जाने लगा और अंग्रेजी राज्य की स्थापना होजाने के बाद तो राजसत्ता की सहायता से यहाँ ईसाई-धर्म का जोर से प्रचार किया गया। फलस्वरूप भारत में एक नया सम्प्रदाय पैदा हो गया जो 'इण्डियन क्रिश्चियन' कहलाता है। आजतक भारत में यूरोप और अमरीका के विदेशी मिशन ईसाई धर्म का प्रचार करते आ रहे हैं। नगर-नगर में ईसाई और उनके पादरी और गिरजे दिखायी देते हैं। आरण्यक जातियों (जैसे भील, गोड, सयाल, कोल आदि) में ईसाई धर्म-प्रचारको के विशेषरूप से केन्द्र बने हुए हैं, और उनमें नियमित रूप से प्रचार हो रहा है। ईसाई पादरी व प्रचारक शिक्षा, चिकित्सा आदि अनेक प्रकार से प्रलोभन भी देते हैं। सन् १९३१ में भारत में ईसाइयों की आबादी ६२ लाख ९७ हजार ७ थी।

पारसी धर्म

ईसा से पूर्व ८ वीं सदी में फारस में पारसी मत की स्थापना हुई। जरथुस्त्र ने इस धर्म की प्रतिष्ठा की। यह फारस का राष्ट्रीय धर्म था। और समस्त फारस में इस धर्म के अनुयायी थे। परन्तु जब सन् ५३७ में मुसलमानों ने फारस पर आक्रमण किया तो उन्होंने बहुत-से पारसियों को मुसलमान बना लिया। जरथुस्त्र के कुछ अनुयायी भारत में आकर बस गये। अब इस सम्प्रदाय के लोग केवल भारत में ही मिलते हैं। पारसी धर्म का आधार नीति-शास्त्र है। ये अहिंसा, दान, पवित्रता और परोत्कार में पूरा विश्वास रखते हैं। ये अग्निपूजक हैं। तपस्या और तास्वी जीवन के लिए पारसी धर्म में कोई स्थान नहीं है। इनकी धर्म-पुस्तक 'अवेस्ता' है। पारसियों में कोई जाति-भेद नहीं है। वे धर्मन्यत और प्रचार में विश्वास नहीं करने। पारसियों में विद्या वैभव और विद्वत्ता अधिक है। पारसी अधिकांश में बम्बई प्रान्त में हैं। भारत में इनकी संख्या ११ लाख के लगभग है।

ता पर या नगता है एक वैश्य क्षत्रिय वन सत्ता है । यदि ब्राह्मण में उसके वर्ण के अनुसार गुण-कर्म न हो तो वह गिर जाता है ।

(१) ब्राह्मण के कर्तव्य—वेद-शास्त्रों तथा समस्त ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन करना, उसी जनता को शिक्षा देना, शुभ कर्म करना, यज्ञ यज्ञ कराना, समाज को विद्यादि श्रेष्ठ गुणों का दान देना और गृहस्थों से अपनी जीविका के लिए दान-दक्षिणा प्राप्त करना । गीता के अनुसार ब्राह्मण में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है—शम, दम, तप, मोक्ष, धर्मा, निरभिमान, ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिकता ।

(२) क्षत्रिय के कर्तव्य—वेद-शास्त्रों का अध्ययन, यज्ञ तथा शुभ कर्म करना, मुग्धों को दात तथा प्रजा को अभयदान, प्रजा की रक्षा, जिनेन्द्रिय रहना, धीरता के काम करना, तेजस्वी होना, आपत्ति के समय धैर्य से काम लेना, सैन्य-विद्या में निपुणता, युद्ध-कौशल, ईश्वर-भक्ति तथा प्रजा को पुत्र के समान मानना ।

(३) वैश्य के कर्तव्य—वेद-शास्त्रों का अध्ययन, यज्ञ करना, दान देना, पशु-पालन, वाणिज्य-व्यापार करना, व्याजलेना तथा कृषि करना ।

(४) शूद्र के कर्तव्य—मनुस्मृति के अनुसार परमेश्वर ने जो विद्याहीन हो जिसको पढ़ने से भी विद्या न आ सके, जो शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो उस शूद्र के लिए अन्य वर्गों की निंदा से रहित प्रीति-पूर्वक सेवा करना यही एक कर्म करने की आज्ञा दी गयी है ।

इन वर्णों का आधार व्यक्ति के गुण, कर्म एवं स्वभाव है—इसके लिए मनुस्मृति का निम्नलिखित प्रमाण दिया जाता है—

“जो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के समान गुण, कर्म स्वभाववाला हो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो जाता है वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ और उसके गुण, कर्म और स्वभाव शूद्र के सदृश हो, तो वह शूद्र हो जाता है ।”

१ शूद्रो ब्राह्मणतानेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाञ्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ मनु० अ० १० श्लोक ६५

उत्प्रेष है तो वह यह निश्चय नहीं। कम्मा कि जातियों धार्मिक सन्ध्याएँ हैं। स्मृतियाँ तो युग विशेष के सामाजिक चित्रों के मन्त्र हैं। उनमें समय-समय पर परिवर्तन होता स्वाभाविक है।

जातियों की उत्पत्ति वस्तुतः हिन्दू-सामाजिक जीवन में अराजकता के फलस्वरूप हुई है। हिन्दू समाज में, जो हजारों उपजातियाँ हैं, वे हिन्दू जन की अन्य विशिष्टताओं से सम्बन्धित हैं। इन विशिष्टताओं में से एक है सम्मिश्रित परिवार।

जाति की तीन मुख्य विशेषताएँ हैं। ये इस प्रकार हैं —

(१) जन्मपरक अपरिवर्तनशील विषमता

इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह आजन्म उसी में गिना जाता है। वह अपनी जाति को बदल नहीं सकता। यदि वह 'महत्तर' के कुल में पैदा हुआ है तो वह चाहे जैसा विद्वान और पण्डित क्यों न हो जाये, उसकी जाति 'महत्तर' ही रहेगी और समाज उसके साथ उभी प्रकार का व्यवहार करेगा।

(२) व्यवसायो व उद्योगों का जाति के आधार पर वर्गीकरण और उनकी विषमता

प्रत्येक जाति के लिए जो व्यवसाय या पेशा निर्धारित है वह उसी को करनी है और अपनी सन्तान को भी वही काम सिखाती है। एक ब्राह्मण कहलानेवाला व्यक्ति पुरोहित का काम करके अपनी जीविका कमाना है, वह आने पुत्र को भी वही काम सिखाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सफाई का काम करता है, वह अपनी सन्तान से भी वही काम कराता है।

(३) विवाह-सम्बन्ध तथा खानपान —

जाति की तीसरी विशेषता यह है कि वह विवाह-सम्बन्ध तथा खानपान अपनी ही जाति तक परिमित रखती है। इस प्रकार जाति रक्त की पवित्रता पर अधिक जोर देती है।

वह कोई दैवी विधान नहीं है जिसे ईश्वर ने हमपर लाद दिया हो। इस प्रकार यह भावना जाग्रत होती जा रही है कि मनुष्य ही समाज-व्यवस्था के निर्माता है।

कुटुम्ब का प्रयोजन

‘कुटुम्ब’ वह छोटे-से-छोटा मानव-समुदाय है जिसमें केवल पति-पत्नी और उनकी सन्तान ही अतः विवाह के बाद ही कुटुम्ब का प्रादुर्भाव होता है।

कुटुम्ब मानव के जन्म के साथ ही पैदा हुआ और आज भी वह विद्यमान है। वास्तव में कुटुम्ब उतना ही प्राचीन है जितनी कि मानव-जाति। मानव के कुटुम्बिक जीवा का समाज से गहरा सम्बन्ध है। वास्तव में मानव-सभ्यता का आधार कुटुम्ब ही है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि कुटुम्ब के नाश होने ही मानव सभ्यता भी नष्ट होकर फिर उसी वर्णर दशा को प्राप्त हो जायेगी। विवाह, उत्तराधिकार, दत्त-विधान आदि सबका कुटुम्ब से सम्बन्ध है। कुटुम्ब और विशेष रूप से संयुक्त कुटुम्ब का आय-संस्कृति में बड़ा महत्त्व है।

भारतवर्ष में प्रारम्भ से ही संयुक्त कुटुम्ब-प्रथा पायी जाती है। भारत के अधिकांश में पितृकुल ही है। दक्षिण में कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जिनमें मातृकुल भी पाये जाते हैं। कुटुम्ब-प्रथा के पीछे दो विचार प्रमुख हैं—स्त्रियाँ पवित्र और साध्वी रहे और उत्तराधिकार का नियंत्रण पुरुषों के हाथ में हो। जबतक समाज में इन दोनों विचारों का आदर होता रहेगा, तबतक कुटुम्ब कायम रहेगा।

संयुक्त-कुटुम्ब-प्रथा

संयुक्त-कुटुम्ब की प्रथा बहुत प्राचीन है। इसमें पति, पत्नी पिता, माता, पितामह, पितामही, बहन, भाई पुत्र पुत्री, दत्तक पुत्र आदि शामिल हैं। कुटुम्ब के विशेष नियम होते हैं। इन्हें कुलाचार कहते हैं। जन्मोत्सव, उपनयन, विवाह, खान-पान, सामाजिक रीति-रिवाज, उत्तराधिकार और

सदाचार आदि उन कुलानारों ही पर निर्भर होते हैं। सयुक्त-कुटुम्ब में गृहपति का स्थान सर्वोच्च है और गृहिणी उसके अधीन रहती है।

हिन्दू-विभाग के अनुसार आजकल कुटुम्ब के निम्नलिखित सदस्यों को सम्पत्ति के अधिकार विरागत मानिये हैं—

(१) पुत्र (२) पौत्र (३) प्रपञ्च (४) पत्नी (५) पुत्री (६) नाती (धेनू) (७) मा (८) पिता (९) भ्राता (१०) भतीजा आदि। दाम्भग-कानून के अनुसार बग़ाज में यदि कोई हिन्दू किसी भी सम्पत्ति को छोड़कर मर जाये या मित्ताक्षरा कानून के अनुसार कोई हिन्दू अपनी पृथक् सम्पत्ति छोड़कर मर जाये तो उसकी एक या सय विधवा स्त्रियों को मिलकर उसके पुत्र के बराबर भाग मिलेगा। परन्तु उसका या उनका सम्पत्ति पर वैसा अधिकार न होगा जैसा स्त्री-धन पर होता है।

सयुक्त कुटुम्ब में स्त्री-पुरुष के अधिकार

सयुक्त-कुटुम्ब में पुरुष को कुटुम्ब में सबसे अधिक अधिकार प्राप्त है। पुत्र का जन्म पिता की आधी सम्पत्ति पर अधिकार होता है। वह उसे अपने पिता के जीवन में विभाजित करा सकता है। जबतक वह जीविकोपार्जन के योग्य नहीं हो जाता तबतक पिता से उसे भरण-पोषण का अधिकार है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या अर्जित सम्पूर्ण सम्पत्ति पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। वह उसे वसीयत में दे सकता है, बेच सकता है या रहन रह्य सकता है। उसे सम्पत्ति ऋण करने का भी अधिकार है। वह उसे दान अथवा दहेज में दे सकता है। उसके अधिकार पर बन्धन नहीं है। परन्तु यदि उसके कोई पुत्र है तो उसे उसके अधिकार पर आघात करने का अधिकार नहीं है। यदि पुत्र के आधे हिस्से को उसने भ्रष्ट कर दिया या उसे अनावश्यक ढंग से खर्च किया तो पुत्र को उसे पुन प्राप्त करने का अधिकार है। पुरुष, सक्षेप में गृहस्वामी है। वह वास्तविक अर्थ में गृह का स्वामी है, स्त्री गृह-स्वामिनी है। परन्तु उसके गृह में अधिकार बहुत सीमित है। कुटुम्ब में स्त्रियों में केवल निम्नलिखित स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकार प्राप्त हैं—

(१) विधवा पत्नी (२) पुत्र की विधवा पत्नी (३) पौत्र की विधवा पत्नी (४) पुत्री (५) मा (६) पितामही (७) बहन (८) पौत्री (९) पुत्र की पुत्री ।

स्त्रियों के सम्पत्त्याधिकार दो प्रकार के हैं । एक को हम स्त्री-अधिकार (Woman's Estate) कहते हैं और दूसरे को स्त्री-धन । पुरुष से जो सम्पत्ति विरासत में प्राप्त होती है, वह स्त्री-अधिकार है । उस सम्पत्ति को केवल भोगने का ही उसे अधिकार है । उस पर उसका पूर्ण स्वामित्व नहीं होता ।

स्त्री-धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार होता है । यहाँ स्त्री-धन का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया है । विशिष्ट स्त्री-धन में निम्नलिखित सम्पत्ति सम्मिलित हैं—

- १ सम्बन्धियों से प्राप्त दान या वसीयत ।
- २ वस्त्राभूषण ।
- ३ विवाह-संस्कार के अवसर पर या उससे पूर्व अन्य पुरुषों से प्राप्त दान ।
- ४ गैर सम्बन्धियों से प्राप्त दान ।
- ५ कुमारावस्था या विधवावस्था में कला-कौशल द्वारा अर्जित सम्पत्ति ।
- ६ बम्बई प्रान्त में जो सम्पत्ति स्त्री अपने पितृ-कुल में वसीयत में प्राप्त करती है, वह चाहे पुरुष से प्राप्त की गयी हो या स्त्री से, स्त्री-धन है ।
- ७ वृत्ति के बदले में मिली सम्पत्ति ।
- ८ विपरीत कब्जे द्वारा प्राप्त सम्पत्ति ।
- ९ ग्राट, दान, समझौते या विभाजन द्वारा प्राप्त सम्पत्ति, यदि दाता का उद्देश्य स्त्री को पूर्ण अधिकार देने का हो ।
- १० स्त्री-धन द्वारा क्रय की हुई सम्पत्ति ।

पुत्रियों के पालन-पोषण का भार कुटुम्ब पर होता है । सपुत्र कुटुम्ब के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्रों के पालन-पोषण, उपनयन-संस्कार तथा विवाह का भार भी कुटुम्ब पर होता है । पुत्रियों व बहनों का विवाह भी कुटुम्ब

कामकाय में लगे रहने से पति को कामकाय में बाध पड़ती है। उससे पति को कामकाय में बाध पड़ती है। पति को कामकाय में बाध पड़ती है। पति को कामकाय में बाध पड़ती है।

पति को कामकाय में बाध पड़ती है। पति को कामकाय में बाध पड़ती है। पति को कामकाय में बाध पड़ती है। पति को कामकाय में बाध पड़ती है। पति को कामकाय में बाध पड़ती है।

हिन्दू पति को बहुत-सी बाधा पड़ती है। वह एक ही समय में एक ही कामकाय में बाध पड़ती है। वह एक ही समय में एक ही कामकाय में बाध पड़ती है। वह एक ही समय में एक ही कामकाय में बाध पड़ती है। वह एक ही समय में एक ही कामकाय में बाध पड़ती है।

हिन्दू-समाज में बाध-विवाह का भी अधिक प्रचार है। यद्यपि सन्

१. ब्रह्म-देश में पति को विवाहोपरान्त ससुराल में रहना पड़ता है। पत्नी बाहर जीविकोपार्जन करती है, बाजारों में दूकान पर बैठती है और पति गृह के काम-काज करते हैं।

समुक्त कुटुम्ब-प्रथा का भविष्य

हिंदू जीवन-प्रथा का रचनात्मक विकास के लिये बाह्य प्रभाव पड़ा है। पारंपारिक स्था में समाज कुटुम्ब की प्रथा नहीं है। यहाँ कुटुम्ब में पति-पत्नी होते हैं जो-अपने-अपने पुत्रों व पुत्रियों का विवाह नहीं होता। अतः वे भी उनके साथ रहते हैं। बाद में वे अलग रहते हैं। पारंपारिक देवा-यज्ञ-विशेष-समाज-संरचना की भाँति के कारण समुक्त कुटुम्ब का विकास नहीं है। आज भारत में नवीन सम्प्रदाय के उद्भव के कारण और युवाओं भी समाज-जीवन-विधानों के लिए समुक्त-कुटुम्ब या त्याग कर रहे हैं। वह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। देश में औद्योगिक जीवन और औद्योगिकरण का भी समुक्त कुटुम्ब पर प्रभाव पड़ रहा है।

यह जीवन-निर्वाह की समस्या इतनी जटिल हो गयी है कि एक व्यक्ति बड़े-बड़े कुटुम्ब का पालन करने में असमर्थ-सा रहता है। गाँवों के लोग शहरों में जाकर बस जाते हैं और मिलों तथा कारखानों में मजदूरी करते हैं। शहरों में जीवन बिताना पड़ा हीमती पड़ता है। इसलिए ये मजदूर ग्राम से अकेले जाते हैं या अपनी स्त्री-बच्चों को साथ ले आते हैं। इस प्रकार समुक्त कुटुम्ब की प्रथा टूटती जा रही है।

आश्रम-व्यवस्था

पुराने समय में भारतीय ऋषियों ने जिस प्रकार सामाजिक जीवन को चार वर्णों में बाँटा था, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन को भी चार आश्रमों में बाँटा हुआ था। मनुष्य की औसत आयु १०० वर्ष मानी गयी है। इसीके आधार पर मानव-जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया था—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबसे पहले २५ वर्ष तक मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद विवाह करके अपनी सहधर्मिणी के साथ समाज-सेवा में रत रहना चाहिए। ५० वर्ष की आयु तक गृहस्थ-जीवन बिताना चाहिए। बाद में वानप्रस्थी बनकर वन में योग-साधन और स्वाध्याय करना चाहिए।

इसकी अवधि ७५ वर्ष की आयु तक है। इसके बाद १०० वर्ष अर्थात् मृत्यु पर्यन्त सन्यासी रहना चाहिए।

परन्तु आज वर्ण-व्यवस्था के साथ यह आश्रम-व्यवस्था भी नष्ट हो-
चुकी है। आज का हिन्दू-जीवन वैदिक-जीवन नहीं रहा। उसमें मौलिक
परिवर्तन हो गया है। आज सिवा आर्य-समाज के गुरुकुलो के और कहीं
'ब्रह्मचारी' नहीं मिलेंगे। गुरुकुलो में २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन
कर वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है।

सन्यासियों का हिन्दू-समाज में बड़ा महत्त्व है। उनकी बड़ी 'पूजा'
की जाती है। आज भारत में ५२ लाख से भी ज्यादा साधु और सन्त
हैं जो हिन्दू गृहस्थों के ७१ करोड़ से भी अधिक रुपये प्रतिवर्ष खाने-पीने,
नशे, कपड़े-लत्ते और भोग-विलास में व्यय करते हैं। जिस देश में रात-
दिन मेहनत करनेवाले मजदूर दो वक्त मामूली खाना भी नहीं खा सकते,
उस देश में भारत के २३६ करोड़ हिन्दुओं के पत्नी की कमाई पर
५२ लाख साधु महन्त और सन्तों का खाना, पीना और मौज उड़ाना
हिन्दू-समाज की अध-श्रद्धा का एक ज्वलन्त प्रमाण है।

अस्पृश्यता

'अस्पृश्यता' हिन्दू-धर्म का महान् पाप है, उसपर लगी हुई जग है।
अत्यजों का तिरस्कार करना मनुष्यता को खोदेना है।^१

'अस्पृश्यता' नाम का रोग हिन्दू-समाज की ही एक विशेषता है। हिन्दू-
शास्त्रों में छुआछूत पर धार्मिक आवरण डाल दिया जाने से वह बढ्मूल
हो गया है। यह वास्तव में एक महान् सामाजिक पाप है जो हिन्दुओं ने
अपने ही धर्म-वन्दुओं के साथ किया है। किसी वर्ग को अस्पृश्य घोषित
करदेना वास्तव में मानवता का अमान ही है। आज भारत में ३
करोड़ से भी अधिक हिन्दू नर-नारी अस्पृश्यता के जमिशाप का दुख
भोग रहे हैं। उन्हें हिन्दू समाज में रहने हुए न धार्मिक अधिकार हैं, न

सामाजिक अधिकार और न नागरिक अधिकार ही प्राप्त हैं। वे अपने नाम पर ही के साथजीवित खास, पम्पास, स्कूल, मन्दिरों, नदी, गलियानों का प्रयोग करता है नहीं कर सकते।

महात्मा गांधी ने सबसे पहले हिन्दू-समाज के इस पाप के विरुद्ध सन् १९३२ में देशवासियों को आशोधित किया। उनका पूरा भी आर्थिकसमाज के प्रतिष्ठित नेता रामजी रामानन्द ने शक्ति-आशोधित और पञ्चायत के प्रतिष्ठित नेता आचार्य अत्रेय ने अन्तर्द्वारा-आन्दोलन शुरू किया। अपने समय में इन आन्दोलनों को एक सीमा तक सफलता भी मिली। परन्तु महात्मा गांधी ने जो आन्दोलन सन् १९३२ में 'साम्प्रदायिक निर्णय' के विरोध में यरवदा-जेल में बन्दी की दशा में शुरू किया, वह कई दृष्टियों में सबसे महत्त्वपूर्ण है।

महात्माजी ने सबसे गहरा प्रहार अस्पृश्यता की धार्मिकता पर किया। उन्होंने ससार और हिन्दू-समाज को यह चुनौती दी कि वह यह सिद्ध करे कि वेदों या शास्त्रों में अस्पृश्यता का विधान है। उन्होंने यह घोषणा की कि अस्पृश्यता धार्मिक नहीं है। वह एक सामाजिक कोड है। उसका निर्माण समाज ने किया है अतः उसका नाश भी समाज के उद्योग से ही सरता है।

साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध में जब गांधीजी ने यरवदा-जेल में जामरफ्त जनशक्ति रखा तब २५ सितम्बर १९३२ को बम्बई में सनातन हिन्दू-धर्म के महान् नेता पं० मदनमोहन मालवीय के सनापतित्व में हिन्दुओं और हिन्दू नेताओं ने सर्व-सम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया—

“यह सम्मेलन यह निश्चय करता है कि भविष्य में हिन्दुओं में कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण अछूत नहीं माना जायेगा और अबतक जो ऐसे माने गये हैं, उन्हें सार्वजनिक कुओं, स्कूलों, सड़कों, और समस्त सार्वजनिक संस्थाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में दूसरे हिन्दुओं के समान अधिकार होगा। प्रथम सुयोग प्राप्त होने पर इस अधिकार को कानूनी स्वीकृति दी जायेगी। यदि पहले से ही इसे कानूनी स्वीकृति नहीं मिली, तो यह स्वराज्य पालमेण्ट के प्रथम कानूनों में से एक होगा।”

“और यह भी निश्चय किया गया है कि सम्प्रदाय हिन्दू-नेताओं ने यह कर्तव्य होगा कि वे मन्दिर शान्तिमय और वे उपायों द्वारा दलित वर्ग पर हमला नहीं करेंगे मन्दिर सामाजिक जयोंगताओं और मन्दिर-प्रवेश सम्बन्ध में प्रतिक्रिया के निवारण के लिए शीघ्र प्रयास करें।”

इस प्रस्ताव द्वारा मन्दिर हिन्दू-नेताओं ने यह घोषणा की कि भविष्य में कोई भी हिन्दू जन जन्म के कारण अशुभ माना जाएगा और साथ ही इस प्रस्ताव के दूसरे भाग द्वारा यह निश्चय किया गया कि दलित वर्ग पर जो सामाजिक प्रतिष्ठा तथा मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में जो हानि है, उसे ‘शान्तिमय तथा वैय’ उपायों द्वारा शीघ्र दूर करने का प्रयत्न किया जाये। शान्तिमय तथा वैय उपायों के अन्तर्गत मन्दिर-सभा द्वारा कानून-निर्माण भी शामिल है। इस प्रकार इन जयोंगताओं के निवारण तथा मन्दिर-प्रवेश की मुविधा देने के लिए केन्द्रीय मन्दिर-सभा तथा प्रांतीय धारा-सभाओं का उपयोग किया जाना उचित है।

‘हरिजन नाम देकर हरिजन-सेवा, यदि देशव्यापी आन्दोलन के सूत्रधार महात्मा गांधी हैं।

‘हरिजन-सेवक-संघ’ नाम की एक अखिल भारतीय संस्था का कार्य ही इन अधिकार-वर्चित हिन्दुओं की तरह-तरह से सेवा करना तथा छुआछूत को मिटाना है, इसी शालाओं के रूप में प्रत्येक प्रान्त में हरिजन सेवक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं।

मुस्लिम जीवन

हिन्दू और मुस्लिम सामाजिक जीवन में स्पष्ट अन्तर दिखायी देता है। मुसलमानों की आदर्श समाज-व्यवस्था का मूलधार सामाजिक एकता की भावना है। मुस्लिम समाज में प्रत्येक मुसलमान बराबर है। यद्यपि मुसलमानों में हिन्दू-समाज-जैसी ३००० से भी ऊपर जातियाँ और अगणित उपजातियाँ नहीं हैं, तो भी मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो बड़े सम्प्रदाय हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक सम्प्रदाय और जातियाँ हैं। उत्तराधिकार, विरासत, वसीयत, विवाह, वक्फ आदि के सम्बन्ध में

मुसलमानों की व्यवस्था मुसलिम कानून के अनुसार होती है। मुसलमानों के हिन्दू समुक्तकुटुम्ब-प्रथा जैसी कोई सस्था नहीं है। सम्मिलित रहने से वे सम्मिलित कुटुम्ब नहीं कहला सकते।

उत्तराधिकार

मुसलमानों में दो सम्प्रदाय प्रमुख हैं और उन दोनों के कानून भी भिन्न-भिन्न हैं। हनाफी-कानून (सुन्नी-कानून) के अन्तर्गत उत्तराधिकारी तीन श्रेणियों में विभाजित हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के हिस्से कानून द्वारा निर्धारित हैं जो निम्न प्रकार हैं—

(१) पिता (२) पितामह (३) पति (४) पत्नी (५) मा (६) पितामही (७) पुत्री (८) पौत्री (९) सहोदर भ्राता (१०) सहोदर भ्राता की पत्नी इत्यादि।

इन सबके हिस्से निर्धारित हैं। इनको देने के बाद दूसरी श्रेणी के उत्तराधिकारियों को हिस्सा मिलता है। पुत्र और पौत्र दूसरी श्रेणी में आते हैं। परन्तु व्यवस्था इसप्रकार की गयी है कि पुत्र व पौत्रों के लिए अपनी हिस्सा बच रहता है। शिया-कानून के अनुसार उत्तराधिकारियों को ३ भागों में बांटा गया है—प्रथम श्रेणी में रक्त-सम्बन्ध रखनेवाले वारिस आते हैं जैसे माता-पिता और उनकी सन्तान, पितामह और पितामही तथा भाई और बहन और उनकी सन्तान, चाचा तथा मामा और उनकी सन्तान, पितामह और पितामही तथा भाई और बहन और उनकी सन्तान, चाचा तथा मामा और उनकी सन्तान, पति-पत्नी विवाह-सम्बन्ध उत्तराधिकारी हैं। मुसलमानों का उत्तराधिकार कानून इतना जटिल और पेचीदा है कि उसे समझना एक समस्या है।

सम्पत्त्याधिकार की दृष्टि से मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति हिन्दू-महिलाओं से कहीं उत्तम और श्रेष्ठ है। मुस्लिम महिलाओं को अपने हिस्से का पूर्ण अधिकार होता है। मुसलमान अपनी सम्पत्ति को वसीयत में दे सकते हैं। परन्तु किसी वारिस के नाम वसीयत उस समय तक नहीं मानी जाती जबतक कि वसीयत करनेवाले की मृत्यु के बाद

दूसरे वारिस अपनी सम्पत्ति न देदे। मुसलमान एक तिहाई से अधिक सम्पत्ति वसीयत द्वारा नहीं दे सकता। यह एक-तिहाई भाग क्रिया-कर्म के खर्च तथा कर्जों को अदा करने के बाद जो बचे उसका हिस्सा माना जाता है। मुसलमान को अपनी सम्पत्ति दान करने का अधिकार है। वह अपनी सारी सम्पत्ति अपने वारिस को भी दान कर सकता है।

विवाह

विवाह को मुसलमानों में धार्मिक सस्कार नहीं माना जाता। वह केवल एक समझौता है जिसका उद्देश्य सन्तानोत्पादन और वच्चों को कानूनी अधिकार-युक्त बनाना है। मुसलमानों में विवाह १५ वर्ष की आयु में किया जा सकता है। परन्तु यदि किसीका विवाह उसकी सम्पत्ति के बिना किया जाये और विवाह के समय उसकी उम्र १५ वर्ष की हो तथा दिमाग भी सही हो, तो ऐसा विवाह अवैध होगा। विवाह के लिए एक पक्ष की ओर से प्रस्ताव होना चाहिए और दूसरे पक्ष द्वारा उसे स्वीकृति दी जानी चाहिए। यह कार्य दो साक्षियों के सामने होना चाहिए। प्रस्ताव और उसकी मजूरी एक ही मिलन में होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव एक बार किया गया हो और उसकी स्वीकृति एक या दो दिन बाद दी जाये तो यह उचित नहीं। विवाह के लिए किसी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक कृत्य की आवश्यकता नहीं है। एक मुसलमान एक समय में एक साथ चार पत्नियाँ तक रख सकता है। मुसलमान अपनी मा, माता-मही, पुत्री, पौत्री, प्रपौत्री, बहन, चाची तथा मामी के साथ विवाह नहीं कर सकता। वह अपनी सास, अपनी पत्नी की पुत्री, अपने पिता की स्त्री या अपने पुत्र की वधू से भी विवाह नहीं कर सकता। परन्तु दो भाइयों या बहनो की सन्तानों में परस्पर विवाह हो सकता है।

शिया-कानून दो प्रकार के विवाहों को स्वीकार करता है, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। एक मुसलमान पुरुष मुस्लिम, ईसाई, यहूदी या पारसी स्त्री के साथ अस्थायी विवाह कर सकता है। परन्तु शिया स्त्री किसी गैर-मुस्लिम पुरुष से अस्थायी विवाह नहीं कर सकती। यह अस्थायी विवाह क्या है? अस्थायी विवाह के लिए यह जरूरी है कि

पहलम की अर्थात् निरा कर दी जाये—यह एक दिन, एक मास या एक साल या अधिक समय के लिए हो जाती है और दूसरी बात यह है कि महर निर्धारित कर दिया जाये। अतः महर निर्धारित नहीं किया जाये तब तक अस्वायी विवाह बंध नहीं हो सकता।

प्रत्येक मुस्लिम स्त्री को विवाह के समय निर्धारित दहेज (Dower) वर की ओर से भेंट किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। एक तो मुद्दागरान में पूर्व देना होता है और दूसरा तलाक या मृत्यु के समय उसके वारिस को देना पड़ता है।

तलाक

मुसलमानों में तलाक की प्रथा है। विवाह-मन्वन्ध-विच्छेद तीन प्रकार से हो सकता है—

(१) पति-द्वारा अपनी इच्छानुसार,

(२) पति-पत्नी की परस्पर सम्मति से,

(३) पति या पत्नी की प्रार्थना पर न्यायालय के निर्णय से।

मुस्लिम पति को जिसका दिमाग सही है तथा जिसकी उम्र १५ साल की है अपनी पत्नी को अपनी इच्छा से बिना कोई कारण बतलाये तलाक देने का अधिकार है।^१ यह वास्तव में स्वेच्छा की पराकाष्ठा है।

पति-पत्नी परस्पर सम्मति से तलाक दे सकते हैं। परन्तु पत्नी को अपनी ओर से तलाक देने का अधिकार केवल निम्न-लिखित दशाओं में ही प्राप्त है। वे दशाएँ निम्न प्रकार हैं—

(१) पति की नपुंसकता, परन्तु नपुंसकता विवाह के समय होनी चाहिए और उसके बाद भी बराबर रही हो और तब उसे उसका ज्ञान न हो।

(२) यदि पति ने पत्नी पर व्यभिचार का मिथ्या दोषारोपण किया हो।

मुस्लिम स्त्री केवल उपर्युक्त दो आधारों पर ही तलाक़ के लिए न्यायालय से प्रार्थना कर सकती है ।

यदि उसका पति व्यभिचार करता है, उपपत्नी रखता है, या उसकी परवरिश नहीं करता है, तो भी पत्नी के लिए विवाह-सम्बन्ध को तोड़ने का अधिकार नहीं है । इस सम्बन्ध में मुस्लिम स्त्री का भाग्य ऐसा नहीं है कि हिन्दू महिला उससे ईर्ष्या करे ।

मुस्लिम महिलाओं में परदे की बड़ी भयंकर कुप्रथा है । इन परदे की प्रथा ने स्त्रियों को विलास की सामग्री बना दिया है । परदे की प्रथा के कारण न स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार व प्रसार हो सकता है और न वे सामाजिक या राजनीतिक आन्दोलन में पुरुषों का हाथ बँटा सकती हैं ।

विवाहों के अवसरों पर दहेजों का रिवाज भी मुसलमानों में बहुत अधिक है ।

मुसलमानों में हिन्दू-समाज की तरह जाति-भेद भी है । जो लोग मुसलमान बनाये जाते हैं, वे अक्सर हिन्दुओं के दलितवर्ग के व्यक्ति ही होते हैं । वे मुसलमान होकर भी मुस्लिम-समाज में 'दलित' ही बने रहते हैं । उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता ।

ईसाई, पारसी आदि जीवनों का यद्यपि भारतवर्ष में अस्तित्व है, जिसका परिचय धार्मिक जीवन में दिया गया है । पर उनका भारतीय संस्कृति में कोई विशेष स्थान नहीं है ।

: १३ :

नागरिकों का स्वास्थ्य

गुणपूर्वक जीवनयापन के लिए स्वास्थ्य अत्यन्त आवश्यक है। यह लोकोक्ति पसिद्ध है कि 'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है।' हममें से प्रत्येक अपने अनुभव में यह जानता है कि यदि हमारे शरीर में कोई कष्ट और पीड़ा हो तो उसका हमारे चित्त और मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है, वह चिन्तन और दुःखी रहता है।

भारतवर्ष में जनता में स्वास्थ्य के प्रति बड़ी उपेक्षा की भावना देखी जाती है। जनता मुन्दर स्वाम्य का न मूल्य समझती है और न आवश्यकता। फिर उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करना तो दूर रहा। यही कारण है कि हमारे देश में जन्म और मृत्यु की औसत संख्या अन्य देशों से बहुत बड़ी-बड़ी है। जल-मृत्यु तथा प्रसूताओं की भीषण मृत्यु-संख्या बड़ी भयानक है और हृदय की कैंपा देनेवाली है।

स्त्री-पुरुषों की मृत्यु संख्या का अनुपात

मृत्यु-संख्या का अनुपात प्रति १०० जन्म इस प्रकार है—

आयु	बालक	बालिकाएँ
०	२४८७	२००१
१	९१८	८६५
२	५६४	५०६
३	३९२	३४०
४	२७८	२३३
५	१९३	१६५
६	१४५	१२५
७	११५	१०१
८	९४	८८
९	८३	८२

सन्	जन्म	अनुपात प्रति १०००	मृत्यु	अनुपात प्रति १०००
१९३१	९१,३५,८९०	३८३	५५,१५,८००	२८९०
१९३२	९०,५८,५०६	३८३	५८,०५,६५०	२६८५
१९३३	९६,३८,८३६	३६८	६०,०६,३८३	२२९५
१९३४	८२,८८,८९०	३३३	६८,५६,२८८	२३००
१९३५	९६,९८,३९८	३६९	६५,३८,३९८	२३६

उपर्युक्त १० वर्ष की मृत्यु और जन-संख्या के अंतर पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जन्म और मृत्यु-संख्या में मोक्षति होती रही है।

सन् १९३० की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति १००० जन्म पीछे १८०-८३ वालका-वालिकाओं की मृत्यु का अनुपात है। इन वर्षों में इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। भारत में बाल-मृत्यु अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही अधिक है। नगरों में और विशेषतः बड़े-बड़े नगरों में मृत्यु का अनुपात तो और भी अधिक है। ५ वर्ष तक की आयु के बालकों की मृत्यु दर एक लाख जन्म पीछे ४५ हजार है।

भारत की जन-संख्या में वृद्धि

भारत की जन-संख्या में उत्तरात्तर वृद्धि होती जा रही है। जन-संख्या की वृद्धि के सम्बन्ध में निम्नलिखित अंकों से इस वृद्धि का अनुमान ज्ञात हो जायेगा —

सन्	भारत की जन-संख्या	वृद्धि की दर
१८९१	२८,७३,१४,६७१	
१९००	२९,४३,६१,०५२ +	७०,४६,३८५
१९११	३१,५१,५६,३९६ +	२,०७,९५,३४
१९२१	३१,८९,८२,४८० +	३८,३६,०८०
१९३१	३५,२८,३७,७७८ +	३,३८,५५,२९८

इस वर्ष (१९४१ में) जो मनुष्य-गणना हुई है, उसके अनुसार भारत की जन-संख्या प्रायः ४० करोड़ हो गयी है। इस प्रकार १०

वर्षों में प्रायः ५ करोड़ जन-संख्या की वृद्धि हुई।

जन-संख्या में यह वृद्धि वास्तव में एक बड़ी विकट समस्या है। भारत में भीषण दरिद्रता की छाया में जनता की संख्या में वृद्धि वास्तव में एक ऐसी समस्या है जो समाज-शास्त्रियों के लिए एक आश्चर्य है। भारत में इतने भीषण रोगों, भयंकर बीमारियों तथा बालमृत्यु-संख्या के बावजूद भी यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है और यदि उन्नीस वषों में संख्या में वृद्धि होती रही तो इन बढती हुई संख्या के पालन पोषण की समस्या बड़ा विकट रूप धारण कर लेगी।

प्रसूति-काल में मृत्यु

भारत में बहुत छोटी आयु में विवाह हो जाने से स्त्रियाँ छोटी आयु में ही गर्भधारण करने लगती हैं। शारीरिक अवस्था भी गर्भधारण के पूर्णतः अयोग्य होती है इसलिए यहाँ प्रसूति-काल में ही माताएँ रोगिणी बन जाती हैं और अन्तिम ही मृत्यु के मुख में चली जाती हैं।

बालमृत्यु-संख्या अकल्पनीय रूप से यह गंभीरता प्रमाणित हो जाती है कि १६ वर्ष की अवस्था तक बालिकाओं की अपेक्षा बाढ़ों की मृत्यु अधिक संख्या में होती है। परन्तु इस आयु के बाद जब वे गर्भधारण करने लगती हैं तो उनकी मृत्युसंख्या का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा बढ़ जाता है। १५ से ४० वर्ष की अवस्था में स्त्रियों की मृत्यु अधिक होती देखी गयी है। इसके कई कारण हैं—(१) बाढ़-पिण्ड (२) कम आयु में शरीर की दुर्बल अवस्था में गर्भधारण (३) प्रसूति-काल में दुर्बल अवस्था (४) स्वच्छ वायु, प्रकाश और स्थान का अभाव (५) पोषित भोजन का अभाव।

प्रसूति-काल में माताओं की मृत्यु के संख्या में १९३३ में सर्व जन गणना ने जांच की थी। उनके अनुसार प्रसूताओं की मृत्यु के एक लाख प्रति हजार हैं।

उनका कथन है कि १००० बहिष्ता माताओं में १०० माताओं की मृत्यु तो प्रसूति-काल में ही हो जाती है जो प्राग्जन्य भयंकर

पुरुषों	१०,३००
स्त्रियों	१०,०००
सिखा जा सकने वाले	१०,०००
होने	१०,०००
जीने के लिए पृथक्-पृथक् रोगों के	१०,०००
युवाओं	१०,०००
जैसे रोगों	१०,०००

भारत में राजममा रोग भी इस रूप में फैल रहा है। सरकारी और निजी दोनों ही ओर से धन मिल रहा है और जेडी लिन-लिंगो ने जो रोगों के रोगियों के प्रतिष्ठान के लिए (King Emperor's Anti-Tuberculosis Fund) को स्थापित किया है जिसमें कई लाख रुपये जमा हो चुके हैं। इस तरह के धन से भारत भर में आयुर्विज्ञान-प्रणाली के अनुसार राजममा के रोगियों के लिए चिकित्सालय व स्वास्थ्यालय बनाई जायेंगी। भारत में इस रोग से ५ लाख व्यक्ति मर जाते हैं। यह रोग सब रोगों से भयंकर घातक और सर्वांगिक स्वास्थ्य का महान् शत्रु है। हैजा, प्लेग आदि तो कभी-कभी प्रकोप करते हैं और कुछ समय के बाद शान्त भी हो जाते हैं, परन्तु यक्ष्मा रोग तो जिस गृह में एक बार उसके किसी सदस्य पर आक्रमण करता है, उस गृह का ही सर्वनाश नहीं करता पतंग पड़ोसियों के लिए भी घातक सिद्ध हो जाता है। समाज के—गृह के सबसे उपयोगी और स्वस्थ लोगों पर इसका प्रभाव अधिक होता है। युवक, युवती स्त्रियों, विद्यार्थियों तथा माताओं पर यह भयंकर रोग अपना बड़ा घातक आक्रमण करता है।

भारत के अपाहिज

भारत में दूसरे देशों की अपेक्षा अपाहिजों की भी संख्या बहुत अधिक है। अपाहिजों में पागल, मूंगे-बहरे, अंधे और कोढ़ी सम्मिलित हैं। सन् १९३१ की जन-गणना के अनुसार समस्त भारत में—

सफाई के नियमों के ज्ञान के अभाव में उनके पाठन की आशा करना व्यर्थ है। भारतवर्ष में स्वास्थ्य तथा सफाई के नियमों के प्रचार तथा नागरिकों-द्वारा उनके पाठन करने की बड़ी आवश्यकता है।

नागरिक भावना का अभाव—इसके अतिरिक्त जनता में नागरिक-भावना (Civic Sense) का भी बड़ा अभाव है। गृह-देविया अपने मकान की सफाई करके कूड़ा-ककंट, गोबर, पाखाना, कीचड़ या मूला पानी, लापरवाही के साथ अपने द्वार के सामने धिखेर देती हैं। वे इतना सोचने का कष्ट नहीं उठाती कि यह कूड़ा ककंट पड़ा रहकर कितनी घातक दुर्गन्ध पैदा करता है और रोग के कीटाणुओं को पैदा करता है। स्वच्छता बनाये रखना मुहल्ले के प्रत्येक व्यक्ति का दायर्य है। इस कूड़े-कचरे को कुत्ते, बिल्ली, पशु-पक्षी (जैसे मृगया यदि मुहल्ले में ईसाई या मुसलमानों के घर हों) तितर-बितर करके आर भी गंदगी बढ़ा देते हैं। घर के पास ही बच्चे पाखाना फिरते देखे जाते हैं। रेलवे के डिब्बे तक में इतनी अधिक गंदगी होती है कि वहाँ बैठना कभी-कभी नरक-यात्रा से कम नहीं होता। यात्री लोग अपनी सीट पर बड़े-बड़े ही हाथ-मुँह धोकर पानी रेल के डिब्बे में ही छोड़ देते हैं, पान की पीक से फर्श को गंदा कर देते हैं और धूंकना तो साधारण-सी बात है। रेल के डिब्बे में जो शौचालय होता है, वह भी गंदा रहता है और इसके लिए यात्रा करने-वाले नागरिक ही जिम्मेदार हैं। यह उनकी स्वस्थ के प्रति उपेक्षा पर एक खेदजनक आलोचना है कि वे इन शौचालयों का भी ठीक तरह से प्रयोग करना नहीं जानते।

मेले, उत्सवों, सम्मेलनों या विवाहादि के समारोहों के समय तो और भी अधिक गंदगी के दर्शन होते हैं। भारत में जब हंजा या इन्फ्लुएन्जा शुरु होता है, तब उसका श्रृंगारण हरिद्वार के कुम्भ, इलाहाबाद के गंगा-स्नान, मथुरा के मेलों तथा गढ़मयतेश्वर के स्नान के मेलों से ही होता है। ऐसे अवसरों पर लोग चाहें जिन स्थान पर मल-मूत्र का त्याग करते हैं और ये मल-मूत्र और विशेषतः हंजा के रोगियों के मल-वमन आदि के कीटाणु साथ पदार्थों में मिलकर स्वस्थ लोगों

स्त्रियों का गिरा हुआ स्वास्थ्य तथा मूर्खों दाइयों-द्वारा प्रसव का सम्पादन। वच्चे जनाने का काम ग्रामों और नगरों में शिक्षित तथा गँवार दाइयों द्वारा किया जाता है। वे अपने स्वास्थ्य के नियमों के प्रति अज्ञान के कारण प्रसव के समय शुद्धि का ध्यान नहीं रखती। फलतः प्रसव-काल में स्त्री के गर्भाशय में विष का प्रसार हो जाता है। इस प्रकार प्रसूताएँ रोगी होकर मर जाती हैं। इस कारण कई प्रान्तों की सरकारों ने म्युनिसिपल बोर्डों-द्वारा शिक्षित धानियो (Midwives) तथा परिचारिकाओं (Nurses) की व्यवस्था कर दी है जो प्रसव-क्रिया का सम्पादन करती हैं। प्रत्येक बड़े नगर में स्वास्थ्य-केन्द्र तथा प्रसूता-केन्द्र (Maternity Centers) खुल गये हैं। तो भी इस दिशा में अभी बहुत-कुछ करने की जरूरत है। ग्रामों में भी ऐसी ही व्यवस्था हो जानी चाहिए।

(२) परदा-प्रथा

भारतवर्ष के समुक्तप्रान्त, बिहार, राजस्थान, मध्य-भारत तथा उत्तराखण्ड और कुछ देशी राज्यों में मुसलमानों तथा हिन्दुओं में परदे की प्रथा आज भी प्रचलित है। बंगाल, पंजाब मद्रास, बम्बई, आसाम तथा महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में स्त्रियों में परदे का बिल्कुल प्रचलन नहीं है। भारत में परदे के कारण स्त्रियों को हर समय घर की छतों में बन्द रहना पड़ता है। वे न शुद्ध हवा पा सकती हैं और न शारीरिक श्रम कर अपने स्वास्थ्य को सुधार सकती हैं। परदे के विरुद्ध जबसे आन्दोलन छिड़ा है और जबसे राष्ट्रीय आन्दोलन ने जोर पकड़ा है तबसे इस दिशा में कुछ सुधार हुआ भी है। प्रसन्नता की बात है कि शिक्षित समाज में से परदा विदा होता जा रहा है।

(३) शुद्ध तथा पीठिक खाद्य-पदार्थों का अभाव

अस्वास्थ्य का एक बड़ा प्रमुख कारण है शुद्ध खाद्य-पदार्थों का अभाव। बाजारों के बाजार में प्रायः कोई भी खाद्य वस्तु शुद्ध रूप में नहीं

मिळती। आटा, चावळ, दाल आदि सडे-गले मिलते हैं। मिठाइयाँ मिलावट के घी की, या खराब तेल की होती हैं और दूध आदि तरल पदार्थ शुद्ध नहीं मिलते। जब राष्ट्र के नागरिकों को ये शुद्ध शीष्टिक पदार्थ खाने के लिए न मिलेंगे तो फिर उनका स्वास्थ्य अच्छा कैसे बनेगा ? म्युनिसिपल बोर्डों तथा जिला बोर्डों की ओर से शुद्ध-भोजन में मिलावट के विरुद्ध कानून चलाये गये हैं, परन्तु कर्मचारियों और अविकारियों की उपेक्षा तथा अवहेलना के कारण इनका ठीक-ठीक पालन नहीं हो रहा है।

(४) असयत-जीवन तथा मादक-द्रव्यों का प्रयोग

भारतवर्ष में जीवन को सदाचारी बनाने की ओर दूसरे देशों की अपेक्षा जितना ही अधिक उपदेश दिया जाता है उतना ही कम उस पर आचरण किया जाता है। समाज में व्यभिचार गुप्त व्यभिचार, बलात्कार तथा वेश्या-वृत्ति का चक्र समूचे समाज के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। भारत में बढ़ती हुई दुष्कृतियाँ तथा अपराध इसका स्पष्ट प्रमाण हैं। रहा-सहा स्वास्थ्य मादक-द्रव्यों के प्रयोग द्वारा नष्ट हो रहा है। भारत के नगरों में मिल और कारखानों के पास ही मादक-द्रव्यों की दुकानें हैं जिन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मजदूर लोग ८—१० घण्टे काम करने के बाद अपनी थकावट मिटाने को शराब, ताड़ी या अफीम आदि का सेवन करते हैं। सन् १९३७ में जब ७ प्रान्तों में कांग्रेस ने मद्यित्व-पद-ग्रहण किया, तब महात्मा गांधी की प्रेरणा तथा आदेश से कांग्रेस मद्यियों ने अपने-अपने प्रान्तों में मादक-द्रव्यों के निषेध (Prohibition) के लिए उद्योग किया था। और मद्रास, बम्बई, सयुक्त प्रान्त, बिहार उड़ीसा, व मध्यप्रदेश में शराबबन्दी कुछ चुने हुए विशेष जिलों व नगरों में की गयी थी।

महात्माजी का यह कार्यक्रम था कि ३ वर्षों में समस्त देश में पूर्ण रूप से शराबबन्दी हो जायेगी, परन्तु नवम्बर १९३९ में युद्ध के कारण कांग्रेसी मन्त्री-मण्डल ने पद-त्याग कर दिया और यह कार्य आगे न बढ़ सका। वर्तमान सरकार उसी पुराने कार्य को उसी मर्यादा में कर

रही है। बम्बई की हाईकोर्ट की ओर से जयसे यह निर्णय हुआ है कि गिरावन्दी की व्यवस्था अर्थात् नया बम्बई नगर में पुनः मग्न निषेध व्यवस्था भग हो गयी है।

(५) अस्वास्थ्यप्रद मकान

ग्रामों और नगरों में मकानों का निर्माण बहुत ही अज्ञानिक ढंग से किया जाता है। सम्पत्तिशाली शिक्षित वर्ग के लोग और बम्बई, कलकत्ता अहमदाबाद जैसे नगरों के सेठ-ब्यापारी अपने आराम के लिए तो खुले स्थानों में बंगले तथा कोठियाँ बनवाते हैं, परन्तु उनके कारखानों व मिलों में काम करनेवाले मजदूरों के लिए बड़ी गन्दी और अस्वास्थ्यकर कोठरियाँ होती हैं। उन्हें ८ फीट लम्बी चौड़ी कोठरियों में ४ से ८ तक की सत्या में गुजर करनी पड़ती है।

नगरों के मकान एक-दूसरे से इतने सटे हुए होने हैं कि उनमें शुद्ध हवा और प्रकाश का प्रवेश स्वतन्त्र रूप से नहीं हो पाता।

(६) आर्थिक दुर्दशा और वरिद्धता

भारतवासियों के हीन स्वास्थ्य का एक प्रधान कारण उनकी आर्थिक दुर्दशा और भयकर गरीबी तथा बेकारी भी है। जून १९४१ में भारत-मन्त्री श्री एमरी ने पार्लमेंट में भाषण करते हुए भारत के सम्बन्ध में कहा—“भारत समृद्धिशाली है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के पास अधिक राज-कोष है।”

परन्तु इस कथन में सचाई का लेश भी नहीं है। भारत की समृद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत-मन्त्री ने प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों की बढ़ती हुई आमदनी पर अपनी दृष्टि डालकर यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि भारत समृद्धिशाली है। परन्तु उन्होंने नयी दिल्ली और लखनऊ, बम्बई कलकत्ता, मद्रास, लाहौर आदि नगरों के सरकारी मजानों के आदिस्त्रोत पर विचार करने का कष्ट नहीं किया।

देश की जाता की समृद्धि का पता शिमला-शैल के भव्य भवनों में

निवास करनेवाले सम्पत्ति-जीवियों से नहीं लग सकता। इसके लिए तो भारत के ग्रामों का भ्रमण आवश्यक है। आप किसी भी ग्राम में चले जाइए, वहाँ आपको दरिद्रता का नाण्डव दिख ही देगा और उत्तरी चारों ओर खड़े दीवंगे रोग, चिन्ता, बेकारी, और दैन्य।

सन् १९३८ में तत्कालीन अर्थ-मन्त्री सर जेम्स ग्रिग ने अपने वजन भाषण में कहा था कि—‘ब्रिटिश भारत की राष्ट्रीय आय १६ अरब रुपये है। यदि इस कयन को सत्य मान लिया जाये तो ब्रिटिश भारत में प्रत्येक व्यक्ति की औसत वार्षिक आमदनी ५३ रुपये ५ आने ४ पाई होती है। यदि इस आय में से केन्द्रीय, प्रान्तीय सरकारों तथा स्थानीय बोर्डों को दिये जानेवाले टैक्सों को कम कर दिया जाये जो अनुमान से ८ रुपये ५ आने ४ पाई होने हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आमदनी ४५ रुपये पड़ती है। इस प्रकार ४ रुपये मासिक से भी कम आमदनी पड़ती है।’

क्या यह भारत की समृद्धि का प्रमाण या उमकी भीषण दरिद्रता का चित्र है ?

(७) स्वास्थ्य-विभाग की अव्यवस्था

सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा तथा सफाई की व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व प्रत्येक प्रान्त की सरकार पर है। प्रत्येक प्रान्त में एक स्वास्थ्य-विभाग होता है। इसका प्रधान अधिकारी तो मंत्री होता है, परन्तु विभाग-सम्बन्धी व्यवस्था का दायित्व इंडियन सिविल सर्विस के सेक्रेटरी पर रहता है। प्रत्येक प्रान्त में स्वास्थ्य-विभाग का एक डाइरेक्टर होता है जिसके नियन्त्रण में स्वास्थ्य-विभाग का कार्य संचालित होता है। यह विभाग अपना कार्य स्थानीय बोर्डों (चुगियों तथा जिन्ना बोर्डों) के द्वारा सम्पादन करता है। इस विभाग के स्थानीय कर्मचारी स्थानीय

१ भारत-मंत्री ऐमरी के भाषण पर सर इब्राहीम रहमतुल्ला खाँ का वक्तव्य—‘लीडर’ (१९ जून १९४१)।

बोर्ड के नियन्त्रण में रहते हैं। स्थानीय बोर्डों का सासन-प्रबन्ध वैसे ही असन्तोषजनक रहता है। इनके सदस्य तथा चेयरमैन राजनीतिक चालों का आश्रय लेकर नागरिक जीवन के साथ खिलवाड़ करना ही अपना मनोरंजन या व्यापार समझते हैं।

यही कारण है कि इन बोर्डों के नियन्त्रण में रहने के कारण स्वास्थ्य-विभाग के स्थानीय अधिकारी भी मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। प्रत्येक नगर में एक हेल्थ आफिसर तथा कई सेनीटरी इन्स्पेक्टर होते हैं। इनका यह कार्य है कि वस्तियों में भ्रमण कर सफाई की व्यवस्था करे। परन्तु देखा यह गया है कि ये अफसर वषों में भी किसी वस्ती में निरीक्षण करने नहीं आते और न सेनीटरी इन्स्पेक्टर ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।

स्वास्थ्य-विभाग की ओर से मेहतारों के रहन-सहन तथा उनके सफाई-कार्य में सुधार करने के लिए इस विभाग की ओर से कोई कार्य नहीं किया गया है। कलकत्ता, बम्बई आदि बड़े नगरों में तो कुछ प्रबन्ध किया भी गया है।

स्वास्थ्य-विभाग की ओर से नगरों में बाटिकाओं व पार्कों, स्वास्थ्य-गृहों तथा जलाशयों की व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु इस ओर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है।

स्वास्थ्य सुधार के उपाय

हमने स्वास्थ्य-हीनता के जिन कारणों पर ऊपर विचार किया है, उनके निवारण द्वारा ही स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यदि उपर्युक्त कारणों के निवारण के लिए समस्त नागरिक मिलकर स्वास्थ्य-विभाग के सहयोग से प्रयत्न करें, तो कोई कारण नहीं कि भारतवासियों के स्वास्थ्य में सुधार न हो सके।

सांस्कृतिक जीवन

शिक्षा साहित्य, भाषा और कला संस्कृति के अंग हैं। अतः भारत के सांस्कृतिक जीवन पर विचार करने में इन पर विचार करना आवश्यक है।

शिक्षा

प्राचीन काल में शिक्षा

अज सभी विद्वान् एक मत से यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य मानव की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का साम-जस्यपूर्ण विकास और उत्कर्ष है। आज भारत में जो शिक्षा-प्रणाली प्रचलित है, उसमें राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। इसलिए उसके प्रति बड़ा अनतोष पैदा हो रहा है और उसमें सुधार और मश-धन के लिए उद्योग किया जा रहा है। अतः भारत में शिक्षा पर विचार करते समय यह उपयोगी होगा कि हम अपनी प्राचीन वैदिक शिक्षा-प्रणाली का तो अवलोकन करें ही, उसकी विशिष्टताओं पर भी विचार करने का प्रयास करें।

पुराने समय में शिक्षा का आधार आध्यात्मिक था। समस्त ज्ञान विज्ञान, कला-कौशल, साहित्य आदि का धर्म से प्रनिष्ठ स्रोत था। उसे आज-कल जैसी सामाजिक जीवन में अलग देवमन्दिरों में तीर्था या मठों तक ही परिमित रहनेवाली चीज नहीं थी। धर्म मन्त्रे ज्यों में सामाजिक जीवन का आधार था। उस समय गुरुकुल थे। गुरुकुल का अर्थ है आचार्य, शिक्षक या अध्यापक का परिवार। उसके सदस्य गुरुकुल के ठान होने थे, जो 'ब्रह्मचारी' रहे जाने थे, क्योंकि गुरु उन्हें 'ब्रह्म' (माता) की ओर ले जाने की मानना में पर-प्रदर्शन करता था। इनमें वादक और पाठिहाण निगुक्त शिक्षा ग्रहण करने थे। गुरुकुल के मन्त्राध्य-म संप्रोत गुरु आश्रित मन्त्राध्या-देता गुरुध्वर का परिवार का अंग होता

या । फलस्वरूप गुरुकुल आर्थिक चिन्ता से मुक्त होकर अपने आचार्यों द्वारा ग्रन्थचारियों को सम्यक् ज्ञान देने में ।

वैदिक साहित्य में आचार्य की जो महत्ता है उसका एकमात्र कारण यह है कि आचार्य ग्रन्थचारी का धर्म-पिता है, वह उसे आचार की शिक्षा देता है, उसका आध्यात्मिक सत्कार करता है । माता-पिता तो उसके शरीर का पालन पोषण मात्र ही करते हैं परन्तु आचार्य के हाथ में इससे भी गुरुतर कार्य—चरित्र का निर्माण—जिसके ऊपर उसका सारा जीवन निर्भर है । चरित्र-निर्माण में शारीरिक और आत्मिक पवित्रता की साधना होती है । इस प्रकार वैदिक शिक्षा शुद्धि का समन्वय थी । अनुशासन द्वारा शरीर की शुद्धि, शिक्षण द्वारा शक्तियों की शुद्धि, ज्ञान द्वारा बुद्धि या मन की शुद्धि और ध्यान तथा मनन द्वारा आत्मा की शुद्धि ।

वैदिक शिक्षा-प्रणाली में अनुशासन पर स्वाध्याय से अधिक ध्यान दिया जाता था । सरल और तपस्वी जीवन पर आग्रह था । वैयक्तिक और सामूहिक आचार, स्वान्वय-सबधी तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन तत्परता से होता था ।

प्राचीन-काल में सार्वजनिक-शिक्षा अधिकांश में गौखिक रूप में हुआ करती थी, आजकल की तरह पुस्तको द्वारा नहीं । धार्मिक शिक्षण द्वारा उस सार्वजनिक शिक्षा को आध्यात्मिक रंग दिया गया और धर्म और कला में सामंजस्य स्थापित करके सस्कृति का निर्माण हुआ । ईसा की नौतवी शताब्दी में जय विद्यापीठों, मठों और मन्दिरों द्वारा इस सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार हुआ तो उस सस्कृति का विस्तार हुआ । ग्रामों में भी शिक्षा का खूब प्रचार हुआ । ग्राम-पाठशालाएँ स्थापित की गयी । हस्कीर्तन और नाटकों द्वारा धर्म और सस्कृति का प्रसार हुआ ।

स्त्रियों की शिक्षा

वैदिक काल में और उसके बाद के युग में स्त्रियाँ को भी पुरुषों के बराबर ही शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार था ।

आज जबकि भारत में शिक्षा के पुनर्संगठन पर विचार हो रहा है वर्तमान शिक्षा के दोषों के परिहार के लिए विचार करने के साथ-साथ उसमें अपने गुणों के समावेश करने का पालन करें जो हमारी वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है तथा जिसमें राष्ट्र का भी हित हो सकेगा है।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली

आज भारत में जो शिक्षा-प्रणाली प्रचलित है उसकी सभी शिक्षा-विद्वानों और लोकनेताओं ने घोर निंदा की है। इन प्रणाली में कई बड़े दोष हैं—पहला यह है कि वह न तो शिक्षा और जीवन में कोई पर्याप्त सम्बन्ध स्थापित करती है और न जीवन की आवश्यकताओं पर ही ध्यान देती है।

यद्यपि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के दोषों को सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं, तथापि इससे कोई इन्कार नहीं करता कि इसने देश की बड़ी सेवा की है। इस प्रणाली ने भारत में ब्रिटिश शासन को शिक्षित शासक ही प्रदान नहीं किये हैं प्रत्युत भारत में राष्ट्रीय और राजनीतिक नवचेतना और जागरण में भी विशेष योग दिया है। नवीन-शिक्षा ने भारत में विद्वान्, वैज्ञानिक और महान् दार्शनिकों को पैदा किया है जिन्होंने न केवल भारत का ही मस्तक ऊँचा किया है प्रत्युत अन्तर्राष्ट्रीय-जगत में भी अपना विशेष स्थान प्राप्त किया है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि भारत में जो विद्वान्, वैज्ञानिक और महापुरुष हुए हैं और जो इस समय मौजूद हैं, उनके निर्माण में केवल पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को ही श्रेय है। उनकी महानता में उनके विशिष्ट व्यक्तित्व, उच्च सत्कार और अपूर्व प्रतिभा ने भी पर्याप्त योग दिया है। फिर भी आज हम यह अनुभव करते हैं कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन की जरूरत है।

दूसरा यह कि इसका लक्ष्य राष्ट्रीयता से दूर है। वास्तव में इसका विनाश भारत में अंग्रेजी शासकों की सुविधा और शासन-संचालन के

उद्देश्य से किया गया था और इस उद्देश्य की पूर्ति में इसने बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है।

तीसरा यह है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाकर भारतीय भाषाओं के विकास और उन्नति पर ध्यान नहीं दिया गया। मातृभाषा में शिक्षा न होने से भी विद्यार्थियों का बहुमूल्य समय अंग्रेजी भाषा को सीखने में व्यतीत होता है।

चौथा यह कि यह शिक्षा सैद्धान्तिक ही है, व्यावहारिक नहीं। इसलिए जब विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज को छोड़कर सत्सार में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें व्यावहारिक जीवन में बड़ी असफलता का सामना करना पड़ता है।

पाँचवाँ और सबसे बड़ा दोष यह है कि पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली आर्य-संस्कृति के विरुद्ध है। वह चरित्र-निर्माण और सदाचार की सर्वथा उपेक्षा करती है। ज्ञान-वृद्धि के लिए वह पर्याप्त सुयोग प्रदान करती है, परन्तु छात्रों की मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक शक्तियों का सामञ्जस्यपूर्ण विकास नहीं करती। वह राष्ट्रीयता एवं एकता की भावना के प्रादुर्भाव के लिए भी कोई ध्यान नहीं देती और न छात्रों में नागरिकता की भावना का प्रादुर्भाव ही करती है।

भारत में विश्व-विद्यालय

भारत में सबसे पहले सन् १८५७ में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में तीन विश्व-विद्यालय स्थापित किये गये थे। विश्व-विद्यालय दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के वे हैं जो अपने अन्तर्गत कॉलेजों की परीक्षा का प्रबन्ध करते हैं। उनकी ओर से कॉलेजों में शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं होता। प्रत्येक कॉलेज जो ऐसे विश्व-विद्यालय में सम्बन्धित होता है, उसके द्वारा निर्धारित पाठ्य-क्रम के अनुसार शिक्षा का प्रबन्ध करने में स्वतन्त्र है। दूसरे प्रकार के विश्व विद्यालय वे हैं जिनके अन्तर्गत कॉलेजों का प्रबन्ध स्वयं विश्वविद्यालय की कार्य-कारिणी कॉमिन्स और बोर्ड के अधीन होता है। पहले प्रकार के विश्व-विद्यालयों में आगरा, बम्बई,

कलकत्ता आदि विश्वविद्यालय हैं। दूसरे प्रकार के विश्वविद्यालयों में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय हैं। भारतवर्ष के विश्वविद्यालय कब कब स्थापित हुए यह नीचे लिखी सारिणी स्पष्ट हो जायेगा।

विश्वविद्यालय	सन्	विश्वविद्यालय	सन्
कलकत्ता वि०वि०	१८५७	अलीगढ़ मुसलिम	१९२०
मद्रास	१८५७	रगून	१९२०
बम्बई	१८५७	लखनऊ	१९२०
पंजाब	१८८२	जनमलाई	१९२०
इलाहाबाद	१८८७	ढाका	१९२१
बनारस, हिंदू	१९१६	दिल्ली	१९२२
पटना	१९१७	नागपुर	१९२३
मैसूर	१९१६	आन्ध्र	१९२६
हैदराबादउसमानिया	१९१८	आगरा	१९२७

इन विश्वविद्यालयों में भाषा-साहित्य, इतिहास, राजनीति, दर्शन, मनोविज्ञान, ज्योतिष, रसायन, भूगर्भ, भौतिक विज्ञान, व्यापार-वणिज्य, अर्थ-शास्त्र, जीव-शास्त्र, वनस्पति-विज्ञान, चिकित्सा, इंजिनियरी, कृषि, कानून आदि की उच्चशिक्षा का प्रबन्ध है।

अन्य शिक्षा-संस्थाएँ

सन् १९३५ की भारत सरकार की शिक्षा-विभाग की रिपोर्ट के अनुसार समस्त भारत में २ लाख ५६ हजार २६३ स्कूल तथा कॉलेज हैं। इनमें कुल १ करोड़ ३५ लाख २ हजार ८६५ छात्र शिक्षा पा रहे हैं। कुल जनसंख्या का ५% भाग शिक्षा पा रहा है। १९३५, के अंक ये हैं—

संस्थाएँ	छात्र-संख्या	छात्रा-संख्या
कॉलेज	१,०९,३१५	२,४९३
हाई स्कूल	९,४४,९२२	९८,९७५
मिडिल स्कूल	११,७२,०६५	१,४६,०४२

१९३७ को राष्ट्रीय-शिक्षा-विचारदो का एक सम्मेलन आमन्त्रित किया गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अपने उपर्युक्त लेखों के आधार पर भाषण दिया और शिक्षा के मुद्धार पर विस्तारपूर्वक अपने विचार व्यक्त किये। इनपर विचार-विनिमय के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया—

(१) राष्ट्रव्यापी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ७ वर्ष तक हो ऐसी व्यवस्था की जाये, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, इस अवधि में महात्मा गांधी के मन्तव्यानुसार शिक्षा रचनात्मक उद्योग द्वारा दी जाये। सम्मेलन को यह आशा है कि इस शिक्षा-पद्धति द्वारा धीरे-धीरे अध्यापकों का वेतन भी प्राप्त किया जा सकेगा।

इस शिक्षा-सम्मेलन ने जामिया मिलिया, दिल्ली के प्रिंसिपल डा० जाकिरहुसैन की अध्यक्षता में वर्धा-शिक्षा-कमेटी की नियुक्ति भी की जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार ७ वर्षों के लिए पाठ्य-क्रम तैयार करने का कार्य सांपा गया।

बुनियादी तालीम

उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सात साल के लिए बुनियादी तालीम (Basic Education) की व्यवस्था की है।

बुनियादी तालीम की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) स्कूल में प्रत्येक बालक को अपनी रुचि के अनुसार एक आधारभूत उद्योग चुनना चाहिए जिसकी व्यवस्था स्कूल के द्वारा की गयी हो। इस उद्योग के आधार पर बालक को शिक्षा दी जाये। इसके साथ ही साथ उसे दो सहायक उद्योगों का भी चुनाव करना चाहिए, जैसे कनाई और बागवानी। १२ वर्ष की अवस्था तक इन उद्योगों की शिक्षा केवल शिक्षा के मूल्य की दृष्टि से दी जाये, औद्योगिक दृष्टि से नहीं। जो बालक भविष्य में उद्योग में निपुणता प्राप्त करना चाहे उन्हें अन्तिम दो सालों में औद्योगिक ढंग पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी। लड़कियों को घरेलू धंधों की शिक्षा दी जायेगी और अन्तिम दो वर्षों में बच्चों के पालन तथा देख-रेख की शिक्षा दी जा सकती है।

(२) 'समाज-सेवा' (ग्राम-स्वास्थ्य, प्रचार, दुष्काल में सेवा, रोग तथा वाढ से पीड़ितों की सेवा, स्थानीय मेलों की व्यवस्था, सम्मेलनों में स्वयं-सेवक का कार्य, किन्डरगार्टन दर्जों की व्यवस्था में सहयोग, स्त्री-समाज-सघ तथा सेवासघ,) प्रकृति-निरीक्षण, भ्रमण, खेल, व्यायाम आदि ।

(३) शिक्षा में कार्यशीलता के सिद्धान्त की स्वीकृति, इसका अर्थ यह है कि बालकों की स्वाभाविक तथा रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन और बालकों की बौद्धिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियों के विकास के लिए पूर्ण सुयोग दिया जाये ।

(४) राज्य को प्रत्येक बालक के लिए ७ वर्ष की आयु से १४ वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ।

(५) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी तथा 'हिन्दुस्तानी' का सामान्य ज्ञान अनिवार्य होगा । पिछले दो वर्षों में अंग्रेजी केवल उनको पढ़ायी जायेगी जो आगे हाई स्कूल या कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों ।

(६) पाठ्य-क्रम में आधुनिक शिक्षा-सम्बन्धी आदर्शों के प्रकाश में परिवर्तन किया जाये ।

(७) नागरिकता की तैयारी के उद्देश्य से पाठ्य-क्रम बनाया जाये, केवल इस लिहाज से नहीं कि प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा का आधार है ।

(८) पाठ्यक्रम में सामान्य नागरिक-शास्त्र और सामान्य विज्ञान को स्थान दिया जाये ।

(९) भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से पढ़ाया जाये, राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सामयिक घटनाओं का भी ज्ञान आवश्यक है ।

(१०) चरित्र-निर्माण को शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाये । सदाचार की शिक्षा सामाजिक एवं मनोविज्ञान की दृष्टि से दी जाये, विशुद्ध धार्मिक दृष्टि से नहीं ।

(११) मनोवैज्ञानिक प्रणाली द्वारा स्कूल के वातावरण को शुद्ध तथा

अनुकूल बनाया जाये। अध्यापक और छात्रों में सहकारिता का भाव हो।

(१२) वार्षिक परीक्षाएँ उठा दी जाये और स्कूलों में रिकार्ड द्वारा ही श्रेणी चढ़ायी जाये।

(१३) बारह वर्ष की आयु में छात्र की मनोवैज्ञानिक परीक्षा की जाये और उसकी रुचि तथा प्रवृत्ति की जाँच की जाये तथा उसके नरभक को सुचनाएँ दी जाये।

(१४) स्कूल के वातावरण, कार्य-प्रणाली तथा शिक्षा में राष्ट्रीय तथा जहिंसात्मक दृष्टिकोण सामने होना चाहिए।

इसमें सन्देह नहीं कि यह शिक्षा की एक त्रान्तिकारी योजना है। इससे राष्ट्र का हित होगा, क्योंकि यह राष्ट्र-हित की दृष्टि में ही तैयार की गयी है। महात्माजी शिक्षा को स्वाधायी (Self supporting) बनाना चाहते हैं। उनका यह नकल्प प्रारम्भिक दशा में पूरा होगा अथवा नहीं, यह अभी से निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। जब इस योजना के अनुसार समस्त भारत में प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध हो जायेगा, तब इसमें जो दोष परीक्षण-काल में मालूम होंगे, उनके निवारण के लिए भविष्य में प्रयत्न किया जा सकेगा। परन्तु इसमें तनिक भी शक नहीं कि वर्धा-शिक्षा-योजना ही एक ऐसी योजना है, जो आज १५० वर्ष के ब्रिटिश शासन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय हित की दृष्टि से रखी गयी है और जिसपर नयुक्तप्रात, मध्यप्रात, उम्बई आदि कई प्रांतों में अमल भी होने लगा है।

भाषा और लिपि

हिन्दी-राष्ट्रभाषा

भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है परन्तु आज वह किसी भी प्रान्त की बोल-चाल की भाषा नहीं है। हा, यह निर्विवाद है कि भारत की अधिकांश पान्तिक भाषाएँ हिन्दी, बगला, मराठी, गुजराती, उर्दू, सिन्धी, पंजाबी, राजस्थानी और उडिया संस्कृत से उत्पन्न और विकसित हुई हैं और शेष द्राविडो—तामिल, तेलग, मलयालम, कन्नड पर भी संस्कृत का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब प्रान्तीय

भाषाओं में हिन्दी ही सबसे अधिक बोली और पढ़ी-लिखी जाती है।

सन् १९३१ में भारत की जनसंख्या ३५,२९,८६,८७६ थी। इनमें देशी रियासतों की संख्या भी शामिल है जो ८ करोड़ से ऊपर है।

हिन्दीभाषी प्रान्त

भारत के संयुक्तप्रान्त, बिहार-उड़ीसा, पंजाब, मध्यप्रान्त-वगैर, दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, और कुछ हिन्दीभाषी रियासतें हैं, जिनकी कुल जनसंख्या सन् १९३१ ई० के अनुसार १७ करोड़ ६३ लाख ७० हजार, ६५० है।

अहिन्दी-भाषी प्रान्त

बंगाल, मद्रास, बम्बई-सिन्ध, कुर्ग, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, बड़ोचि-स्तान, आसाम, त्रिपुरा तथा कुछ अहिन्दीभाषी रियासतें हैं जिनकी जनसंख्या १७ करोड़ ६८ लाख ७० हजार ९०० है।

इस प्रकार हिन्दी-भाषाभाषियों और इनकी भाषा-भाषियों की जनसंख्या प्रायः बराबर है। इसलिए हिन्दी भाषा ही राष्ट्र की भाषा कहलानेयोग्य है। परन्तु, मुसलमानों की ओर में यह दावा पेश किया जा रहा है कि उर्दू ही राष्ट्र-भाषा हो सकती है। इस प्रकार भाषा के इस राष्ट्रीय प्रश्न पर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण में विचार करने की पद्धति गुरु हो गयी है। आजकल सामान्यभाषा और राष्ट्र-भाषा—इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाने लगा है। इस प्रकार हमने भ्रान्तिपूर्ण विचारों का प्रचार होन लगा है। सामान्य-भाषा क्या है? यह वह भाषा है जो प्रत्येक प्रान्त में शोक-चाद में काम आती है और जिसे बोझ नहीं मानी समझ सकते हैं और शोक सकते हैं। सामान्य भाषा पर स्थानीय भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे, कश्मीर के वाजवाले में बोली जानेवाली भाषा, उस भाषा में मिश्रित है जो बम्बई के वाजवाले में बोली जाती है। कश्मीर की शोक-चाद की भाषा में बंगाल के अधिक शब्द होते हैं। इसी प्रकार बम्बई की शोक-चाद की भाषा में गुजराती के शब्द अधिक होते हैं। इस प्रकार

मे श्री रामनाथ 'सुमन' ने लिखा है—

“यह भाषा अन्तर्प्रतीय यातायात, रेल, व्यापार ओर बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के खड़े हो जाने से बनी है। इसे किसी सस्था ने नहीं बनाया, न इसके बनाने में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, हिन्दी-प्रचार-सभा या कांग्रेस-का हाथ है। यह भाषा उत्तर भारत (मुख्यतः संयुक्तप्रान्त, मध्यभारत तथा बिहार) के उन गरीब प्रवासियों की राष्ट्र को देन है, जो गरीबी के कारण अपना घरबार छोड़कर नौकरी की तलाश में दूर-दूर के सूबों में गये और वहाँ मेहनत-मजदूरी करके पेट पालने लगे। इनमें से किसी ने बोझा ढोने का काम किया, कुछ स्टेशनों पर कुली बने, कुछ आफिसों में चपरासी बने, कुछ को मिलो, रेलों के कारखानों और दुकानों में काम मिला। कुछ ने दरबानी की, कुछ पुलिस और ट्राम की नौकरी में भरती हुए, कुछ इक्का-तांगा हाँकने लगे। बहुतों ने ग्वाले, नाई, रसोई का काम संभाला, और बहुतों ने छोटे-छोटे धन्धे अपनाये। ये शिक्षित न थे और जहाँ गये वहाँ अपनी बोली और रीति-रिवाज साथ ले गये। जिस हिन्दी के बारे में यह कहा जाता है कि वह अधिकांश भारतीयों द्वारा समझी जाती है, वह यही सामान्य बोली है। इसका न कोई निश्चित व्याकरण है और न आजतक कोई पुस्तक इस भाषा में लिखी गयी।”

अतः यह स्पष्ट है कि भारत में प्रचलित 'सामान्य भाषा' राष्ट्रभाषा नहीं है। जो ऐसा मानते हैं, वे भारी भ्रम में हैं।

देश में राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ राष्ट्रीय नेताओं ने राष्ट्रभाषा-निर्माण के प्रश्न को प्रस्तुत किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत में राष्ट्रीय नवचेतना और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि भारत के सभी प्रान्तों में एकता स्थापित की जाये। एकता उसी समय स्थापित हो सकती है जब कि विचार-विनिमय के लिए एक अन्तर्प्रान्तीय भाषा हो। अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा है जिसे सभी प्रांतों में पढ़ा और बोला जाता है, पर वह स्कूलों और कालिजों के विद्यार्थियों तथा अंग्रेजी पढ़े समुदायों तक ही सीमित है—जनता की भाषा नहीं

कहना शुरू कर दिया कि अब गांधीजी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाकर उर्दू और मुसलिम संस्कृति का नाश कर देंगे। अतः गांधीजी ने इस नाम में परिवर्तन करके इसे 'हिन्दुस्तानी' का नाम दिया। शायद ऐसा सोचा गया कि इस नाम से मुसलमानों को कोई आपत्ति न होगी। राष्ट्रीय मुसलमानों ने इस नाम को पसंद किया और इसकी आड़ में उन्हें उर्दू के प्रचार के लिए काफी गुंजाइश मिल गयी। परन्तु मुस्लिम-लीग के कर्ता-धर्ता श्री मुहम्मदअली जिन्ना का विरोध और भी तीव्र होना गया।

जब भारत के ८ प्रान्तों में कांग्रेस की सरकारें बनीं तब इन सरकारों द्वारा 'हिन्दुस्तानी' भाषा के प्रसार के लिए प्रयत्न किया गया। मद्रास, बम्बई और बिहार में 'हिन्दुस्तानी' के प्रचार तथा प्रसार के लिए सरकारों की ओर से प्राथमिक कक्षाओं में हिन्दुस्तानी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया। मुस्लिम-लीग की ओर से इसका घोर विरोध किया गया।

हिन्दुस्तानी

'हिन्दुस्तानी' भाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जिसे महात्मा गांधी उत्तरी भारत के हिन्दू और मुसलमानों की भाषा मानते हैं। तब केवल हिन्दी ही क्यों न कहा जाये जैसा कि आज में २३ वर्ष पहले गांधीजी ने कहा था।

उन्होंने यह अनुभव किया है कि 'हिन्दुस्तानी' नाम से हिन्दी-उर्दू का झगडा शान्त हो जायेगा। वह यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तानी भाषा में संस्कृत, अरबी या फारसी के अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाये। उसमें हिन्दी और उर्दू के शब्दों को स्थान मिले तथा अन्य भाषाओं के चलते शब्दों का भी प्रयोग किया जाये। भाषा अत्यन्त सरल और बोलचाल की हो जिसे मामूली लोग भी समझ सकें। 'हिन्दुस्तानी' भाषा नागरी और फारसी को दोनों लिपियों में लिखा जा सकता है।

कांग्रेसी शासन-काल में बिहार, मद्रास, बम्बई में हिन्दुस्तानी भाषा में सरकार की ओर से प्राथमिक पाठशालाओं तथा प्रौढ-पाठशालाओं में

आगे व प्रोडा के लिए हिन्दुस्तानी भाषा की शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी। हिन्दुस्तानी भाषा में बिहार में सरकार के काग्रेसी मंत्री डा० संयद महमूद ने प्रोड-शिक्षा के लिए हिन्दी-उर्दू में हिन्दुस्तानी भाषा की पुस्तकें तैयार करायीं। मद्रास में श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने हिन्दुस्तानी भाषा को अनिवार्य कर दिया। इसी प्रकार बम्बई में भी श्री बाल गंगाधर तिलक ने हिन्दुस्तानी भाषा को समस्त स्कूलों में अनिवार्य कर दिया। कहीं-कहीं हिन्दुस्तानी के नाम पर हिन्दी में संस्कृत भाषा के प्रचलित शब्दों का न अपनाकर उनकी जगह उर्दू-फारसी के बे-मोजूँ शब्द जबरदस्ती रने गये, जिसमें हिन्दीभाषी जनता में, खास तौर से बिहार और मधुप्रान्त में, धार अमलाप उठ खड़ा हो गया।

यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना उचित है कि प्रत्येक भाषा का उसके वादनामों में अनिष्ट सम्भव है। यही नहीं, वह एक प्रकार से उसकी संस्कृति की निदर्शिका भी है। भाषा विचारों का व्यक्त करने का माध्यम है और विचारों का मूलधार भी है। हम जिन भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी भाषा में विचार भी करते हैं। इसलिए भाषा और विचारों का जुड़ना सम्भव है। हिन्दी भाषा की जननी संस्कृत है और दूसरी कई प्राचीन भाषाओं की जननी भी संस्कृत ही है। संस्कृत भाषा में हिन्दुत्व और संस्कृति सुरक्षित है, क्योंकि वेद, उपनिषद्, जैन-ग्रन्थ, गीता, महाभारत, रामचरितमानस तथा प्राचीन साहित्य, नाटक और कवित्त आदि सब संस्कृत में ही उपलब्ध हैं। इन्हीं वस्तुओं में संस्कृति निहित है। इसलिए जो समाज जिस भाषा द्वारा इस प्रकार का अवकाश करेगा, उसका संस्कृति का प्रभाव पड़ना जरूरी है।

सांस्कृतिक दृष्टि से हिन्दी और उर्दू भाषाओं में जो अन्तर और भेद-भेद हैं। उर्दू अपनी संस्कृति का व्यक्त करता है और हिन्दी अपने संस्कृति का। वे अस्मत्त्व में ही भिन्न हैं। इन दोनों का निश्चय हमें हिन्दुस्तानी भाषा के रूप में करना ही चाहिये और इससे भाषा का विकास होना चाहिए।

इस प्रकार हमें हिन्दुस्तानी भाषा को ही अपना लेना चाहिए।

भाषा केवल इस प्रकार कृत्रिम रूप से जनायी हुई सरल और बोल-चाल की भाषा नहीं हो सकती। राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जिसमें राष्ट्र के नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की आवश्यकताओं को तृप्त करनेवाली सुरुचिपूर्ण सामग्री प्रदान करने की क्षमता हो।

सुप्रसिद्ध बौद्ध लेखक श्री भदन्त आनन्द कीस्त्यायन का यह मत विद्या-प्राप्त्य और उपयुक्त है कि—

“अब हिन्दी कुछ वर्षों पहले की ‘भाषा’ नहीं रह गयी है। हम उसे अपनी ऊँची से ऊँची शिक्षा का माध्यम बनाने चले हैं। हम जहाँ यह चाहते हैं कि वह काश्मीर से कन्याकुमारी तक समझी जाये, वहाँ यह भी चाहते हैं कि उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म, जटिल से जटिल, अर्वाचीन से अर्वाचीन भावों को प्रकट करने का सामर्थ्य आ जाये। हम चाहते हैं कि उसमें न केवल समुद्र-सा फैलाव हो, बल्कि उसकी गहराई भी हो। अब हम यह हैं कि आज के ससार में जितने और जैसे गंभीर विषयों का अध्ययन हो रहा है, जब हमें हिन्दी में उन सभी विषयों पर ग्रन्थ देखने की ज़रूरत है, तो क्या वे ग्रन्थ उसी भाषा में लिखे जा सकते हैं जिसे, गुस्ताखी माफ हो तो, हम बाजारू भाषा कहे, तो कोई हर्ज नहीं। हिन्दुस्तान में एक राष्ट्रभाषा है जिसे पेशावर से लेकर मद्रास तक रेलवे स्टेशनों पर हम उस समय बोलते हैं जब हमें कुलियों से निवटना होता है। अब क्या उस तरह की भाषा में किसी शास्त्रीय विषय की चर्चा की जा सकती है? आपसे यदि कोई कहे कि आप प्रसिद्ध गणितज्ञ आइन्स्टाइन के ‘सापेक्ष-वाद’ पर एक पुस्तक लिखें जिसमें न संस्कृत के शब्द हों और न अरबी फारसी के, तो क्या आप लिख सकेंगे? आइन्स्टाइन के सापेक्षवाद को जाने दीजिए—कहते हैं उसे अध्यापन-सत्तार में केवल दो-तीन आदमियों ने ही ठीक तरह समझा है—अपने ही दर्शन-शास्त्र पर आप कुछ भी लिख सकते हैं? यदि नहीं, तो जब हमें अपने इतिहास की कुछ गहरी व्याख्या करनी होगी, जब हमें सत्तार के भौतिक भूत की कुछ बातें समझनी-समझानी होगी, जब ऊँचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए शास्त्रीय ढंग की पुस्तकें लिखनी लिखानी होगी, तब किसी ऐसी राष्ट्रभाषा से, जिसमें न

सस्कृत के शब्द हो और न फारसी के, हमारा काम नहीं चल सकता । हमें न केवल पारिभाषिक शब्दों के लिए, बल्कि ऐसे शब्दों के लिए भी जो हमारे गहरे चिंतन के यथार्थ प्रतिबिम्ब हो सकें, सस्कृत अथवा अरबी की शरण लेनी होगी ।”

अन्तिम भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के शिमला-अधिवेशन में सभापति-पद में हिन्दी के विद्वान और अनुभवी पत्रकार श्री वाव्गव विष्णु पराडकर ने भी राष्ट्रीय भाषा के सम्बन्ध में अपने अभिभाषण में कहा था—

“मौलाना अबुल कलाम आजाद जिसे सर्वप्रान्तीय व राष्ट्रीय भाषा बनने की अधिकारिणी समझते हैं वही यदि यह ‘हिन्दुस्तानी’ है तो मैं निःसंशय चित्त से साहित्य-सम्मेलन को सलाह दूंगा कि वह निर्भीकता के साथ स्पष्ट शब्दों में इसका विरोध करे ।” हिन्दुस्तानी के नाम पर यह जो अनर्थ हो रहा है, उससे केवल हिन्दी की ही नहीं बल्कि भारतीय सस्कृति की रक्षा करने के लिए मैं कहता हूँ कि हमारी राष्ट्रभाषा का नाम हिन्दी होना चाहिए और उसकी प्रवृत्ति भी हिन्दी यानी हिन्द की होनी चाहिए ।”

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और राष्ट्रभाषा

उपरोक्त विवाद पर निर्णयात्मक विवेचन करने के लिए इस झगड़े के मूल को देखना होगा । महात्मा गांधी के सभापतित्व में इंदौर में होनेवाले हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के चौबीसवें अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ था—

“इस सम्मेलन को मालूम हुआ है कि राष्ट्रभाषा के स्वरूप के सबंध में हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में कुछ गलतफहमी फैली हुई है और लोग उसके लिए अलग-अलग राय रखते हैं । इसलिए यह सम्मेलन घोषित करता है कि राष्ट्रभाषा की दृष्टि से हिन्दी का वह स्वल्प मान्य समझा जाये जो हिन्दू-मुसलमान आदि सब धर्मों के ग्रामीण और नागरिक व्यवहार करते हैं, जिसमें रूढ़ सर्व-सुलभ अरबी, फारसी, अंग्रेजी या सस्कृत शब्दों या मुहाविरों का बहिष्कार न हो और जो नागरी या उर्दू

लिपि में लिखी जाती हो।'

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के शिमला-अधिवेशन में सम्मेलन की नियमावली में संशोधन किये गये और १९ सितम्बर सन् १९३८ को संशोधित नियमावली के अनुसार उद्देश्य धारा २ (क) और (ख) में इस प्रकार निर्धारित किया गया—

- “(क) हिन्दी-साहित्य के सब अंगों की पुष्टि और उन्नति का प्रयत्न करना,
(ख) देशव्यापी व्यवहारों और कार्यों को सुलभ करने के लिए राष्ट्रलिपि देवनागरी और राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार बढ़ाने का प्रयत्न करना,
(ग) हिन्दी भाषा को अधिक सुगम, मनोरम, व्यापक और समृद्ध बनाने के लिए समय-समय पर उसके अभावों को पूरा करना और उसकी शैली और वृत्तियों के संशोधन का प्रयत्न करना।”

यद्यपि सम्मेलन के उद्देश्यों में ‘हिन्दी राष्ट्रभाषा’ का उल्लेख है— उसमें ‘हिन्दुस्तानी’ का उल्लेख नहीं है, तथापि इंदौर के उपर्युक्त निश्चय में ‘हिन्दुस्तानी’ शब्द न होते हुए भी ‘हिन्दुस्तानी’ का स्वरूप वही विद्यमान है जिसे आज महात्मा गांधी ‘हिन्दुस्तानी’ कहते हैं।

इन्दौर-सम्मेलन के बाद ‘हिन्दुस्तानी भाषा का प्रचार बढ़ता रहा। जुलाई सन् १९३७ में जब कांग्रेस मन्त्रि-मण्डली ने शासन-भार संभाला तब हिन्दुस्तानी प्रान्तीय सरकारों द्वारा भी स्वीकार कर ली गयी। हिन्दी साहित्यिकों के सामने ‘हिन्दुस्तानी’ का व्यवहार्य स्वरूप ‘रीडरो’ में आया तो हिन्दी-साहित्य-सेवियों को उसे देखकर घोर निराशा हुई और उसका फल यह हुआ कि पत्र-पत्रिकाओं द्वारा उसका घोर विरोध किया जाने लगा। सितम्बर १९३८ के शिमला-अधिवेशन में ‘आज’ के यशस्वी विद्वान् संपादक तथा सम्मेलन के अध्यक्ष श्री बाबूराव विष्णु पराडकर ने अपने भाषण में विचारपूर्वक हिन्दुस्तानी भाषा की आलोचना की और उसका विरोध करने के लिए सम्मेलन को सलाह भी दी। सम्मेलन के इस अधिवेशन में हिन्दी भाषा को सुगम बनाने के सम्बन्ध में जो निश्चय किया गया वह इस प्रकार है—

“इस सम्मेलन के विचार में हिन्दी के आधुनिक साहित्य-निर्माण के

लिए ऐसी भाषा उपयुक्त है जिसका परम्परागत सम्बन्ध संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से है जिसकी शक्ति कबीर, तुलसी, मूर मलिकमुहम्मद जायसी, रहीम, रसखान और हरिश्चन्द्र की कृतियों से आयी है, जिसका मूलाधार देशी और तद्भव शब्दों का भण्डार है, और जिसके पारिभाषिक शब्द प्राकृत अथवा संस्कृत के क्रम पर डाले गये हैं किन्तु जिसमें रूढ़, सुलभ और प्रचलित विदेशी शब्दों का भी स्थान है।”

पहले दिये गये इन्दौर-सम्मेलन और शिमला-सम्मेलन के निश्चयों में मौलिक अन्तर है। इन्दौर के निश्चय के अनुसार ‘हिन्दी का वह स्वरूप मान्य है जिसे हिन्दू-मुसलमान आदि सब धर्मों के ग्रामीण और नागरिक व्यवहार करते हैं।’

और शिमला के निश्चय के अनुसार ‘हिन्दी के आधुनिक साहित्य-निर्माण के लिए ऐसी भाषा उपयुक्त है जिसका परम्परागत सम्बन्ध संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से है, जिसकी शक्ति हिन्दी के प्राचीन कवियों तथा साहित्यकारों की रचनाओं से आयी है।’

ये दोनों निश्चय परस्पर-विरोधी हैं। पर धीरे-धीरे सम्मेलन में हिन्दुस्तानी-विरोधी तत्त्व का बहुमत होता गया। अपने पिछले पूना-अधिवेशन में उसने इस बात को कुछ-कुछ स्पष्ट कर दिया है। पूना का प्रस्ताव यह है—

“सम्मेलन की नियमावली के नियम (न) में आये हुए ‘राष्ट्रभाषा’ शब्द के स्पष्टीकरण के लिए सम्मेलन के इन्दौरवाले अधिवेशन का जो निश्चय दिया गया है, उसका निम्नलिखित रूप हो—

‘इस सम्मेलन को मालूम हुआ है कि राष्ट्रभाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में कुछ गलतफहमी फैली हुई है और लोग उसके लिए अलग-अलग राय रखने हैं। इसलिए यह सम्मेलन घोषित करता है कि राष्ट्रभाषा की दृष्टि में हिन्दी का वह स्वरूप मान्य नमूना जानें जो हिन्दू, मुसलमान आदि सब धर्मों के ग्रामीण और नागरिक व्यवहार करने हैं, जिसमें नट, सर्वमुक्तन बरखी, फार्मी, अंग्रेजी या संस्कृत शब्दों या मुहावरों का प्रहिण्कार नहीं होता और

जो माधारण रीति से राष्ट्रलिपि नागरी में तथा कहीं-कहीं फारसी लिपि में भी लिखा जाता है ।'

राष्ट्रभाषा के नाम और स्वरूप का विवाद अतन्त इतना तीव्र और सफट हो गया कि अंबोहर सम्मेलन के महापति का चुनाव ही इसी प्रश्न को लेकर हुआ और उसमें हिन्दुस्तानी पक्ष की हार हुई ।

भारतीय साहित्य-परिषद् और 'हिन्दी हिन्दुस्तानी'

देश की सब भाषाओं के साहित्यिकों में विचार-विनिमय के सम्बन्ध में संगठन करने के विचार से सन् १९३५ में इन्दौर के अधिवेशन में निम्नलिखित मन्तव्य प्रकाशित हुआ—

"देश की प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यिकों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने तथा हिन्दी भाषा की वृद्धि में उनका सहयोग प्राप्त करने के अनिप्राय से यह सम्मेलन निम्नलिखित सज्जनों की एक समिति बनाता है और उसको अधिकार देता है कि वह अपने साथ अन्य सज्जनों को आवश्यकतानुसार सम्मिलित कर ले ।"

इस निश्चय के अनुसार जो भारतीय साहित्य परिषद् बनी, उसके सयोजक सुप्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार श्री कन्हैयालाल मुन्शी थे । नागपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन के अवसर पर परिषद् का पहला अधिवेशन हुआ । भारतीय साहित्य-परिषद् के कार्य के लिए कित्त भाषा का प्रयोग किया जाये और उसका नाम क्या हो—यह प्रश्न उठा । इसने ऐसी भाषा के लिए महात्मा गांधी की राय से 'हिन्दी हिन्दुस्तानी' नाम स्वीकृत किया । पर खेद है कि भारतीय साहित्य-परिषद् का काम अधिक दिनों नहीं चल सका ।

राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति और हिन्दुस्तानी

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के नियम ३८ के अनुसार अहिन्दी-भाषी प्रान्तों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार के लिए २१ सदस्यों की एक प्रचार-समिति है जो राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति कहलाती है । इसका कार्य असम, बंगाल, उत्कल, सिन्ध, पश्चिमोत्तर-प्रदेश, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र

जैसा कि लिखा जा चुका है दोनों दलों का झगडा मूल में राष्ट्र-भाषा के नाम और स्वरूप पर है। काका कालेलकर तथा उनके समर्थकों का जोर राष्ट्रभाषा को

(१) 'साहित्यिक हिन्दी' या 'उर्दू-ए-मुअल्ला' बनाने पर नहीं है और

(२) उसे वे कांग्रेस द्वारा किया स्वीकृत 'हिन्दुस्तानी' नाम से ही पुकारना राष्ट्र के लिए हितकर मानते हैं।

दूसरी ओर उत्तरभारत के हिन्दीभक्त उसे

(१) 'संस्कृत, प्राकृत के क्रम पर' ढालना चाहते हैं और

(२) उसे वे 'हिन्दी' नाम से ही पुकारना चाहते हैं।

इस वार जो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अबोहर-अधिवेशन के चुनाव में संघर्ष रहा, वह इसी मतभेद का लक्षण था। अबोहर के अधिवेशन में जो मत बहुमत में है वह अवश्य अपने निर्णय को कड़े से कड़े शब्दों में प्रकट करेगा, ऐसी सम्भावना है।

परन्तु राष्ट्रभाषा का प्रश्न अकेले हिन्दीवालों का ही नहीं है उसे अखिल भारतीय दृष्टि से देखना चाहिए। हमारी दृष्टि में भाषा की पवित्रता जैसी कोई चीज है ही नहीं। आधुनिक हिन्दी में कई विदेशी भाषाओं (पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी) के शब्द इस बुरी तरह से मिल गये हैं कि उन्हें निकालना मुश्किल है। इसी प्रकार देशभाषाओं के शब्द भी मिलेगे। हाँ, यह मिलावट बलात् नहीं होनी चाहिए। भाषा 'बलात्कार' को सहन नहीं कर सकती। वह अन्य भाषा के शब्दों से मधुर समन्वय ही कर सकती है जिसे कोई नहीं रोक सकता।

राष्ट्र-लिपि की समस्या

महात्मा गांधी और राष्ट्रीय महासभा देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियों को राष्ट्र-लिपि स्वीकार करने के पक्ष में हैं। देश का सबसे विशाल जन-समुदाय देवनागरी लिपि को पसन्द करता है। सन् १९३१ की जन-संख्या के अनुसार प्रति १० हजार मनुष्यों में ४,०५६ मनुष्य देवनागरी-लिपि में लिखी जानेवाली भाषाएँ व्यवहार में लाते हैं।

जा गिना जाता है यही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा जाता है, वही गिना जाता है ।

साहित्य

मसाल में सबसे प्राचीन आर्य जाति है और इसी कारण सबसे प्राचीन आर्य-संस्कृति तथा साहित्य है ।

पाश्चात्य विद्वानों ने मुक्तकठ से यह स्वीकार किया है कि आर्य-संस्कृति तथा साहित्य मसाल में सबसे प्राचीन है । सृष्टि के आदि में परमात्मा ने चार ऋषियों को जो अपना ज्ञान दिया, वह वेद के नाम से प्रसिद्ध है । वेद ईश्वरीय ज्ञान है । उसकी रचना किसी मानव ने नहीं की । ईर्ष्याएँ यह अनादि हैं और उसका नाश भी नहीं होता । वैदिक युग में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद—इन चार वेदों का ही आदर था और जन-समाज इनके अनुसार ही अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करता था । ये चार वेद ही वैदिक काल का साहित्य, धर्म-पुस्तक और कला-कृति थे । सामवेद का ऋषिगण गायन करते थे । उसे संगीत का जन्मदाता कहा जाता है ।

कुछ काल के बाद इन वेदों की ऋषियों-मुनियों ने व्याख्याएँ करना शुरू किया । अतः उपनिषदों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों की रचना हुई । इसके बाद दर्शन-शास्त्रों की रचना की गयी । इस युग का जो साहित्य आज उपलब्ध है वह आध्यात्मिक-धार्मिक ही है । उस समय भारतीय कला का विकास कैसा हुआ था इसका आज कोई प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है ।

ब्राह्मण-ग्रन्थों के निर्माण के समय जनता की रुचि, कला-कृति तथा सरस साहित्य की ओर होने लगी । जनता काव्य और कविता में आनन्द लेने लगी । उस समय जन-समाज की मातृभाषा संस्कृत थी । अतः इस काल के ग्रन्थों का निर्माण संस्कृत में किया गया । सबसे प्राचीन काव्य-ग्रन्थ जिसका वर्णन इतिहास में आज उपलब्ध है, महर्षि वाल्मीकि की 'रामायण' है ।

‘रामायण’ की रचना के बहुत वर्षों के पश्चात् महर्षि व्यास ने जय काव्य की रचना की। इसमें महाभारत का काव्यमय वर्णन है। पीछे से इसी ग्रन्थ का नाम महाभारत प्रसिद्ध होगया।

भरत-मुनि ने नाट्य-शास्त्र की रचना की। इस ग्रन्थ में भारतीय नाट्य-कला के सिद्धान्त बताये गये हैं। नाटक के लिए उपयोगी तथा आवश्यक सभी बातों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। सबसे पहला नाटक भास कवि ने इसी ग्रन्थ के सिद्धान्तों के अनुसार लिखा।

ईसा की पाँचवीं शताब्दी में महाकवि कालिदास का जन्म हुआ। कालिदास संस्कृत के महाकवि थे और वाल्मीकि के बाद वही सबसे महान् कवि माने गये हैं। आज ससार में कालिदास की कला-कृतियों का जो आदर और सम्मान है, वह इसीलिए है कि उन्होंने ऐसे अमर साहित्य की सृष्टि की जो युगों तक जनता के हृदय को प्रभावित करता रहेगा।

महाकवि कालिदास के अतिरिक्त और भी कई प्रसिद्ध काव्यकार हुए जिनकी अमर कृतियों के कारण आज संस्कृत-साहित्य ससार की भाषाओं के सम्मुख खड़ा हो सकता है और संस्कृत भाषा में ऐसे रत्न भरे पड़े हैं जिनके कारण वह विश्व-साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त कर सकती है।

हिन्दी-साहित्य

बौद्ध-काल तक भारत में साहित्य-रचना की भाषा जोर सभवन जनता की मातृभाषा संस्कृत रही। परन्तु बौद्ध-काल में पाली भाषा का अधिक प्रचार हो गया। इसी कारण इस युग की बौद्ध-साहित्यिक तथा धार्मिक कृतियाँ पाली भाषा में मिलती हैं। पाली भाषा के बाद भारत में प्राकृत भाषा का अधिक प्रचार बढ़ा। परन्तु जबसे भारत में विदेशी आक्रमणकारियों ने प्रवेश आरम्भ किया तबसे यहाँ की भाषाविषयक एकता भग हो गयी और प्रान्तीय भाषाओं का जन्म होने लगा। ११वीं या उसके अन्तर्द्वी में आस-पास ही हिन्दी, उर्दू, बंगला, गुजराती, तामिल, तेलगू, मलयालम और मराठी आदि भाषाओं का विकास हुआ।

हिन्दी-साहित्य का इतिहास सन् ११९१ में आरम्भ होता है जब कवि चन्द्रवरदार्द्र ने 'पृथ्वीराज रासो' नामक काव्य की रचना की। इस प्रकार हिन्दी-साहित्य आज ९०० वर्षों से उत्तरी भारत की जनता में अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करता रहा है। आज हिन्दी का साहित्य अन्य समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है। एक युग था जब बंगला-साहित्य भारतीय साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। परन्तु गरुच्चन्द्र तथा रवीन्द्रनाथ के युग के समाप्त हो जाने पर उसने कोई प्रगति नहीं की।

हिन्दी-साहित्य सदा प्रगतिशील रहा है और आज भी वह प्रगति के पथ पर है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी 'रामचरितमानस' जैसी अमर कृति से हिन्दी को सदैव के लिए उच्च आसन पर बिठा दिया। 'रामचरितमानस' वास्तव में ऐसी उच्चकोटि की कला-पूर्ण रचना है जिसमें सम्पूर्ण मानव-जीवन की बड़ी सरस व्याख्या की गयी है। उसमें राम के प्रति गोस्वामीजी ने भक्ति की जैसी मनोहर अभिव्यक्ति की है वैसे किसी भी साहित्य में मिलना दुर्लभ है, साथ ही उन्होंने जनता के हृदय को भी बड़ी मायित्वा के साथ स्पर्श किया है। वह जनता का अपना साहित्य है। आज भारतवर्ष में 'रामचरितमानस' का बड़ा आदर है और उसकी चौपाइयाँ एक अपठ किसान के मुख से भी सुनायी पड़ती हैं। हिन्दी-साहित्य का यह सबसे लोकप्रिय काव्य है। अन्य भाषाओं में भी तुलसीदास की इस अमर कृति का अनुवाद हो गया है।

आधुनिक काल में श्री मैथिलीशरण गुप्त हिन्दी के सबसे बड़े कवि हैं। उनकी रचनाएँ जनता में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। श्री सुमित्रानन्दन पन्त, श्री मूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', श्री रामकुमार वर्मा, श्री महादेवी वर्मा आदि हिन्दी काव्य-जगत की आधुनिक भावना-धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी कविताएँ विश्व-साहित्य में स्थान पाने योग्य हैं।

उपन्यास-क्षेत्र में प्रेमचन्द ने जैसा नाम पाया है वैसे हिन्दी के किसी दूसरे लेखक ने नहीं पाया। प्रेमचन्द हिन्दी-संसार की एक मूल्यवान् निधि है। उन्होंने अपने उपन्यासों तथा कहानियों के द्वारा हिन्दी-साहित्य को

जो स्न प्रदान किये हैं, उनमें वह तो गोस्वामिन हुआ ही है, उन विश्व-साहित्य को भी एक मूल्यान्तर्दान मिला है।”

हिन्दी-साहित्य में श्री जयशंकर 'प्रसाद' ने नवीन नाटक की रचना करके वह गिद्ध कर दिया है कि हिन्दी नाटक आधुनिक नाट्य-कला में किमी भी नाया के साहित्य में पीछे नहीं है। उन्होंने अपनी नाट्य-कला के द्वारा भारतीय जाय-संस्कृति तथा कला का जो पुनरुज्जीवन किया है, वह उनकी साहित्य और मनाज की एक स्थायी देन है।

अन्या-मास्त्रिय के श्री पहिमन्त्र, श्री गन्धर्व और श्री रसोन्माय
अमर हैं । यदि अन्या-मास्त्रिय में कुछ भी न रहें तो भी रसोन्माय
उन अमर अनाम के शिष्य साक्षी हैं । अ० रसोन्माय का हृदय श्री ३
मन्त्र में नहीं है और उनका पुत्र भी गीत चुका, परन्तु उन्होंने
हृदय-हृदिय से निष्पात किया है । विश्व-मास्त्रिय की अपर परा
है । और वह भी उनका मान है । अन्या के ही मन्त्राली, नाट्यकार
और शिष्या नहीं हैं, प्र-सूत का पुत्र के मन्त्र अमर ही हैं । अ
नाम ही के मन्त्रों कायक और आनन्द-हृदय के साक्षी हैं ।

गुनरत्नी-भाटि-इ, नयाश्री-भाटि-इ तथा नाभिद-इत्यू आर मं
नाशि-इ न नी वरी इति हो । एवम्यापना-इत यूरी इति योय
न विद्वन् नाभिद-इत्यू है ।

कन।

ਮਾਨਯੋਗ ਕਰਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼

आज भारत में, साहित्यिक जगत में एक युग से, आदर्शवाद तथा यथार्थवाद की कलह एक युग याद-विवाद रचा हो गया है। कला में यथार्थ का चित्रण होना चाहिए—नसार तो हम जैसा देखते हैं, उसका ज्यों का त्यों चित्रण ही करना है, ऐसा यथार्थवादी का मत है। दूसरी ओर आदर्शवादी का मत यह है कि नसार में बुराई-भलाई सभी को हम देखते हैं, परन्तु यह सभी यथार्थ नहीं—सत्य नहीं। इसलिए हमें जो वास्तव में सत्य है—आदर्श है, उसीका चित्रण करना चाहिए। एक मत के अनुसार कला में इन दोनों का समन्वय ही उचित मार्ग है।

यहाँ इन दोनों यादों की समीक्षा अभिप्रेत नहीं है। हमें तो यह देखना है कि ये दोनों याद भारतीय-कला के आदर्शों के कहीं तक अनु-कूल हैं। यह हम ऊपर ही कह चुके हैं कि भारत में कला का उद्देश्य अन्य देशों की कला-साहित्य की अपेक्षा भिन्न है। भारतीय और विशेषतः आर्य-जीवन का लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार फलों की प्राप्ति। इन्हीं को धार्मिक भाषा में पुरुषार्थ कहा गया है। मानव-जीवन का लक्ष्य है इन चारों की सिद्धि। वस्तु इसी चरम लक्ष्य की दृष्टि में रखकर समस्त भारतीय साहित्य तथा कला का निर्माण हुआ है। इस प्रकार कला, भारतीय की दृष्टि में, पाश्चात्य देशों की तरह, मनोरंजन का साधन नहीं है, प्रत्युत वह जीवन की मुक्ति-वधन से मोक्ष की ओर ले जाने का एक मार्ग है—साधन है। जिस प्रकार योग-साधना द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य-साधन और कला की उपासना द्वारा भी ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है।

भारतीय आर्य साहित्य में वधन से मुक्ति की ओर जाने के लिए जो भावना ओतप्रोत है, उसका हमारे धार्मिक सिद्धांतों से गहरा संबंध है। ससार भर में जायों (हिन्दुओं) के सिवा शायद और कोई जाति पुनर्जन्म तथा कर्म-फल के सिद्धान्तों में विश्वास नहीं करती। पाश्चात्य देशों में तो इसी जन्म में मनुष्य को भोग-विलास का जीवन बिताकर अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करनी है। उनकी जनता का परलोक-जीवन

ही अवाञ्छनीय प्रभाव जनता के हृदय पर पड़ा है—वह यह कि आज समाज में यदि किसी ब्राह्मण की उच्च स्थिति है, तो वह उसके अपने कर्मों के कारण है और यदि आज किसी दलित जन की दुर्दशा है तो वह उसके कर्मों का फल है। इसलिए समाज की जैसी स्थिति विद्यमान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि आज नारी-जाति की हीन दशा है, तो वह उनके कर्मों का फल है, यदि आज मजदूर पूँजीपतियों के अत्याचारों के शिकार हैं तो अपने प्रारब्ध के कारण, और यदि आज किसान-वर्ग पीड़ित हैं तो अपने कर्मों के फल से। इस प्रकार की विचारधारा ने भारतीय समाज का बड़ा अनिष्ट किया है और जनता में भाग्यवाद तथा नैराश्य को जन्म देकर उसे अपग और शक्तिहीन बना दिया है। प्रत्येक सुधार-आन्दोलन में इस विश्वास ने बड़ी ठेस पहुँचायी है।

यह विश्वास सर्वथा गलत है। मनुष्य के कर्मों का फल मिलता है, परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता नहीं है। मनुष्य वर्तमान में जो कार्य करता है, वही आगे उसके प्रारब्ध-कर्म बन जाते हैं। इसलिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से सुयोग मिलना चाहिए जिससे वह अपना प्रारब्ध-निर्माण भली भाँति कर सके।

आधुनिक भारतीय साहित्य पर समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी आदर्शवाद तथा डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रहस्यवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा है। इस युग के साहित्य की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) राष्ट्रीय जीवन की भाँति साहित्य में भी स्वातन्त्र्य-प्रियता का दर्शन हमें मिलता है। कविता को छन्द-शास्त्र के बन्धन मुक्ति के प्रयत्न में भी यह स्वाधीनता-प्रेम ही है।

(२) साहित्य आज किसी एक वर्ग की आकांक्षा की पूर्ति का साधन नहीं रहा है। वह अब जनता का साहित्य बन गया है। उसमें नैतिकता व लोक-कल्याण की भावना की प्रतिष्ठा फिर से नये ढंग से हो रही है।

(३) आज का साहित्य जीवन के अधिक निकट हो गया है और उसमें

मुन्धर तब तक नहीं है जब उसे देना ही निश्चित करनी है। इसलिए तबि पहले योगी और मननित हैं, ताकि उनका हृन् का जन्म ज्ञान, योग और साधना के द्वारा ही सम्भव है।

सगीत-कला

प्राचीन काल में संगीत-कला का भाग्य ने बड़ा प्रचार था। मृदंग-गण वगैरह तथा अन्य उत्तरीयों पर सान-गान से जनता का मनोरंजन करते थे। सानवेद ही संगीत का आदि-ग्रन्थ माना जाता है। ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी में भरत मुनि ने अपने नाट्य-शास्त्र की रचना की। यह नाट्य-शास्त्र ही भारतीय संगीत पर सबसे पुराना ग्रन्थ है जो आज प्राप्य है। नाट्य-शास्त्र में मुख्यतः नाटका के सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया है, परन्तु इसमें संगीत-कला के विषय में भी विवेचन दिया गया है। इसके बाद १३वीं शताब्दी में काश्मीर के शारंगदेव ने 'सगीत-रत्नाकर' नामक ग्रन्थ लिखा। संगीत-कला पर यह बड़ी प्रामाणिक पुस्तक है और उस समय से अतक संगीतज्ञ तथा संगीताचार्यों ने इससे प्रेरणा प्राप्त की है। चौदहवीं सदी में लोचन कवि ने राजतरंगिणी की रचना की। यह भी संगीत-कला की मीमांसा करती है। अकर के शासन-काल में खानदेश में पुरीक विठ्ठल का जन्म हुआ। उन्होंने सद्गुण-चन्द्रोदय, रागमाला, रागमजरी और नर्तन-निर्णय ग्रन्थ लिखे। सत्रहवीं शताब्दी में जहोवाश ने 'सगीत-पारिजात' की रचना की। इसी काल में गड देश के राजा महाराजा हृदयनारायण देव ने भारतीय संगीत पर 'हृदय-प्रकाश' नामक एक बड़ी उत्तम पुस्तक लिखी। शाहजहाँ के शासन-काल में भाव भट्ट ने संगीत पर तीन पुस्तकें लिखी—अनुपसंगीतरत्नाकर, अनुपकुपा और अनुप-विलास। इसके बाद हमें इस कला पर कोई रचना प्राप्त नहीं होती। आधुनिक काल में श्री बी० एन० भातखण्डे ने संस्कृत में दो ग्रन्थ संगीतशास्त्र पर लिखे हैं—लघु संगीतम् और अभिनव रागमजरी। ये दोनों भारतीय संगीत पर अन्तिम ग्रन्थ हैं। इसके बाद कोई भी ग्रन्थ नहीं लिखा गया।

मेर	वरा	श्रावण-भाद्रपद
भैरव	हेमन्त	आश्विन-कार्तिक
श्री	हेम	अगहन-पौष
मालकोश	शिशिर	माघ-फाल्गुन

संगीतज्ञों ने एक दिन-रात्रि को एक वर्ष मानकर संगीत के लिए उसका ६ ऋतुओं में विभाजन किया है। इस प्रकार प्रत्येक काल-भाग के लिए भी एक-एक राग निर्धारित किया गया है—

भैरव	प्रातः ८ बजे से ८ बजे तक,
हिजोला	प्रातः ८ से १२ तक,
मेघ	मध्याह्न-काल १२ से ४ तक,
श्री	सायंकाल ४ से ८ तक,
दीपक	रात्रिकाल ८ से १२ तक,
मालकोश	मध्यरात्रि १२ से प्रातःकाल ४ तक,

भारतवर्ष में प्राचीन काल से दो प्रकार का संगीत प्रचलित है—
 मौखिक (vocal) और वाद्य-यंत्र द्वारा (Instrumental music)। तबला, सितार, वीणा, हारमोनियम, जल-तरंग, सरोज, पखावज, वायलिन आदि वाद्य-यंत्रों द्वारा गायन किया जाता है। आधुनिक समय में संगीत-कला के पुनरुज्जीवन तथा उसके प्रचार में दो महानुभावों ने सबसे अग्रगण्य भाग लिया। वे हैं महाराष्ट्र के संगीताचार्य पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर और संगीत-कला-विशारद श्री भातखण्डे।

प्राचीन प्रणाली के संगीत में बम्बई के संगीत-समर्थ श्री अल्लादिया खाँ और श्री फैयाज खाँ हैं। लाहौर के प्रो० दिलीपचन्द वेदी भारत के सर्वश्रेष्ठ स्याल-गायक हैं। प्रो० नारायणराव व्यास तथा श्री वी० एन० पटवर्धन प्राचीन संगीत के आचार्य हैं। उस्ताद अल्लाउद्दीन खाँ भारत में सर्वश्रेष्ठ सरोद-गायक हैं। तबला में आबिदहुसैन अन्तर्राष्ट्रीय स्याति के कला-विशारद हैं। इलाहाबाद के श्री गगनचन्द्र चट्टोपाध्याय, जो गगनबाबू के नाम से प्रसिद्ध हैं, वायलिन के सर्वश्रेष्ठ गायक हैं।

इस प्रकार आज भारत में संगीत कला के पुनरुज्जीवन के लिए जो

नृत्य की परम्परा को कायम रखने में एक सीमा तक योग दिया ।

देश में राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन और राजनीतिक नवचेतना में स्फूर्ति पाकर कला-प्रेमियों ने संगीत तथा नृत्य-कला के पुनरुज्जीवन के लिए फिर से प्रयत्न किया । १०-१५ वर्षों में ही इस क्षेत्र में कलाकारों ने बड़े मनोयोग से कार्य किया है । जिसका फल आज प्रत्यक्ष दीख पड़ता है । आज नृत्य-कला का संगीत में भी कहीं अधिक आदर है । बड़े-बड़े नुमस्त्रुत तथा सभ्य परिवारों की कुमारिकाएँ, बालिकाएँ और स्त्रियाँ आज नृत्य-कला को सीख रही हैं ।

भारतीय नृत्य के तीन भेद हैं — (१) नाट्य (२) नृत्य और (३) नृत्त ।

नाट्य में नर्तक या नर्तकी रगमच पर नाटक के अन्य पात्रों के साथ नृत्य करता या करती है । नृत्य में राग, ताल और भाव तीनों की आवश्यकता होती है, परन्तु उसमें भाव का ही प्राधान्य होता है । और इसमें नर्तक या नर्तकी ऐतिहासिक या पौराणिक काल के किसी वीर नायक या नायिका के जीवन की किसी सामान्य घटना को अभिव्यक्त करता या करती है । नृत्य में ताल की प्रधानता होती है । स्वर और ताल के साथ नाचना पड़ता है । नृत्त दो प्रकार का होता है— (१) ताण्डव (२) लास्य । शिवजी के नृत्त को ताण्डव तथा पार्वती के नृत्त को लास्य कहा जाता है । इसी कारण पुरुष ताण्डव करते हैं और स्त्रियाँ लास्य करती हैं ।

नृत्य में भाव, रस, राग, ताल और अभिनय होता है । नर्तक में जो भाव होते हैं वह उन्हें किसी न किसी रस द्वारा स्वर और ताल के साथ अपने अभिनय द्वारा व्यक्त करता है ।

भावों का अभिनय चार प्रकार से किया जाता है— (१) आंगिक (२) सात्विक (३) वाचिक और (४) बाह्य ।

१ आंगिक अभिनय में नर्तक मुद्रा-प्रदर्शन अर्थात् अंगों और विशेष रूप से हाथों के सकेतों द्वारा भाव प्रदर्शन करता है ।

२. सात्विक अभिनय में नर्तक आँसू, कपन, स्वरभेद, भय, मूर्च्छा, मुस्कान, आदि शारीरिक अवस्थाओं के द्वारा भाव प्रदर्शन करता है ।

३ वाचिक अभिनय में शब्द या ध्वनि द्वारा भाव-प्रदर्शन किया जाता है ।

४ वाह्य अभिनय में वस्त्रालंकार तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है ।

भारतवर्ष में आजकल दो प्रकार के नृत्य सबसे अधिक प्रचलित हैं—कथक और कथाकली । कथक लास्य नृत्य है और कथाकली ताण्डव ।

कथक नृत्य

इस नृत्य में नृत्य लय और ताल में बँधा होता है । इस नृत्य में अधिकांश में शृंगार रस से परिपूर्ण मनोभावों की अभिव्यक्ति की जाती है । नृत्य में पग, हस्त, गर्दन, भवे, और खास एक दूसरे से मिलकर तान में चलते हैं । उत्तरी भारत में इस नृत्य का अधिक प्रचार है ।

कथाकली-नृत्य

इस नृत्य का दक्षिण भारत और विशेष रूप से केरल प्रान्त में बड़ा प्रचार है । परन्तु यह अब समस्त भारत में लोकप्रिय हो गया है । इस नृत्य में मुद्रा के प्रदर्शन द्वारा नृत्य किया जाता है । इसमें हाथ, हथेली और उँगलियों के भिन्न संकेतों द्वारा भावों का प्रदर्शन किया जाता है । एकाकी कर-मुद्राएँ और समुक्त-कर-मुद्राएँ कुल ६० हैं जिनका नृत्य में प्रयोग किया जाता है । इन दोनों प्रकार की कर मुद्राओं द्वारा ५०० में अधिक शब्द व्यक्त किये जा सकते हैं । परन्तु मुख्यतः ५ एकाकी मुद्राओं और कुछेक समुक्त-मुद्राओं का प्रयोग सामान्यतया किया जाता है ।

कुछ नृत्य-कला के आचार्यों के अनुसार कथाकली में लास्य तथा ताण्डव दोनों प्रकार के भेद होते हैं । अर्थात् ताण्डव में वीर तथा भयानक और रौद्र रस की अभिव्यक्ति की जाती है और लास्य में शृंगार, भक्ति तथा करुण रस की ।

आजकल भारतीय नाट्य-कला के आचार्यों, समार-प्रसिद्ध नृत्य-कला-विगारद श्री उदयशंकर भारती में नृत्य-कला के पुनरुज्जीवन के लिए उद्योग

कर रहे हैं। उन्होंने यूरोप और अमरीका में वर्षों तक अपनी कला का प्रदर्शन करके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। अलमोडा की एक उपत्यका में, प्रकृति की मनोरम गोद में उन्होंने भारत-सांस्कृतिक-केन्द्र (India Culture Centre) की स्थापना करके नृत्य के पुनरुज्जीवन के लिए प्रयत्न आरम्भ कर दिया है।

स्वयं श्री उदयशंकर के शब्दों में “इस केन्द्र में सम्मिलित होनेवाले कलाकार गतिमय ससार को देखने, उसकी रंग-विरंगी रूपरेखा को परखने और सजीव मूर्ति-रूप में उसे व्यक्त करने तथा उसकी नाना प्रकार की कोमल और भावपूर्ण भंगियों को साकार रूप से दृष्टिगोचर करने और कराने की शिक्षा दी जायगी। इसके पाठ्य-क्रम तथा अभ्यास की नींव शास्त्रोक्त रीति से होते हुए भी शरीर की सहज सुन्दर भाव-भंगी के आधारभूत होंगे। छात्रों में सक्रिय कल्पना-शक्ति की वृद्धि के लिए उन्हें कुछ खास तरह के ऐसे अभ्यास बताये जायेंगे, जिनसे वे चित्र को एकाग्र और भावुकता को बढ़ाने में समर्थ होते हुए अपनी भूलें और कमियाँ स्वयं समझ सकें।

यह तो है सांस्कृतिक-केन्द्र का लक्ष्य। जत्र कला के विषय में कलाकार उदयशंकर के विचार भी मननीय हैं—

“यद्यपि कलात्मक दिग्दर्शन वास्तविक जीवन से निम्न होना है, परन्तु वह आधारित रहता है जीवन पर ही। भारत में हम कला को विविध दृष्टिकोण से देखते हैं। इनमें एक है मृदा-तो की सहायता से कला का दिग्दर्शन कराना। इसमें वास्तविक से, जो रंगमंच पर किया जाता है, अधिक अर्थसूचक होता है और यही रस को अनुभवि है। यह जल के ऊपर के बुलबुलों की भाँति नहीं बल्कि समुद्र के स्थायी अन्तःस्त्रोत की भाँति होता है। दर्शक और कलाकार का वास्तविक समागम तभी सम्भव है जब कि कलाकार रस के इन स्त्रोतों की सहायता से सुर उठ सके और उसे समवेत रसिक-मण्डली तक पहुँचाने में समर्थ हो सके। तिरुं टेक्निक याद करने से काम नहीं चलेगा। कलाकार का समूचा जीवन कलात्मक बनाना होगा जिससे वह समुद्र-स्त्रोत की

व्यक्त कर सके और तभी वह आध्यात्मिक विकास तथा भावना में प्रवेश कर सकेगा।”^१

श्री उदयशंकर, बान्धव मे, आर्य संस्कृति और कला के एक महान् उन्नायक हैं। उन्होंने भारत की मृतप्राय नृत्यकला को पुनरुज्जीवित करके उसमें मौलिकता तथा नवीनता की स्थापना की है। नृत्य भारत में अश्लीलता तथा कामुकता का बोधक बन गया था, पर उन्होंने उसे अपनी साधना तथा सिद्धि द्वारा एक दैवी कला के रूप में फिर से उपस्थित किया है।

भारत में नृत्य-कला का प्रचार दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। कुमारी कनकलता, कुमारी अमलानन्दी, श्री साधना बोन, रुक्मिणीदेवी, श्री रागिनीदेवी (अमरीकन महिला) और श्रीमती मीनाक्षी रामाराव ने इस कला में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। और भारत के लिए विशेष गौरव की बात यह है कि भारत में बाहर इन कलाकारों के प्रदर्शनों ने प्रभावित होकर अमरीका व यूरोप में भारतीय नृत्य अधिक लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। आज से प्रायः ३०-३५ वर्ष पूर्व अमरीका में मिन रूथ सेंट डेनिस, ने जो अमरीका में हिन्दू नृत्यकला की आचार्या मानी जाती हैं, अपने भारतीय नृत्यों से लोगों की श्रद्धा और प्रशंसा प्राप्त की। वर्तमान समय में ला-मेरी नाम की अमरीकन महिला अमरीका में भारतीय नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही है।

चित्रकला

चित्र-कला भी भारत में प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठित है। यो तो चित्र-कला के सवध में अनेक प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है, परन्तु विष्णु धर्मोत्तर पुराण के ‘चित्रसूत्र’ अध्याय में उसका विस्तृत और सरस वर्णन है। डा० स्टेला क्रामरिश ने अंग्रेजी भाषा में इस अध्याय का अनुवाद किया है। डा० आनन्द कुमार स्वामी ने भी इसका अनुवाद

किया है। श्री नान्हालाल चमनलाल मेहता आई बी एस के मतानुसार 'शिल्प, नृत्य और चित्र-कला का महत्त्व समझने के लिए 'चित्रसूत्र' इतने महत्त्व का ग्रन्थ है कि उसका हिन्दी में किसी योग्य व्यक्ति द्वारा प्रामाणिक अनुवाद तुरन्त कराना चाहिए।' १

उपर्युक्त ग्रन्थ के आरम्भ में मार्कण्डेय मुनि ने लिखा है—“विना तु नृत्यशास्त्रेण चित्रसूत्रमुदुविदम्।” नृत्य शास्त्र के अभ्यास के बिना 'चित्र सूत्र' समझना कठिन है।

सन् ११२९ में चालुक्य वंश के नरेश नोमदेव के भूपति ने 'मान-सोल्लास' नामक ग्रन्थ में चित्रकला का विवेचन किया और १६ वीं शताब्दी में श्री कुमार ने शिवरत्न नामक ग्रन्थ लिखा जिसमें चित्रकला का उल्लेख है।

वात्स्यायन के 'काभसूत्र' ग्रन्थ में चित्र के ५ अंग बताये गये हैं जो ये हैं

- १ स्वभेद (आकृतिभेद) २ प्रमाण ३ भाव ४ वास्तव-सौम्यता
- ५ सादृश्य और ६ शैलिक भग (रंगों का मिश्रण) ।

भारतीय चित्रकला के अन्तर्गत ७ प्रकार के चित्रों का उल्लेख मिलता है

- १ भित्ति-चित्र—ये चित्र भग्ना, भविष्य और वास्तविकता की दीवारों पर बनाये जाते हैं। अजन्ता भी गुफा में इसी प्रकार के चित्र हैं।
- २ चित्रपट—ये चित्र कपड़े या तानज पर बनाये जाते हैं।
- ३ चित्र-कागज—ये चित्र पत्थर या लकड़ी पर बनाये जाते हैं।
- ४ धृति-चित्र—ये चित्र रंगों से पृथ्वी पर बनाये जाते हैं। आज-कल मनुष्यप्रान्त तथा अन्य प्राणी भी चित्रों को देख कर अजन्ता की धृति रंगों से पृथ्वी पर चित्र बनाती है। उन्ने चित्र देखते ही जान लेते हैं।

चित्रों का रंग चित्रकला के अन्तर्गत होता है। इसे चित्रकला के अन्तर्गत

नेताओं तथा अभिनेत्रियों का पूरा हाव है। ऐसे भी बहुत से चित्र मिलेंगे जिन्हें मुस्लिम चित्रकारों ने बनाया है।

अजन्ता की गुफाओं की चित्र-कला

निजाम राज्य हैदराबाद में औरंगाबाद से ५० मील दूर पर अजन्ता प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ चट्टान में खोदकर ३२ गुफाएँ बनायी गयी हैं। जिनमें २९ विहार और ३ चैत्य हैं। अजन्ता की इन गुफाओं में आज से प्रायः दो हजार वर्ष पूर्व चित्र बनाये गये थे। अजन्ता की तरह एलोरा में भी चित्र-कला की शोभा दर्शनीय है। परन्तु इन दोनों में अन्तर यह है कि अजन्ता की कला विशुद्ध बौद्धकला है और एलोरा की कला में बौद्ध, जैन और हिन्दू-कलाओं का मिश्रण है। इन चित्रों से तत्कालीन जनता के रीति-रिवाजों, संस्कृति और धार्मिक-जीवन का पूरा पता लग जाता है। इन विहारों में महात्मा बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं को कलाकारों ने बड़े मार्मिक तथा प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। वास्तव में ये भारतीय कला के आश्चर्य-जनक प्रतीक हैं, जो आज भी उसकी सर्वश्रेष्ठता को पुकार-पुकारकर बताते हैं।

श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने चित्र-कला में जो युगान्तर उपस्थित किया है तथा स्व० श्री शारदाचरण उकील ने जिन परम्परा को चलाया है उनमें इस कला में बड़ी उन्नति हुई है। आजकल नन्दगाल दसु, अमितकुमार हालदार आदि अच्छे चित्रकार हैं।

वास्तु-कला

प्राचीन भारत में जहाँ आर्य-जाति ने अन्य कलाओं में उन्नति की वहाँ वास्तु (भवन-निर्माण) कला में भी आश्चर्यजनक उन्नति की थी। प्राचीन संस्कृत साहित्य तथा विशेषतः रामायण और महाभारत के अध्ययन से यह स्पष्टरूप से विदित हो जाना है कि आर्यों ने अपने निवास-स्थान बनाने, राज-शाला, धर्मशाला तथा अन्य सार्वजनिक भवन आदि बनाने में वास्तु-कला के सिद्धान्तों ने काम लिये थे। धानु के भी नवान

नागरिक जीवन और कला

नागरिक जीवन को सर्वश्रेष्ठ और समाजोपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे संस्कृति के ढाँचे में ढाला जाये। संस्कृति का अर्थ है—परिष्कार और संस्कार। मानव-जीवन को सुसंस्कृत बनाने के लिए कला ही सर्वोत्तम साधन है। प्रत्येक युग में जब मानव-समाज ने अभ्युदय प्राप्त किया तब ऐसा वह कला के विकास द्वारा ही कर सका। वास्तव में मानव-एकता और विश्व-वन्धुत्व की स्थापना करने में कला का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है। जब-जब समाज ने विशुद्ध कला की साधना की तब-तब उसने शान्ति, समृद्धि और मानव-एकता को प्राप्त किया और जब-जब समाज कला के नाम पर विलासिता और कामुकता में लीन होगया, तब-तब उसे पतनोन्मुख होना पड़ा है। इतिहास इसका ज्वलन्त प्रमाण है। इसकी सिद्धि के लिए भारतीय इतिहास से दो प्रमाण दे देना उचित होगा।

मौर्य-काल में समाज कितना प्रगतिशील था और जनता में कितनी सुख-समृद्धि थी। उस काल में मानव-समाज में विशुद्ध कला की पूजा की जाती थी। परन्तु मुगल काल में जब कला को राजाओं तथा नवाबों के राज-प्रासादों में परिमित कर—जनता के बीच से उसे पृथक् कर—उनके मनोरंजन तथा विलासिता का साधन बना दिया गया तब हिन्दू-कला के पतन के साथ भारतीय जीवन और चरित्र का भी पतन हो गया। यही कारण है कि हम मौर्य-कालीन चित्रकला में भक्ति-भावना की उलक पाते हैं—उसमें जीवन के बंधन से मुक्ति पाने की साधना का स्पष्ट आभास मिलता है। परन्तु मुगल काल की कला में हम कामुकता, निम्न-कोटि के शृंगार और विलासिता की छाया पाते हैं। कारण स्पष्ट है कि मौर्य-काल में कला जन-समाज में एकता स्थापित करने के लिए थी, परन्तु मुगल-शासन में वह अपने इस उच्च ध्येय से भ्रष्ट कर दी गयी और एक वर्ग-विशेष के मनोरंजन की साधन बन गयी।

कला का लक्ष्य मानवता को मुक्ति में ओर ले जाना है। यह मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम करती है। यह समाज में एकता

की प्रतिष्ठा के लिए एक सर्वोत्कृष्ट साधन है ।

वर्तमान काल में हम जो विश्व-मस्कृति तथा समाज-एकता के विनाश का भयानक दृश्य देख रहे हैं उसका कारण है सच्ची कला की उपासना की उपेक्षा । वैज्ञानिकों ने बड़े चिंतन तथा परिश्रम के बाद जिन नवीन-नवीन आविष्कारों तथा वैज्ञानिक चमत्कारों का आविर्भाव मानव-कल्याण के लिए किया था, उनका प्रयोग आज मानवता के विनाश के लिए हो रहा है ।

कला और विज्ञान इन दोनों का मानव-जीवन के उत्कर्ष में महान् स्थान है । जिस प्रकार मनुष्य-शरीर में मस्तिष्क और हृदय का स्थान है, उसी प्रकार मानव-जीवन में विज्ञान और कला का स्थान भी है । विज्ञान मानव-मस्तिष्क की उपज है और कला का स्रवण हृदय से है । विज्ञान विचार-प्रधान है—वह सत्य की जाँच करता है और कला भावना-जगत में उस सत्य की प्रतिष्ठा करती है । एक का विकास तथा उत्कर्ष दूसरे पर निर्भर है । एक की अशुद्धि का प्रभाव दूसरे पर अनिवार्य है । यदि हृदय किसी तरह विकारपूर्ण हो जाये तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़े बिना न रहेगा और फलतः सम्पूर्ण शरीर उस विकारपूर्ण हृदय से प्रभावित हो जायेगा । इसी प्रकार यदि मानव-जीवन में कला अपने उद्देश्य या लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाये तो विज्ञान भी उससे प्रभावित हुए बिना न रहेगा ।

आज ससार में जो भीषण ताण्डव हो रहा है और जिसके फलस्वरूप मानवता का सहार हो रहा है, उसका मूल कारण यही है कि पाश्चात्य देशों ने कला को भ्रष्ट कर उसे अपने विलास का साधनमात्र बना लिया है । इसी कारण आज वहाँ कला और विज्ञान दोनों में कोई स्रवण नहीं रहा है । कला-शून्य जीवन में विज्ञान आज कल्याण के न्याय पर सर्व-नाश की वर्षा कर रहा है ।

अतः सारांश यह है कि नागरिक-जीवन में कला—विशुद्ध कला को फिर से उसी उच्चासन पर बिठाया जाये जिसने वह मानव-समाज में एकता की स्थापना कर भके ।

संस्कृति

संस्कृति क्या है ?

‘संस्कृति’ शब्द संस्कृत से बना है। संस्कृत का अर्थ है शुद्ध किया हुआ, परिमार्जित, परिष्कृत, सँवारा हुआ। संस्कृत विशेषण है और संस्कृति सज्ञा है। अतः संस्कृति का अर्थ हुआ शुद्धि, परिमार्जन तथा परिष्कार। मानव-समाज के सामाजिक जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनानेवाली जो एक प्रवृत्ति है, उसी का नाम संस्कृति है। प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक सर मॉरिस ग्वायर ने अपने एक भाषण में संस्कृति के सबब में जो विचार प्रकट किये हैं उनसे इसका अर्थ और भी स्पष्ट हो जायेगा।

“मैं यह कहना चाहूँगा कि सच्ची संस्कृति का मुख्य निर्देशक सहानुभूति है, दिखावा अथवा उसका दावा नहीं। पांडित्य का भांडार, कला का ज्ञान तथा मनुष्यों व पुस्तकों से परिचय ‘संस्कृति’ बनाते हैं, ऐसा मैं नहीं समझता, पर संस्कृति जिससे बनती है वह वह वृत्ति है जो इन सबके मिल जाने से उत्पन्न होती है। सच्ची संस्कृतिवाले मनुष्य में मूल्य आँकने और ठीक-ठीक नापतोल की योग्यता मिलती है। और ऐसे मनुष्य के हृदय में कभी ऐसा विचार आ ही नहीं सकता कि वह वह नहीं है जो दूसरे मनुष्य हैं, या जो मानवता सबमें व्याप्त है उसे भूल जायें।”

संस्कृति के सम्बन्ध में योग्य विद्वान् ने जो अपना मन्तव्य प्रकाशित किया है, उससे शायद ही किसी सच्चे सुसंस्कृत व्यक्ति का मतभेद हो। वास्तव में संस्कृति का प्रयोजन मानव-समाज की एकता ही है। एक संस्कृत पुरुष के लिए सब मानव समान हैं। वह न जाति के भेद-भाव को मानता है और न धर्म के भेद को। संस्कृति मानव-एकता का अनुभव कराती है। वह मनुष्य को यह सिखाती है कि सब मानव बराबर हैं, कोई मानव किसी दूसरे से भिन्न नहीं।

आर्य-संस्कृति के आदर्श

मानव-शरीर के तीन मुख्य भाग हैं—निर, हृदय और पंड। नस्तिष्क के भी तीन महत्वपूर्ण भाग हैं—अनुमति, भाव और इच्छा।

उसी प्रकार संस्कृति के भी, जिसका मानव-जीवन के विकास और मानसिक उत्कर्ष से सम्बन्ध है, तीन अंग हैं। उसका दर्शन और विज्ञान, उसका धर्म और कला और उसका कर्मकाण्ड। इन तरह संस्कृति ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय है।

आर्य-संस्कृति के दार्शनिक पहलू पर विचार करने में यह स्पष्ट जाता है कि उसका सबसे प्रधान लक्ष्य लोकसमग्र—मानव-मात्र का कल्याण है। उसकी दृष्टि में केवल मानव ही नहीं सभी प्राणी समान हैं। जाति, रंग तथा मत के भेदभाव को नहीं मानती।

आर्य-संस्कृति का आदर्श यह है कि मानव विश्व में धर्म, अर्थ और काम की साधना द्वारा अभ्युदय को प्राप्त करना हुआ नि श्रेयस की मित्रता के लिए पुरुषार्थ करे। यह तो निर्विवाद है कि आर्य-संस्कृति आध्यात्मिक है, उसमें आत्मोत्कर्ष को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है। परन्तु इसमें तात्पर्य यह नहीं कि वह भौतिक उन्नति का विरोध करती है।

आर्य-संस्कृति के अनुसार मानव का यह धर्म है कि वह धर्मशास्त्रों के अर्थ को प्राप्ति करे—वह अपनी जीविका धर्म-युक्त कार्यों में ही कमाये। उसे इसके लिए अवध का आश्रय न लेना चाहिए। यह है आर्य-संस्कृति का दर्शन-शास्त्र।

आर्य-संस्कृति का भक्ति-पक्ष सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का सा समन्वयपूर्ण समन्वय है। सरस्वती का अर्थ है विद्या, ज्ञान-विज्ञान, लक्ष्मी का अर्थ है, धन-सम्पत्ति और दुर्गा का अर्थ है शक्ति। मानव को अपने जीवन में इन तीनों की आवश्यकता है। वह पहले सरस्वती की पूजा करे अर्थात् ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे, उसमें वह लक्ष्मी की पूजा करने में समर्थ होगा। वह ज्ञान-विज्ञान द्वारा उद्योग-धन्यो में उन्नति करके धन पैदा कर सकेगा और इस तरह धन में उसे शक्ति प्राप्त होगी। वह शक्ति केवल पारमार्थिक ही नहीं होगी, क्योंकि उसके धन में ज्ञान-विज्ञान की प्रेरणा होगी। वह शक्ति केवल 'आर्थिक' नहीं होगी क्योंकि उसमें आध्यात्मिकता का अंग भी होगा।

आर्य-संस्कृति का तीसरा पक्ष है—स्वतंत्रता। ज्ञान और शक्ति के साथ

कर्म जाता है। आर्य-संस्कृति का सारा कर्मकांड पतञ्जलि के योगदर्शन के एक सूत्र में निहित है। यह सूत्र है—यम-नियम का। अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच 'यम' हैं और शौच, सतोय, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति ये पाँच 'नियम' हैं। जो सत्सार में सुखी जीवन बिताना चाहता है और उसके बाद पारलौकिक शान्ति की इच्छा करता है, उसे इन दस नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए।

संक्षेप में यही आर्य-संस्कृति का मौलिक स्वरूप है। आज के हिन्दु-समाज में, यद्यपि हम इन आदर्शों की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं पाते, तथापि यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि आज भी हिन्दु-जीवन न आदर्शों के अनुसार आचरण करना अपना धर्म मानता है।

आर्य-संस्कृति की प्रवृत्तियाँ

आर्य-संस्कृति का अनुशीलन करने पर आर्य-जीवन की कई विशेष-ताएँ व्यक्त होती हैं।

आर्य-संस्कृति की प्रथम और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि वह पारलौकिक आनन्द, शान्ति या मुक्ति को जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानकर मानव को भोगवाद से पद-पद पर सतर्क रखने की चेष्टा करती है। यह शरीर तथा जड़ जगत नाशवान् है इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आत्मा को— जो अजर है, अमर है, अजन्मा है तथा अनादि है—इस भोगवाद से पतित हो जाने से बचाना चाहिए। इसीलिए हिन्दु-जीवन में तपस्या, व्रत, दान दक्षिणा आदि का विशेष महत्त्व है।

आर्य-संस्कृति में व्यक्ति का उच्च स्थान है परन्तु यह समाज में ऊँचा नहीं है। वर्ण-व्यवस्था से बौद्धिक समाजवादी प्रवृत्ति का पूरा निर्देश मिलता है। समाज के हित के लिए मनुष्य को अपने हित का बलिदान करने की शिक्षा आर्य-संस्कृति का पुराना आदर्श है।

आर्य-संस्कृति अपनी समाजवादी प्रवृत्ति के कारण ही व्यापक पर जनित खोर देती है। यह भोगवाद को आन्तरिक तथा आध्यात्मिक अन्तर्द्वार में बाधक मानती है।

आर्य-सस्कृति में धर्म ओतप्रोत है। वह समाजनीति, अर्थनीति, और राजनीति सभी में विद्यमान है। वह वास्तव में जीवन की एक मूल प्रेरक शक्ति है।

आर्य-सस्कृति में हम सामजस्य की भावना पाते हैं। हम चाहे भाषा को ले, चाहे साहित्य को, चाहे कला को, चाहे सामाजिक जीवन को— सभी क्षेत्रों में सहयोग की भावना मिलेगी। मधर्प और वर्गवाद के लिए आर्य-सस्कृति में कोई स्थान नहीं है।

अरबी और मुस्लिम सस्कृति

भारत में अरबी सस्कृति का प्रवेश मुसलमानों के आगमन में हुआ। अरबी सस्कृति धार्मिक, सैनिकवादी और राजनीतिक है। यह एकेश्वरवादी और मूर्ति-पूजा-विरोधी है। अरबी सभ्यता में प्रचार की भावना ओत-प्रोत है। अरबी सस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता है धार्मिक प्रवृत्ति। हिन्दू सस्कृति के समान ही मुस्लिम सस्कृति में धर्म और ईश्वर की भावना ओतप्रोत है। मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर धर्म का प्रभाव है। इस्लाम के कानूनों का आधार भी कुरान ही है जो मनुष्य-कृत नहीं है। मुसलमानों की जीवनचर्या भी इस प्रकार निर्धारित की गयी है कि वे ईश्वर और धर्म को विस्मृत नहीं कर सकते। दिन में पाँच बार नमाज़ पढ़ना तथा शुक्रवार को मस्जिद में सम्मिलित रूप में नमाज़ पढ़ना उनकी धार्मिकता का एक प्रमाण है।

मुस्लिम सस्कृति में वीर-पूजा को ऊँचा स्थान प्राप्त है। वीर-पूजा का अर्थ इस हद तक लगाया गया है कि जो क़ाफ़िरो के माथे धर्म-युद्ध में अपना बलिदान करदे तो वह मोठा मर्याद को जाना है।

मुस्लिम सस्कृति में दानशीलता भी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। मुसलमान दान-वसिआ देना तथा इस्लाम की उन्नति के लिए मस्जिद बनवाना तथा धर्म-प्रचार के लिए दान देना अपना सर्वोच्च समझते हैं।

मुस्लिम सस्कृति में स्त्री की गरिमा तथा उसके मनोव्यवस्था की रक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था है। मुसलमान अपनी स्त्रियाँ ही कहे

परदे में रखते हैं और मुस्लिम कानून में भी ऐसी व्यवस्था की गयी है कि मुस्लिम स्त्री विधर्मी के साथ विवाह नहीं कर सकती। मुस्लिम पुरुष तो ईसाई, पारसी या यहूदी के साथ शादी कर सकता है।

मुस्लिम सस्कृति में मानवीय एकता तथा समानता पर अधिक जोर दिया गया है। सब मनुष्य परमात्मा की दृष्टि में समान हैं। मनुष्य को मनुष्य के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।

मुस्लिम सस्कृति में परिवर्तन

हमने अरबी सस्कृति की जो विशेषताएँ ऊपर बतलायी हैं, वे आदिम अवस्था की विशेषताएँ हैं। जब मुसलमान आने अरब देश को छोड़ कर विदेशों में इस्लाम के विस्तार के लिए गये तब उनकी सस्कृति पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा और उसमें परिवर्तन होने लगे।

मुस्लिम सस्कृति में जो परिवर्तन हो गया, उसका वर्णन श्री हरिभाज उपाध्याय ने इस प्रकार किया है—

“मुसलमान को यह सिखाया जाता है कि ‘हमारा ही मजहब दुनिया में सबसे अच्छा है; यही एक ईश्वर तक पहुँचने का सबसे बेहतर रास्ता है। जो खुदा को नहीं मानता वह काफिर है, काफिर खुदा का मुन्किर—ईश्वर-विमुख—है, इसलिए वह मार डालने के लायक है। जो एक भी काफिर को दोने इस्लाम में लाता है, वह खुदा की मेहर हासिल करता है—जिस तरह हो सके इस्लाम को बढाओ। इसी उपदेश में मुस्लिम सस्कृति और मुसलमानों के स्वभाव में पायी जानेवाली अमर्याद हितावृत्ति, अतर्हिण्यता का बीज है। मुसलमानों का यह उप हिंसक स्वभाव चाहे तत्कालीन अरब की परिस्थिति के कारण बना हो, चाहे पंगम्बर साहब के कुछ उपदेशों का दुरुपयोग करने के कारण बना हो—आज के सभ्य जगत् में वह आक्षेपयोग्य एवं अक्षम्य है।”

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि आधुनिक मुस्लिम सस्कृति ने

१ श्री हरिभाज उपाध्याय ‘धर्माभीजी का बलिदान और हमारा कर्तव्य’, पृ० ८४

की प्रथा को उठा दिया है। आज वहाँ मुस्लिम केवल एक ही पत्नी से शादी कर सकता है। अब वह एक साथ चार पत्नियाँ नहीं रख सकता।

आर्य-संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव

जब एक जाति दूसरी जाति के सम्पर्क में आती है तो स्वाभाविक रूप से उन दोनों में संस्कृतियों का आदान-प्रदान होता है। भारत में कई सदियों तक मुसलमानों का शासन रहा। उस समय भारत का राजधर्म इस्लाम होने के कारण उसका हिन्दू-संस्कृति पर भी बहुत प्रभाव पड़ा।

हिन्दुओं में जो कट्टरपथी थे उन्होंने इस्लाम के प्रभाव से अपनी रक्षा करने के लिए सामाजिक बन्धनों को और भी कड़ा बनाने का उद्योग किया और जातपात के नियमों का बड़ी कठोरता के साथ पालन किया जाने लगा।

वे मुसलमानों को म्लेच्छ कहते थे और उनके सम्पर्क तथा ससर्ग से बचने के लिए बड़े सतर्क रहते थे। अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए ही सामाजिक बहिष्कार की प्रथा शुरू हुई है।

इस्लाम के सम्पर्क में आने का प्रभाव यह हुआ कि हिन्दू समाज में जातपात की कुप्रथा ने अधिक भयंकर रूप धारण कर लिया और अस्पृश्यता का भी पालन बड़ी सतर्कता से किया जाने लगा। मुसलमानों से छूतछात की जाने लगी और जो लोग मुसलमानों के सम्पर्क में रहने लगे उनसे भी कट्टरपथी छूतछात करने लगे। इस प्रकार वे हिन्दू-समाज के लिए 'अस्पृश्य' बन गये।

हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था पर भी मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ा। हिन्दू-समाज में ऐसे अनेक मुखारक और धार्मिक नेता तथा महात्मा पैदा हुए हैं जिनके उपदेशों में इस्लाम के उपदेशों की झलक स्पष्ट हो दीव पड़ती है। रामानन्द, कबीर, नानक, चैतन्य, बल्लभाचार्य आदि ऐसे कितने ही सन्त पैदा हुए जिन्होंने जाति-प्रथा के विरुद्ध प्रबल प्रचार किया और हिन्दू-समाज में समता के आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए उपदेश दिये।

१. हेनरी ई० एलेन 'इस्लाम एण्ड सम मॉडर्न प्रॉग्रेस इन इंडिया' ('हिन्दुस्तान रिपब्लिक', जलाई १९३४)

भारत में मुस्लिम सस्कृति के प्रभाव में हिन्दुओं में परदा-प्रथा का विकास हुआ। मुसलमानों से अपनी मा-बहनों की रक्षा करने के लिए उन्हें परदे में रखा जाने लगा। इस तरह परदा हिन्दू-समाज का एक रिवाज बन गया।

मुसलमानों के आगमन से पहले हिन्दुओं की पोशाक बँनी वी जँनी हम राजपूत-काल के चित्रों में देवते हैं वे सिर पर पगड़ी बाँधने थे और देह पर एक बड़ा लम्बा चोगा-सा पहनने थे जो घुटनों से भी नीचे तक होता था। धोती तो बहुत ही पुरानी पोशाक है।

मुसलमानों का अनुकरण करके हिन्दू भी कुर्ता, पाजामा, अवकन शेरवानी आदि पहनने लगे। स्त्रियों के जाभूषणों में भी नये-नये नकशों का अनुकरण किया गया।

मुसलमान बादशाह तथा नवाब अपनी विशासिता के लिए बदनाम थे। मुगल-दरबार व्यभिचार और पाप-लीला का केन्द्र बन गया था। ऐसी दशा में हिन्दू महिलाओं का सतीत्व सकट में था। नवयुवतियों और कुमारियों का अपहरण और उनके साथ बलात्कार सामान्य घटना थी। इसी कारण हिन्दुओं में बाल-विवाह तथा अनमेल विवाह का रिवाज चल पड़ा।

हिन्दुओं के नैतिक जीवन पर भी मुस्लिम सस्कृति का बड़ा प्रभाव पड़ा। समाज में मदिरा-पान और विलासिता अधिक बढ़ गयी। अज्ञान तथा धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण सैकड़ों प्रकार के अन्ध-विश्वासों ने यहाँ अपनी जड़ जमा ली। अवनक तो हिन्दू देवी-देवतों की ही पूजा होती थी। परन्तु अब अज्ञानी हिन्दू स्त्री-पुरुष मुसलमान फकीरों, मुल्लाओं और मौलवियों से तावीज, गण्डे और दवा लाने लग गये। यह अन्ध-विश्वास यहाँ तक बढ़ा कि मुसलमानों के पीर, मदार, सैयद और कब्रों के पत्थरों तक की पूजा होने लगी।

मुसलमानों के शासन-काल में अरबी और फारसी को राजभाषा का पद मिला। भारत के उत्तरी प्रान्तों में मुसलमानों का शासन अधिक काल तक रहा। आगरा, देहली तथा लखनऊ मुगलकाल में राजधानी रह चुके हैं। फलतः भारत के उत्तर में सस्कृत भाषा का प्रचार

कम हो गया और उनके दक्षिणी प्रान्तों में उमका प्रचार बढ गया। हिन्दू जनता में हिन्दी भाषा का प्रचार बढने लगा। इस काल में जो साधु-सन्त पैदा हुए, उन्होंने अपनी पुस्तकें हिन्दी भाषा में लिखीं। फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग करनेवाले मुसलमान जब हिन्दुओं के सम्पर्क में आते थे तो उन्हें अपनी भाषा में संस्कृत, हिन्दी तथा बोलचाल के सरल शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था जिससे वह हिन्दुओं के लिए बोधगम्य हो सके। यही भाषा धीरे-धीरे विकसित होकर 'उर्दू' हो गयी।

भारतीय वास्तु-कला, संगीत, काव्य, साहित्य तथा भाषा पर भी मुसलमानों की संस्कृति का प्रभाव पड़ा, परन्तु इन क्षेत्रों में मुस्लिम संस्कृति का जो प्रभाव पड़ा वह ऐसा नहीं था कि जिससे आर्य्य-संस्कृति के आदर्शों पर कोई आघात पहुँचा हो।

मुस्लिम संस्कृति पर आर्य्य संस्कृति का प्रभाव

केवल आर्य्य संस्कृति पर ही मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि मुस्लिम-संस्कृति भी आर्य्य-संस्कृति से प्रभावित हुई। भारतीय वेदान्त और एकेश्वरवाद का अनेक मुस्लिम सन्तों तथा दार्शनिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा और इस प्रकार प्रभावित होकर उन्होंने मुसलमानों में कई ऐसे मतों की स्थापना की जो शान्ति और मानवता एवं सहिष्णुता में विश्वास करते हैं।

मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शेख अबुलफजल प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान् और इतिहासकार हुआ है। उसने एक फारसी इतिहास-ग्रन्थ 'जाहिने अकबरी' लिखा है। शेख अबुलफजल यद्यपि सूफीमत का अनुयायी था, परन्तु उसपर वेदान्त और गीता का बड़ा प्रभाव पड़ा था। उसने लिखा है—

“मुझपर यह बात रोशन हो गयी है कि आमतौर पर लोगों का यह कहना कि हिन्दू लोग उस अद्वितीय परमेश्वर के साथ औरों को भी शरीक करते हैं, सत्य के अनुकूल नहीं। यद्यपि किसी-किसी बात की व्याख्या और उसकी युक्तियों के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है, तथापि

भाषा और मनोवृत्ति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करती है। नैतिक विजय के अभाव में राष्ट्रीय विजय का स्थायी होना असम्भव है। विदेशी शासन से बड़कर जातीय चरित्र को भ्रष्ट करनेवाली और कोई भी वस्तु सत्कार में नहीं है। गुलामी जातीय चरित्र के पतन का कार्य और कारण दोनों ही हैं। नैतिक पतन के कारण जातियाँ गुलाम बनती हैं और गुलामी के कारण उनका नैतिक पतन होता है।

अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कंपनी ने जब भारतवर्ष की स्वतन्त्रता छीनी तो उसे भी अपनी राष्ट्रीय विजय को स्थायी बनाने के लिए भारतवर्ष पर नैतिक विजय प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अंग्रेजों को यह अनुभव हुआ कि जबतक हम भारत के सामाजिक जीवन का सर्वनाश न कर देंगे तबतक भारत सदैव के लिए हमारी गुलामी में न आ सकेगा। इसलिए भारत की नैतिक विजय प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी शासकों ने भारतीय सामाजिक जीवन और नैतिक जीवन पर अपना नियन्त्रण रखना शुरू किया।

कंपनी ने भारतीय बच्चों की शिक्षा के लिए कई स्कूल और कालेज खोले जिनमें भारतीय भाषा और साहित्य के साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाने लगी। इन नवीन शिक्षा-संस्थाओं में ब्राह्मण 'आचार्य' का स्थान अंग्रेज 'प्रिंसिपल' ने लिया। भारत की प्राचीन वैदिक शिक्षा-पद्धति का उच्छेद किया गया और उसके स्थान में पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य भारतीयों में ऐसी मनोवृत्ति पैदा करना था जिससे वे अपने को अंग्रेजों से धर्म, इतिहास, दर्शन, ज्ञान-विज्ञान, सभ्यता तथा संस्कृति में हीन समझते रहे और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा न हो सके। कंपनी के शासकों को ऐसे छोटे कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते हों। इन दो उद्देश्यों से भारत में अंग्रेजी साहित्य, भाषा और विचारधारा का प्रचार किया गया।

इसके अतिरिक्त जब भारत में 'ईस्ट इंडिया कंपनी' का शासन प्रबन्ध था, उसे भारत में अंग्रेजी राज्य को स्थायी बनाने तथा शासन-

व्यवस्था की सुविधा के लिए ऐसे भारतीयों की आवश्यकता पड़ी जो छोटी-छोटी सरकारी नौकरियों पर नियुक्त किये जा सकें। यह युक्ति ली गयी कि कम वेतन पर भारतीयों को छोटी-छोटी नौकरियाँ जाये। इससे उनमें रिश्तखोरी बढ़ेगी तथा उनका चारित्रिक पतन होगा। वे इसके लिए अपने देशवासियों को ही दोष देगे।^१

जो अंग्रेज भारतवासियों को नौकरियाँ देने का समर्थन करते थे उनके पक्ष थे। एक पक्ष का कहना था कि भारतवासियों को केवल प्राचीन भारतीय साहित्य, भारतीय विज्ञान और सस्कृत, फारसी, अरबी तथा भाषाएँ पढ़ानी चाहिएँ, उन्हें पश्चिमी विचारों की हवा भी न देने देनी चाहिए, क्योंकि भारतवासियों को जब यूरोप के इतिहास ज्ञान होता है और वे पश्चिम के राष्ट्रीय विचारों के सम्पर्क में हैं, तो मुठ्ठीभर विदेशियों के द्वारा उन्हें अपने देश का शासित होना करने लगता है और वे स्वभावतः अपनी मातृभूमि के मस्तक से गुलामी कलक को मिटा देने की बात सोचने लगते हैं।

दूसरे पक्ष का यह विचार था कि भारतवासियों के चरित्र को जब यूरोपियन सॉचे में न डाला जायेगा, तब तक हमारे चरित्र के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं उत्पन्न हो सकता, जो शासन के स्थायित्व के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा वे हमको ठग, म्लेच्छ और विदेशी समझते रहेंगे, और जब अवसर पायेंगे तब अपने देश से बाहर भगाने की चेष्टा करेंगे। इसके विपरीत यदि अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी विज्ञान और अंग्रेजी सभ्यता

१. "If we are to have corruption, it is better that it should be among the natives than among ourselves, because the natives will throw the blame of the evil upon our countrymen, they will still retain high opinion of our moral integrity, and our character, which is one of the greatest supports of our power, will be maintained"

—Sir Thomas Munro, Governor of Madras

तो वे वही प्रसन्नतापूर्वक हमारे पूजार्थ के गुणों का चरित्र से शिक्षा ग्रहण करेंगे और उनके अनुसार चेष्टा करेंगे। ऐसी अवस्था में वे अपना विरोध तो आशा तो पालन करने में अपना गौरव समझेंगे का अनुकरण करके हमारे राज को अपना अहो-नीति का स्पष्टीकरण लॉर्ड मैकाले के सन् १८३५ का है जिसमें लिखा है—

ऐसे मनुष्यों की एक ध्रुवीय पैदा कर देने का शक्ति-हिए जो हमारे और उन करोड़ों भारतवासियों के असन करते हैं, दुभापिये का काम करे। इन लोगों ए कि वे केवल रंग और रक्त की दृष्टि से भारतीय तार, भाषा और बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज।”

तो है कि भारत पर पाश्चात्य सस्कृति, भाषा, ति-रिवाज, रहन-सहन की प्रणाली आदि लादने के गठित रूप से भयकर आयोजन किया गया। और हेंदुस्तानियों में आज हाथ मिलाना, विदेशी भाषा व की बात समझना, टी-पार्टी, एट-होम, डिनर, -प्रमोद मनाना, डबलरोटी, बिस्कुट चाय, केक, पीना, स्त्री-पुरुषों की वेशभूषा में अंग्रेज जाति का विल मॅरिज और डाइवोर्स (तलाक) का आश्रय री प्रथाएं आ गयी हैं और भारतीय सस्कृति को

की सस्कृति, सभ्यता, भाषा, साहित्य, विचारधारा, पीय सभ्यता का प्रभाव नहीं पडा प्रत्युत यहाँ के और सामाजिक आदर्शों पर भी इंग्लैण्ड की सभ्यता है

करने पर भी वे सदैव अन्न के लिए चिंतित रहते हैं। उनके शरीर पर मोटे कपड़े तक नहीं होते।

फिर, इस भयंकर गरीबी में अज्ञान का अखण्ड राज है। ९०% जनता निरक्षर है, ९४% मनुष्यों को अक्षर-ज्ञानमात्र है और शेष व्यक्ति शिक्षित हैं।

भारत का क्षेत्रफल १८ करोड़ वर्गमील है। इसमें ४० करोड़ व्यक्ति रहते हैं जो समस्त ससार की जनसंख्या का १/३ भाग है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में एक वर्गमील में औसतन १९५ व्यक्ति रहते हैं। परन्तु कितने ही प्रान्तों में ऐसे स्थान भी हैं जहाँ इससे चार या पाँच गुनी अधिक आबादी एक वर्गमील में रहती है। यूरोप में एक वर्गमील में १२७ व्यक्ति और अमरीका में एक वर्गमील में ४१ व्यक्ति रहते हैं। इस दृष्टि से भारत में बड़ी घनी आबादी है। किन्तु जन्म-मृत्यु की दृष्टि से हमारा देश ससार के दूसरे देशों से हीन है। सन् १९३१ में भारत में मृत्यु-संख्या का औसत १००० में २४५ था और जन्म-संख्या का ३३। उस समय ब्रिटेन की मृत्यु-संख्या १२५, जर्मनी की ११ और अमरीका की ११३ थी। भारतीय जीवन का औसत मान भी बहुत ही कम है। सन् १९३१ की मनुष्य-गणना के अनुसार भारतीय की औसत आयु २६७ वर्ष है, जबकि इंग्लैंडवासी की ५७६, अमरीकावासी की ५६४, जर्मन की ५९०४, फ्रान्सीसी की ५० और जापानी की ४४५ वर्ष हैं।

औद्योगिक स्थिति

भारत की कुल ३५ करोड़ की जन-संख्या में १५ करोड़ ३९ लाख अर्थात् ३/४ व्यक्ति कार्य करने और जीविका कमाने लायक थे। इनमें से १५ करोड़ २० लाख उपयोगी उद्योग-धन्धों व व्यवसायों में लगे हुए थे शेष १८ लाख ४४ हजार अनुपयोगी धन्धों में। यह नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जायेगा

व्यवसाय कार्य करने योग्य व्यक्तियों की संख्या
कृषि, मछली पकड़ना व शिकार—१० करोड़, ३२ लाख, ९४ हजार ४३९

उद्योग-धन्यो और खानो मे काम—	१ करोड़, ५६ लाख, ९७ हजार, ९५३
व्यापार और यातायात—	१ करोड़, २ लाख, ५५ हजार, ३
सरकारी नौकरियाँ और सेना—	१८ लाख, ३६ हजार, ७५८
वकील, डाक्टर और कलाकार—	२३ लाख, १० हजार, १४१
घरेलू नौकर	— १ करोड़, ८ लाख, ९८ हजार, २७७
अन्य विविध पेशे	— ७७ लाख, ७८ हजार, ६४२
अनुपयोगी धन्ये	— १८ लाख, ४४ हजार, ६४२

ब्रिटिश भारत में लगभग २८ करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती है। प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में १.०२ एकड़ भूमि आती है। इस भूमि पर हर वर्ष कृषि द्वारा २० अरब, ३२ करोड़ रुपये की पैदावार होती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में ६४ रुपये की सामग्री आती है। यही सख्या अमरीका में १७५, कनाडा में २१३, जापान में ५७ और इंग्लैंड में ६२ रुपये है। कृषि की आमदनी की दृष्टि से भारत इंग्लैंड और जापान से कुछ अच्छा है, परन्तु उद्योगों में वह बहुत पिछड़ा हुआ है। अन्य औद्योगिक देशों में जनसख्या का अधिक भाग उद्योग-धन्यों में लगा हुआ है और बहुत ही कम भाग खेती पर निर्भर है, परन्तु दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश में उद्योग-धन्यों में बहुत कम लोग लगे हुए हैं। औद्योगिक पैदावार का औसत प्रति व्यक्ति अमरीका में ७२१, ब्रिटेन में ४१२, कनाडा में ४३० और जापान में १५८ रुपये है। भारत में यह औसत केवल १५ से २० रुपये है।

व्यापारिक स्थिति

भारत की व्यापारिक स्थिति भी अत्यन्त शोचनीय है। आर्थिक सकट के पूर्व, सन् १९२८-२९ के अनुसार, भारत का आयात-व्यापार २५३३ करोड़ रुपये और निर्यात-व्यापार ३३०१ करोड़ रुपये का था। इस प्रकार प्रति व्यक्ति पीछे में प्रति वर्ष १७ रुपये का व्यापार होता है। अन्य देशों में प्रति व्यक्ति पीछे व्यापार का अनुपात इस प्रकार है—इंग्लैंड में ५९७, अमरीका में २१८, कनाडा में ९२ और जापान

भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति पर जोसत कर इस प्रकार है—

वर्ष	रुपये आना पाई	वर्ष	रुपये आना पाई
१९२२-२३	५ ४ ५	१९२७-२८	५ ५ ०
१९२५-२६	५ ६ ७	१९३२-३३	५ ० ६

इस प्रकार ५५ रुपये वार्षिक औसत आय में से ५ रुपये अर्थात् आय का $\frac{1}{11}$ भाग करो में दे देना पड़ता है ।

भारत की भयंकर गरीबी और दरिद्रता के सबध में भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री रेमजे मैकडानल्ड ने लिखा है—

“... ५ करोड़ तक कुटुम्ब (जिसका मतलब हुआ १५ से लेकर २५ करोड़ तक मनुष्य) साढ़े तीन आने की आय पर अपना गुजारा करते हैं । “हिन्दुस्तान की दरिद्रता केवल कल्पना नहीं बल्कि वस्तु-स्थिति है । सर्वथा-सम्पन्न-काल तक में कर्जखोरी चक्की का मोटा पाट किसान के गले में लटका रहता है । “ग्रामों में घूमने पर ऐसे ककाल दिखायी पड़ते हैं जो दिन-रात के परिश्रम से चकनाचूर हो गये हैं और जो भूखे पेट मन्दिर में जाकर खिल्लवदन होकर परमेश्वर की उपासना करते हैं ।”

श्री आर्यावेन ने अपनी पुस्तक ‘भारत का बाग’ (Garden of India) में भारत के मजदूरों की स्थिति के बारे में लिखा है—

“अनाज में से ककर की तरह निकाले हुए अधनगे-भूखे लोग गांव-गांव में सर्वत्र दिखायी पड़ते हैं । उनके पास मवेशी न होने के कारण जीविका का कोई साधन नहीं है । कुदाली से खोदी हुई जमीन के सिवा उनकी जीविका की ओर कोई वस्तु नहीं है । उन्हें वो सेर के भाव का बिल्कुल हलका अनाज अथवा डेढ़ या दो आने रोज की मजदूरी मिलती है और यह नगण्य मजदूरी भी पूरे वर्ष भर नहीं मिलती । क्षुधा-पीड़ित और बहुधा वस्त्र-हीन स्थिति में ये लोग सर्दियों के दिनों में चोरों और पशुओं से अपनी रक्षा करके किस तरह जी सकते हैं, यह एक आश्चर्य ही है ।”

धातु या पैदावार ससार का प्रतिशत धातु या पैदावार ससार का प्रतिशत

बोस्सीट	० ४	जूट	९८ ७
कच्चा काम	५ ३	गेहूँ	६ ६
कच्चा ताँबा	० ५	चावल	४३ ५
कच्चा लोहा	१ ९	मक्का	१ ६
कच्चा मेगनीज	१७ ९	जौ	५ ४
कोपला	१ ९	काफी (कहवा)	१ ७
पेट्रोल	० १	चाय	४२ ०
मेगनीसाइट	० ९	शक्कर	१८ ७
पोटाश	० १	तम्बाकू	१९ ६
सोना	१ ०	रेप-बीज	७३ ६
रबड़	१ ०	बिनीला	१४ २
रई	१२ ३	मूँगफली	५० ९
ऊन	२ ५	जलमी	१३ ०
रेशम	० १	सीसामम	५९ ८

आर्थिक साधनों में भारत में श्रम-शक्ति भी महत्वपूर्ण है। अभी-तक भारत की मानव-शक्ति का भी इस दिशा में अच्छी तरह उपयोग नहीं हो सका।

भारत का आर्थिक सगठन

हमारे देश का आर्थिक सगठन अत्यन्त विषम है, वह आर्थिक समता या आर्थिक न्याय पर आधारित नहीं है। ग्रामों में समस्त भूमि के स्वामी जमींदार और किसान हैं जो किसानों से बड़ी-बड़ी रकमें लगान के रूप में वसूल करते हैं और उसका एक अंश सरकारी कोष में मालगुजारी के रूप में अदा करते हैं। ग्रामों में जमींदारों और ताल्लुकेदारों का किसानों के न केवल आर्थिक जीवन पर ही बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर भी पूरा नियन्त्रण है। किसानों को जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों की दया-दृष्टि के भरोसे रहना पड़ता है। जमींदार किसानों को

खेती के लिए भूमि देते हैं, साहूकार खेती के लिए कर्ज देते हैं और व्यापारी उनकी पैदावार को खरीदते हैं। प्रायः इन तीनों का गुट्टू-सा रहता है।

नगरों में बड़े-बड़े कारखाने हैं जिनके स्वामी बड़े-बड़े सेठ, पूंजीपति महाजन और बैंकर हैं। ये कारखाने कपनियों के रूप में हैं। इनमें ग्रामों से शहरों में आये हुए बेकार मजदूर काम करते हैं। उन्हें पूरी और पर्याप्त मजदूरी तक नहीं मिलती। काम भी अधिक लिया जाता है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल का कोई प्रबन्ध नहीं होता। रहन-सहन भी बड़ी अस्वास्थ्यप्रद होती है। पूंजीपति इनके परिश्रम में मालामाल होते हैं, परन्तु इनका उचित भाग तक इन्हें नहीं दिया जाता। फलतः औद्योगिक मजदूरों में भीषण अशान्ति और असन्तोष रहता है। जगह-जगह मजदूरों के सगठन भी बन गये हैं जो अपने सुधार के लिए काम करते रहते हैं। समाजवादी और साम्यवादी नेता इनमें प्रचार तथा सगठन का कार्य करते रहते हैं।

आज-कल देश में आर्थिक समस्या के मध्य में दो प्रकार के विचार प्रचलित हैं। एक वर्ग का विचार है कि आर्थिक प्रणाली को म्याक्स-वल्मी बनाया जाना चाहिए। देश में तैयार हो जानेवाली चीज़ों के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। वे ग्रामों में उद्योग-धन्दा तथा घरेलू व्यवसायों की उन्नति पर अधिक जोर देने हैं। उनका कहना है कि खादी का प्रचार बढ़ाया जाये और सत्र लॉग हाथ का रता-बुना कपड़ा ही पहनें। जमींदारी ज्यों की त्यों कायम रहे और वे अपने को किसानों का ट्रस्टी मानें। इस विचारपारा के प्रवर्तक तथा प्रमुख मन्त्र्य महात्मा गांधी तथा दूसरे गांधीवादी नेता हैं।

दूसरे वर्ग के लोग वे हैं जो देश के आर्थिक जीवन का निर्माण औद्योगीकरण और बड़े-बड़े उद्योग-धन्दों के सगठन में करना चाहते हैं। वे जमींदारी-प्रथा और पूंजीवाद को आज के युग में अनावश्यक समझते हैं। प० जवाहरलाल नेहरू, श्री मुनायकन्दर पन्त, श्री मानवेन्द्रनाथ राय, आचार्य नरेन्द्रदेव आदि नेता देश में पान्थान्त्र दशा-मेंना औद्योगीकरण चाहते हैं। वे ग्रह-उद्योग, नारी या ग्रामोद्योग का देश के लिए आर्थिक जीवन का म्यायी जगन हो मानते हैं। उनकी राय

में ये ग्रामोद्योग केवल सक्रमण-काल के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ।^१

भारत की गरीबी के मूल कारण

भारत की भयंकर गरीबी के मूल कारणों में सबसे प्रधान राजनीतिक पराधीनता और उसके फलस्वरूप आर्थिक पराधीनता है । भारतीय जनता की आर्थिक नीति का पूर्ण नियन्त्रण ब्रिटिश सरकार के हाथ में है । भारतीय जनता को उसमें हस्तक्षेप करने का कुछ भी अधिकार नहीं है । व्यापारिक सवधो, व्यापारिक नीति, तट-कर संरक्षण, व्यापारिक कंपनियों पर नियन्त्रण, विनियम की दर आदि सभी पर ब्रिटिश सरकार का पूरा नियन्त्रण है ।

दूसरा प्रमुख कारण है भारत में निरक्षरता और शिक्षा का अभाव । जनता के अशिक्षित होने के कारण उनमें ज्ञान-विज्ञान से लाभ उठाने की प्रवृत्ति का अभाव रहता है । फलतः वह उद्योग-व्यवसायों को वैज्ञानिक ढंग से उन्नत बनाने में विफल रहते हैं ।

तीसरा प्रमुख कारण है भारत में कृषि की प्रधानता । कृषि-प्रधान होने से भारत कच्चा माल तैयार करने पर तो खास ध्यान देता है, परन्तु वह, इस कारण, औद्योगिक प्रगति में पिछड़ा हुआ है ।

भारत के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सर एम. विश्वेश्वरैया का कथन है कि भारतवासियों को अपना जयघोष यह बनाना चाहिए—‘उद्योगवादी बनो’ । उन्होंने काशी विश्वविद्यालय के दीक्षान्त-समारोह-भाषण (१९३७) में कहा था—

“पिछली शताब्दी से कनाडा में अन्न पैदा करनेवाले मजदूरों की सख्या बराबर घटती आ रही है और यह सख्या ७५% से घटकर आज १७% हो गयी है । स्वीडन में भी खेती का काम करनेवालों की सख्या में भारी कमी हो गयी है । वहाँकी एक बहुत बड़ी सख्या उद्योग, व्यवसाय, शिल्प और व्यापार में लग गयी है । पचास वर्षों से हर देश में यही प्रवृत्ति देखने

में आरही है, जैसा कि रूस, जर्मनी और जापान में प्रत्यक्ष है। भारत को अक्सर कृषि-प्रधान देश कहा जाता है, परन्तु जनता को यह साफ-साफ नहीं बतलाया जाता कि उसकी सुरक्षा कृषि की अपेक्षा उद्योग और नौकरी पर निर्भर है। उद्योगों को प्रोत्साहन देना प्रगतिशील देशों में मौलिक नीति स्वीकार की गयी है। परन्तु यहाँ उसकी अपेक्षा की जाती है।”

गरीबी का चौथा कारण यह है कि भारत में उत्पादन और उसका वितरण न्यायोचित ढंग से नहीं किया जाता। खेती की पैदावार की बिक्री में भी कोई अच्छी पद्धति नहीं है। इस कारण किसानों को कम मूल्य पर सस्ते दानों में अपना माल बेचना पड़ता है। भारत में कृषि की पद्धति भी जनता की गरीबी का एक प्रधानकारण है। भूमि का वितरण में सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर नहीं है।

जबतक भारत पूर्णतः उद्योगवादी राष्ट्र नहीं बन जाता तबतक भारतीय व्यापार के संरक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है और जबतक सरकार भारत के उद्योग-धन्यों का संरक्षण नहीं करेगी, तबतक औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति होना संभव नहीं।

श्री देवीप्रसाद खेतान का मत है कि भारत-सरकार द्वारा शक्कर व्यवसाय को १५ वर्ष के लिए संरक्षण मिलने का अन्तर यह हुआ है कि चार वर्ष में ही भारत शक्कर के व्यवसाय में स्वावलम्बी हो गया है। शक्कर-व्यवसाय की उन्नति से १५ करोड़ रुपये विदेशों में जाने से बचेंगे। इनमें से ८ करोड़ रुपये तो किसानों को मिल जाते हैं। १ विगत १० वर्षों में भारत में सूती-वस्त्र-व्यवसाय, शक्कर, दियासलाई, कागज, लोहे, गुड आदि व्यवसायों ने आश्चर्यजनक उन्नति की है, जो नीचे हुई तालिका से प्रकट होती है—

१ कानपुर के इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट आफ शुगर टेक्नोलॉजी के रेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सन् १९३९-४० में १२, ४१, ० टन शक्कर बनायी गयी। इससे पहले साल में ६, ५०, ८०० टन शक्कर बनायी गयी। भारत में इस समय १४५ शक्कर के मिल काम रहे हैं।

इन वर्षों में भारत की प्रायः १०० करोड़ की आय हुई है।

व्यवसाय	सन् १९२५-२६	सन् १९३५-३६
दियासलाई	१२ करोड़ ६० लाख दर्जन	२९ करोड़ ४० लाख दर्जन
कागज	२८ हजार टन	६८ हजार टन
सूती कपड़ा	१९५ करोड़ ४० लाख गज	३५७ करोड़ १० लाख गज
हाथबुना कपड़ा	११६ करोड़ गज	१६६ करोड़ गज
शक्कर	३ लाख २१ हजार टन	११ लाख ६६ हजार टन
गुड़	३५ लाख टन	६७ लाख ५० हजार टन
लोहा	३ लाख २० हजार टन	अप्राप्त

भारत की जनता की गरीबी के कारण आर्थिक के अतिरिक्त सामाजिक भी है। भारत में ऐसी सामाजिक कुप्रथाएँ प्रचलित हैं जिनके कारण भी जनता को अपने धन का बहुत बड़ा भाग व्यर्थ खर्च करना पड़ता है। इन सामाजिक प्रथाओं में सबसे हानिप्रद प्रथाएँ हैं—बाल-विवाह, विवाहों में धन का अपव्यय, मृत-भोज, श्राद्ध तथा तीर्थ-यात्रा में महत्तो, साधुओं और पुजारियों को दान-दक्षिणा, शराबखोरी, जुआ, वेश्यागमन इत्यादि।

ये सामाजिक बुराइयाँ न केवल आर्थिक दृष्टि से ही हानिप्रद हैं, बल्कि नैतिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी घातक हैं। इनका कुप्रभाव केवल फिजूलखर्ची करनेवाले तक ही सीमित नहीं रहता सारे कुटुम्ब, ग्राम और समाज पर भी पड़ता है।

कृषि

भूमि-प्रणालियाँ

भारत में दो प्रकार की भूमि-प्रणालियाँ (Systems of Land Tenures) प्रचलित हैं। एक जमींदारी और दूसरी रेंयतवारी। जमींदारी प्रणाली विशेषतः बंगाल, बिहार, सयुक्त-प्रान्त और उत्तरी मद्रास में प्रचलित है। इसके अनुसार जमींदार भूमि के स्वामी होते हैं और वे उसकी मालगुजारी सरकार को देने के लिए बाध्य हैं। जमींदार

अपनी भूमि किसानों को जोतने-बोने के लिए दे देते हैं और उसके एवज में उनसे लगान वसूल करते हैं। इस लगान का एक नियत भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में दे दिया जाता है और शेष उनके हिस्से में आता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार का जमींदार ही से सीधा सम्बन्ध होता है। किसानों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसलिए जमींदार के किसानों पर होनेवाले अत्याचार में वह हस्तक्षेप नहीं करती।

रयतदारी भूमि-प्रणाली भारत के शेष भाग पंजाब, बम्बई, सिन्ध, मध्यप्रान्त, सीमाप्रान्त, दक्षिण-मद्रास आदि में प्रचलित है। इस प्रथा के अनुसार भूमि के स्वामी किसान ही होते हैं। प्रत्येक किसान को सीधे सरकार को मालगुजारी देनी पड़ती है। उनके और सरकार के मध्य में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता जो भूमि का स्वामी कहलाये।

बन्दोवस्त

किसान अपनी जोत का जो लगान जमींदार या सरकार को देता है, उसपर समय-समय पर पुनः विचार किया जाता है। इसके लिए जो कार्यवाही की जाती है उसे बन्दोवस्त कहते हैं। भारत में दो तरह के बन्दोवस्त हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी बन्दोवस्त में लगान हमेशा के लिए स्थिर कर दिया जाता है, जो किसान से नहीं बल्कि जमींदार से वसूल किया जाता है। सन् १७९५ में अवध और मद्रास में स्थायी लगान निश्चित कर दिया गया था। शेष सारे देश में अस्थायी बन्दोवस्त की प्रथा जारी है। सरकार के सर्वे-विभाग द्वारा की गयी सर्वे के आधार पर तीस-तीस वर्ष में प्रत्येक जिले की जमीन की पूरी जाँच होती है। प्रत्येक गाँव की पैमायश होती है, नकशे बनते हैं, हर एक किसान के खेत को उसमें पृथक्-पृथक् बताया जाता है। उनके अधिकार का एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें जमीनों का लेन-देन आदि लिखा जाता है। इस रजिस्टर को 'वाज़िबुल अर्ज' (Record of Rights) भी कहते हैं। यह सब जाँच करके उसके अनुसार लगान कायम करने का काम भारत सरकार की सिविल सर्विस के विशेष अफसरों

द्वारा होता है जिन्हे 'सेटिलमेण्ट अफसर' कहा जाता है ।

लगान की दर

भारत में जमीन पर जो लगान लिया जाता है, उसकी एक निश्चित दर नहीं है । वह स्थायी बन्दोबस्तवाले प्रान्तों में एक प्रकार की है और अस्थायी बन्दोबस्तवाले सूबों में दूसरे प्रकार की । फिर जमींदार तथा रयतवारी प्रान्तों में भी लगान की दरें भिन्न-भिन्न हैं । वे जमीन की किस्म और उसके अधिकार आदि के अनुसार निर्धारित की जाती हैं । बंगाल में १६ करोड़ रुपये जमींदार लगान में किसानों से वसूल करते हैं, परन्तु चूँकि वहाँ स्थायी बन्दोबस्त प्रचलित है, इसलिए सरकार उसमें से केवल ४ करोड़ रुपये मालगुजारी के रूप में ले लेती है । अस्थायी बन्दोबस्तवाले प्रदेशों में जमींदारों से अधिक-से-अधिक लगान का ५० फी सदी सरकार वसूल करती है । किसी-किसी प्रान्त में वह इससे भी कम वसूल करती है ।

जमींदारी प्रथा की उत्पत्ति और विकास

वेद-काल में भारत में जमींदारी-प्रथा नहीं थी । राजा और प्रजा का सीधा सम्बन्ध था । प्रजा राजा को लगान देती थी । उस काल में समस्त भूमि चार प्रकार की थी—(१) वास्तु भूमि, (२) ~~वास्तु~~ भूमि, (३) गोचर भूमि, (४) वन्य भूमि । वास्तु-भूमि का स्वामी किसान होता था ।^१

रामायण-काल में भी हमें जमींदारी प्रथा का कोई प्रमाण मिलता । स्मृति-काल तथा महाभारत-युग में भी जमींदारी प्रथा बौद्ध-काल में भी जमींदारी प्रथा पाई मिलती । सब के मालिक थे ।^२ मौर्य-काल में ~~राज~~ ^{राज} ~~स्वामि~~ ^{स्वामि}

१ प्रो० सन्तोषकुमार दास ।

२ रामदास गोड़ 'हमारे गाँवों

ग्राम स्वतन्त्र थे। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम-पचायत होती थी इस पचायत का जो मुखिया होता उसे ग्रामपति कहते थे। परन्तु वह आज-काल के जमींदार का पूर्वज नहीं है। जमींदारी का कोई रिवाज नहीं था। सब किसान अपने खेतों के मालिक थे।^१ पठान और मुगल काल में भी जमींदारी-प्रथा नहीं थी।

मुगल-काल में भी सैद्धान्तिक रूप से राज्य ही समस्त भूमि का स्वामी था, परन्तु भूमि को पैदावार किसान और सरकार के बीच में बाँटने की व्यवस्था थी। लगान-वसूल करनेवाले लोग किसानों से लगान वसूल करके सरकारी कोष में जमा कर देते थे। इस प्रकार लगान वसूल करनेवाले व्यक्तियों का एक वर्ग बन गया जो सरकार की ओर से नियुक्त किये जाते थे और उन्हें सरकार से वेतन मिलता था। ये लगान वसूल करनेवाले सरकारी कर्मचारी होते थे। जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा और शासन-व्यवस्था अस्तव्यस्त होने लगी तो ये लगान वसूल करनेवाले स्वतन्त्र होते गये और उन्होंने सरकार की कमजोरी का लाभ उठाकर अपने पद को मौलसी बना लिया। सरकार की सत्ता मालगुजारी की आमदनी पर निर्भर थी। लगान वसूल करनेवालों की स्वच्छदता के कारण सरकार को बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़ा। अन्त में सरकार ने यह निश्चय किया कि लगान वसूल करनेवाले 'रेवन्यू फार्मर' कहलायेंगे। अर्थात् वे निर्धारित मालाना मालगुजारी सरकार को देंगे और उन्हें यह स्वतन्त्रता दे दी जायेगी कि वे रैयत से मनमाना लगान वसूल करें। सबसे पहले बंगाल प्रान्त में यह प्रणाली जारी की गयी। यह मुगल-साम्राज्य-काल में शुरू हुई और मारे [भारत में व्याप्त हो गयी।^२

आज के युग में यह वनशने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में जमींदारी-प्रथा किसानों के लिए बड़ी दुस्तदायिनी है और यह निश्चित

१. रामदाम गोड़ : 'हमारे गांवों की कहानियाँ'

२. डॉ० जेड. ए. अहमद : 'द एंग्लो-इण्डियन प्रॉब्लम इन इंडिया'

जमींदार स्वयं खेती करते हैं। १२ लाख जमींदार ऐसे हैं जो एक रुपये से कम मालगुजारी देते हैं। इसलिए वे तो नाममात्र के ही जमींदार हैं। १०० रुपये तक मालगुजारी देनेवाले जमींदारों की संख्या ४६ लाख है। १०० रुपये से अधिक मालगुजारी देनेवाले जमींदारों की संख्या १ लाख ६२ हजार और इनमें से १,१०० जमींदार ५००० रुपये या इससे अधिक लगान देते हैं। और केवल २०३ जमींदार २०,००० रुपये या इससे ज्यादा मालगुजारी देते हैं। इस प्रकार २० लाख जमींदारों में अधिकांश किसान ही हैं। केवल १ लाख ६२ हजार जमींदार ऐसे हैं जिनका गुजारा मुख्यतया जमींदारी की आमदनी से होता है। इसके नाथ ही यह भी जान लेना जरूरी है कि जमींदारों पर प्रायः ९० करोड़ का कर्ज है।

अंग्रेजी राज के आरम्भ में किसानों का भूमि पर अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। जमींदार भूमि के स्वामी बन गये परन्तु किसानों को भूमि पर स्थायी रूप से जोतने-बोने तक का अधिकार नहीं मिला। जमींदार जब चाहे तब काश्तकार को खेत से बंदाखुल कर सकता था। बाद में जब किसानों के लिए कृषि-कानून बनाये गये तब किसानों के अधिकारों की व्याख्या की गयी। इसी समय से जमींदारों ने अपने लिए खेती के निमित्त भूमि सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। यही सुरक्षित भूमि 'सीर' कहलाने लगी। पहले सीर से अभिप्राय उस भूमि से था जिसे जमींदार स्वयं अपने लिए जोतता-बोता था, परन्तु समय-समय पर कृषि-कानूनों द्वारा सीर की परिभाषा में परिवर्तन होता रहा। अन्त में सीर का नाम उस भूमि को दिया गया जो जमींदारों के निजी प्रयोग के लिए सुरक्षित होती थी और जिसपर किसानों की मोहसी अधिकार प्राप्त नहीं होता था। जब जमींदार की जमींदारी बिक जाती थी, तो उसके साथ उसकी सीर नहीं बिकती थी।

इस प्रकार सीर जमींदारों का एक महत्वपूर्ण अधिकार बन गया। अवध-कानून-कानून १९२१ तथा आगरा-कृषि-कानून, १९२३ के अनुसार उस सब भूमि पर जमींदारों को सीर का अधिकार प्राप्त है जिसे वे स्वयं या उनके नीकर व मजदूर जोतते-बोते थे और जो भूमि उपर्युक्त कानूनों

के वनने से १ वर्ष पहले खुदकास्त दर्ज थी। अब उन्हें यह भी अधिकार प्राप्त हो गया है कि किसी भी १० साल की खुदकास्त को वे सीर दर्ज करा सकते हैं, परन्तु अपनी जमींदारी की भूमि के १०% से अधिक भाग में उन्हें सीर का अधिकार प्राप्त न हो सकेगा। अर्थात् जो ०० एकड़ भूमि का जमींदार है वह १० एकड़ से अधिक में इस प्रकार अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। सन् १९३५-३६ में आगरा प्रान्त में ४९३६ लाख एकड़ और अवध में ७२४ लाख एकड़ जमीन सीर थी।

सयुक्तप्रान्त में किसान और उनके अधिकार

सन् १९३१ में खेती करने और खेती से जीविका कमानेवालों की समस्या इस प्रकार थी—

कुल कृषक	१७, ७६, ५४, ३१
जमींदार (जो खेती नहीं करते)	२६, ०६, १०
जमींदार (जो खेती करते हैं)	१, ७९, ५५, ३६
काश्तकार (जो खेती करते हैं)	१२, ०१, १६, २१
काश्तकार (जो खेती नहीं करते)	१९, ३८, ७७
खेतिहर मजदूर	३, ४१, ९१, ८५
माली आदि	३, २१, ३९

सन् १९३५-३६ में सयुक्तप्रान्त में ३५, २७, ८०, ०० एकड़ भूमि पर कृषि होती थी और ९६ लाख एकड़ भूमि व्यर्थ पड़ी हुई थी। कृषियोग्य भूमि में ३३, ७६, ६२५ एकड़ भूमि पर जमींदारों की सीर है और २८, १५, १४५ एकड़ भूमि पर उन्हें खुद काश्त का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार ६१ लाख से ऊपर एकड़ भूमि पर जमींदारों की सीर व खुदकास्त है। २, ५९, ६४१ एकड़ भूमि ऐसी है जो किसानों के पास है और जो लगान से बरी है।

सयुक्तप्रान्तीय कृषि-कानून १९३९ के अनुसार सयुक्तप्रान्त में ७ प्रकार के किसान मजूर किये गये हैं जो निम्नलिखित हैं—

(१) हरद्वारान कब्जा मुस्तकिल

- (२) शरह मुअज्जअन काश्तकार
- (३) अवध में विशेष अधिकारवाले काश्तकार
- (४) साकितुल मिलकियत काश्तकार
- (५) नये मोम्सी काश्तकार
- (६) दरगिलकार काश्तकार
- (७) गैरदरगिलकार काश्तकार

प्रथम तीन प्रकार के काश्तकार अवग और पूर्वी जिला में हैं जिनमें स्वाधी बन्दोबस्त प्रचलित है। हुकदारान कब्जा मुस्तकिल जमीन और किसान के बीच उस समय से चले आये हैं जब स्वाधी बन्दोबस्त हुआ। इनका जमान स्वाधी रहता है और इनका अनिहार मूल्य के मा इनके वाग्मिया हो मिटता है। वे चाहें तो अपने अनिहार का नेत्र मारते हैं, रहन रह सकते हैं या हिस्से कर सकते हैं।

दुसरी श्रेणी के काश्तकारों के लिये भी वही नियम है। इनका अधिकार भी सीमित है।

नीसरी श्रेणी के छात्रों का केन्द्र प्रान में है। ये वे छात्रों हैं जिनका पढ़ाई विशेष इच्छावाना या मर् १८८२ के अग्र-उत्थान का मूल न पढ़ते न्यायालय के निर्णय में हुआ है। मौखी छात्रों का भी अग्रि का प्रान है, ३ मर् १८८२ में प्रान है।

ਚੰਦ੍ਰਾ ਚੰਦ੍ਰਾ ਕ ਨਾਮਿਨੁਤ ਨਿਭਿ ਕਯਾ ਛਾਤਕਾਏ ਤੇ ਦੇ ਨਾ ਅਮੋਗਾ,
 ਅਨਾਮ ਨਾਮਿਨੁਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾਨ ॥ ੧ ॥ ਮੁਕਤਿ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਮ ਨਾਮਾਸਾ ਅਧਿਕਾ
 ਮੁਕਤਿ ਕੇ ਦੇਵਨ, ਯਹੁੰ ਛਾਤਕਾਏ ਨਾਮਿਨੁਤ ਕੇ ਅਨਾਮ ਨਾ ਘੋਰ ॥ ੨ ॥
 ਛਾਤਕਾਏ ਅਨਾਮ ਨਾਮਿਨੁਤ ॥ ੩ ॥ ਯਹੁੰ ਛਾਤਕਾਏ ਅਨਾਮ ਨਾ ਘੋਰ, ਛਾਤਕਾਏ
 ਅਨਾਮ ਨਾ ਘੋਰ ॥ ੪ ॥ ਛਾਤਕਾਏ ਅਨਾਮ ਨਾ ਘੋਰ ॥ ੫ ॥

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

(- 8-10 0'35 N 179 W AS 11716'0 440 [643 5 33

हो, परन्तु वह सीर का काश्तकार न हो और न शिकमी काश्तकार (Subtenant) हो ।

(३) प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस कानून के अन्तर्गत मौरूसी अधिकार प्राप्त कर लिये हो ।

छठी श्रेणी दखीलकार काश्तकारों की है । ये वे काश्तकार हैं जिन्हें पहले लगान-कानून के अन्तर्गत दखीलकार काश्तकार के अधिकार प्राप्त थे ।

जो काश्तकार उपर्युक्त किसी श्रेणी में नहीं हैं वे गैरदखीलकार काश्तकार हैं ।

अन्तिम श्रेणी के काश्तकार को छोड़कर शेष काश्तकारों की सभी श्रेणियों को नीचे लिखे अधिकार प्राप्त हैं—

(१) हकदारान कब्जा मुस्तकिल और शरह मुअइअन काश्तकार दोनों को अपनी जमीन पर पूरा अधिकार है । वे उसे बेच सकते हैं, रहन कर सकते हैं और उनके वारिस भी उसे उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकते हैं ।

(२) अवध के खास काश्तकार, साकितुल मिल्कियत काश्तकार, दखीलकार, मौरूसी तथा गैर-दखीलकार काश्तकारों को जमीन बेचने या रहन रखने का अधिकार नहीं है । वह केवल वारिसों को ही प्राप्त हो सकती है ।

(३) प्रत्येक काश्तकार को जोत पर अपनी जमीन दूसरे काश्तकार को उठा देने का अधिकार है । परन्तु यह अधिकार शिकमी काश्तकार तथा सीर के काश्तकार को नहीं है ।

(४) काश्तकार को लिखित पट्टा प्राप्त करने का अधिकार है ।

(५) हकदारान कब्जा मुस्तकिल, शरह मुअइअन काश्तकार, अवध में दखीलकार काश्तकार, या खास अधिकारवाले काश्तकार अपनी जमीन पर कोई भी सुधार कर सकते हैं ^१ । शेष काश्तकारों को भी

१ खेती के सम्बन्ध में काश्तकारों को निम्नलिखित सुधार करने का अधिकार है—

सब प्रकार के सुधार करने के अधिकार हैं। परन्तु वे निम्नलिखित सुधार जमींदार की लिखित आज्ञा के बिना नहीं कर सकते जबतक कि ऐसा रिवाज ग्राम में प्रचलित न हो जिससे उन्हें अधिकार प्राप्त हो जाये—

(अ) जोत के पास ही आराम या सुविधा के लिए मकान बनाना,

(व) खेती के काम के लिए तालाब बनाना।

(६) गैर-दखीलकार काश्तकार को जमींदार की आज्ञा के बिना जोत में कोई भी सुधार करने का अधिकार नहीं है।

(७) काश्तकारों को अपनी जमीन पर पेड़ लगाने का अधिकार है।

(८) काश्तकार को लगान अदा करने पर जमींदार से उसके हस्ताक्षर सहित रसीद पाने का अधिकार है।

(९) कृषि-वर्ष के अन्त होने से ३ मास पहले तक काश्तकार को जमींदार से ब्याज का हिसाब प्राप्त करने का अधिकार है।

(१०) बकाया लगान के लिए जो काश्तकार अपनी कुल काश्त या उसके किसी हिस्से से वेदखल किया जायेगा उससे बकाया लगान, चाहे

१. अपनी जोत पर अपने या मवेशी के लिए मकान या गोबाम बनाना।

२ जोत की तरबकी के लिए कोई भी काम करना, जिनमें निम्न-लिखित काम शामिल हैं—

१. खेती के लिए कुआ बनाना या पानी जमा करने के लिए प्रबन्ध करना;

२ बाढ़ तथा पानी से फसल की रक्षा के लिए नालियाँ बनाना,

३ जमीन की सफाई करना, घेरा लगाना तथा उसे समतल बनाना,

४. जोत के समीप आराम के लिए मकान बनाना;

५ खेती के लिए तालाब बनाना,

६. उपर्युक्त कामों को फिर से बनाना।

उसकी डिग्री हुई हो या न हुई हो, वसूल करने का जमींदार को हक न होगा।

(११) यदि कोई काश्तकार अपनी जोत से बंदखल कर दिया गया हो तो उसे उस गाँव में उसके रहने के मकान से बंदखल न किया जा सकेगा।

इस कानून में संयुक्तप्रान्त के ३४ लाख से ऊपर खेतिहर मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इन खेतिहर मजदूरों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। शहरों में, मिलों में काम करनेवाले मजदूरों के लिए मजूरी, काम के घटे तथा छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में कानून बन गये हैं परन्तु खेतों पर काम करनेवाले किसानों के सम्बन्ध में अभी तक कोई कानून नहीं है। उनसे दिन-रात काम लिया जाता है और दो या ढाई आने मजदूरी दे दी जाती है। अक्सर यह मजदूरी भी नहीं मिलती। प्रायः जमींदार बेगार में ही उनसे काम लेते हैं। फसल काटने के समय मजदूरी कुछ बढ़ा दी जाती है। स्त्रियों को दो आने रोज से अधिक मजदूरी नहीं दी जाती। खेतिहर मजदूर वास्तव में गुलामी की दशा में हैं। वे अधिकांश में उस वर्ग में से हैं जिसे 'दलित' कहा जाता है।^१

वैसे तो समस्त भारत में खेतों पर काम करनेवाले मजदूरों की अवस्था बुरी है परन्तु बिहार और गुजरात प्रान्त में तो उनकी दशा गुलामी की तरह है। गुजरात में इन्हें हाली और बिहार में भूमिया कहा जाता है।

हाली खेतों पर काम करनेवाले मजदूर हैं जो अपनी मर्जी से मजदूरी पर काम नहीं करते, परन्तु उन्हें बड़े-बड़े जमींदारों द्वारा स्थायी रूप से पुश्तैनी नौकर बनाकर रखा जाता है और उनके साने तथा रहने का प्रबन्ध जमींदारों द्वारा ही किया जाता है। वे अपने काम को छोड़कर दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। इस प्रकार इन हालियों और अमरीका के खेतों पर काम करनेवाले उन गुलामों में कोई अन्तर नहीं जो गृहयुद्ध से पूर्व अमरीका में पाये जाते थे। वस्तु, अन्तर केवल।

ही है कि अदालतें इन मजदूरों तथा इनकी मजदूरी पर जमींदारों का निरपेक्ष स्वामित्व नहीं स्वीकार करती। ये कानूनी रूप से स्वतन्त्र हैं पर वस्तुतः गुलाम हैं।'

किसानों का कर्जा

किसान न केवल गरीब, नासमझ और अत्याचार-पीडित ही हैं, बल्कि उनके सिर पर कर्जों का बड़ा बोझ भी है जिससे वे दबे जा रहे हैं। सन् १९३० में प्राविन्द्यल वैकिंग इन्क्वायरी कमिटी ने किसानों के कर्जों का जो अनुमान लगाया था, यद्यपि वह सर्वांश में सत्य नहीं है, तो भी उससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि किसानों पर कर्जों का कितना भारी बोझ है। प्रत्येक प्रान्त में किसानों पर कर्जा करोड़ रुपयों में इस प्रकार था—

बम्बई-सिन्ध	८१	बिहार-उड़ीसा	१५५
मद्रास	१५०	आसाम	२२
बंगाल	१००	केन्द्रीय प्रदेश	१८
संयुक्तप्रान्त	१२४	ब्रह्मा	५०५
पंजाब	१३५	कुर्ग	३५५५ लाख
मध्यप्रान्त-बरेल	३६५		

उद्योग-व्यवसाय

विगत अर्द्धशताब्दी में, विशेष रूप से विगत महायुद्ध के बाद से, भारत में उद्योग-धन्धों की पर्याप्त उन्नति हुई है। एक समय था जब भारत में उँगलियों पर गिनी जाने लायक मिले थे और उनमें जो माल तैयार होता था वह विदेशी माल के मुकाबिले बहुत ही घटिया था। इस समय (सन् १९४०-४१) ब्रिटिश भारत में कुल रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या १०,७८२ है। ९,७४३ कारखाने चले जिनमें ६,०८६ कारखाने सालभर काम करते रहे और ३,६५७ ऋतु-विशेष में।

१ जे० एम० मेहता : 'ए स्टडी ऑफ रूलर इकनॉमी ऑफ गुजरात'

कारखाने

रुई की धुनाई, कपड़े की बुनाई, कोच बनाने, मोटरकारों की मरम्मत करने, इजीनियरिंग, छपाई, जिल्दसाजी और चावल के उद्योगों में काफी उन्नति हुई है। मोजे, तेल, ग्लास, सीमेंट, ईट, टाइल, चाय और कपड़ा बनाने के उद्योगों का भी पर्याप्त विस्तार हुआ है।

इन कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की संख्या सन् १९३८ में १७,३८,००० थी। यह अवतक की संख्याओं में सबसे अधिक है। रुई के उद्योग में ५,१२,००० और जूट के उद्योग में २,९५,००० मजदूर लगे हुए हैं। जिनमें २४१,००० स्त्री-मजदूर और १०,७४२ बालक हैं।

पैदावार

महायुद्ध के बाद भारतीय उद्योग-धन्धों में जो प्रगति हुई उसका अनुमान निम्नलिखित विवरण से भली भाँति लग जाता है

भारत में विदेशों से आनेवाला माल

वस्तुएँ	सन् १९१३-१४	सन् १९३८-३९
सूती वस्त्र	५३,२०,५१,०००	२२,६६,२०,०००
लोहा व इस्पात	१२,४८,५०,०००	६,६७,२०,०००
ऊनी कपड़ा	३,२४,६०,०००	२,८१,९०,०००
कोच का सामान	१,६१,९२,०००	१,२५,१२,०००
तम्बाकू	५२,७४,०००	४०,२७,०००
सीमेंट	५२,७७,०००	१०,०५,०००
शक्कर	१२,९२,५०,०००	४५,४८,०००
मिट्टी का सामान	५२,१९,०००	३९,१९,०००
तिलाने	४०,०५,०००	३७,३०,०००
दियासलाई	१,५३,३१,०००	२३,५२,०००
साबुन	६१,८७,०००	२२,४४,०००
छाते	४१,९४,०००	१४,८७,०००
	<hr/> ८८,२९१,००० रु०	<hr/> ३६,२४,२४,००० रु०

सन् १९३८-३९ में भारत से निम्नलिखित माल विदेशों में भेजा गया :

चीजें	रुपये	चीजें	रुपये
कच्चा जूट	१३,३९,६७,०००	खाने-पीने की चीजें	५९,३२,०००
तैयार जूट	२६,२६,११,०००	रंगने तथा चमड़ा	
कच्ची रुई	२४,६६,६५,०००	वनाने की चीजें	५९,११,०००
तैयार रुई	७,११,७९,०००	खाद	३७,२२,०००
चाय	२३,४२,४७,०००	मोम	३६,२५,०००
बीज	१५,०९,२२,०००	दवाइयाँ	२७,८३,०००
अनाज, आटा-दाल	७,७४,१२,०००	सुअर के बाल	२६,३२,०००
चमड़ा	५,२७,५८,०००	शक्कर	२४,१८,०००
धातु	४,९१,०२,०००	हड्डियाँ	२३,७१,०००
ऊन	३,८४,९५,०००	लकड़ी	२३,६६,०००
कच्चा चमड़ा	३,८४,६७,०००	ब्रुश तथा ब्रुशिंग	१५,७१,०००
खली	३,०१,२०,०००	इमारती सामान	१४,७५,०००
तम्बाकू	२,७५,६७,०००	पोशाक	१२,६२,०००
फल-तरकारी	२,२६,८६,०००	गन्धक	१०,८९,०००
कोयला व कोक	१,३६,२५,०००	चारा	८,९६,०००
लाख	१,२६,६५,०००	जानवर (जीवित)	८,२३,०००
भोडर	१,१४,१२,०००	रंगी	८,१२,०००
तेल	१,०३,३९,०००	रेशम	४,२६,०००
ताँबा	९६,०१,०००	टैलो	३,२७,०००
मसाले	७३,६६,०००	सींग	२,३६,०००
कहवा	७५,११,०००	वस्त्रियाँ	२,०००
गर्जा	७१,९८,०००	अफीम	१,०००
कच्ची रबड़	७१,५८,०००	दूसरी चीजें	५,८०,७७,०००
मछलियाँ	६९,२९,०००		१,६२,९२,५५,००० रुपये

भारत के आयात-निर्यात का तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित अंकीय विवरण दिया जा सकता है—

वर्ष	आयात (रुपयों में)	निर्यात (रुपयों में)
१९२५	१,१५,३५,७०,१४४	१,४७,२५,०६,८२०
१९२६	१,३२,२८,६४,६५३	१,५१,६६,९७,४९७
१९२७	१,२५,२४,०५,४२५	१,९६,१२,४६,२८६
१९२८	१,३४,४२,३२,३८५	१,६०,५२,३६,९९४
१९२९	१,७३,७८,७६,०८९	१,८०,९२,४२,२२१

इंवायण्ट स्टॉक कम्पनियों की पूँजी

भारत में इस समय विविध उद्योग-धन्धों में कम्पनियों की जो पूँजी लगी हुई है, उसका अध्ययन यह बताता है कि देश में उद्योग-धन्धों में वृद्धि हो रही है। १९३६-३७ के अंकीय विवरण के अनुसार भारत के बैंकिंग, वाणिज्य, जहाजी, रेलवे तथा ट्रामवे कम्पनियों, रुई, जूट, ऊनी तथा रेशमी मिल, रुई व जूट के प्रेस, आटे के मिल, चाय, दूसरे मिल, कोयला खनन आदि उद्योग-धन्धों और व्यवसायों की भारत में रजिस्टर्ड कम्पनियों में २ अरब ९७ करोड़ ९३ लाख ४४ हजार रुपये की और विदेशों में रजिस्टर्ड कम्पनियों में ७ अरब २५ करोड़ ३९ लाख २ हजार पाँच की पूँजी लगी हुई है।

मजदूरों की दशा

भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास में पूँजी और उत्पादन के अन्य माध्यमों का तो महत्त्व है ही मानव की श्रम-शक्ति का महत्त्व भी कम नहीं है। पूँजीपति और भित्ति-भाँटिक, वास्तव में, मजदूरों की इस धन-हीनता से ही नागमाऊ होने हैं। अब मजदूरों का उद्योग में विशेष स्थान है। नए उद्योगों का विकास होने लगी है, तबसे मिल में काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी घटित होती जा रही है।

मजदूरों की मजदूरी, काम करने के घण्टे, उनके साथ भाँटियों का व्यवहार, वेतन आदि की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबन्ध, उनके

बालको की शिक्षा तथा स्वास्थ्य-रक्षा की व्यवस्था, अपाहिज तथा वृद्ध मजदूरों की वृद्धावस्था में सहायता, छुट्टियों के नियम, वेतन-वृद्धि तथा भत्तों के नियम आदि ऐसे प्रश्न हैं जिनका अभी तक समुचित समाधान नहीं हो सका है। यही कारण है कि आज मजदूरों में घोर असन्तोष और अशान्ति है। उनके पास अपनी शिकायतों के दूर कराने के लिए केवल एक ही साधन है और वह है—हड़ताल।

मजदूरों के पारिश्रमिक (मजदूरी) का प्रश्न बड़ा विकट है। बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों में मिलों और कारखानों में काम करनेवाले मजदूर अक्सर ग्रामों से आते हैं। अपने परिवारों को अपने ग्राम में छोड़कर, वे शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। ऐसे भी मजदूर हैं जो अपनी स्त्री-बच्चों को साथ ले आते हैं। कारखानों में उन्हें वेतन कम मिलता है और इस पर उन्हें शहर के खर्चीले जीवन का सामना करना पड़ता है। शहरों में मकानों का किराया अधिक होता है। एक-एक छोटी सी कोठरी में चार-चार-छ-छ स्त्री-पुरुष रहते हैं। एक-एक कोठरी में, जिसका क्षेत्रफल १२×१२ वर्गफीट होता है, कभी-कभी दो-दो तीन-तीन मजदूरों को सपरिवार रहना पड़ता है। खाना खाने, बैठने, सोने आदि के लिए ऐसे छोटे-छोटे कमरों का एक भाग ही उन्हें मुश्किल से मिलता है।

अहमदाबाद और बम्बई में मजदूरों के रहने के लिए चालें बनायी गयी है जिनका किराया उन्हें देना पड़ता है। ये चालें इतनी गन्दी तथा अस्वास्थ्यकर हैं कि इनमें पशुओं को बांधना भी अन्याय होगा।

मिल-मालिकों की ओर से अब वा म्यूनिसिपल बोर्डों ने शहरों में मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाने का प्रयत्न किया है। परन्तु अभी तक इधर जो प्रयत्न हुआ है वह नतोषप्रद नहीं है। सयुक्तप्रान्त में ४५४ क्वार्टर बनाये गये हैं। ये अधिकांश में शक्कर-मिलों की तरफ से बनाये गये हैं। मद्रास में मजदूरों के लिए कम किराये पर क्वार्टर बनाये गये हैं। कुछ नाऊ पहले डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा बम्बई में मजदूरों के लिए चालें बनायी गयी थीं। अब उनमें सुधार किया गया है और उनमें

मजदूरो को रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। २०७ चालो में से १९२ में अब मजदूर रहने लगे हैं। इन चालो में ६३,००० मजदूर रहते हैं। अहमदाबाद में म्यूनिसिपल बोर्ड ने १५६ क्वार्टर मजदूरों के लिए बनवा दिये हैं। बंगाल में २० मिलों ने अपने मजदूरों के लिए मकान बनवा दिये हैं। अजमेर-मेरवाड़ा, बिहार-उड़ीसा, मध्यप्रदेश-बरार, देहली तथा सीमाप्रांत में मजदूरों के लिए अभी कोई योजना नहीं बनायी गयी है।

कानपुर के मजदूरों की दशा की जाँच के लिए ३० अगस्त १९३७ को संयुक्तप्रान्त की सरकार ने एक जाँच-कमेटी बनायी थी। इस कमेटी के सामने कानपुर की मजदूर-सभा की ओर से एक वक्तव्य दिया गया जिसमें मजदूरों के विषय में लिखा है—

“मिलों में प्रधान-निरीक्षक के कथन से विदित होता है कि संयुक्त-प्रान्त में, जहाँ का मुख्य व्यावसायिक केन्द्र कानपुर है, कपड़ों की मशीनों पर काम करनेवाले मजदूर को ३३ रुपये और सूत कातने की मशीन पर काम करनेवाले मजदूर को २५ रुपये मासिक मिलते हैं। पंजाब, दिल्ली और बंगाल में इससे अधिक मजदूरी नहीं मिलती। बम्बई की चुनौ हुई १९ मिलों की जाँच करने से पता चलता है कि वहाँ मजदूरों को ४० रुपये १२ आने २ पाई से ५४ रुपये ७ आने तक मजदूरी मिलती है।”

मजदूर-जाँच-समिति को यह विश्वास है कि संयुक्तप्रान्त में पस्न-व्यवसाय की क़ाफ़ी उन्नति हुई है और उसने यह सिफारिश की है कि कानपुर के मजदूरों की मजदूरी में १० से १२ प्रतिशत वृद्धि कर दी जाये। कमेटी ने मजदूरों को पाँच श्रेणियों में विभाजित कर दिया है और उनकी मजदूरी में इस प्रकार वृद्धि करने की सिफारिश की है

श्रेणी	वृद्धि	कुल वेतन
१३) से १९) रु० तक २३ आने प्रति १०	अधिक से अधिक २१।)	
१९) से २५) " " २ आने " "	" " २३।)	
२५) से ३२) " " ११ आने " "	" " ३५)	
३२) से ४०) " " १ आने " "	" " ४१।)	

४०) से ५९) रु० तक ३ आना प्रति रु० अधिक से अधिक ६०॥)

मजदूरों को ४ श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिनका वेतन क्रमशः

४०) रुपये से अधिक, ३०) से ४०) तक, १५) से ३०) तक और १५) रुपये तक है और उन मजदूरों का औसत आय-व्यय रूपों में इस प्रकार है

श्रेणी	आय	व्यय	वचत	घाटा
पहली	५३-८-५	५३-५-९	०-२-८	०-०-०
दूसरी	३५-२-२	३७-५-११	०-०-०	२-३-९
तीसरी	२०-११-२	२२-२-३	०-०-०	१-२-११
चौथी	१२-१०-२	१५-५-६	०-०-०	२-११-४

३०) वेतन पानेवाले मजदूर का जीवन वगैरह इस प्रकार होता है—

	सपरिवार	अकेला
आटा	३)	२)
दाल	१॥)	१)
शाह-सब्जी	१)	॥)
नमक	१२)	३)
मसाले	१)	॥)
शाह-मिट्टी	१)	}
दूध-पानी	२॥)	
अन्य आवश्यकार्थ	१)	
लहसुन-मिर्च	२)	२)
बन्धन	१)	१)
मकान-किराया	२॥)	२)
नाई-दाई	१)	॥)
बस्त्र-दि	॥)	॥२)
सपना	१॥)	१)
अन्य आवश्यकार्थ	२)	२)
दर-दा	२)	१)
	१२२)	१२)

मजदूरों के हित के लिए कानून

मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए प्रान्तीय सरकारों ने कुछ कानून हाल में बनाये हैं जिनमें से निम्नलिखित कानून उल्लेखनीय हैं—

(१) प्रसूता-सहायक-कानून—इससे कारखानों व मिलों में काम करनेवाली स्त्री-मजदूरों के लिए प्रसव से पूर्व और उसके बाद निर्धारित समय के लिए सवेतन अवकाश देने की व्यवस्था की गयी है।

(२) मजदूर-संघ-कानून—इसके अनुसार मजदूरों को अपने कल्याण के लिए संगठन करने तथा आन्दोलन करने का अधिकार प्राप्त है।

(३) मजदूर-विवाद-कानून—इसके अनुसार मिल-मालिकों तथा मजदूरों के पारस्परिक झगड़ों को शान्तिपूर्वक निपटाने की व्यवस्था की गयी है।

(४) मजदूर-क्षतिपूर्ति-कानून—कार्यकाल में किसी मजदूर की मृत्यु हो जाये या उसे कोई शारीरिक हानि पहुँचे तो इससे उसे मुआविजा देने की व्यवस्था की गयी है।

: १६ :

राष्ट्रीय जीवन

शासन-पद्धति

आजकल भारत का शासन सन् १९३५ के भारत-सरकार-कानून अनुसार चल रहा है। इस कानून से पहले सभी भारत-सरकार-के केवल ब्रिटिश भारत में ही लागू होते थे लेकिन इस शासन-विधान सवध प्रान्तों और देशी राज्यों दोनों से है। इस विधान के दो भाग हैं। एक भाग में सघ-शासन की योजना है और दूसरे भाग प्रान्तीय शासन की।

भारतीय सघ-शासन

भारतीय सघ-राज्य के दो प्रधान भग निर्धारित किये गये हैं (१) गवर्नरों के प्रान्त और (२) देशी राज्य। इसमें चीफ कमिश्नर प्रान्त भी शामिल हैं।

भारतीय शासन में गवर्नर-जनरल और वायसराय ये दो अलग-अलग पद हैं। गवर्नर-जनरल सम्राट की ओर से भारतीय सघ सर्वोच्च शासक होगा। वायसराय की हैसियत से वह उन देशी नरेशों का नियंत्रण करेगा जो सघ-राज्य में शामिल न होंगे और उन विषयों का भी जो सम्राट् उसे सौंप दे। गवर्नर-जनरल की नियुक्ति के सम्राट् की ओर से आदेश-पत्र दिया जायेगा जिसके अनुसार वह भारत का शासन करेगा। इस आदेश-पत्र में दो बातें विशेषतः उल्लेखनीय हैं। गवर्नर-जनरल उस व्यक्ति के परामर्श से मंत्रियों को नियुक्त करेगा जिसके साथ उसके विचार में व्यवस्थापक सभा का बहुमत होगा वह अपने अधिकारों का प्रयोग मंत्रियों के परामर्श से उस समय तक करेगा जबतक कि उसकी विशेष जिम्मेदारियों में कुछ बाधा न पड़े।

भारतीय सघ-शासन की मुख्य विशेषता है उत्तरदायित्व का अभाव तथा द्वैध-शासन-प्रणाली की स्थापना। सन् १९३५ से पहले जिस प्रकार

भारत के प्रान्तों में शासन होता था, केन्द्र में भी उसी पद्धति की स्थापना की गयी है।

सेना, ईसाई-धर्म, पर-राष्ट्र नीति और पिछड़े प्रदेशों का शासन 'सुरक्षित विषय' बने गये हैं। इन विषयों का शासन-प्रबन्ध गवर्नर जनरल भारत-मन्त्री के नियंत्रण में स्वेच्छानुसार करेगा। वह अपनी सुविधा के लिए सुरक्षित विषयों के प्रबन्ध में सहायता के लिए तीन परामर्शदाता नियुक्त कर सकेगा। इस प्रकार उपर्युक्त सुरक्षित विषय और अपनी विशेष जिम्मेदारियों का छोड़कर सघ-शासन के अन्य विषयों का राज-प्रबन्ध गवर्नर-जनरल मन्त्रि-मण्डल के परामर्श से करेगा। मन्त्रि-मण्डल में ६ सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति गवर्नर-जनरल के द्वारा होगी।

गवर्नर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं—

(१) भारतवर्ष या उसके किसी भाग में शान्ति-भंग करनेवाले तत्वों का निवारण,

(२) सघ-शासन की आधिक स्थिरता और सख्त का सुरक्षित रखना,

(३) आप-सत्यक जन समुदायों के उचित हितों की रक्षा करना,

(४) सरकारी नौकरियों के सदस्यों और उनके अधिकारों की शासन-विधान द्वारा दिये गये अधिकार दिलाना और उनको रक्षा करना,

(५) व्यापारिक और जातिगत भेदभाव-सम्बन्धी उन नियमों पर अमल करना जिनकी व्यवस्था विधान के पाँचवें भाग के तीसरे अध्याय में की गयी है,

(६) इरान और इंग्लैंड के बने हुए आयात-माल के सम्बन्ध में ऐसे मामलों की रीयता जिनके कारण इस माल के साथ भेदभाव की नीति का व्यवहार होता हो,

(७) उसी रियासत और उनके नरदों के जीविकता व सन्तानों की रक्षा करना,

(८) इस बात का प्रबन्ध करना कि अपने विषय एवं अधिकारों के नियमों द्वारा नियंत्रित जातिगत मामलों के सम्बन्ध में अल्प-संख्यक जन-संख्या की रक्षा हो सके।

उपर्युक्त विषयों के शासन में गवर्नर-जनरल अपनी नीति और कार्यों के लिए भारतमन्त्री के प्रति उत्तरदायी होगा और अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य-संपादन करेगा। गवर्नर-जनरल पर भारतमन्त्री का नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त उसपर किसी भारतीय सच-सत्या या जनता का नियंत्रण नहीं है और न वह सच के प्रति उत्तरदायी ही है। वह भारत का सर्वोच्च है।

संघीय व्यवस्थापक-मण्डल में सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नर-जनरल, कौंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ असम्बली शामिल हैं। कौंसिल ऑफ स्टेट में २६० सदस्य होंगे। इनमें से १५६ ब्रिटिश भारत के और १०४ देशी राज्यों के होंगे। चुनाव साम्प्रदायिक प्रणाली के आधार पर होगा। उसके अधिकांश सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होगा। हिन्दू, सिख तथा मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव उन्हींके सम्प्रदायों के निर्वाचकों द्वारा होगा। बड़े देशी राज्यों को अकेले एक सदस्य और छोटी रियासतों को कई मिलकर एक प्रतिनिधि मनोनीत कर भेजने का अधिकार होगा। एंग्लो-इंडियन, यूरोपियन, भारतीय ईसाई और दलित जातियों के प्रतिनिधि परोक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इनके चुनाव में वे ही व्यक्ति मताधिकारी होंगे, जो प्रान्तीय व्यवस्थापक-मण्डल के सदस्य होंगे। इस कौंसिल का कार्य-काल ९ वर्ष का होगा। एक तिहाई सदस्य ३ साल के लिए, एक तिहाई ६ साल के लिए और शेष एक तिहाई ९ साल के लिए होंगे। $\frac{1}{4}$ सदस्यों का कोरम होगा और साल में एक बार अधिवेशन अवश्य होगा।

हाउस ऑफ एसम्बली में ३७५ सदस्य होंगे। इनमें से २५० ब्रिटिश भारत के और १२५ देशी राज्यों के होंगे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि विभिन्न प्रान्तों में इस प्रकार होंगे—मद्रास ३७, बम्बई ३०, बंगाल ३७, संयुक्तप्रान्त ३७, पंजाब ३०, बिहार ३०, मध्यप्रान्त व वरार १५, आसाम १०, सीमाप्रान्त ५, उड़ीसा ५, सिन्ध ५, ब्रिटिश विलोचिस्तान १, दिल्ली २, अजमेर १ और कुर्ग १। ३ प्रतिनिधि उद्योग-धन्धों के और १ मजदूरों का होगा। चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर होगा।

असेम्बली का जीवन-काल ५ वर्ष होगा। उसकी अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। असेम्बली के सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप से प्रान्तीय असेम्बली के सदस्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर होगा।

उपर्युक्त सघीय व्यवस्थापक-मण्डल के तीन अधिकार होंगे। (१) शासन-निरीक्षण (२) नियम-निर्माण और (३) आर्थिक।

गवर्नर-जनरल के सुरक्षित विषयो, विशेष उत्तरदायित्वो और व्यक्तिगत निर्णयो के कामो को छोड़कर, सघीय-मन्त्रि-मण्डल हस्तान्तरित विषयो के शासन में सामूहिक रूप से सघीय व्यवस्थापक-मण्डल के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रत्येक सदस्य को नियमानुसार मन्त्रियो से उनके कार्यों के बारे में प्रश्न पूछकर उत्तर माँगने का अधिकार होगा। वे शासन-विभाग की आलोचना करते हुए स्थगित प्रस्ताव भी रख सकेंगे। कानून बनाने की सुविधा के लिए शासन-विधान द्वारा समस्त विषय प्रान्तीय और सघीय दो श्रेणियों में विभाजित कर दिये हैं। सघीय व्यवस्थापक-मण्डल को सम्पूर्ण सघीय विषयो पर कानून बनाने का अधिकार होगा।

कोसिल ऑफ स्टेट तथा असेम्बली दोनों का एक-एक निर्वाचित अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तथा प्रधान-उपप्रधान होगा।

प्रत्येक कानून दोनों सभाओं की स्वीकृति से बनाया जायेगा। गवर्नर-जनरल कानून बनाने के लिए दोनों या सयुक्त अधिवेशन भी आभणित कर सकेगा। उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी 'बिल' ऐक्ट नहीं बन सकेगा। गवर्नर-जनरल की स्वेच्छानुसार आर्डिनेंस जारी करने तथा कानून बनाने का भी अधिकार होगा। आवश्यकता पड़ने पर वह सारे शासन विधान को स्थगित कर उसकी जागह पर अपने हाथ में ले सकेगा।

भारतीय सभ के प्रांतो व राज्यों के पारस्परिक तालों, विभाजन-संघर्षों निपट तथा व्याख्या के लिए एक सघीय-व्यापार-तन्त्र होगा। इन व्यापार-तन्त्र में कोई भी मान्यता विधानानुसार निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा और अपील भी की जा सकेगी। प्रांतो में या देशो राज्यों

मे यदि किसी अधिकार के सबध मे झगडा होगा, तो सघीय न्यायालय को निर्णय देने का अधिकार होगा ।

सक्षेप मे यह भारत के केन्द्रीय शासन की रूप-रेखा है । विधान के अनुसार-सघ शासन की स्थापना के लिए दो शर्तों की पूर्ति आवश्यक है

(१) कम-से-कम इतने देशी राज्य सघ में शामिल होने के लिए तैयार हो जायें जो कांसिल ऑव स्टेट में ५२ सदस्य भेज सके और जिनकी जन-सख्या समस्त देशी राज्यों की जन-सख्या की आधी हो ।

(२) प्रथम शर्त की पूर्ति के पश्चात, यदि ब्रिटिश पार्लमैट की दोनों सभाएँ सम्राट से सघ-राज्य स्थापित करने की प्रार्थना करे, तो सम्राट इस आशय की घोषणा करेगे कि अमुक तिथि से सम्राट के अधीन मघ-शासन स्थापित किया जाये ।

जब सन् १९३५ मे ब्रिटिश पार्लमैट ने भारत का शासन-विधान स्वीकृत किया तभी से भारत के वायसराय लार्ड लिनलियगी द्वारा देशी राज्यों को सघ में शामिल कराने के लिए प्रयत्न हो रहा था । परन्तु नरेशो ने अपनी स्वीकृति नहीं दी थी । इतने ही मे सितम्बर १९३९ मे इंग्लेड और जर्मनी मे युद्ध छिड गया और सरकार ने भारतीय सघ की स्थापना के प्रयत्न को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया ।

भारतीय लोकमत ब्रिटिश पार्लमैट द्वारा प्रस्तावित इस सघ-योजना के विरुद्ध शुरु से ही है । कांग्रेस तो सम्पूर्ण शासन-विधान को अस्वीकार्य घोषित कर चुकी है और सघ-योजना के अनुसार शासन की स्थापना न होने देने के लिए भी वह प्रयत्न कर रही थी । मुस्लिम लीग भी सघ-योजना के विरुद्ध है, परन्तु उसका दृष्टिकोण और उद्देश्य भिन्न है । देशी राज्यों के नरेश भी इसके विरुद्ध है ।

ऊपर कहा जा चुका है । कि भारतीय शासन-विधान के 'सघ-शासन' और 'प्रान्तीय स्वराज्य' दो प्रमुख अंग हैं । इनमें से 'प्रान्तीय स्वराज्य' की स्थापना भारत के ग्यारहो प्रान्तो मे १ अप्रैल १९३७ से हो गयी है । अब प्रश्न यह है कि 'प्रान्तीय स्वराज्य' की स्थापना के बाद से 'सघ-शासन'

तक के काल में भारत का केन्द्रीय शासन किस प्रणाली पर होगा ? इस सक्रमण-काल में सपरिपद् गवर्नर-जनरल सघीय शासन-विभाग का काम करेगा और केन्द्रीय व्यवस्थापक-मण्डल सघीय व्यवस्थापक-मण्डल का । गवर्नर-जनरल की सारी जिम्मेदारियाँ नये विधान के अनुसार होगी । वह भारत-मन्त्री के आधीन होगा । फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल रेलवे ऑथारिटी तथा फेडरल कोर्ट की स्थापना हो चुकी है । शासन-विधान में परिवर्तन पार्लमेंट द्वारा अथवा आर्डर-इन-कौंसिल द्वारा ही हो सकेगा ।

प्रान्तीय शासन-प्रणाली

भारत में दो प्रकार के प्रान्त हैं (१) गवर्नर के प्रान्त और (२) चीफ कमिश्नर के प्रान्त । गवर्नरों से शासित ११ प्रान्त हैं—बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त-प्रान्त, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, आसाम, सिंध, सीमा-प्रान्त और मध्यप्रान्त तथा चीफ कमिश्नरों के प्रान्त हैं—ब्रिटिश बिलो-चिस्तान, अजमेर-मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग अन्डमान-निकोबार और पथ-पिपलोदा ।

सन् १९३५ के विधान के अनुसार केवल उपर्युक्त ११ गवर्नरों के प्रान्तों में ही उत्तरदायी शासन की स्थापना की गयी है । इसीको 'प्रान्तीय स्वराज' कहा जाता है । गवर्नर-जनरल की भाँति गवर्नरों को भी नियुक्ति के समय आदेश-पत्र मिलता है । इस आदेश-पत्र में यह बतलाया जाता है कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं ? गवर्नर उस व्यक्ति के परामर्श से अपने मंत्रियों को नियुक्त करेगा जिसके साथ, उसके विचार में, प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा (असेम्बली) का बहुमत हो । वह अल्पसंख्यक जन-समुदायों के प्रतिनिधियों को जहाँ-तक संभव होगा, मिलाने की कोशिश करेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि समस्त मन्त्रि-मण्डल में व्यवस्थापक-मण्डल को विश्वास हो । वह मन्त्रि-मण्डल के संयुक्त उत्तरदायित्व पर जोर देगा । प्रान्तीय गवर्नर अपने शासन-संबन्धी अधिकारों का उपयोग मंत्रियों के परामर्श से तबतक

करेगा जबतक उसके विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करने में कोई बाधा न पड़े। विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करने में बाधा पड़ने पर वह मंत्रियों के परामर्श से प्रतिकूल व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य-संपादन करेगा।

प्रत्येक प्रान्त के शासन में गवर्नर की सहायता करने और उसे परामर्श देने के लिए एक मंत्रि-मंडल होता है। मंत्रि-मंडल के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। किसी प्रान्त में ३ मंत्री हैं, किसी में १०, किसी में ६। मंत्रियों की नियुक्ति व्यवस्थापक-मंडल में बहुमत-दल के नेता के परामर्श से गवर्नर द्वारा की जाती है। उसी बहुमत-दल का नेता प्रधान-मंत्री होता है। प्रत्येक मंत्री का व्यवस्थापक-मंडल का सदस्य होना आवश्यक है।

गवर्नरों के विशेष उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं—

(१) प्रान्त या उसके किसी भाग में शान्ति-भंग करनेवाले खतरों को दूर करना,

(२) अल्प-संख्यक जनसमुदायों के उचित हितों की रक्षा करना,

(३) सरकारी नौकरियों के सदस्यों और उनके आश्रितों को शासन-विधान द्वारा दिये गये अधिकारों को दिलाना और उनके उचित अधिकारों की रक्षा करना,

(४) इंग्लैंड और ब्रह्मा के बने हुए जायात माल के मन्वथ में ऐसे कामों को रोकना जिनके कारण इस माल के साथ भेदभाव-मन्वथी नीति का व्यवहार होता हो,

(५) प्रान्त के जिन भागों को नये शासन-विधान के अनुसार पथक् रोपित किया जाये उनके शासन तथा सुव्यवस्था का प्रबंध करना,

(६) देशी राज्यों के अधिकारों और उनके नरेशों के अधिकारों और मर्यादा की रक्षा करना,

(७) गवर्नर-जनरल के उन आदेशों पर अमल करना जो वह अपने व्यक्तिगत निर्णय अथवा विवेक के द्वारा किये गये कार्यों के लिए जारी करे।

उपर्युक्त विषयों का शासन प्रान्तीय गवर्नर स्वेच्छानुसार करते हैं। इस प्रकार प्रान्तों में आज भी पूर्ण उत्तरदायी शासन-प्रणाली जारी नहीं है। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त और भी कार्य हैं जिन्हें गवर्नर अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय से करते हैं और जिनके लिए वे प्रान्तीय व्यवस्थापक-मण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते।

गवर्नरों के अधिकार

गवर्नरों को तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं—शासन-संबंधी (Executive), व्यवस्था-संबंधी (Legislative) तथा आर्थिक (Financial)।

(१) शासन-सम्बन्धी अधिकार—

- (१) मन्त्रि-मंडल की नियुक्ति,
- (२) मन्त्रि-मंडल के अधिवेशनों का सभापतित्व,
- (३) एडवोकेट जनरल की नियुक्ति तथा पदच्युति,
- (४) आतंकवाद के दमन के लिए विशेष व्यवस्था,
- (५) मन्त्रि-मंडल के कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाना,
- (६) वैधानिक शासन-पद्धति के असफल होने पर अपने विवेक के अनुसार घोषणा द्वारा उसके अन्तर्गत उल्लिखित सारे काम अपने विवेक या इच्छानुसार कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार, हाई-कोर्ट के अधिकारों के अतिरिक्त, किसी भी प्रान्तीय शासन-संस्था के अधिकारों को स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की घोषणा की सूचना भारत मंत्री द्वारा पार्लमेंट को देनी पड़ती है। छ मास बाद इसका कार्यकाल पार्लमेंट की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। इस घोषणा के अनुसार शासन अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक किया जा सकता है।^१

१ यूरोपीय युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेसी मन्त्रि-मंडलों द्वारा त्याग-पत्र दे देने के बाद नवम्बर सन् १९३९ से भारत के उन प्रान्तों (मद्रास, बम्बई, सयुक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा सीमाप्रान्त) में गवर्नरों द्वारा परामर्शदाताओं की सहायता से शासन हो रहा है। प्रान्तीय व्यवस्थापक-मण्डल स्थगित कर दिये गये हैं।

(२) व्यवस्था-संबंधी अधिकार—

(१) व्यवस्थापक सभाओं के अधिवेशन आमंत्रित करने तथा विसर्जन करने का अधिकार,

(२) व्यवस्थापक-मंडल भंग करने का अधिकार,

(३) दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित करना,

(४) सदस्यों या मंत्रियों का त्यागपत्र मंजूर करना,

(५) प्रान्तीय व्यवस्थापक-मंडल द्वारा पास कानूनों पर स्वीकृति देना या न देना गवर्नर-जनरल के लिए सुरक्षित रखना,

(६) किसी भी कानून के मसविदे को पुनर्विचार के लिए पुनः व्यवस्थापक सभा में भेजना,

(७) आर्डिनेंस जारी करना,

(८) गवर्नर के कानून बनाना और जारी करना,

(३) आर्थिक अधिकार—

(१) प्रान्तीय व्यय की सारी मांगें गवर्नर की सिफारिश पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा में पेश की जाती हैं। व्यय के दो भाग हैं—

(अ) प्रांतीय व्यय का वह भाग जिसका उल्लेख विधान में किया गया है।

(ब) वह व्यय जिसकी मांग प्रथम भाग के अतिरिक्त पेश की जाती है।

अमुक मांग प्रथम भाग की है या द्वितीय की—इसका निर्णय गवर्नर पर निर्भर है। प्रथम भाग की मांग पर व्यवस्थापक सभा को मत देने का अधिकार नहीं है। द्वितीय भाग की मांगों पर सभा की राय जरूरी है।

प्रान्तीय व्यवस्थापक-मंडल

नये विधान के अनुसार भारत के केवल छ प्रान्तों बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, बिहार और आनाम में व्यवस्थापक-मंडल के अन्तर्गत दो सभाएँ हैं जो कांसिल और असेम्बली कहलाती हैं। शेष ५ प्रान्तों में केवल एक व्यवस्थापक सभा है जो असेम्बली कहलाती है। प्रान्तीय कांसिलें म्याथी मस्याएँ हैं और उनका कार्यकाल ९ वर्ष का है। प्रति

तीसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य नये चुने जाते हैं। उसके सगठन का आधार साम्प्रदायिकता है। असेम्बली की रचना भी साम्प्रदायिक है।^१

व्यवस्थापक-मण्डल के अधिकार तीन प्रकार के हैं—(१) शासन-नियन्त्रण (२) कानून निर्माण (३) आर्थिक।

(१) शासन नियन्त्रण—

प्रान्तीय गवर्नर अपने विवेक और व्यक्तिगत निर्णय के कामों को छोड़कर शेष सब कार्य अपने मन्त्रि-मण्डल की सहायता एवं परामर्श से करते हैं। गवर्नर के द्वारा किये जानेवाले उन कार्यों पर जिन्हें वे अपने व्यक्तिगत निर्णय या विवेक से करते हैं प्रान्तीय व्यवस्थापक-मण्डल का कोई अधिकार नहीं है। व्यवस्थापक-मण्डल का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी विभाग की नीति व कार्य के सवध में प्रश्न पूछ सकता है और मन्त्रियों को ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। शासन-नीति के विरोध के लिए व्यवस्थापक सभा के अधिवेशन को स्थगित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर मन्त्रि-मण्डल को त्याग-पत्र देना पड़ता है।

१ प्रान्तीय कौंसिलो का सगठन इस प्रकार है—

प्रांत	सामान्य मु० यूरो० हि० ईसाई			असेम्बली द्वारा गवर्नर द्वारा योग		
				नियुक्त	नियुक्त	
मद्रास	३५	७	१	३	८ से १०	५६
बम्बई	२०	५	१		३ से ४	३०
बंगाल	१०	१७	३	२७	६ से ८	६५
संयुक्तप्रांत	३४	१७	१		६ से ८	६०
बिहार	९	०	१	१२	३ से ५	३०
असम	१०	२	२		३ से ५	२२

प्रान्तीय असेम्बलियों का सगठन इस प्रकार है—

प्रान्त	कुल सदस्य	हिन्दू	दलितों के सुदक्षित	स्थान	पिछड़ी जातिवां व	प्रदेश	सिक्ख	मुसलमान	एंगलो इंडियन	यूरोपियन	हिं० ईसाई	ब्यापार-मध	मजदूर	जमींदार	विश्वविद्यालय	महिला
मद्रास	२१५	१४६	३०		१		०	३३	०	२	०	२	१	२	०	२
बंगाल	१७५	११४	१५		१		०	१६	२	१	२	७	१	२	०	०
बम्बई	२५०	७८	३०		०		०	७१	३	२	२	१	२	२	०	०
सयूक्तप्रांत	२२८	११०	२०		०		०	१३	१	२	२	१	२	२	०	०
पंजाब	१७५	४२	७		०		३३	८७	१	२	२	१	२	२	०	०
बिहार	१५२	८६	१५		७		०	१६	१	२	२	१	२	२	०	०
मध्यप्रान्त	११२	८४	२०		१		०	१६	१	२	२	१	२	२	०	०
आसाम	१०८	७७	७		१		०	१६	०	२	२	१	२	२	०	०
सीमाप्रान्त	५०	१	०		०		३	३६	०	०	०	०	०	०	०	०
उड़ीसा	६०	४७	५		५		०	३	०	०	०	०	०	०	०	०
सिन्ध	६०	१८	०		०		०	३३	०	०	०	०	०	०	०	०

करता है और सुचारु रूप से काम चलाने के लिए अर्थ-समिति, शिक्षा-समिति, जल-व्यवस्था-समिति, पब्लिक वर्कमें कमेटी आदि उपसमितियाँ निर्वाचित करता है।

म्युनिसिपल बोर्ड अपने कार्य-संचालन में एक बड़ी सीमा तक स्वतन्त्र है, परन्तु कमिश्नर और सरकार का उनपर नियंत्रण होता है। नागरिक जीवन को अधिक-से-अधिक सुखी बनाना ही इनका मुख्य लक्ष्य है। वे जनता की प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियमों का पालन कराते हैं, भोजन की शुद्धि और पवित्रता की रक्षा कराते हैं, मकान आदि बनाने के लिए मजूरी देते हैं और अपने नगरवासियों पर अनेक तरह के कर भी लगाते हैं।

ज़िला-बोर्ड

ज़िले के प्रबन्ध के लिए प्रायः प्रत्येक ज़िले में एक बोर्ड होता है, जिन्हें प्रान्तीय सरकार बनाती है। भारत में कुल २०७ ज़िला बोर्ड हैं। इनकी भी रचना, सगठन, कार्य-प्रणाली, अधिकार इत्यादि म्युनिसिपल बोर्ड के समान ही हैं और चुनाव भी साम्प्रदायिक प्रणाली के आधार पर होता है।

ग्राम-पंचायतें

प्रत्येक प्रान्तीय सरकार अपने प्रान्त में ग्राम-पंचायत-कानून द्वारा ग्राम-पंचायतों की स्थापना करती है। (वगाल में इन्हें यूनियन-बोर्ड कहा जाता है) ये ग्राम-पंचायतें ग्रामों के स्थानीय मामलों से सम्बन्ध रखती हैं। प्रत्येक ग्राम या कई ग्रामों की एक ग्राम-पंचायत होती है। इसकी सदस्य-संख्या ५ या इससे अधिक होती है। ग्राम-पंचायत के सदस्य, जिन्हें सरकार मनोनीत करती है, 'पंच' कहलाते हैं। कहीं-कहीं (जैसे मध्यप्रान्त में) पंचों का चुनाव होता है और कहीं-कहीं (जैसे सयुक्तप्रान्त में) उनकी नियुक्ति कलेक्टर करता है।

इन पंचायतों के अधिकार दो प्रकार के हैं—(१) न्याय-संवर्ध और (२) शासन-संवर्ध।

संयुक्त-प्रान्त में ग्राम-पचायते निम्नलिखित फौजदारी-दीवानी सगडो ही जांच करता और फैसले देती हैं—

- (१) २५) रुपये तक के रुपये-पैसे के मुकद्दमे,
- (२) साधारण मार-पीट या १०) रुपये तक की चोरी या १०) रुपये तक की हानि या जानबूझकर अपमान करने के फौजदारी मुकद्दमे,
- (३) जानबूझकर जानवर पकड़ने और स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों] पर ध्यान न देने के मुकद्दमे ।

ग्राम-पचायतो को फौजदारी के मामलो में १०) रुपये, मवेशियों के मामलो में ५) रुपये और स्वास्थ्य-सम्बन्धी मामलो में १) रुपये तक ज़ुर्माना करने का अधिकार है, परन्तु मुचलके की कार्रवाई करने पर जमानत लेने अथवा कंद् की सज़ा देने का अधिकार नहीं है ।

पचायतो के शासन-सम्बन्धी-कार्य निम्नलिखित हैं—

ग्रामों में सड़के बनाना, रास्ते बनाना, नये कुएँ बनाना, तालाबों और कुओं की सफाई, स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों की देखभाल, ग्रामवालों की शिक्षा, उनके खेल-तमाशों का प्रबन्ध, स्मशान-भूमि की व्यवस्था आदि । लेकिन बंगाल के 'यूनियन बोर्ड' के अधिकार क्षेत्र में सफाई, सार्व-जनिक हित के काम आदि की भी देखभाल होती है ।

राष्ट्रीय नवजागरण

राष्ट्रीयता का उदय

पृथ्वीराज के पतन के बाद से ही मुस्लिम शासन की जड़ जमी, जो मुगल साम्राज्य के निर्मूल होने पर उखड़ी, किन्तु उसको निर्मूल करनेवाली भी एक विदेशी सत्ता ही थी । मुगल खानदान के सदियों लम्बे शासन-काल में ही अंग्रेजों ने भारतवर्ष में अपना सिक्का जमाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था । मन् १६०८ में व्यापार के लिए आये हुए अंग्रेजों ने सूरत नगर में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनायी । इसके तीन साल बाद इंग्लैण्ड के राजा ने सर टामस रो को जहाँगीर के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त करके भेजा । इसी समय में भारत में

अंग्रेजी व्यापार की जड़ जम गयी। धीरे-धीरे तराजू के साथ-साथ तलवार का राज्य भी जमने लगा।

मुगल शासन-काल और कम्पनी के शासन-काल में भारतीय जनता पतन की सीमा तक पहुँच चुकी थी। राजनीतिक पराधीनता के साथ-साथ भारतवासियों में सामाजिक तथा धार्मिक पतन के लक्षण भी साफ-साफ दिखायी देने लगे। दस्तकारियों और ग्रामोद्योगों के नाश के साथ-साथ संस्कृति, कला तथा साहित्य का भी ह्रास होने लगा। हिन्दू लोग ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित होने लगे और अपनी भाषा, साहित्य और धर्म का परित्याग कर विदेशी (ईसाई) धर्म, संस्कृति तथा भाषा को अपनाने लगे।

एक ओर भारतीय जीवन में इस अवाञ्छनीय परिवर्तन ने हिन्दू समाज के सामने एक भयानक समस्या ला दी, दूसरी ओर कम्पनी के शासक मनमाने ढंग से जनता का शोषण करने लगे। मई १८५७ में जो भारतीय विद्रोह (गदर) हुआ वह इसी दुःशामन के प्रति विद्रोह था। यह भारत का अन्तिम सशस्त्र विद्रोह था जिसमें राजा-रक्त मभी ने भाग लिया था।

इस प्रकार भारत में राष्ट्रियता के उदय का बीज वहाँ के विदेशी शासन की दमन और शोषण-नीति में ही छिपा हुआ है।

हमारे जाचार-विचार, धर्म, संस्कृति आदि की भावनाओं को उदर-वादी हानिकारक पाश्चात्य शिक्षा का एक व्याम यह भी हुआ कि भारतीयों में पश्चिम के नवीन राजनीतिक आदर्श तथा विद्वान्ता को प्रवृत्त करने की प्रवृत्ति हुई। भारतीयों में विदेशी में अथर्वन के लिए गये और वहाँ के स्वतन्त्र आत्मरक्षण में उन्होंने नयी प्रेरणाएँ पायीं। विदेश में स्वतन्त्रता और समानता का जेमा स्वल्प उन्होंने देा, स्वयं में साम्राज्य पर उनका उन्होंने अनुभव पाया। इनसे उन्हें अपनी गौरवशालि या बोन हुआ। कल्ल विविध वर्ग में जातीय उदरग हुआ।

उन्नीसवीं सदी ने भारतीयों में राष्ट्रिय पुनरुद्धार-का भावना का स्वयं हुआ। राजा राममोहनराय ने उपायन प्रवृत्त मना है।

स्थापना की। महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर और श्री केशवचन्द्रसेन ने उनके कार्य में सहयोग दिया। बम्बई में प्रार्थना-समाज स्थापित हुआ। न्यायमूर्ति रानाडे, सर रामकृष्ण भडारकर और सर नारायण चन्द्रावरकर ने बम्बई में हिन्दू-समाज-सुधार आन्दोलन की नींव डाली। श्री ईश्वरचन्द्र विद्या-सागर ने विधवा-विवाह आन्दोलन का श्रीगणेश किया। श्री प्यारीचरण सरकार ने मद्य-निषेध-आन्दोलन द्वारा जनता के स्वास्थ्य-निर्माण में योग दिया। महर्षि दयानन्द ने 'आर्य-समाज' की स्थापना करके उनके द्वारा ज्ञान-प्रचार से अधविश्वासों या रूढ़ियों को छिन्न-भिन्न करने का काम किया। स्वामी दयानन्द ने अपने ग्रन्थ "सत्यार्थ-प्रकाश" में लिखा है कि "विदेशी राज्य से, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य, चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियाँ क्यों न हों, अच्छा होता है।" आर्य-समाज ने भारत में धार्मिक जाग्रति के साथ-साथ सामाजिक सुधार तथा राजनीतिक स्वाधीनता का भी मार्ग दिखाया।

मद्रास प्रान्त में वियोसाफिकल सोसायटी (ब्रह्मविद्या-समाज) की स्थापना हुई। इसकी सचालिका श्रीमती क्लायस्टकी और उनके सह-योगी कर्नल आल्कर ने राष्ट्रीय जागरण में प्रमुख योग दिया। श्रीमती वासन्तीदेवी (ऐनी बीसेंट) ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। प्राचीन भारतीय सस्कृति के पुनरुद्धार के लिए समाज ने पर्याप्त उद्योग किया। रामकृष्ण परमहंस और उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त का भारत में ही नहीं विदेशों में, और विशेषरूप से अमरीका में भी प्रचार किया।

यद्यपि मूलतः ये आन्दोलन धार्मिक थे, किन्तु उनका एकमात्र लक्ष्य विदेशी जाति द्वारा शासित प्रजा में तबधेतना तथा नवजागरण की भावना उत्पन्न करना ही था। इन आन्दोलनों ने भारतवासियों के हृदय पर पुनः परछाया लगा दी कि जाति-संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ है, वैदिक धर्म ही प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ धर्म है, भारत ही प्राचीन इतिहास तथा गौरवपूर्ण है आदि। इन विचारधारा ने जनता में देशनिरागी की भावना उत्पन्न हुई।

धार्मिक पुनरुत्थान के साथ-साथ ही, साहित्य तथा औद्योगिक

क्षेत्रों में भी राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार होने लगा। साहित्यकारों ने अपने नाटकों, काव्यों, कहानियों, उपन्यासों और लेखों द्वारा जनता में देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता के भाव भरना शुरू किया।

राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना

जब भारत में हिमाचल में लेकर कन्याकुमारी और मिन्य से लेकर ब्रह्मा तक राष्ट्रीय भावना का जागरण हो गया तो एक राजनीतिक मगठन की स्थापना की आवश्यकता अनुभव होना स्वाभाविक ही था। फलतः बंगाल में सन् १८५१ में 'ब्रिटिश भारतीय सभा' (British Indian Association) की स्थापना हुई।

बम्बई तथा पूना में भी 'बाम्बे प्रेसोडेन्सी एसोसियेशन' तथा 'पूना सार्वजनिक सभा' खोली गयी। सन् १८७६ में बंगाल में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 'इंडियन एसोसियेशन' की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य बंगाल और सामान्यतया समस्त भारत में राजनीतिक आन्दोलन करना था। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उत्तरी भारत में भ्रमण करके अपने ओजस्वी व्याख्यानों तथा भाषणों द्वारा राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। सन् १८७७ में देहली में राज-दरबार हुआ। इसमें भारत के सभी प्रसिद्ध नेता तथा राजा-महाराजा सम्मिलित हुए। ऐसा कहा जाता है कि इस सुविशाल दरबार को देखकर श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के हृदय में एक अखिल भारतीय संस्था स्थापित करने का विचार आया और जब सन् १८८३ में कलकत्ता के एलवर्ट हाल में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ तो उसमें श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने एक अखिल भारतीय संस्था स्थापित करने पर जोर दिया। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के लिए सबसे पहले किसके हृदय में विचार पैदा हुआ, परन्तु यह तो निश्चित है कि देश में ऐसी संस्था की स्थापना के लिए वातावरण पहले से तैयार था। इंडियन सिविल सर्विस के अवकाश-प्राप्त सदस्य श्री एलेन ऑस्टेवियन ह्यूम ने इस दिशा में आगे पग बढ़ाया और २३ मार्च १८८५ में पूना में प्रथम राष्ट्रीय सभा (Indian National Union) बुलायी।

राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) की स्थापना

पूना में हैजे के प्रकोप के कारण उपर्युक्त निश्चय के अनुसार सभा न हो सकी। इसलिए प्रथम अधिवेशन बम्बई में ता० २८ दिसम्बर १८८४ को हुआ। इसमें देश के ७२ प्रमुख नेता शामिल हुए। इस अधिवेशन में केवल ९ प्रस्ताव स्वीकार किये गये। इन प्रस्तावों का सारांश इस प्रकार है—

भारत में शासन-प्रबन्ध की जाँच की जाये, भारत-मन्त्री की कौंसिल भग कर दी जाये, धारा-सभाओं में सुधार किये जाये, आई० सी० एस० की परीक्षाएँ भारत और लन्दन में साथ-साथ हों, सेना-व्यय में कमी की जाये तथा भारत में ब्रह्मा को न मिलाया जाये।

कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कुरुक्ता में दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में हुआ। इसमें ४४० प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रारम्भ में दो-तीन वर्षों तक सरकारी अफसर तथा अंग्रेज कांग्रेस के कार्य में सहयोग देते रहे, परन्तु बाद में सरकारी अफसर इसके विरोधी हो गये।

वग-भग और स्वदेशी आन्दोलन

कुछ वर्षों तक कांग्रेस के कार्यक्रम में कोई रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं रही। वह एक सुधारवादी वैधानिक सत्ता थी। जनता से भी उसका सम्पर्क नहीं के बराबर था। उसके नेता उच्च-मध्यमवर्ग के धनी और उच्च-शिक्षित जन थे। लार्ड कर्जन की दमन-नीति और बंगाल के विभाजन से जनता में असन्तोष उठ खड़ा हुआ। इसके फलस्वरूप जनता राजनीतिक आन्दोलन में दिलचस्पी लेने लग गयी। पूना में महामारी के प्रकोप के अवरोध के लिए जो उपाय काम में लाये गये, वे इतने कठोर थे कि जनता उनके कारण बड़ी पीड़ित थी। वग-भग का उद्देश्य सरकार ने बताया यह कि इससे शासन-प्रबन्ध में सुविधा मिलेगी, परन्तु वास्तव में इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय जागरण को सिधिल कर देना था।

सरकार पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत बनाकर एक

समूचा मुस्लिम प्रान्त बना देना चाहती थी, जिससे वे हिन्दुओं के विरुद्ध हर समय आन्दोलन में लगे रहे। १९०५ को १९ जुलाई को सरकार ने वग-भग का प्रस्ताव स्वीकृत किया। इसके विरोध में बंगाल में घोर आन्दोलन किया गया, परन्तु इस विरोध पर भी सरकार ने १६ अक्टूबर १९०५ को बंगाल को दो प्रान्तों में बांट ही दिया। इसी समय बंगाल में स्वदेशी-आन्दोलन का जन्म हुआ। विलायती वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। वग-भग के दो परिणाम निकले। एक तो यह कि समस्त भारत में स्वदेशी-आन्दोलन व्याप्त हो गया और दूसरा यह कि इसके गर्भ से साम्प्रदायिकता को जन्म मिला। अबतक हिन्दू-मुस्लिम नाम की कोई समस्या नहीं थी। परन्तु इसी समय से यह समस्या अपने उग्ररूप में हमारे सामने आ खड़ी हुई।

स्वराज की माँग

सन् १९०८ में कांग्रेस का ध्येय इस प्रकार निश्चित किया गया —
 'कांग्रेस का उद्देश्य भारत की जनता के लिए एक ऐसी शासन-प्रणाली की स्थापना करना है जैसी ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत उपनिवेशों में प्रचलित है। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य के दायित्वों एवं अधिकारों में समानता के साथ भाग लेना भी उसका एक उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति वैधानिक उपायों द्वारा ही की जाये' ।

सन् १९०६ में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य 'स्वराज' की प्राप्ति घोषित कर दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शब्द—'स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है'—सारे देश में प्रतिध्वनित होने लगे। इसी समय कांग्रेस में दो दल पैदा हो गये—नरम और गरम। जब सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इन दोनों दलों में तीव्र मतभेद पैदा हो गया। इस अधिवेशन में गरम तथा नरम दोनों दलों में सघर्ष हो गया। लोकमान्य तिलक गरम-दल के नेता थे और सर फीरोजशाह मेहता तथा श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी नरम-दल के। नरम-दल के नेताओं ने कांग्रेस का अधिवेशन हो जाने पर एक कमेटी

बनायी जिससे कांग्रेस का विधान तैयार किया गया। वंदे उपायो द्वारा भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करना उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। गरम-दल के नेता इसके विरुद्ध थे, इसलिए सन् १९१६ तक वे कांग्रेस से पृथक् रहे और कांग्रेस पर नरम-दल का पूरा प्रभुत्व स्थापित हो गया।

यद्यपि लार्ड कर्जन भारत से विदा हो चुके थे तो भी सरकार का दमन-चक्र पूर्ववत् चल रहा था। कांग्रेस के गरम-दल के नेताओं का देश से निर्वासन किया गया और राजद्रोह के अपराध में नेताओं को राज-वन्दी बनाया गया। इसी काल में मिंटो-मार्ले शासन-सुधार योजना के अनुसार भारत में नये शासन-सुधारों को कार्यान्वित किया गया। इस योजना द्वारा सर्वप्रथम साम्प्रदायिक चुनाव-प्रणाली को स्वीकार किया गया।

राष्ट्रीय आन्दोलन

गांधी-युग का आरम्भ

सन् १९१४ में यूरोप में जर्मनी और ब्रिटेन में महायुद्ध छिड़ा। ब्रिटिश सरकार की ओर से कांग्रेस के नेताओं को यह आश्वासन दिया गया कि महायुद्ध की समाप्ति पर भारत की आकांक्षा पूरी कर दी जायेगी। इस आशा से लाखों की सख्या में वीर भारतीयों ने यूरोप की रणभूमि में अपने प्राणों का होम किया तथा करोड़ों रुपये युद्ध-संचालन के निमित्त ब्रिटिश सरकार को दिये। महात्मा गांधी स्वयं युद्ध में घायलों की सेवा के लिए गये और बारडोली तथा खेडा आदि ग्रामों में उन्होंने सेना में भर्ती के लिए प्रचार किया। उस समय गांधीजी गाँव-गाँव में यह सन्देश सुनाते थे कि साम्राज्य की रक्षा से ही हमें स्वराज मिलेगा।

परन्तु राजभक्ति का पुरस्कार मिला—रोलट-कानून^१ के रूप में दमन। इस कानून का समस्त देश में घोर विरोध किया गया।

१ सन् १९१५ में भारत में प्रान्तिकारी-दल ने विप्लव की एक योजना बनायी, किन्तु उसका रहस्योद्घाटन हो जाने से वह सफल न

महात्मा गांधी ने रोलट-कानून के विरोध में सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू किया। उनके आदेशानुसार ६ अप्रैल १९१९ को समस्त भारत में हड़ताल की गयी और सार्वजनिक उपवास रखा गया। पंजाब में घोर दमन हो रहा था। वहाँसे गांधीजी को निमंत्रण मिला। ८ अप्रैल १९१९ को जब वे मयूरा होकर रेल द्वारा पंजाब के लिए जा रहे थे, तब पलवल स्टेशन पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बम्बई ले जाकर छोड़ दिया। अमृतसर के जलियाँवाला बाग और अहमदाबाद में हत्याकांड हुए और वहाँ मार्शल-ला (फौजी-कानून) जारी किया गया। नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से देश में अशान्ति की आग सुलगती गयी।

दमन तथा शासन-सुधार

भारत में अंग्रेजी शासन की यह एक विशेषता रही है कि वह दमन के साथ-साथ शासन-सुधार की योजनाएँ भी तैयार करके उदार-दली भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उद्योग करती रही है। एक ओर १३ अप्रैल १९१९ को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा पर, जिसमें कोई २०,००० स्त्री-पुरुष मौजूद थे, जनरल डायर ने १५० सैनिकों से गोली चलवा दी, जिसमें ४०० व्यक्ति मारे गये तथा लगभग २००० व्यक्ति घायल हुए और दूसरी ओर भारत के वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड तथा भारत-मंत्री मि० माण्टेग्यू भारत में शासन-सुधार के लिए योजना तैयार कर रहे थे।

जब अमृतसर में दिसम्बर १९१९ में कांग्रेस का अधिवेशन होनेवाला था, तो उससे २-३ दिन पहले २४ दिसम्बर को ब्रिटिश सम्राट की ओर से भारत के शासन-विधान पर स्वीकृति के हस्ताक्षर कर दिये गये।

हो सकी। भारत सरकार ने दमन के लिए भारत-रक्षा-कानून बनाया। यह युद्ध-काल में जारी रहा और युद्ध के बाद भी इसे जारी रखा गया। स्थिति पर विचार करने के लिए जस्टिस रोलट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गयी जिसने यह सिफारिश की कि दमन जारी रखा जाये।

कांग्रेस के दोनो दलों में मतभेद इतना अधिक बढ़ गया था कि उनका मिलकर काम करना असंभव था। नरम-दल के कांग्रेसी शासन-सुधारों को कार्यान्वित कर प्रान्तों में पदग्रहण करना चाहते थे और गरम-दल इससे विरुद्ध था। अंत में १९२० में नरम-दल के लोग कांग्रेस से अलग हो गये और उन्होंने उसी वर्ष कलकत्ता में अखिल भारत-व्यापी उदार-संघ (All India Liberal Federation) की स्थापना की।

असहयोग-आन्दोलन

सन् १९२० में महात्मा गांधी ने 'असहयोग आन्दोलन' का श्रीगणेश किया। कलकत्ता-कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग की नीति को स्वीकार किया। विद्यालयों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया, वकीलों ने न्यायालयों का बाँकौट किया, व्यापारियों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया तथा कांग्रेस-जनो ने धारासभाओं से त्याग-पत्र दे दिये। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियों को अपने-अपने प्रान्त में व्यक्तिगत सत्याग्रह संचालन करने की आज्ञा मिली। सबसे पहले गुजरात के बारडोली और आनन्द स्थानों में आन्दोलन किया गया।

इसी समय 'खिलाफत आन्दोलन' भी बड़े जोर से चलने लगा। मौलाना मुहम्मदअली और मौलाना शौकतअली गांधीजी के दाहिने हाथ थे। कांग्रेस में मुसलमानों की संख्या भी बढ़ गयी। १ फरवरी १९२२ को गांधीजी ने वायसरॉय को इस आशय का एक पत्र लिखा कि एक सप्ताह में सरकार अपनी नीति में परिवर्तन कर दे अन्यथा बारडोली में सत्याग्रह किया जायेगा। यह पत्र वायसरॉय के पास नहीं पहुँचा कि गोरखपुर में चोरीचोरा की दुर्घटना से सारे देश में क्षोभ पैदा हो गया। चोरीचोरा के पुलिस घाने पर कांग्रेस-भीड़ ने आक्रमण करके उसमें आग लगा दी। १३ मार्च १९२२ को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये। उनपर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया और उन्हें ६ वर्ष कैद की सजा दी गयी। इसके बाद कांग्रेस-आन्दोलन में शिथिलता आयी और कांग्रेस-जन कीतिल-प्रवेश के लिए लालायित हो उठे।

स्वराज-दल का जन्म

दिसम्बर १९२२ में गया में देशबन्धु श्री चित्तरजन दास के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस में इस समय दो दल थे— एक परिवर्तनवादी और दूसरा अपरिवर्तनवादी।

परिवर्तनवादी कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम में परिवर्तन चाहते थे। वे कांग्रेस द्वारा कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम स्वीकार कराने के पक्ष में थे। स्वर्गीय श्री चित्तरजनदास, प० मोतीलाल नेहरू, श्री श्रीनिवास अयंगर, हकीम अजमल खाँ, श्री विठ्ठल भाई पटेल जादि परिवर्तनवादी थे और श्री राजगोपालाचार्य, डा० अन्सारी आदि नेता अपरिवर्तनवादी थे। गया-कांग्रेस में पिछले दल का बहुमत था। इसलिए कौंसिलवादियों की इसमें पराजय हुई। सितम्बर १९२३ में मोलाना अबुलकलाम आज़ाद के सभापतित्व में देहली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इस प्रकार कांग्रेस के अन्तर्गत स्वराज-दल की स्थापना की गयी। कांग्रेसवादी प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारासभाओं में सदस्य चुने गये। बंगाल की धारा-सभा में देशबन्धु चित्तरजनदास के नेतृत्व में स्वराज-दल ने कार्य किया। केन्द्रीय धारासभा में प० मोतीलाल नेहरू स्वराज-दल के नेता चुने गये। इस प्रकार अगले सत्याग्रह (१९३०) तक कांग्रेसवादी सदस्य कौंसिलों के भीतर कार्य करते रहे। वे असहयोग की जिस नीति का स्वीकार करके कौंसिलों में गये उसका पालन न कर सके। इनमें शक नहीं कि विरोधी दलों के रूप में इन्होंने अवरोध-नीति का काफी प्रयोग किया।

सन् १९२७ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शासन-सुधारों की जाँच के लिए एक शाही कमीशन सर जान साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया जिसमें ७ अंग्रेज सदस्य थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नियुक्त नहीं किया गया। अतः कांग्रेस ने कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया। इसमें कांग्रेस को पूरी सफलता मिली।

पूर्ण स्वराज की ओर

मद्रास-कांग्रेस के प्रस्तावानुसार कांग्रेस कार्य-समिति ने भारत के शासन-विधान बनाने के निमित्त एक सर्व-दल सम्मेलन (All parties' Conference) आमन्त्रित किया। फलतः फरवरी १९२८ में भारत के सभी दलों का सम्मिलित अधिवेशन हुआ जिसमें निश्चय किया गया कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए शासन-विधान की रचना की जाये। मई १९२८ में बम्बई में सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ जिसने प० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में विधान की रूप-रेखा बनाने के लिए एक समिति नियुक्त की। इसने जगस्त १९२८ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट 'नेहरू-रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ के सर्वदल सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में वह स्वीकृत हुई। कलकत्ता में समस्त राजनीतिक दल, व्यापारिक तथा मजदूर-समिति विधान-निर्मात्री परिषद् (Constituent Assembly) के रूप में सम्मिलित हुए और एक प्रस्ताव द्वारा 'नेहरू-रिपोर्ट' को शासन-विधान के रूप में स्वीकार किया गया। परन्तु साम्प्रदायिक प्रश्न पर अन्तिम रूप से निर्णय न हो सका।

दिसम्बर १९२८ में कलकत्ता में प० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस हुई। इसमें पूर्ण स्वराज तथा औपनिवेशिक स्वराज के प्रश्न पर बड़ा वादविवाद हुआ। प० जवाहरलाल नेहरू तथा श्री सुभाषचन्द्र पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे और प० मोतीलाल नेहरू औपनिवेशिक स्वराज के पक्ष में। अन्त में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया गया कि ब्रिटिश सरकार 'नेहरू रिपोर्ट' को ३१ दिसम्बर १९२९ तक स्वीकार न करे तो कांग्रेस अपना ध्येय 'पूर्ण स्वराज' घोषित कर देगी। ३१ दिसम्बर १९२९ तक ब्रिटिश सरकार ने 'नेहरू-रिपोर्ट' को स्वीकार नहीं किया। प० जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रपतित्व में लाहौर-कांग्रेस में 'पूर्ण स्वराज' का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सत्याग्रह-आन्दोलन

सन् १९३० की २६ अप्रैल को कांग्रेस की ओर ने दशमर में

‘स्वाधीनता-दिवस’ मनाया गया। इस अवसर पर सार्वजनिक मनाओं में एक प्रतिज्ञा पड़ी गया। तबसे प्रति वर्ष यह राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस-मिति ने १७ फरवरी १९३० को सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू करने का निश्चय किया। गांधीजी सचालक नियुक्त हुए। मार्च १९३० को महात्मा गांधी ने वायसराय लार्ड इर्विन के समक्ष अपने पत्र में निम्नलिखित ११ मांगें रखीं। मादक-द्रव्य-निषेध, एक रुपया १६ पैस के बराबर माना जाये; मालगुजारी में ५०% कमी की जाये, सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में ५०% कमी हो, सामुद्रिक तटकर-सुरक्षण कानून बनाया जाये, राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जाये, सन् १८१८ के रेग्यूलेशन ३ तथा दण्ड-विधान की धारा १२४ अ (राज द्रोह) को रद्द कर दिया जाये, निर्वासित भारतीयों को भारत में आने की आज्ञा दी जाये, खुफिया विभाग या तो बन्द कर दिया जाये या भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया जाये, स्वदेशी वस्त्र-व्यवसाय के सुरक्षण के लिए विदेशी वस्त्र-व्यवसाय पर अधिक कर लगाया जाये, आत्म-रक्षा के निमित्त अस्त्र-शस्त्रों के रखने की आज्ञा दी जाये।

वायसराय ने इन मांगों में से एक को भी स्वीकार नहीं किया। अतः १२ मार्च १९३० को गांधीजी ने नमक-कानून भंग करके सत्याग्रह आरम्भ कर दिया।

यह सत्याग्रह-आन्दोलन पूरे एक वर्ष तक जारी रहा। इसमें हजारों की सख्या में कांग्रेसवादियों को जेल-यात्रा करनी पड़ी। अन्त में सर तेजबहादुर सप्रू तथा श्री मुकुन्दराव जयकर के प्रयत्नों से लार्ड इर्विन और गांधीजी में ५ मार्च १९३१ को समझौता हो गया। इसे ‘गांधी-इर्विन समझौता’ कहा जाता है। इसके अनुसार सत्याग्रह स्वर्गित कर दिया गया, ब्रिटिश मालका बहिष्कार बन्द कर दिया गया, कांग्रेस कानूनी सस्था घोषित कर दी गयी, समस्त कांग्रेसी बन्दी रिहा कर दिये गये, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने की सुविधा मिल गयी, परन्तु नमक-कर कायम रहा।

गोलमज-परिपद्

गांधी-इर्विन समझौते का भंग कई प्रान्तों में किया गया। कांग्रेस ने

सरकार पर इसका दोषारोपण किया और सरकार ने कांग्रेस पर। अन्त में महात्मा गांधी, प० मदनमोहन मालवीय तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू के साथ गोलमेज-परिषद (लन्दन) में कांग्रेस के प्रतिनिधि की हस्तियत से भाग लेने गये।

जब २८ दिसम्बर १९३१ को वह वापस आये तो भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। किसानों में भारी सकट पैदा होगया था। महात्माजी के भारत आने से ५ दिन पूर्व ही प० जवाहर लाल नेहरू, श्री तसद्दुक अहमद शेरवानी तथा श्री पुरुषोत्तमदास टंडन गिरफ्तार कर लिये गये। सीमाप्रान्त में खुदाई खिदमतगार नेता खान अब्दुलगफ्फार खाँ और डा० खानसाह्य भी गिरफ्तार किये जा चुके थे। जब गांधीजी भारत में आये तो उन्होंने वायसराय लार्ड विलिंगडन से भेट करने के लिए आज्ञा मांगी, परन्तु उन्हें आज्ञा नहीं मिली। ६ जनवरी १९३२ को महात्माजी को भी राजवन्दी बना लिया गया।

ऐतिहासिक उपवास

१७ अगस्त १९३२ को ब्रिटिश प्रधान-मंत्री स्वर्गीय श्री रेमजे मैकडानल्ड ने अल्प-संख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में अपना 'साम्प्रदायिक निर्णय' (Communal Award) प्रकाशित कर दिया। गोलमेज परिषद में महात्माजी अपने एक भाषण में यह कह चुके थे कि यदि दलित जातियों को पूरक निर्वाचन दिया गया तो मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी उसका विरोध करूँगा। इस निर्णय में दलित जातियों के लिए 'विशेष निर्वाचन-पद्धति' निर्धारित की गयी, जिससे अनुसार दलित जातियों के मतदाताओं को अपने निर्वाचन-क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों को चुनने का अधिकार दिया गया और साथ ही उन्हें हिंदुओं के गुनाह में भाग देने और लड़े होने का भी अधिकार दिया गया।

गांधीजी ने इस निर्णय को दलित जातियों-नवधो बुद्धिमान-वन्द्या के विरोध में अस्पृश्यता के तत्त्व से २० दिसम्बर १९३२ को उत्तम आरम्भ

किया। उनकी जीवन-रक्षा के लिए देश भर में प्रार्थनाएँ की गयीं तथा बम्बई और पूना में दलित जातियों तथा हिन्दू नेताओं का सम्मेलन हुआ जिसके अध्यक्ष प० मदनमोहन मालवीय थे। इसमें परस्पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया और २५ सितम्बर को गांधीजी ने व्रत छोड़ा। इसके बाद गांधीजी यरवदा जेल से 'हरिजन-आन्दोलन' का संचालन करने लगे।

८ मई १९३३ में गांधीजी ने पुन आत्म-शुद्धि के लिए व्रत रखा। गांधीजी जेल से मुक्त कर दिये गये। मुक्ति के बाद गांधीजी ने राष्ट्रपति से यह सिफारिश की कि सत्याग्रह-आन्दोलन १६ मास के लिए स्थगित कर दिया जाये। अत आन्दोलन स्थगित हो गया।

१२ जुलाई १९३३ को पूना में कांग्रेस-जनों का एक सम्मेलन स्थिति पर विचार करने के लिए हुआ। इसमें यह निश्चय किया गया कि समझौते के लिए गांधीजी वायसराय से मिलें। परन्तु वायसराय ने इसे स्वीकार नहीं किया। १ अगस्त को गांधीजी ने पुन रास गाँव में सत्याग्रह करने का विचार किया। परन्तु वह पहले ही गिरफ्तार कर लिये गये। ४ अगस्त १९३३ को वह छोड़ दिये गये और उन्हें कहा गया कि यरवदा से बाहर रहे। गांधीजी ने यह आज्ञा नहीं मानी, अत उन्हें ६ ठे में फिर गिरफ्तार कर लिया गया और १ वर्ष की सजा दी गयी। जेल में हरिजन-कार्य सम्बन्धी सुविधाओं के न मिलने पर उन्होंने फिर १६ अगस्त से व्रत रखा। २३ अगस्त को उनकी हालत बहुत नाजुक हो गयी, और उन्हें मुक्त किया गया। तब उन्होंने यह प्रण किया कि मैं ४ अगस्त १९३४ तक कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे जेल जाना पड़े। तबसे वह अपना सारा समय हरिजन-सेवा में लगाने लगे।

विधानवाद की ओर

देहली में ३१ मार्च १९३४ को डा० असारी के महापतित्व में कांग्रेस-जनों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि स्वराज-दल की पुन स्थापना की जाये। यह भी निश्चय किया गया कि

केन्द्रीय धारासभा के चुनावों में भाग लिया जाये। मई १९३४ में रांची में कांग्रेसवादियों का एक दूसरा सम्मेलन हुआ। इसमें पहले सम्मेलन के प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। १८ व १९ मई १९३४ को पटना में कांग्रेस-कार्य-समिति और अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन हुए, जिनमें सत्याग्रह-आन्दोलन को स्थगित करने तथा कौन्सिल-प्रवेश का कार्यक्रम स्वीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

तदनुसार दिसम्बर १९३४ में कांग्रेस ने केन्द्रीय चुनावों में भाग लिया और उसे आशातीत सफलता मिली।

नया शासन-विधान और कांग्रेस

सन् १९३५ में जो नया शासन-विधान बनाया गया था उसे कार्यान्वित करने के लिए तैयारियाँ होने लगी। सन् १९३६ के नवम्बर मास से ही चुनाव-संग्राम शुरू हो गया। भारत के ११ प्रान्तों में से ७ में धारासभाओं के चुनावों में कांग्रेस सफल हुई।

सयुक्तप्रान्त, बम्बई, मध्यप्रान्त, मद्रास, बिहार, उड़ीसा में और बाद में सीमा-प्रान्त में कांग्रेस का बहुमत हो गया। इन प्रान्तों में कांग्रेस शासन-भार को ग्रहण करने में समर्थ थी। अतः कांग्रेस में दो प्रकार के दल पैदा हो गये। एक दल मन्त्रि-पद ग्रहण करने के पक्ष में था और दूसरा इसके विरुद्ध।

जब दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में पद ग्रहण के प्रश्न पर विचार किया गया, तो ऐसा प्रतीत होता था कि इस विषय पर कांग्रेस में तीव्र मतभेद हो जायेगा, परन्तु महात्मा गांधी ने पद-ग्रहण का प्रस्ताव अपने प्रभाव से इस सत्त के साथ स्वीकार करा लिया, कि गवर्नर अपने विशेषाधिकारों को प्रयोग न करने का आश्वासन दे दे। ऐसा आश्वासन न मिलने के कारण, कांग्रेस ने ३ मास तक मन्त्रिमण्डल नहीं बनाये। अन्त में स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाने पर जुलाई १९३७ में ६ प्रान्तों में कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल बने, बाद में

सीमाप्रान्त और आसाम में भी मन्त्रि-मण्डल बनाये गये । इस प्रकार ८ प्रान्तों में कांग्रेस का शासन स्थापित हो गया ।

कांग्रेस सध-शासन का विरोध तथा विधान का अन्त करने के लिए धारा-सभाओं में गयी थी । इस कार्य में उसे कहाँ तक सफलता मिली, यह नहीं कह जा सकता, परन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि कौंसिलों में जाकर कांग्रेस अपने वास्तविक कार्यक्रम और लक्ष्य से दूर हटकर 'शासन-संचालन' में तल्लीन हो गयी । हाँ, कुछ रचनात्मक कार्य अवश्य आरम्भ हुआ, जिससे कई लोकोपकारी सुधार हुए—मादक द्रव्य-निषेध, ग्राम-सुधार, जेल-सुधार तथा शिक्षा-सुधार ।

कांग्रेस मन्त्रि-मण्डलों का पद-त्याग

१ सितम्बर १९३९ को यूरोप में इंग्लैंड और जर्मनी में महायुद्ध छिड़ गया । भारत के वायसराय ने यह घोषणा कर दी कि इस यूरोपीय युद्ध में भारत भी ब्रिटेन के साथ है । ऐसी घोषणा करने का विधान के अनुसार वायसराय को पूरा अधिकार था । परन्तु कानूनी दृष्टि से अधिकार होने पर भी नैतिक दृष्टि से यह उचित था कि भारत को युद्ध में सम्मिलित करने से पहले भारतीय नेताओं से परामर्श किया जाता । इस स्थिति से भारतीय लोकमत बड़ा विक्षुब्ध हो गया और कांग्रेस भारत-सरकार की इस नीति से असन्तुष्ट हो गयी ।

१४ सितम्बर १९३९ को कांग्रेस कार्य-समिति ने एक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया । इसमें कांग्रेस ने अंग्रेज सरकार से कहा कि वह युद्ध और शान्ति के उद्देश्यों की घोषणा करे । यदि यह युद्ध वास्तव में प्रजातन्त्र और स्वाधीनता की रक्षा के लिए है, तो क्या ब्रिटिश-सरकार इन सिद्धान्तों को भारत में भी लागू करना चाहती है ? इस घोषणा का सरकार ने कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दिया ।

कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता चाहती है अतः भारत को स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया जाये । भारत का शासन-विधान-निर्माण करने का अधिकार वयम्क

मताधिकार द्वारा चुनी हुई विधान-निर्माणी-परिषद् (Constituent Assembly) को ही होना चाहिए ।

ब्रिटिश सरकार ने भारत में 'ओपनिवेशिक स्वराज' की स्थापना को अपना अन्तिम लक्ष्य घोषित कर दिया है, जैसा कि वह पिछली बार भी कई बार घोषित कर चुकी है । उसने इस बार यह और जोड़ दिया है कि ओपनिवेशिक स्वराज शीघ्र से शीघ्र दिया जायेगा और वह सन् १९३० के वेस्टमिंस्टर-कानून (Westminster Statute) के ढंग का होगा । परन्तु अभी तक पार्लिमेण्ट ने इस सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की । यह भी निश्चय-पूर्वक नहीं कहा गया है कि ओपनिवेशिक स्वराज कब स्थापित किया जायेगा ?

८ अगस्त १९४० को वायसरॉय ने जो घोषणा की, उससे स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ । इस प्रकार भारत की इस वैधानिक समस्या को सुलझाने का लगातार दोनों ओर से प्रयत्न किया गया, परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली ।

युद्ध-विरोधी सत्याग्रह

समझौते के लिए एक साल तक घोर प्रयत्न करने के बाद महात्मा गांधी ने प्रकट किया कि जब आज स्वयम् इंग्लैंड तकट में है, तो भारत को उससे अपनी स्वाधीनता माँगना उचित नहीं है । एक भाषण में गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि स्वाधीनता माँगने से प्राप्त नहीं की जा सकती । उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है ।

तदनुसार स्वाधीनता के प्रश्न को अलग रखकर उन्होंने भाषण-स्वातन्त्र्य के प्रश्न पर अक्तूबर १९४० में देशव्यापी व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया । गांधीजी तथा कांग्रेस, जिसके वह अधिनायक हैं, वर्तमान युद्ध में इंग्लैंड की सहायता नहीं देना चाहती । साथ ही गांधीजी इस युद्ध में ब्रिटेन की हार भी नहीं चाहते । यह ब्रिटेन के युद्ध-प्रयत्न में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं चाहते । परन्तु वर्तमान युद्ध में भारत का भाग लेना या सहायता देना अनैतिक और हिंसात्मक मानते हैं । उनके

द्वारा संचालित इस सत्याग्रह-आन्दोलन में सत्याग्रहियों ने युद्ध-विरोधी नारा लगाकर सत्याग्रह किया और जेल गये ।

मुस्लिम लीग की राजनीति

इसमें थोड़ा भी शक नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय-जीवन को विपंला बनाने में सबसे अधिक काम साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली ने किया है । सन् १९०९ में ब्रिटिश सरकार ने भारत में मुसलमानों की पृथक चुनाव की माँग को मजूर कर वास्तव में एक बड़ी भारी भूल की और सबसे भयंकर भूल तो कांग्रेस ने की—जब सन् १९१६ में उसने लखनऊ-पैक्ट को स्वीकार करके साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली को भी स्वीकार कर लिया ।

कांग्रेस की दुर्बल नीति तथा कांग्रेस-मन्त्रि-मण्डली की मुस्लिम-पक्षीय नीति ने अखिल-भारतीय मुस्लिम लीग और उसके सर्वेसर्वा श्री मुहम्मदअली जिन्ना को एक शक्तिशाली व्यक्तित्व और सत्ता प्रदान कर दी । आज भारत की मुस्लिम राजनीति पर उनका प्रभाव है, चाहे मुस्लिम जनता पर उनका प्रभाव भले ही न हो । 'प्रजातन्त्र' अध्याय में कहा जा चुका है कि मुस्लिम लीग ने उनके सभापतित्व में मार्च १९४० के लाहौर-अधिवेशन तथा अप्रैल १९४१ के मद्रास-अधिवेशन में 'पाकिस्तान का नारा लगाया है और आज वह भारत में 'पाकिस्तान' की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है ।

सकीर्ण साम्प्रदायिकता के फलस्वरूप ही सन् १९४१ के अप्रैल मास से पूर्व जिस मुस्लिम लीग का लक्ष्य भारत में पूर्ण स्वाधीनता की स्थापना करना था उसीका लक्ष्य उस वर्ष से भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गया है ।

इसमें सन्देह नहीं कि 'पाकिस्तान'-योजना का एक स्वर से सभी हिन्दुओं, कांग्रेस-जनो, सिक्खों तथा ईसाइयों ने विरोध किया है । भारत की दलित जातियाँ भी उसके विरुद्ध हैं । अप्रैल १९४० में दिल्ली में 'अखिल भारतीय आज़ाद-मुस्लिम-सम्मेलन' ने भी 'पाकिस्तान' का घोर विरोध किया ।

इस सम्मेलन में मुसलमानों की प्रमुख प्रभावशाली सस्थाओं ने भाग लिया जिनमें निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं—(१) मजलिसे अहरार (२) जमीयत-उल्-उलेमा-ए-हिन्द (३) बिहार मुस्लिम स्वतन्त्र दल (४) अजुमन ए-वतन (५) अखिल भारतीय मोमिन सम्मेलन (६) राष्ट्रीय मुस्लिम ।

इसमें शक नहीं कि भारत की वैधानिक उलझन के समाधान में साम्प्रदायिक समस्या एक बड़ी भारी अड़चन है । इसके समाधान पर ही भारत का भविष्य निर्भर है ।

नरम-दल की राजनीति

आज से बीस वर्ष पूर्व भारत में पुराने नरम-दली कांग्रेसजनों ने त्याग-पत्र देकर अखिल-भारतीय उदार-सघ की स्थापना की ।

यह उदार-सघ भारत के उच्चशिक्षित, सुसंस्कृत तथा अर्द्ध-सरकारी पजीपतियों का सघ है । इसका संगठन कांग्रेस-जैसा नहीं है, बल्कि उच्चकोटि के नेताओं का एक सघ है जिसका जनता से कोई सम्पर्क नहीं है । यही कारण है कि प्रान्तीय धारा-सभाओं में इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है । हाँ, वैद्रीय व्यवस्थापक-मण्डल—लेजिस्लेटिव असेम्बली तथा पौंसिल ऑफ स्टेट (जो माटेग्यू-चेम्सफोर्ड की योजना के अनुसार बनायी गयी थी) में इनके कुछ सदस्य हैं । इस सघ के प्रसिद्ध नेताओं में सर तेजबहादुर सप्रू, प० हृदयनाथ कुजूर, माननीय प्रकाशनारायण सप्रू, सर बधासजी अहंगीर, सर चिमनलाल सीतलपाद, माननीय श्रीनिवास शास्त्री आदि प्रमुख हैं । इसका न कोई आर्थिक कार्यक्रम है न सामाजिक । इसका राजनीतिक लक्ष्य है—भारत में भारतीयता के लिए औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करना । नीची बारबार् से लिबरल लोग अलग रहने हैं । एनी ए पे वेयर प्रस्तावों द्वारा सरकार की नीति की जाँच करना । रो में ही स मुष्ट हो लेते हैं और उसके साथ सहयोग के लिए हर हाथ में तैयार रहते हैं । वे स्वाभिमानियों (Vested Interests) की रक्षा तथा पक्षधरता (Partisanship) से अनास्थाओं का दमन करने के पक्ष में हैं ।

भारतीय ईसाई और राष्ट्रीयता

भारतीय ईसाई भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान
 रखता है। भारत के भारतीय ईसाइयों की जितनी भारतीय संस्थाएँ
 हैं, उतनी ही भारतीय ईसाई सम्प्रदायों के नाम से प्रसिद्ध हैं।
 'यस' नामान्वित जे. एन. डी. रामचन्द्र राव हैं। यद्यपि भारतीय ईसाई
 संस्थाएँ हैं, जो भी इस आधार पर मुस्लिम-श्रीमंतों
 की तरह ही वैधानिक प्रणालि तथा राष्ट्रीय-जीवन के विकास में
 योगदान करती हैं।

[illegible]

परा रह न करदी गयी हो, १० वर्ष तक कायम रहेगी।

६. सुरक्षित स्थानों के लिए दलित-वर्ग के लिए निर्वाचन-प्रणाली, जिसका उल्लेख धारा १ से ४ तक है, उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि परस्पर समझौते द्वारा उसका अन्त न कर दिया जाये।

७. प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारासभाओं में दलित-वर्ग के लिए मताधिकार लोथियन रिपोर्ट के अनुसार होगा।

८. किसी भी व्यक्ति को केवल दलित-समुदाय का सदस्य होने के कारण स्थानीय बॉर्डों के चुनावों में खड़ा होने या सरकारी नौकरियों में भर्ती होने के अयोग्य न माना जायेगा। इन दोनों में दलित-वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए प्रयत्न किया जायेगा, परन्तु प्रत्येक नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता आवश्यक होगी।

९. प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा के लिए स्वीकृत कोष में से यथेष्ट धन दलित-वर्ग की शिक्षा के लिए निर्धारित कर दिया जायेगा।

पूना-समझौते की उपर्युक्त धाराओं पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके मुख्य उद्देश्य दो हैं। पहला तो यह कि सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए दलित-वर्ग की उन्नति के लिए पर्याप्त संरक्षण और सुविधाएँ मिले और दूसरा यह कि दलित-वर्ग को नौकराज से अभिन्न बन जाये।

दूसरा उद्देश्य नहीं कि नये शासन-विधान में धारासभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलने के कारण इन जातियों को अपनी उन्नति के लिए पर्याप्त सुविधा मिले। परन्तु वे उनसे वास्तविक लाभ न उठा सकें।

६ राजनीतिक, समाज-नीति की भाँति, राजनीतिक दलों के संघर्ष का ही प्रारम्भ हुआ था। वे ग्रामों में जमींदारों के आचरण के कारण अपने मतानुसार या प्रयोग स्वरूप जाति से उबर सके। भारत में उनके कुल १५० सदस्यों में से १०० से अधिक तो छोड़कर शेष सभी राजा तो निर-धन, राजा तो राजा ही रहेंगे। उन निर्वाचन क्षेत्रों में सुयोग्य कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे जो राजा के अधिकारों के विरुद्ध लड़ें, परन्तु ऐसा नहीं होना चाहता।

यद्यपि मद्रास, सयुक्तप्रान्त, विहार—इन तीनों प्रान्तों में दलित-वर्ग के कांग्रेसी सदस्यों का बहुमत है, तो भी इन प्रान्तों के दलित-समुदाय की जनता में कांग्रेस के सदस्य बहुत ही कम हैं। कांग्रेसी उम्मीदवार के लिए मत प्राप्त कर लेना दूसरी बात है। यही कारण है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटियों में भी इनके बहुत ही कम सदस्य हैं—शायद उगलियों पर गिनने लायक। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक इन जातियों ने कांग्रेस के सन्देश को ग्रहण नहीं किया है।

दलित जातियों का कोई अखिल भारतवर्षीय दृढ़ और देशव्यापी संगठन नहीं है। इनके सुधार के लिए जो कुछ कार्य हो रहा है, वह प्रान्तीय आधार पर ही हो रहा है। प्रत्येक प्रान्त में अलग-अलग संगठन हैं। आवश्यकता है अन्तर्प्रान्तीय संगठन की।

दलित जातियों में प्रभावशाली नेतृत्व का भी अभाव तो है ही, पर उच्च शिक्षा का अभाव, आर्थिक कठिनाइयाँ, उच्च संस्कृति तथा प्रगतिशील विचार धारा का अभाव भी इनकी अवनति का एक मूल कारण है। इनके अतिरिक्त दलित जातियों पर ग्रामों में बड़े भीषण और अमानुषिक अत्याचार किये जाते हैं।

दलित जातियाँ, हिन्दू-समाज का ही अंग हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि सामाजिक दृष्टि से इनकी समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न किया जाये। केवल राजनीतिक दृष्टि से इन्हें हिन्दू समाज का अंग मान लेने से न तो इनका कल्याण हो सकेगा और न वे राष्ट्र के उपयोगी अंग ही बन सकेंगे।

सहायक ग्रन्थों की सूची

अंग्रेजी

- 1 Atharvaveda Harvard Oriental Series.
- 2 Old Testament (Bible)
- 3 G D H Cole Review of Europe to-day (1933).
- 4 Leonard Woolf Intelligent Man's Way to Prevent War (1933)
- 5 A Draught Social and Political Problems at the end of the 19th century
- 6 Ramsay Muir Nationalism and Internationalism
- 7 Beni Prasad The State in Ancient India
- 8 Beni Prasad Theory of Government in Ancient India.
- 9 K P Jaiswal Hindu Polity
- 10 Freda and Bedi India Analysed, Vol I
- 11 W B Curry The Case for Federal Union.
- 12 S Mussolini The Political and Social Doctrine of Fascism in Encyclopaedia Italiana (1932)
- 13 M K Gandhi Mahatma Gandhi's Speeches and Writings
- 14 Hobhouse Elements of Social Justice
- 15 H J Lasky Liberty in the Modern State (1937).
- 16 K P Shah Federal Structure (1938).
- 17 Shrinivas Iyengar The Problem of Democracy in India (1939)
- 18 James Bryce Modern Democracies
- 19 K M Panikkar Hinduism and the Modern World
- 20 Paul Weiss Contemporary Indian Philosophy
- 21 B R Ambedkar An Introduction of Caste
- 22 D P Mulla Principles of Mohammedan Law
- 23 D P Sharma History of the Congress
- 24 D P Sharma My Struggle

- 25 The Harijan, Poona.
26. The Leader (19 6 1941)
- 27 The Hindustan Review (July 1934).
- 28, The Indian Information (Government of India, New Delhi)
- 29 League of Nations' Statute of Court
- 30 League of Nations' Statistical Year Book, 1930-31
- 31 The Constitution of Socialist Soviet Russia

हिन्दी

- १ जवाहरलाल नेहरू मेरी कहानी
- २ मोहनदास करमचन्द गांधी हिन्द-स्वराज
- ३ रामदास गोड हमारे गांवों की कहानी
- ४ महाभारत
- ५ वेनीप्रसाद नागरिक-शास्त्र
- ६ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् गांधी अभिनन्दन-ग्रन्थ
- ७ हरिभाऊ उपाध्याय स्वामीजी का बलिदान और हमारा कर्तव्य
- ८ नान्हालाल चमनलाल मेहता भारतीय चित्रकला
- ९ भगवानदास केला नागरिक-शास्त्र
- १० मो० क० गांधी हमारा कलक
- ११ रामनारायण यादवेन्दु राष्ट्रमघ और विश्व-शान्ति
- १२ रामनारायण यादवेन्दु भारतीय शासन-विधान
- १३ वर्मा-शिक्षा-समिति की रिपोर्ट
- १४ 'सरस्वती' (जनवरी, १९३३), प्रयाग
- १५ 'हरिजन-सेवक', पूना
- १६ 'विश्वमित्र' (जगम्त १९४०), कलकत्ता
- १७ 'कर्मयोगी' (जनवरी, १९३३), प्रयाग

मन्ता साहित्य मण्डल के प्रकाशन

नवोदय-साहित्य माला

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. निरवश	स्वेट मार्टिन	1/-
2. मोती साहिब	काका कलिलकर	11/-
3. गणित प्रश्न	ऋषि निरवतलुवर	111/-
4. मन्ता मन्त्रालय अभिचार	वैजनाथ महोदय	111/-
5. निरवश	जगन्नाथरायण देव शर्मा	111/-
6. निरवश	महात्मा गांधी	111/-
7. निरवश	"	1/-
8. निरवश	स्व० चन्द्रशेखर शास्त्री	1/-
9. निरवश	अश्विनीकुमार दत्त	1/-
10. निरवश	महात्मा आनन्ददास	1/-
11. निरवश	गणेशदत्त शर्मा 'द्वन्द्व'	11/-
12. निरवश	महात्मा डा. आनन्द	11/-
13. निरवश	"	11/-
14. निरवश	गणेशदत्त शर्मा 'द्वन्द्व'	11/-
15. निरवश	महात्मा डा. आनन्द	11/-
16. निरवश	गणेशदत्त शर्मा 'द्वन्द्व'	11/-
17. निरवश	महात्मा डा. आनन्द	11/-
18. निरवश	गणेशदत्त शर्मा 'द्वन्द्व'	11/-
19. निरवश	महात्मा डा. आनन्द	11/-
20. निरवश	गणेशदत्त शर्मा 'द्वन्द्व'	11/-
21. निरवश	महात्मा डा. आनन्द	11/-
22. निरवश	गणेशदत्त शर्मा 'द्वन्द्व'	11/-
23. निरवश	महात्मा डा. आनन्द	11/-
24. निरवश	गणेशदत्त शर्मा 'द्वन्द्व'	11/-
25. निरवश	महात्मा डा. आनन्द	11/-
26. निरवश	गणेशदत्त शर्मा 'द्वन्द्व'	11/-
27. निरवश	महात्मा डा. आनन्द	11/-
28. निरवश	गणेशदत्त शर्मा 'द्वन्द्व'	11/-
29. निरवश	महात्मा डा. आनन्द	11/-
30. निरवश	गणेशदत्त शर्मा 'द्वन्द्व'	11/-

९२ ब्रह्मचर्य	महात्मा गांधी	॥॥
९३ हमारे गांव और किसान	मुख्तारसिंह	॥॥
९४. गांधी-अभिनन्दन ग्रन्थ	सर्वपल्ली राधाकृष्णन्	१॥, २॥
९५ हिन्दुस्तान की समस्याएँ	जवाहरलाल नेहरू	१॥
९६ जीवन-सन्देश	सलील जिन्नान	॥॥
९७. समन्वय	भगवान्दास	२॥
९८ समाजवाद पूंजीवाद	वर्नार्ड शॉ	॥॥
९९ मेरी मुक्ति की कहानी	म० टॉलस्टॉय	॥॥
१०० खादी मीमांसा	वालूभाई मेहता	१॥॥
१०१ बापू	घनश्यामदास बिडला	॥३॥, २॥
१०२ मधुकर	विनोबा	१॥
१०२ लडखडाती दुनिया	जवाहरलाल नेहरू	१॥
१०४ सेवाधर्म सेवामार्ग	कृष्णदत्त पालीवाल	१॥
१०५ दुनिया की शासन-प्रणालियाँ	रामचन्द्र वर्मा	१॥॥
१०६ डायरी के पन्ने	घनश्यामदास बिडला	॥॥॥, १॥
१०७ तीस दिन मालवीयजीके साथ	रामनरेश त्रिपाठी	२॥
१०८ युद्ध और अहिंसा	महात्मा गांधी	॥॥॥
१०९ महावीर वाणी	बेचरदास दोशी	१॥॥
११०. भारतीय संस्कृति	रामनारायण यादवेन्दु	१॥
१११ बिखरे विचार	घनश्यामदास बिडला	॥॥॥
११२ अहिंसा-विवेचन	किशोरलाल मशरूवाला	॥॥॥

नवजीवन-माला

१ गीता-बोध	२ मंगलप्रभात	म० गांधी	७ ७
३ अनासक्तियोग	म० गांधी	सारी ३॥ श्लोक सहित ३॥ सजित्	१॥
४ सर्वोदय	"		७
५ नवयुवको से दो बातें	प्रिन्स 'कोपाडकिन		७
६. हिन्द-स्वराज्य	म० गांधी		३॥
७ छूतछात की माया			७

८. हिमानो का सवाल	जेड ए. अहमद	३
९. ग्राम-सेवा	म० गांधी	३
१०. तादी ओर गादी की लडाई	विनोय	३
११ मनुमस्ती पालन		३
१२. गाँवो का आर्थिक सवाल		३
१३ राष्ट्रीय गीत		३
१४ सादी का महत्व	गुलजारीलाल नन्दा	३॥
१५ जय अग्नेज नहीं आये थे		३
१६ सोने की माया	हिशोरलाल मशहवाला	३
१७. सत्यवीर मुरुरात	म० गांधी	३

सामयिक साहित्य माला

१ कांग्रेस-इतिहास	(१९३५-१९३९)	१७
२ दुनिया का रगमच	जवाहरलाल नेहरू	३
३ हम कहाँ हैं ?	„	३
४ युद्ध-सकट और भारत : म० गांधी, राष्ट्रपति आदि के वक्तव्य		३
५ सत्याग्रह क्यों, कब और कैसे ? म० गांधी		३
६ राष्ट्रीय पचायत महात्माजी, जवाहरलाल नेहरू, राजाजी		३
७ देशी राजाओ का दरजा	प्यारेलाल	३
८ यूरोपीय युद्ध और भारत	म० गांधी, जवाहरलाल	३
९. रचनात्मक कार्य-क्रम	म० गांधी	३

विविध प्रकाशन

१ पण्डित मोतीलाल नेहरू	रामनाथ 'सुमन'	३
२ पण्डित जवाहरलाल नेहरू	„	३
३. सप्त सरिता	काका कालेलकर	३
४ चारा दाना और उसके खिलाने के उपाय	परमेश्वरीप्रसाद गुप्त	३
५ पशुओं का इलाज	परमेश्वरीप्रसाद गुप्त	३॥
६ उपनिषदों की कथाएँ	शकर दत्तात्रेय देव	३
७ आदर्श बालक	चतुरसेन शास्त्री	३॥

